छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **द्वितीय सत्र**

सोमवार, दिनांक 26 फरवरी, 2024

(फाल्गुन 07, शक सम्वत् 1945)

[अंक 15]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2024

(फाल्गुन 7, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वान्ह 11.00 बजे समवेत् हुई.

{अध्यक्ष महोदय, (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अरहर, उड़द, मूँग एवं अन्य दलहनी फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु बनाए गए खरीदी केंद्र

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

1. (*क्र. 2382) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में अरहर, उड़द, मूँग एवं अन्य दलहनी फसलों की खेती की जाती है? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** कण्डिका 'क' की दलहनी फसलों की खरीदी का समर्थन मूल्य कितना है? किसानों की सुविधा के लिए समर्थन मूल्य पर इन फसलों की खरीदी के लिए किन-किन जिलों में कितने खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) प्रदेश में अरहर, उड़द, मूँग एवं अन्य दलहनी फसलों की खेती की जिलेवार, फसलवार, रकबावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ** एवं **प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ख)** कण्डिका 'क' की दलहनी फसलों की खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार है-

फसल	**न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू./ क्विं.)**
अरहर	7000
उड़द	6950
मूंग	8558
चना	5440
मसूर	6425

किसानों की सुविधा के लिए समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द एवं मूँग फसलों की खरीदी के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 20 जिलों में 20 केन्द्र बनाये गये थे, जिलेवार तथा कार्यक्षेत्रवार केन्द्रों

की **जानकारी संलग्न**[1] **प्रपत्र स अनुसार** है। वर्ष 2023-24 में दलहनी फसलों का उपार्जन नहीं किया गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर में वर्ष 2022-2023 में प्रदेश में चना का रकबा 2 लाख 54 हजार 901 हेक्टेअर है । जबकि उड़द, मूंग, तुअर का रकबा मात्र 1 लाख 15 हजार हेक्टेअर है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि जब कम रकबा वाले दलहन-तिलहन की खरीदी की जा रही है तो चना को समर्थन मूल्य में खरीदने की क्या व्यवस्था की गई है, इसकी जानकारी चाहिये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि चने की जो बाजार दर है, वह समर्थन मूल्य से ज्यादा है, इसलिये उससे खरीदने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय....।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप लोगों ने तो रबी फसल को समर्थन मूल्य में खरीदने घोषणा की थी । आज तक क्यों नहीं खरीदे ? अब प्रश्न लगाने आ गये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं पुराने कार्यकाल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रही हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी सरकार ने घोषणा की रबी फसल खरीदने की घोषणा की थी कि नहीं की थी ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जबकि कम रकबा वाले को खरीदा जा रहा है...।

डॉ.चरणदास महंत :- आदरणीय अध्यक्ष जी, चन्द्राकर जी हरेक प्रश्नकर्ता को उलझाते हैं, अभी की बात हो रही है, पिछले पांच सालों की बात नहीं हो रही है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पूर्ववर्ती सरकार की बात नहीं कर रही हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सिर्फ याद दिलाने के लिये कहा है कि रबी सरकार को खरीदने की घोषणा आपकी सरकार ने की थी ।

डॉ.चरणदास महंत :- मुझे याद दिला देना, नेता प्रतिपक्ष मैं हूँ । उन [XX][2] को क्यों परेशान करते हो ?

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX] है, भईया । वह [XX] है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, अगर हम संजारी बालोद विधान सभा की बात करें तो वाटर लेवल कम हो रहा है, वाटर लेवल कम होने के कारण जो किसान लोग हैं, वह चना अधिक मात्रा

---

[1] परिशिष्ट "एक"

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

में बोआई करने की शुरूआत कर चुके हैं । अगर रकबा की बात करूं तो रकबा पहले से डबल और ट्रिपल होने जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर रही हूँ, वाटर लेवल डाऊन होने के कारण लोग चना की ओर ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, चना बोवाई कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, रकबा बढ़ चुका है । अध्यक्ष महोदय, जब कम हेक्टेअर वाले को खरीदा जा रहा है तो चना को भी समर्थन मूल्य में खरीदे जाने का आपके उत्तर में आया है । अध्यक्ष महोदय, चने का समर्थन मूल्य 5440 रूपये है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि चना खरीदने के लिये कोई खरीदी केन्द्र की व्यवस्था की गई है ? क्या कोई खरीदी केन्द्र खोला गया है, मुझे उसकी जानकारी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय :- जब बाजार में कीमत ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा कीमत में बिकने लगता है तो समर्थन मूल्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है । बृजमोहन जी ने वही जवाब दिया कि इस कीमत से ज्यादा अगर बिकने लगा है तो फिर मंडी में बिल्कुल चना नहीं आयेगा, क्योंकि ज्यादा कीमत में बिक रहा है । आपका जवाब बृजमोहन जी ने बहुत साफ दिया है, और आगे कोई प्रश्न है तो करिये ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने दलहन-तिलहन के धान खरीदी की जानकारी चाही है...।

अध्यक्ष महोदय :- बस, वह ले लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 जिलों में धान खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं और उनके माध्यम से अगर कोई आता है, पहली बात कोई आता नहीं है, अगर कोई आता है तो हम उसको खरीदने के लिये तैयार है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं बस इतना चाह रही हूँ कि आज के डेट में सभी जगह दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ चुका है । मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जो 20 जगह बता रहे हो, उसको सभी जिले में खोला जाये या ब्लॉक स्तर पर दलहन-तिल्हन खरीदी केन्द्र खोला जाये, मैं यह सरकार से निवेदन कर रही हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से किसान बेचने के लिये आते हैं और कोई आवश्यकता होगी तो नये खरीदी केन्द्र खोलने में कोई दिक्कत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत अच्छा । श्री रामकुमार टोप्पो जी ।

<u>सरगुजा संभाग अंतर्गत मांझी समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किए जाना</u>

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 1653) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या सरगुजा संभाग अंतर्गत "मांझी" समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने में जाति की मात्रा त्रुटि सम्बन्धी कोई समस्या है ? यदि हाँ, तो क्या त्रुटि सुधार या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु क्या योजना है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :जी हां। सरगुजा संभाग अंतर्गत मांझी/माझी समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण जारी करने में जाति की मात्रात्मक त्रुटि संबंधी समस्या परिलक्षित है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अनुसूचित जनजाति की सूची अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों ही स्वरूप में जारी की गई है, जिसके अंग्रेजी वर्तनी की सूची में अनुक्रमांक 28 पर "MAJHI" उल्लेखित है जबकि हिन्दी वर्तनी की सूची में ‘‘मांझी’’ शामिल है। उक्त त्रुटि के निराकरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री राम कुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय ...। मैं आदिम जाति विकास मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ....।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- एक मिनट भईया ।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में ?

डॉ.चरणदास महंत :- नहीं, इसमें नहीं पूछ रहा हूँ । माननीय हमारे वरिष्ठ चन्द्राकर जी ने विधायक महोदया के लिये [XX] [3] और मेरे लिये [XX] शब्द का उपयोग किया है, मैं शायद इसे असंसदीय नहीं मान रहा हूँ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कहा कि इन [XX] को मत उलझाओ करके, मैंने कहा कि [XX] नहीं है, [XX] है ।

डॉ.चरणदास महंत :- [XX] शब्द ...।

अध्यक्ष महोदय :- किसी ने भी बोला है, विलोपित किया जाता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कहा कि यह [XX] को मल उलझाईये। मैंने कहा कि वह [XX] नहीं हैं, [XX] हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- हां तो यहां [XX] शब्द का उपयोग करना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- जिसने भी यह शब्द बोला है, उसे विलोपित किया जाता है।

---

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदिम जाति विकास मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरगुजा संभाग में मांझी समाज के जाति प्रमाण-पत्र में मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनका जाति-प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। क्या इसमें किसी प्रकार की गाईडलाईन जारी की गयी है या इसको किसी विभाग में भेजा गया है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस संबंध में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय को पत्र भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री रामकुमार टोप्पो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्रवाई जल्द करने की जरूरत है क्योंकि मैं जिस समाज के बारे में उल्लेख कर रहा हूं, उनकी परिस्थिति अति दयनीय हैं और उनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह अपनी जमीन विक्रय करते हैं, तो उनकी साक्षरता उस हिसाब से नहीं के कारण यदि वह एक एकड़ जमीन बेच रहे हैं तो इसका फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व उसके आगे शून्य लगाकर उनकी पूरी की पूरी जमीन हथियाने का और उन्हें बंधुवा मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। यह समाज निरंतर अपनी जाति प्रमाण-पत्र के लिये लड़ाई कर रहा है। यह अति गंभीर विषय है, इसलिये जल्दी से इस त्रुटि को सुधारने की प्रकिया की जाये।

अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है, जिसे जनसंपर्क के दौरान एक बच्चे ने मुझसे किया था। मैं उस सवाल को सदन के सामने रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी भी इस सवाल पर गौर करें। मैंने उस बच्चे से पूछा कि तै स्कूल जाथस के नइ जाथस ? उसका जवाब यह था कि हमर तो जाति प्रमाण-पत्र बनेच नइ हे ता में हर स्कूल जा के का करव। यदि एक 10 साल का बच्चा जो समाज की एक नई पीढ़ी भी है। यदि सिर्फ एक जाति प्रमाण-पत्र के कारण उसके दिमाग में ऐसी भावनाएं फैल रही है, जबकि जो सौता और सवता है, वह दोनों एक ही जाति के लोग हैं और दोनों की सामाजिक परिस्थिति खराब है, इसको जल्दी से सुधारा जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उस 10 साल के बच्चे का जवाब दें। धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र की सरकार ने आपके समय के प्रस्ताव पर 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया और केंद्र की सरकार इस मामले में संवेदनशील है और केंद्र के नेतृत्व में चलने वाली हमारी विष्णु देव साय जी की सरकार भी संवेदनशील है। हमने सरकार में आते ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और हम जल्द ही इस संबंध में पूरा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे। माननीय विधायक जी का जो दर्द है, वह स्वाभाविक है क्योंकि वह अंग्रेजी में माझी है और हिंदी में मांझी है और एक मात्रात्मक गलती के कारण उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश होगी कि हम इसमें जल्द से जल्द सुधार करें।

श्री रामकुमार टोप्पो :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री प्रबोध मिंज जी।

प्रश्न संख्या 3 : XX XX

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में ऐसी कई जातियां हैं, जिनको मात्रात्मक त्रुटि के कारण न एस.टी. का और न ही एस.सी. का प्रमाण पत्र मिल रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी ओर से ऐसी सभी जातियों की त्रुटियों के सुधार के लिये पहल की जाये और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष जी की जो चिंता है, वह हम सब की भी चिंता है। क्योंकि आप केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी को तो लिंग परिवर्तन में आपत्ति हुई। वह इसे विलोपित करवा दिये। मैंने [xx] को [xx] कह दिया, उसमें सिर्फ लिंग परिवर्तन हुआ। वे उसमें आपत्ति ले लिये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है जवाब हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी की जो चिंता है, वह हम सब की भी चिंता है और इसलिये हमारी कोशिश होगी कि जिनको मात्रात्मक त्रुटि के कारण लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी जल्द से जल्द लाभ मिले। इसके लिये हमारी सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है और हम इस काम को करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी, यदि आपके पास कोई सूची हो तो आप भिजवा दीजिये।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, जी, मैं बिल्कुल भिजवा दूंगा। इसी सदन ने मेरी जाति को आदिवासी जाति में सम्मिलित करने के लिये भेजा है, उसको भी देख लीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- श्री इंद्र साव जी।

<u>जिला -बलौदाबाजार-भाटपारा अंतर्गत अवैध कॉलोनी पर कृत कार्यवाही</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (*क्र. 1998) श्री इंद्र साव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला -बलौदाबाजार-भाटपारा अंतर्गत वर्ष 2021 से 2023 तक ऐसी कितनी कॉलोनी डेव्हलप कीगई हैं, जिनका पंजीयन रेरा अंतर्गत किया गया है ? यदि पंजीयन नहीं किया गया तो ऐसी कॉलोनी का नाम, कॉलोनाइजर का नाम सहित उन पर की गई कार्यवाही विकासखण्डवार, वर्षवार देवें ? **(ख)** कंडिका ''क'' अनुसार कितनी कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया है ? कितनी कॉलोनियों का नियमितिकरण किया गया है? विकासखण्डवार, कॉलोनीवार, वर्षवार जानकारी देवें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रेरा अंतर्गत 03 कॉलोनी पंजीकृत की गई है। जानकारी निरंक है। **(ख)** जानकारी निरंक है।

श्री इंद्र साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भाटापारा विधान सभा के कॉलोनी के संबंध में प्रश्न था। जिसमें रेरा के अंतर्गत मात्र 03 कॉलोनी पंजीकृत बतायी गई है और बाकी जो जानकारी है, वह निरंक बताई गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रेरा का गठन नवंबर, 2017 में हुआ था, तब से लेकर अब तक जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत भाटापारा विधान सभा में कितनी कॉलोनियों का रेरा में पंजीयन हुआ और उन कॉलोनियों के नाम, स्थान कृपया बताने की कृपा करेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक निजी कॉलोनियों के पंजीकरण के संदर्भ में पूछा है। हम लोगों ने वर्ष 2021, वर्ष 2022 और वर्ष 2023 का जवाब दिया है। अगर इनको पिछले समय की जानकारी चाहिए तो हम अलग से उस सूची को उपलब्ध करवा देंगे।

श्री इन्द्र साव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में इसका संशोधन भी नहीं आया है और इसमें नवम्बर 2017 से जानकारी मांगी गयी है और भाटापारा विधान सभा में अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों का निर्माण बहुत भारी पैमाने पर चल रहा है। यह किसानों का भी मुद्दा है। वहां बहुत से कॉलोनाईजर अवैध प्लाटिंग करके, बाऊण्ड्री वॉल खड़ी कर दे रहे हैं और किसानों को रास्ता नहीं मिलने के कारण, वह औने-पौने दामों पर अपनी भूमि को बेच रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है और मैं इस पर चाहता हूँ कि वहां ऐसे कॉलोनाईजर, बिल्डर पर कार्यवाही होनी चाहिए ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक निजी कॉलोनियों के पंजीकरण के संदर्भ में जानकारी मांगी है। इसमें उसकी जानकारी दी गई है और इस बीच में अभी तक विभाग को किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी निर्माण के संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि सदस्य को विशेष रूप से ऐसी कोई शिकायत है तो आप हमें अलग से बता देंगे, उसे दिखवा लिया जायेगा।

<u>छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया कर्ज</u>

[वित्त]

5. (*क्र. 1616) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2021 से अक्टूबर, 2023 तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितनी संस्थाओं से, कितनी राशि का कर्ज लिया गया ? वित्तीय वर्षवार, राशिवार जानकारी देवें ? **(ख)** उक्त अवधि में छत्तीसगढ़

सरकार द्वारा लिए गये कुल कर्ज में कितना मूलधन एवं ब्याज की राशि को वापस जमा किया गया एवं अक्टूबर, 2023 की स्थिति में कितनी ऋण की राशि जमा किया जाना शेष है ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रश्नांकित अवधि में संस्थावार लिये गये ऋण की जानकारी [4]**"संलग्न प्रपत्र अ"** अनुसार हैं। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में लिये गये कर्ज में मूलधन एवं ब्याज भुगतान की जानकारी **"संलग्न प्रपत्र ब"** अनुसार है एवं अक्टूबर 2023 की स्थिति में 92,311 करोड़ मूलधन जमा किया जाना शेष है।

श्री सम्पत अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय वित्त मंत्री जी से था। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर आया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उसी से संबधित यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2021-वर्ष 2022, वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो कुल कर्ज लिया गया था, वह राज्य के जी.डी.पी. का कितना प्रतिशत था ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जनवरी, 2021 से अक्टूबर, 2023 तक जो जानकारी मांगी थी, उसकी जानकारी लिखित में दे दी गई है। कुल जो ऋण है, हम उसमें इनको जी.डी.पी. का प्रतिशत अलग से उपलब्ध करवा देंगे।

श्री सम्पत अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि किसी भी वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा अपने जी.डी.पी. का कितना प्रतिशत भाग के बराबर कर्ज लिया जा सकता है, क्या अधिकतम कर्ज लिये जाने की कोई तय सीमा है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य ऋण की सीमा जी.डी.पी. से कम्पेयर कर के पूछ रहे हैं ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कर्ज लेने की किसी भी राज्य की सीमा एफ.आर.बी.एम. एक्ट के तहत 3 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब ठीक है। आ गया।

श्री सम्पत अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आखरी, एक छोटा सा प्रश्न है। कर्ज के रूप में प्राप्त राशियों को जिन मदों में व्यय के लिए आवंटित किया गया था, क्या उस विभाग द्वारा उन समस्त आवंटित राशियों को पूर्ण व्यय कर लिया गया है ? क्या कोई ऐसे भी प्रकरण हैं जिसमें आवंटित राशि समय में खर्च न हो पायी हो । अगर ऐसा है तो क्यों ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह कौन से वर्ष का पूछ रहे हैं ? आप कब से कब तक की जानकारी पूछ रहे है ? आप वर्तमान वर्ष का पूछ रहे है ?

श्री सम्पत अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वर्ष की जानकारी पूछ रहा हूँ।

---

[4] परिशिष्ट "दो"

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितना कर्ज लिया गया था, वह अलग-अलग मद से खर्च हो गया क्या ? थोड़ा डिटेल प्रश्न है। यह काफी व्यापक प्रश्न है आप इसकी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे तो यह अच्छा होगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। हम इसकी जानकारी उपललब्ध करवा देंगे। वैसे विभाग द्वारा जो राशि खर्च नहीं होती है, वह सरकारी खजाने में जमा हो जाता है।

श्री सम्पत अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा ।

प्रश्न संख्या : 06 xx xx

<u>कलेक्टर (आदिवासी विकास) तथा एकी. आदि. वि. परियोजना कार्यालय दंतेवाड़ा द्वारा व्यय राशि</u>

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

7. (*क्र. 2275) श्री चैतराम अटामी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2021-2022 से दिनांक 30 जनवरी, 2024 तक कलेक्टर आदिवासी विकास (सहायक आयुक्त) ज़िला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना दंतेवाड़ा द्वारा किस-किस मद से कितने कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार , मदवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के कार्यालयों को प्रश्नांकित अवधि में डी.एम.एफ.टी. मद से भी व्यय हेतु राशि प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो प्राप्त राशि को, किस-किस प्रयोजन हेतु कितना-कितना, व्यय किया गया ? वर्षवार, जानकारी उपलब्ध करावें । **(ग)** क्या प्रश्नांश "ख" के प्राप्त राशि को निर्माण / मरम्मत कार्यों तथा सामग्री खरीदी हेतु भी व्यय किया गया ? यदि हाँ, तो कितने कार्यों हेतु, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? कार्य ऐजेंसी/ ठेकेदार / सामग्री आपूर्तिकर्ता फ़र्म/ व्यक्ति के नाम सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न**[5] **प्रपत्र "अ"** अनुसार है। **(ख)** जी, हां। जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"**अनुसार है। **(ग)** जी, हां। कार्यों पर किये गये व्यय तथा कार्य एजेंसी/ठेकेदार/सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म/व्यक्ति के नाम की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "स"**अनुसार है।

[5] परिशिष्ट "चार"

श्री चैतराम अटामी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आदिम जाति विकास मंत्री जी से प्रश्न किया था कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से दिनांक 30 जनवरी, 2024 तक कलेक्टर आदिवासी विकास (सहायक आयुक्त) जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना दंतेवाड़ा द्वारा किस-किस मद से कितने कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार, मदवार, कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावे।

मेरे प्रश्न के "ख" भाग में प्रश्न किया था कि क्या प्रश्नांक "क" के कार्यालयों को प्रश्नांकित अवधि में डी.एम.एफ.टी. मद से भी व्यय हेतु राशि प्राप्त हुई है ? यदि हॉ तो प्राप्त राशि को, किस-किस प्रयोजन हेतु कितना-कितना, कब-कब व्यय किया गया गया ? वर्षवार, कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आप प्रश्न कर लिये, अब जवाब सुनिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दंतेवाडा जिला में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कुल 127 छात्रावास, आश्रम संचालित हैं और उसमें कुल 12,625 सीटें स्वीकृत हैं। इसके ऊपर में जो मरम्मत इत्यादि पर खर्च किया गया है, वह लगभग 2 करोड़ 33 लाख रुपये है और इसमें 242 करोड रुपये मिला था। इन छात्रावासों के निर्माण में, बच्चों की परवरिश में और वहां की मरम्मत में कुल खर्च 34 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च किया गया है।

श्री चैतराम अटामी :- किन-किन कार्यों में, किस-किस मद खर्च हुआ है ? वह छात्रावास का अकेला प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। वह डिटेल जानकारी पूछ रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में उन्होंने विशेष रूप से डी.एम.एफ. का पूछा है, उसके बारे में हमने वर्षवार परिशिष्ट में जानकारी दी है। अगर आपका अलग-अलग जानकारी देने का निर्देश हो तो मैं बता दूंगा। वर्ष 2021-22 में डी.एम.एफ. 1 करोड़ 44 लाख रुपये खर्च हुआ है। 2021-22 में ही अन्य मदों में 15 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च हुआ है। वर्ष 2022-23 में 3 करोड़ 96 लाख रुपये खर्च हुआ है। सामग्री और आपूर्ति में 2021-22 में 17,05,48,100 रुपये खर्च हुआ है। वर्ष 2022-23 में 15,33,59,300 रुपये खर्च हुआ है। वर्ष 2023-24 में 23,38,40,000 रुपये खर्च हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका और कोई प्रश्न है ?

श्री चैतराम अटामी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या प्रश्नांख "ख" के प्राप्त राशि को निर्माण/मरम्मत कार्यों तथा सामग्री खरीदी हेतु भी व्यय किया गया ? यदि हॉ, तो कितने कार्यों हेतु, कब-कब, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? कार्य एजेंसी/ठेकेदार/सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म/ व्यक्ति के नाम, पता सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह पूरी जानकारी परिशिष्ट में उपलब्ध करवा दी है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको परिशिष्ट में पूरी जानकारी दे दी गई है। आपने परिशिष्ट पढ़ा होगा, यदि उसमें और कोई प्रश्न है तो बताईये।

श्री चैतराम अटामी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप संतुष्ट हैं। श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह।

<u>जिला जांजगीर - चांपा में अमानक बीज/दवा/खाद सप्लाई पर कार्यवाही</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

8. (*क्र. 2393) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला जांजगीर-चाम्पा में कृषि विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में दिसम्बर, 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के किन-किन संस्थानों/फर्मों से बीज/दवा की खरीदी की गई? खरीदी हेतु कौन सी प्रक्रिया का पालन किया गया? कौन-कौन से बीज/खाद की खरीदी की गई? क्या गुणवत्ता जाँच की गई? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अवधि में किन-किन संस्थानों/फर्मों द्वारा अमानक बीज की सप्लाई की गई? इस संबंध में क्या विभाग को किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है? शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा खाद एवं बीज सप्लाई करने वाली संस्थानों/फर्मों का विगत तीन वर्षों में निरीक्षण किया गया? क्या सेंपल जाँच की गई? किन-किन कंपनियों द्वारा सप्लाई की गई दवा/बीज की गुणवत्ता अमानक पाये गए? किन-किन संस्थानों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में कृषि विभाग द्वारा विगत तीन वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में दिसंबर 2023 तक छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, खोखसा, जिला-जांजगीर-चाम्पा एवं राष्ट्रीय बीज निगम, रायपुर को बीज, कीटनाशी रसायन, बायोफर्टिलाईजर एवं माईक्रोन्यूट्रियेंट की आपूर्ति हेतु प्रदायगी आदेश जारी किए गए हैं। उक्त अवधि में छ.ग. राज्य के बाहर की किसी भी संस्था/फर्म को बीज, कीटनाशी रसायन, बायोफर्टिलाईजर एवं माईक्रोन्यूट्रियेंट की आपूर्ति हेतु प्रदायगी आदेश जारी नही किया गया है। रसायनिक उर्वरकों की आपूर्ति हेतु किसी भी संस्था को कोई प्रदायगी आदेश उक्त अवधि में जारी नहीं किया गया है। उक्त जारी किए गए प्रदायगी आदेश राज्य शासन द्वारा आदान सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अधिकृत संस्थाओं को ही दिए गए हैं। आपूर्ति किए गए बीज, कीटनाशी रसायन, बायोफर्टिलाईजर एवं माईक्रोन्यूट्रियेंट की वर्षवार, संस्थावार, सामग्रीवार नाम एवं गुणवत्ता परीक्षण की **जानकारी संलग्न[6] प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र-द अनुसार है।**उद्यानिकी विभाग अंतर्गत क्रय किये गये बीज एवं खाद

[6] परिशिष्ट "पांच"

खरीदी का संस्थावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'इ' एवं प्रपत्र 'फ' अनुसार है।** क्रय किये गये बीज की गुणवत्ता की जॉच प्रदायकर्ता संस्था द्वारा कराया गया है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' की अवधि में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग अंतर्गत आपूर्तिकर्ता संस्थानों/फर्मों द्वारा अमानक बीज आपूर्ति किये जाने की जानकारी निरंक है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः शेष प्रश्नांश् की जानकारी निरंक है। **(ग)** जी हाँ। विगत तीन वर्षों में विभागीय कीटनाशक/उर्वरक/बीज निरीक्षकों द्वारा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, खोखसा, जिला जांजगीर-चाम्पा का निरीक्षण कर नमूने लेकर प्रयोगशालाओं को परीक्षण हेतु प्रेषित किए गए हैं। प्रयोगशालाओं से प्राप्त परीक्षण परिणाम के अनुसार सभी नमूने मानक स्तर के पाए गए हैं, अतः शेष जानकारी निरंक है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैंने एक प्वाईन्टेड प्रश्न किया था। जिला जांजगीर-चांपा में कृषि विभाग द्वारा विगत तीन वर्षो 2021-22, 2022-22 एवं 2023-24 में दिसम्बर 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के किन-किन संस्थानों/फर्मो से बीज/दवा की खरीदी गई ? और खरीदी हेतु कौन सी प्रक्रिया का पालन किया गया है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, इसमें उन्होंने फर्म का नाम तो दिया है। जितने छत्तीसगढ़ के बाहर की फर्म हैं, उनका एक भी नाम नहीं है। माननीय मंत्री जी मेरे पास जानकारी है, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं आपको उस जानकारी को दे भी दूंगा । चूंकि यह किसानों का मामला है। इनके खिलाफ कई शिकायतें भी आई थीं, जिसका उल्लेख भी इसमें नहीं किया गया है। मैंने प्वाइंटेड प्रश्न पूछा था कि खरीदी हेतु कौन सी प्रक्रिया का पालन किया गया है? उसकी भी जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पूरी जानकारी दे दी है। हमारे शासन का बीज विकास निगम है और बीज विकास निगम के माध्यम से ही हमारे यहां बीज की खरीदी की जाती है। हमारे यहां जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उन रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से ही बीज की खरीदी की जाती है और उसके द्वारा ही किसानों को बीज वितरण किया जाता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि पहले उसके सैम्पल लिये जाते हैं, उस सैम्पल का परीक्षण किया जाता है, उसके बाद ही किसानों को बीज की सप्लाई की जाती है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जो छत्तीसगढ़ के बाहर के फर्म है, उनसे वहां पर कुछ डायरेक्ट खरीदी हुई है और यही मेरा प्रश्न था। इसमें वीना, एलवेन और नेप्च्युन, यह तीन कंपनियां हैं, जिनसे बाहर से खरीदी की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप एक बार इसकी जांच करवा दीजिये क्योंकि इनके खिलाफ किसानों के द्वारा कई शिकायतें आ गई थीं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी कंपनी के द्वारा सीधे किसानों को बीज की सप्लाई नहीं की जाती है। किसानों को जो बीज की सप्लाई की जाती है, वह हमारे बीज विकास निगम के द्वारा की जाती है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ या जांच की आवश्यकता ही

नहीं है। अगर किसी किसान को खराब बीज भी जाता है और उसका 60 प्रतिशत से कम जर्मिनेशन होता है तो बीज का जितना पैसा है, वह कृषि विकास निगम के द्वारा उसको वापिस किया जाता है।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह विष्णु देव जी की सरकार है। इसमें तो जांच पर जांच हो रही है। अगर हम कह रहे हैं कि ऐसे तीन कंपनियां हैं, जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, जिन्होंने बीज सप्लाई की है, जिसका जर्मिनेशन रेट कम है, जिन्होंने गलत दवाईयां और गलत बीज दी है, उसमें जांच कराने में आपको क्या आपत्ति है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जितनी कंपनियां हैं, वह बीज विकास निगम को सप्लाई करती हैं और बीज विकास निगम किसानों को सप्लाई करता है। बीज विकास निगम जितनी भी सप्लाई करता है, वह जांच-परख के बाद ही करता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ही नहीं है। जब कोई शिकायत नहीं है तो हम क्या जांच का करवायेंगे ? अगर विधायक जी के पास में कोई शिकायत है तो हमको उसकी कापी दे दें।

डॉ. चरण दास महंत :- मंत्री जी, मैं यही कह रहा हूं कि आपको लिख कर दे दिया जाएगा कि कितनी जगह से गलत बीज की सप्लाई हुई है? कितने-कितने सीधे सप्लाई हुए हैं? उनकी जांच करायेंगे, आप यह घोषणा कर दीजिये। बस।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ गलत ही नहीं हुआ है तो किस चीज की जांच की घोषणा करें?

अध्यक्ष महोदय :- लिख कर दे देंगे तो आप जांच करा लेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, वह लिखकर दे दें, तो निश्चित रूप से हमारी जानकारी में ..।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां की शिकायतें हैं, वह मैं मंत्री जी को बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप बता दीजिये, वह हो जाएगा। डॉ. चरण दास महंत जी।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं किसान हूं और हम बीज विकास निगम में लेन-देन भी करते हैं। वास्तव में बीज विकास निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बीजों का वितरण होता है और छत्तीसगढ़ से उत्पादन करके देते हैं। एक बार डी.एम.एफ. मद से हमारे हजारों किसानों को पायोनियर कंपनी की मक्के की सप्लाई हुई थी। वह मक्का कहीं पर जर्मिनेशन नहीं हुआ। हमारा खाद भी गया और सरकार का जो बीज का काम था, वह बेकार हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- आपको प्रश्न करना है तो प्रश्न करिये न।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक ही है कि हमारे किसानों को पायोनियर कंपनी का मक्का दिया गया था। माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 60 प्रतिशत जर्मिनेशन हुआ था, लेकिन वह मक्का 6 प्रतिशत जर्मिनेशन नहीं हुआ था। हमारा खाद भी गया था और उस सत्र का दूसरे फसल लिये थे, उसका भी हम लाभ नहीं पाये।

अध्यक्ष महोदय :- आप कब की बात कर रहे हैं? आप कौन सी वर्ष की बात कर रहे हैं?

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, यह तीन वर्ष पहले की बात है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखकर दे दीजिये।

श्री राजेश मूणत :- उस समय किसकी सरकार थी?

श्री ब्यास कश्यप :- सरकार किसी की भी रहे, लेकिन हमको भी तो तकलीफ हुई है न। आप लोग सिर्फ एक ही प्रश्न करते हैं कि किसकी सरकार थी? सरकार कोई भी रहे, अगर गलत हुआ है तो गलत है। सीधी सी बात है। किसान की बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप इधर देखकर मत बोलिये। आप आराम से बैठ जाईये।

श्री राजेश मूणत :- आप चिंता मत करिये। यह विष्णु देव सरकार है।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखकर दे दीजिये।

श्री ब्यास कश्यप :- ठीक है, यदि विष्णु देव की सरकार है तो ..।

श्री राजेश मूणत :- पहले आपकी पार्टी की सरकार थी तब आपकी बात नहीं सुनते थे।

अध्यक्ष महोदय :- राजेश जी, बैठ जाईये।

श्री ब्यास कश्यप :- भैया, ऐसी बात नहीं है। हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। किसानों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मैं आपसे सहमत हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। (मेजों की थपथपाहट) हम 3100 रूपये में 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। इन्होंने दो साल बोनस की घोषणा की। इन्होंने 2 साल का बोनस नहीं दिया। वह भी हमने किसानों के खाते में पहुंचा दिया है। यह पहली सरकार है जो पांच साल में अपने वादों को पूरा नहीं कर पाये, उन वादों को हम पूरा कर रहे हैं और उसके बाद में ये बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 3 महीने में अपने वायदे पूरे कर दिये । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पूर्ववर्ती सरकार की जो समर्थन मूल्य की राशि है उसे आप देंगे ? जो चौथी किस्त बची है क्या आप उसको देंगें ? (व्यवधान) पूर्ववर्ती सरकार की चौथी राशि बची है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप 4 किस्त में देते थे हम एक किस्त में दे देंगे और जल्दी दे देंगे । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको दे दीजिये । जो चौथी किस्त बची है उसकी राशि डालिये । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के अनुसार नहीं दिये। (व्यवधान)

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय कृषि मंत्री जी, वर्ष 2016-17 और 2017-18 का बोनस देने की बात थी ।

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी खड़े हैं । आप लोग इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हों तो दूसरे को बैठ जाना चाहिए । नये विधायकों को इतना तो समझ में आना चाहिए ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय वरिष्ठ मंत्री जी, अभी आपने कहा । आदरणीय बृजमोहन भैया अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके पहले मूणत जी ने कहा कि विष्णुदेव की सरकार है । आप पहले यह बता दें कि सरकार किसकी चल रही है उसके बाद प्रश्न पूछा जाये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह मोदी जी की भी है, यह विष्णुदेव साय जी की भी है ।

डॉ. चरणदास महंत :- मोदी जी की गारंटी वाली सरकार ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह भारतीय जनता पार्टी की भी है और यह कमल फूल की भी सरकार है और यह जनता की सरकार है और यह आपकी भी सरकार है।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. चरणदास महंत जी आप अपना प्रश्न करें ।

डॉ. चरणदास महंत :- हां, मैं यह कह रहा था कि यदि मैं आने वाले दिनों में, शब्दों में या समय में इस तरह की भाषा का उपयोग करूंगा तो नाराज मत होइएगा।

<u>प्रदेश में फ्लाईएश उत्सर्जन की मात्रा, निराकरण एवं कार्यवाही</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (*क्र. 2409) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) फ्लाईऐश का उत्सर्जन करने वाले संयंत्रों की संख्या एवं वार्षिक मात्रा वर्तमान में जिलावार कितनी-कितनी है ? (ख) संयंत्रों से उत्सर्जित फ्लाईऐश का नियमों के अनुसार निराकरण किस-किस प्रकार

से, कितनी-कितनी मात्रा में वर्ष 2022-23 में किया गया ? संयंत्रवार बताएं ? नियमानुकूल निराकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ? उसका पालन हो रहा है या नहीं ? (ग) फ्लाईऐश के अनियमित निराकरण के कितने-कितने प्रकरण, किस-किस संयंत्र के विरूद्ध 2021-22 से 2023-24 की अवधि में प्रकाश में आए ?उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई और कितना-कितना अर्थदंड अधिरोपित किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ में फ्लाई ऐश उत्सर्जित करने वाले कुल 101ताप विद्युत संयंत्र स्थापित/संचालित है। वर्ष 2022-23 में जिलेवार विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित फ्लाई ऐश मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ के कॉलम 04 अनुसार है।(ख)संयंत्रों से उत्सर्जित राखड का नियमानुसार अपवहन की संयंत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ के कॉलम 05, 06, एवं 07अनुसार है। विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाईऐश अपवहन नियमानुसार सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्थायें की गई है:- (1) फ्लाई एश लोडिंग एवं अनलोडिंग के दौरान उड़ने वाले राखड की रोकथाम हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। (2) फ्लाई एश का परिवहन तारपोलीन से ढके हुये वाहनों से कराया जाता है। (3) फ्लाई एश का यथा संभव लाभकारी कार्यो यथा सी मेंट उत्पादन, ईट निर्माण,खदान भराव, सड़क निर्माण,भू-भराव आदि में उपयोग किया जा रहा है। विभाग द्वारा पालन सुनिश्चित कराया जाता है। (ग) विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो फ्लाई ऐश उत्सर्जन होता है । वह हमारे दिल, दिमाग, शरीर, पानी और वातावरण सभी को अशुद्ध करता है तो चूंकि छत्तीसगढ़ में इसका इतना ज्यादा उत्सर्जन होने लगा है, मैं उसकी जानकारी चाहता था कि उद्योगों ने कहां-कहां, किस-किस कार्य के लिये जैसे इन्होंने परिशिष्ट में दिया है कि सीमेंट उत्पादन में उपयोग होता है, ईंट बनाने में इसका उपयोग होता है और भराव में या कहीं पटक देने में, फेंक देने में भी उपयोग होता है तो यह जो जानकारी आपको उद्योगों से प्राप्त हुई है । माननीय मंत्री जी आप कृपया यह बताने की कृपा करें कि क्या आपने अपनी ओर से इसका सत्यापन कराया है या जो इंडस्ट्री वालों ने दिया है उसको मान लिया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग अपनी जानकारी देते हैं और समय-समय पर विभाग उसका सत्यापन कराती है । विभाग यह देखकर सुनिश्चित करती है कि उन कंपनियों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उन स्थानों पर उस राखड़ का उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है । वैसे आप भी राखड़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं और हम भी उससे लगे हैं ।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिये यह मान लेते हैं कि हम दोनों एक ही क्षेत्र के हैं। आप कोरबा तो जाते होंगे ? कोरबा में एक मानिकपुर ओपन कॉस्ट है । उसको भरने की अनुमति एस.ई.सी.एल. ने दी है । ओपन कॉस्ट या कहीं भी ऐश डालने के बाद उसमें दो फीट की मिट्टी डाली जाती है लेकिन कोरबा

क्षेत्र में कहीं भी मिट्टी नहीं डाली जा रही है और इसकी जो राख है वह उड़-उड़कर आम जनमानस को तकलीफ दे रही है तो ऐसे जो कार्य हो रहे हैं इसके लिये आप क्या करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जो बता रहे हैं । चूंकि जो भी संयंत्र नियम को पूरा नहीं करते हैं तो हम उस पर कार्यवाही भी करते हैं । हमने वर्ष 2021 से लेकर अभी तक 169 ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही की है जिन्होंने उन नियम-शर्तों का उल्लंघन किया है और उनसे 2 करोड़ 74 लाख 16,000 रूपये की पैनाल्टी भी ली है यदि इस प्रकार का कोई स्थान हो जहां पर नियम का पालन नहीं हो रहा हो तो आप उसको बताईये निश्चित रूप से विभाग उसको दिखवायेगा ।

डॉ. चरणदास महंत :- ठीक है । मैं यह कह रहा हूं कि यह आपका परिशिष्ट है यह आपके पास है ? आपका परिशिष्ट आपके पास है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- है ।

डॉ. चरणदास महंत :- मंत्री जी, इसमें 1 से लेकर 27 तक जितनी भी रायपुर की इस तरह की खदानें हैं जो ऐश का उत्पादन करती हैं उन्होंने लगभग अपने पूरे उत्पादन का अधिकतम हिस्सा सीमेंट और ईंट बनाने में किया है लेकिन कोरबा में एन.टी.पी.सी. जमनीपाली, राज्य स्टेट जनरेशन कोरबा, श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को, अमरकंटक पॉवर लिमिटेड कोरबा, एस.सी.बी. इंडिया कोरबा, भारत एल्युमिनियम कंपनी कोरबा, मारूति क्लीन कोल पॉवर लिमिटेड, मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पॉवर ये तो कोरबा के हो गये। उसी तरह रायगढ़ के हैं। जिंदल स्टील प्लांट, सालासर स्पंज प्लांट, रूकमणी पॉवर, मेसर्स एम.जे. एनर्जी, जिंदल पॉवर, जे.एस.डब्ल्यू. स्टील और जिंदल स्टील। इन्होंने लगभग अपना जितना होता है, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा खदान भराव और रोड के आजू-बाजू में फेंकने का कार्य किया है, जिसके कारण रायगढ़ और कोरबा, ये दोनों क्षेत्रों में जनजीवन बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो चुके हैं, वहां के लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपको पता है कि कितनी खतरनाक है, जो पानी पर भी असर करता है, हवा पर भी असर करता है। आदमी के शरीर पर भी असर करता है। तो इन जगहों से जहां से आपको ये जानकारी मिली है, आप उसकी पुन: जांच करायेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग के पास नहीं आयी है जो भी शिकायत आती है, उस पर हम जांच कराते हैं। आपका यह कहना ठीक है कि सड़कों के किनारे गर्मियों में हवा से, धूल से पर्यावरण प्रदूषित होता है। आम जनजीवन के लिए मुश्किल होता है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत दो-तीन महीनों से जब से माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सरकार आयी है, इस प्रकार की घटनाओं पर हमने लगाम लगाया है और निश्चित रूप से सड़क के किनारे जो राखड़ फेंकने वाले ऐसे जो भी संयंत्र हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे।

डॉ. चरण दास महंत :- जब से विष्णु देव साय जी की सरकार आयी है, कोरबा में सड़क के किनारे फेंखने वालों की संख्या बढ़ गई है। वही लोग जो पहले काम करते थे, वही लोग अब काम करते हैं। पहले एक ट्रक चलाते थे और अब दो ट्रक चलाते हैं। तो आप ऐसा मत कहिए कि विष्णु देव जी की सरकार आने के बाद यह काम बंद हुआ है। आज आपका सौभाग्य समझिए, मेरा भी सौभाग्य समझ लीजिए कि आप वित्त मंत्री जी का जवाब दे रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब मैं कहूं फ्लाई ऐश में सिलिकॉन आक्साइड, एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड, फेरस ट्राई ऑक्साइड नामक रासायनिक मिलते हैं और ये मनुष्य को, पशु को, जल को, जमीन को, वनस्पति को, वायु को सबको खराब कर देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो डॉक्टर ही हैं। ये सांस लेने से नाक के द्वारा जब इनके कण घूस जाते हैं तो ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी घटाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता घटने के बाद दिल की बीमारी भी होती है। हार्ट-अटैक भी होता है। कैंसर भी होता है। सांस की कई तरह की बीमारियां भी होती हैं और अंत:मृत्यु भी हो जाती है। तो इतना खतरनाक है। आप हेल्थ मिनिस्टर के नाते समझ लीजिए। उत्तर देते समय वित्त मंत्री के नाते समझ लीजिए। इतने कठिन-कठिन रासायनिक पदार्थों का किस तरह से भारत में हमारे छत्तीसगढ़ में लोग यहां-वहां सब जगह परेशान हो रहे हैं, इसको देखते हुए इसमें गंभीरता से कार्रवाई करेंगे क्या?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने पहले भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को कहा है कि स्पेशिफिक अगर कहीं आपके संज्ञान में कोई ऐसा विषय है कि किसी विशेष संयंत्र से इस प्रकार के जो हानिकारण तत्व हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं और जो सही जगह में उनका जो नियम के तहत नहीं है। पर्यावरण मंडल के तहत नहीं है, उसको हम निश्चित रूप से दिखवायेंगे और आपकी भावनाओं को और साथ में मेरी भावनाओं को दोनों को मिलाते हुए उसको ठीक करेंगे।

डॉ. चरण दास महंत :- अच्छा महोदय, एक बता दीजिए। मैंने तो कोरबा वालों का नाम पढ़ा है। रायगढ़ वालों का नाम पढ़ा है और आपके परिशिष्ट से पढ़ा है और यहां विधान सभा में इन्होंने लिख भी लिया होगा तो उनको बुलाकर आप इन कंपनियों पर जो कोरबा में स्थित हैं, अगर कोई तकलीफ हो तो आपके बाजू में लखनलाल जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, वे भी परेशान हैं या नहीं और रायगढ़ वाले भी होंगे, उनसे भी पूछ लीजिए। मैं स्पेशिफिक रायगढ़, कोरबा में जो उत्सर्जन हो रहा है, जिसका अधिकतम पार्ट सड़कों में बिना इजाजत के फेंका जा रहा है, सड़क बनाने में डालिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सड़कें हमारे यहां बन रही हैं। आप खदान में पाटें, कोई आपत्ति नहीं है। मगर इन सबके लिए एक नियम बना हुआ है, उस नियम के तहत ही आप फेंकिए न। राखड़ को फेंकिए। मुझे तो सिर्फ इतनी ही आपत्ति है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, उनका पालन करना चाहिए ।

श्री शयाम बिहारी जायसवाल :- नेता प्रतिपक्ष जी के सुझावों पर विभाग विशेष रूप से ध्यान देकर उस पर अमल करेगा, ताकि आम जन-जीवन को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह ।

श्री ब्यास कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, महंत जी के प्रश्न पर मैं छोटी से जानकारी उपलब्ध कराना चाह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री जी जो जानकारी दे रहे हैं ?

श्री ब्यास कश्यप :- मैं सरकार को अवगत करा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ।

श्री ब्यास कश्यप :- बरीडीह, कोरबा जिले का गांव और जांजगीर-चांपा जिले का नकटीडीह और कल्याणपुर गांव । चूंकि मनरेगा से खुदाई किया हुआ तालाब है, इन तालाबों को भी राखड़ से पाट दिया गया है । यह राखड़ उड़कर प्रदूषण फैला रहा है, यह जानकारी मैं दे रहा हूं । कृपा करके इस पर भी विचार करें, मैंने भी प्रश्न लगाया था, चूंकि प्रश्न नहीं आ पाया, इसलिए मैंने यह जानकारी दी ।

प्रश्न संख्या : 10 XX XX

<u>पैरादान व उसके परिवहन का भुगतान</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

11. (*क्र. 1574) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिनांक 1 जनवरी, 2019 से 30 सितंबर, 2023 तक किस योजना में शासन को कितना पैरा दान मिला? जिलावार अलग-अलग बताइये? (ख) पैरा का परिवहन किस दर से, किस वाहन से किया गया और परिहन का दर किस आधार पर निर्धारित किया गया पैरा परिवहन का भुगतान राज्य शासन ने कौन से मद से किया? (ग) प्रश्नाश ‘‘ख‘‘ जिस मद से भुगतान किया गया, उस मद के खर्च के नियमों के तहत् क्या पैरा परिवहन का भुगतान करने का प्रावधान था? भुगतान को जिलावार अलग-अलग बताने का कष्ट करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 30 सितंबर, 2023 तक विभिन्न योजना अंतर्गत प्रदेश के गोठान समितियों को 45.69 लाख क्विंटल पैरादान मिला। जिलावार जानकारी [7]संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) पैरा का परिवहन स्थानीय दर पर ट्रेक्टर एवं अन्य उपलब्ध वाहन से किया गया। परिवहन का दर दूरी के आधार पर किया गया है। परिवहन का

[7] परिशिष्ट "सात"

भुगतान गोधन न्याय योजना, मूलभूत, 14 वें एवं 15 वें वित्त मद से किया गया है। (ग) जी हाँ। जिलावार वर्षवार भुगतान की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जोरदार प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका हर प्रश्न जोरदार रहता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसी बुद्धि आप लोगों ने कहां से जुटाई, उस बुद्धि को तो हमको बताइए । हम चरण स्पर्श करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

श्री चरणदास महंत :- फ्लाईएश के बारे में बोल रहे हैं या किसी दूसरे विषय पर बोल रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मेरा 11वां प्रश्न है उसके बारे में बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप चरण स्पर्श करेंगे । चरण जी बैठे हैं इसलिए पूछ रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनका तो दिन भर कर लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है (हंसी) ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पैरा खरीदी की गई, उसकी दर किस आधार पर और कैसे निर्धारित किया गया और उसी का सहायक प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग और गोधन न्याय योजना जो बनाई गई थी, क्या उससे पैरा खरीदी की जा सकती है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, पैरा खरीदी नहीं की गई है, पैरा दान में मिला है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं स्वीकार कर लेता हूं कि पैरा दान में मिला था । पैरा दान के परिवहन में आप 14वें/15वें वित्त आयोग या गोधन न्याय योजना की राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या ? उस योजना में है क्या ? और 45 लाख टन को तौलाने में आपने कितना पैसा खर्च किया । कैसे निर्धारित किया ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा परिवहन के राशि जो राशि भुगतान की गई है, उसका प्रावधान योजना में था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर नहीं आया । मैंने कहा कि दर का निर्धारण किस आधार पर हुआ ? 14वें/15वें वित्त आयोग से पैरा परिवहन किया जा सकता है, ऐसा है क्या ? दूसरा, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पैरा परिवहन किया जा सकता है क्या ? बहुत स्पष्ट प्रश्न है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, क्योंकि गौठान प्रबंधन समितियां हैं उनको 2021-22 में 24 करोड़ 80 लाख रूपए, 2022-23 में 28 करोड़, 26 लाख, 50 हजार रूपए और इस प्रकार से 53 करोड़, 06 लाख, 50 हजार की राशि गौठान समितियों को दी गई है और गौठान समितियों ने परिवहन में इसका व्यय किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, फिर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। आप उत्तर देख लीजिए, 14वें/15वें वित्त आयोग के मद से किया गया है । गोधन न्याय योजना से किया गया है । यह प्रश्न में ही है । मैंने प्रश्न किया है कि गोधन न्याय योजना और 14-15वें वित्त आयोग की राशि से पैरा परिवहन किया जा सकता है क्या ? जब आपने 53 करोड़ का हिसाब दिया है तो 53 करोड़ रूपया कौन कौन से मद से दिया ? मेरे पास पूरी जानकारी है । मैं पूछ चुका हूं । कौन कौन से मद का 53 करोड़ रूपया गोठान समितियों को स्थानांतरित किया गया है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, 14वें और 15वें वित्त आयोग के पैसे को गोठान समितियों को स्थानांतरित किया गया है । 4651 स्वावलम्बी गोठान हैं उनको 40 हजार रूपए प्रति गौठान दिया गया है और 3529 जो सक्रिय गौठान हैं उनको 30 हजार रूपए प्रति गौठान के हिसाब से राशि की गई है और इसी राशि में से गौठानों ने पैरा परिवहन की राशि का भुगतान किया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे भी आग्रह करूंगा। अब आप परिशिष्ट खोल लीजिए जो मैं खोलना नहीं चाहता था। यह जितनी राशि बता रहे हैं, आप किसी भी जिले का भुगतान देख लीजिए। एक जिले का भुगतान तो लाखों में है। आपने 53 करोड़ रूपए स्थानांतरित किया है। 14वें, 15वें वित्त आयोग की राशि पंचायत की है, वह गौठान समिति को किसी सूरत में स्थानांतरित नहीं हो सकती। आपका कथन गलत है, गलत है नहीं बोलता, आपका कथन सही नहीं है। दूसरी बात, मैंने 3 दिन पहले प्रतिवेदन के जवाब में कहा था कि 14वें, 15वें वित्त आयोग के जो नॉर्म्स बने हैं, स्वच्छता, पेयजल, अधोसंरचना, विद्युतीकरण, शिक्षा, परिसंपत्ति का रख रखाव है। यह पंचायत की राशि है। आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि 14वें, 15वें वित्त की राशि कौन से पंचायत को, किस गौठान समिति को स्थानांतरण किया गया है। एक जिला, एक पंचायत का उदाहरण दीजिए। दूसरा, आपने 53 करोड़ का जो हिसाब बताया, वह कौन-कौन से मद का है?

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा प्रेम से पूछिए, नाराजगी से नहीं। आप एकदम प्रेम से पूछिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज ऐसी है, आप 20 साल से देख रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- हमर भैया के पैदायसी वइसनेच हे।

श्री अजय चंद्राकर :- ते पइसा खाए हस ते हा उगलही देखबे ना। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि 14वें और 15वें वित्त आयोग की जो राशि है, उसमें से गौठानों को दी गयी है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर नहीं आ रहा है। 14वें, 15वें वित्त आयोग की राशि से एक पंचायत, एक जगह का नाम बता दीजिए कि इस पंचायत या इस जिले से इतनी राशि गौठान समिति को स्थानांतरित की गयी। अभी आपने कहा कि 14वें, 15वें वित्त आयोग की

राशि गौठान समिति को स्थानांतरित की गयी। आप एक उदाहरण बता दीजिए। कौन से जिले में किस प्रक्रिया के तहत उसको स्थानांतरित की गयी ? फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभी जिलों में और सभी गौठानों को स्थानांतरित की गयी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप फिर परिशिष्ट देख लीजिए। 14वें, 15वें वित्त आयोग से सिर्फ 3 जिलों में भुगतान हुआ है। सभी में कहां से आ जाएगा ? माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी का है। सभी जिलों में 14वें, 15वें वित्त आयोग से भुगतान हुआ है। बाकी जगह गोधन न्याय से भुगतान हुआ है। जब तीन ही जिले में भुगतान हुआ है तो आपने कैसे कह दिया कि सभी जिलों में भुगतान हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। 14वें, 15वें वित्त आयोग की राशि में रखरखाव का एक मद है और दूसरा जो मूल अनुदान की अनाबद्ध राशि है, उसमें से जो 10 प्रतिशत राशि है, व्यय और संचालन में खर्च की जा सकती है, इन्होंने उस राशि में से पेमेंट किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में आपको बता देता हूं कि 14वें, 15वें वित्त आयोग की राशि से पैरा परिवहन नहीं किया जा सकता, वह पंचायत की परिसंपत्तियों का रख रखाव कर सकती है, पैरा परिवहन रख रखाव नहीं है। तीन जिलों में हुआ है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सभी जिलों में यह राशि दी है। यह आपके सामने ही कहा है, आप परिशिष्ट देख लीजिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने 14 दिसंबर, 2021 की प्रश्नोत्तरी मुझे जवाब दिया था। जो गौठान सेस लगाया था, उसकी राशि से पैरा परिवहन किया गया। अभी 14वें वित्त आयोग और गोधन न्याय योजना कहा। अभी मुझे नहीं बताया कि गोधन न्याय योजना से क्या पैरा परिवहन किया जा सकता है, इसका उत्तर नहीं दिया। जो 53 करोड़ रूपए स्थानांतरित किया गया, वह कौन-कौन से मद के थे, यह बता दीजिए ? जो गौठान समितियों को दिया गया है ? इस-इस मद की राशि गौठान समिति को दी गयी, जो आपने उल्लेख किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने बताया न कि 10 प्रतिशत जो अनाबद्ध राशि है, उससे किया गया। दूसरा, 1.86 लाख, 67 हजार रूपये 14वें, 15वें वित्त आयोग से और मूलभूत निधि से 90 लाख रूपये पेमेंट किया गया।

श्री अजय चंद्राकर :- वह तो 14वें, 15वें वित्त आयोग का बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जो 3 जिला है, आपने सब जिला कह दिया था। मैं शुरू से पूछ रहा हूं, क्या गोधन न्याय योजना की स्कीम में पैरा परिवहन किया जा सकता है ? आपने 28 करोड़ और 24 करोड़ गौठान समिति को स्थानांतरित किया, जिससे पैरा परिवहन हुआ। 24 करोड़ और 28 करोड़ कौन-कौन से मद के थे ? जब बताएंगे तो यही तो असली भ्रष्टाचार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि में 10 प्रतिशत पैसा इस काम में खर्च करने की अनुमति है और उसी राशि से यह पैसा खर्च किया गया है। गोधन न्याय योजना के मद से 53 करोड़ 50 लाख रूपए दिया गया है। जो मजदूरी और परिवहन व्यय में खर्च किया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने सेस की राशि से पैरा परिवहन किया है या नहीं किया है, मुझे यह बता दीजिए ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं आपको इसकी जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसका प्रमाण दे रहा हूं कि 14 दिसम्बर, 2021 को।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खड़े हे, तेखर मन के ए प्रश्न हा कतेक बेर ले चलही? हमेशा गोबर भरे हे। जब देखबे गोबर-गोबर करथे।

श्री अजय चंद्राकर :- आप रूकिये तो।

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी अलग से जानकारी नहीं चाहिए। मुझे इस सदन में इसकी जानकारी चाहिए। यहां पर अधिकारी बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो प्रश्नकाल में दूसरे विकल्प भी होते हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो इस विषय पर चर्चा भी ले सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 4 दिन का समय शेष है। यदि आप चर्चा स्वीकृत करेंगे तो मैं इस विषय पर चर्चा भी कर लूंगा। लेकिन मैं आपको दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 के प्रश्न के माध्यम से इसका प्रमाण दे रहा हूं कि इन्होंने शेष की 15 करोड़ रूपये की राशि को उन्नयन बोर्ड को स्थानांतरित की और उसने वह राशि गौठान समिति को स्थानांतरित की कि ये पैसे पैरा ढुलाई के लिए हैं। शेष की राशि और 14वें व 15 वेंवित्त की राशि सिर्फ गोधन न्याय योजना की राशि है। वह राशि गोबर खरीदी के लिए है, पैरा परिवहन के लिए नहीं है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि शेष की राशि का उपयोग किया गया है। मैं टेबल कर दूंगा। मेरे पास उसके परिशिष्ट हैं। आप इसमें आधे घण्टे की चर्चा की व्यवस्था दे दीजिए या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराएंगे? यदि जांच की घोषणा होगी तो मैं दर पर प्रश्न नहीं पूछूंगा, नहीं तो मैं दर पर प्रश्न पूछूंगा। आप परिशिष्ट को पढ़िये, उसमें दर पर लिखा है कि स्वविवेक और दूरी के आधार पर किसमें ढुलाया गया? कितना ढुलाया? कौन सी दर है? बोझा के हिसाब से दिया गया या मेटाडोर के हिसाब से दिया गया या गाड़ी के हिसाब से दिया गया या ट्रक के हिसाब से दिया गया और कितनी दूरी का दिया गया?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसमें पहले एक का उत्तर आ जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके पास जो पूर्व की जानकारी है। निश्चित रूप से गौधन न्याय योजना में पैसे स्थानांतरित किये गये। सरकार ने गौधन न्याय योजना की राशि खर्च की है। इसलिए उनके पास जो पूर्व की जानकारी है, वह भी सही है। गौधन न्याय योजना में जो पैसे आये, हमने उस गौधन न्याय योजना से पैसे खर्च किये हैं। यह जो परिवहन का रेट पूछ रहे हैं तो ट्रैक्टर और छोटी गाड़ियों से परिवहन किया गया है। उसमें परिवहन का व्यय 285 रूपये से 1000 रूपये तक दिया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत क्लियर कट है कि मैं आपको इसका प्रमाण दे रहा हूं कि शेष की राशि का उपयोग पैरा ढुलाई के लिए हुआ है। जिसको इसमें छिपाया गया है। यदि आप अनुमति देंगे तो मैं उस प्रमाण को अभी टेबल कर सकता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आप जो पैरा ढुलाई में दूरी के आधार पर परिवहन का व्यय 285 रूपये से 1000 रूपये तक बता रहे हैं। आपने 14वें व 15वें वित्त आयोग से भुगतान किया होगा तो आप कोई भी एक जिला ले लीजिए और यदि पैरा ढुलाई हुई होगी हो तो उसकी जांच करवा लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं कि क्या आप विधायकों की समिति से इसकी जांच करवाएंगे ? क्योंकि विधान सभा को गुमराह किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री जी इसमें भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर उनका प्रश्न है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। उन्होंने इसमें जांच की मांग की है तो निश्चित रूप से हम वरिष्ठ अधिकारियों की समिति से इसकी जांच करवाएंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, आप विधायकों की समिति से इसकी जांच करवाइये, क्योंकि पैरा ढुलाई कागज में हुई है। आपने 45 लाख टन पैरा किसमें तौलवाया है, उसकी मुझे एक रसीद बता दीजिए। आपके अधिकारी यहां पर पर बैठे हैं तो वह 45 लाख टन पैरा की रसीद भेज दें।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जांच कराने के लिए सहमत हो गये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच अधिकारियों से नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही तो सब करा-धरा है। मैं तो विधायकों की समिति या प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जांच कराने की मांग कर रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर तो जतका अधिकारी मन गड़बड़ हें।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट, आप बैठिये।

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी, प्रश्नकाल में खड़े नहीं होते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जांच की बात कही। उसके लिए मैं आपको विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि पैरा दान हुआ ही नहीं है। मेरा यह आरोप है कि 53 करोड़ रूपये कागज में बुक हुए हैं। जिन लोगों ने यह किया है। ठीक है कि आज विभाग बदल गये हैं, लेकिन आप विधायकों की समिति या प्रश्न एवं संदर्भ समिति से इसकी जांच करवाने की घोषणा कर दीजिए। अधिकारियों से जांच करवाने पर उसकी पूरी हेरा-फेरी हो जाएगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी सहमति होगी तो हम प्रश्न एवं संदर्भ समिति से इसकी जांच कराने की अनुमति देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, इसकी प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जांच करवा लीजिए। सुश्री लता उसेंडी जी।

श्री अजय चंद्राकर :- धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी, धन्यवाद।

<u>कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्रांतर्गत गोबर खरीदी का भुगतान</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

12. (*क्र. 2476) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य शासन द्वारा विगत 3 वर्षों में कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कितने गोठानों का निर्माण किया गया? निर्माण हेतु किस मद से राशि उपलब्ध कराई गई? कितने गोबर की खरीदी की गई एवं कितना भुगतान किया गया तथा विभाग को क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई एवं किन-किन शिकायतों का निराकरण किया गया ? वर्षवार शिकायतवार जानकारी देवें? **(ख)** कोंडागांव विधान सभा क्षेत्र में गोधन न्याय योजना अंतर्गत कितने गोबर की खरीदी की गई ? कितना भुगतान किया गया एवं कितना भुगतान शेष हैं? **(ग)** कोंडागांव विधान सभा क्षेत्र में गोधन न्याय योजना अंतर्गत किन-किन हितग्राहियों को 30000 (तीस हजार) या उससे अधिक मूल्य के गोबर की खरीदी का भुगतान किया गया? हितग्राहीवार, भुगतानवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कोंडागांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड कोण्डागांव एवं माकड़ी मे विगत 3 वर्षों 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में 100 गोठानों का निर्माण किया गया है। गोठान निर्माण हेतु मदवार राशि का **विवरण संलग्न प्रपत्र[8] अनुसार है।** प्रश्नधीन अवधि में 96,959.84 क्विं. गोबर की खरीदी की गई एवं राशि रू. 193.92 लाख का भुगतान किया गया। विभाग को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ख)** कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड कोण्डागांव एवं माकड़ी में प्रश्नांश "क" की अवधि में योजना अंतर्गत मात्रा

[8] परिशिष्ट ''आठ''

96,959.84 क्विं. गोबर खरीदी किया जाकर राशि रू. 193.92 लाख का भुगतान किया गया। भुगतान हेतु शेष राशि की जानकारी निरंक है। **(ग)** कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड कोण्डागांव एवं माकड़ी मे प्रश्नांश "क" की अवधि में हितग्राहियों को राशि रु. 30,000 या उससे अधिक मूल्य के गोबर की खरीदी का भुगतान की जानकारी निरंक है।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पैरे की बात आई है। मैं गोबर की बात भी करना चाहूंगी। क्या सरकार ने गोबर खरीदी के लिए कोई अलग से मद रखा है या यहां पर जो जानकारियां दी गई थीं कि इसके लिए अलग-अलग मद रखे गये हैं या बजट में इसके लिए कोई अलग से विशेष मद रखा गया है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गौठान समिति के माध्यम से ही गोबर खरीदी का मद रखा गया है।

सुश्री लता उसेण्डी :- अध्यक्ष जी, गौठान समितियों को गोबर खरीदने के लिए क्या सरकार अलग से पैसा देती है या फिर किस मद से भुगतान दिया जाता है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गोबर खरीदी के लिए अलग से मद है, उस मद से उनको पैसा दिया जाता है ।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी गई है कि किसी भी हितग्राही को 30 हजार रूपए तक का भुगतान नहीं किया गया है। हितग्राही के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि हमारे पास जितने मवेशी हैं, उसके आधार पर हमारे पास उतना गोबर नहीं है, लेकिन भुगतान की सूची देखेंगे तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर लोगों के पास जितने मवेशी नहीं हैं, उससे ज्यादा गोबर बेचने और खरीदने का मामला है और उसको भुगतान भी उसी तरीके से किया गया है । जिस तरीके से माननीय अजय चन्द्राकर जी के प्रश्न को समिति से जांच कराने की बात की गई थी । मैं यहां जानकारी देना चाहूंगी कि एक हितग्राही के पास 10 मवेशी है, वह खुद कह रहा है कि मेरे पास 52000 किलोग्राम ही गोबर उपलब्ध था, लेकिन वहां पर 5,44,923 किलोग्राम गोबर खरीदी गई है ।

अध्यक्ष महोदय :- इनका मूल प्रश्न यह है कि चारा कम खाये और गोबर ज्यादा कैसे दिए ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र में कुल 96,959 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है और उस गोबर खरीदी के विरूद्ध 2020-21 में 60 लाख रूपए, 21-22 में 57,62,000 रूपए और 2022-23 में 75 लाख रूपए का भुगतान हुआ है । इस प्रकार कुल 1 करोड़, 93 लाख रूपए का भुगतान हुआ है ।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही तो प्रश्न है । जिसके पास मवेशी कम है, उसको राशि प्रदान की गई है और गोबर ज्यादा खरीदी गई है । क्या इसकी जाँच समिति से कराएंगे ?

क्योंकि शराब का पैसा कहां-कहां पहुंचा है, वह तो सबको पता है । गोबर का पैसा कहीं-कहीं पर पहुंचा है, उसकी जांच कराएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- किस नस्ल की गाय या भैंस है, उसकी जांच करानी पड़ेगी, माननीय सदस्या का यह प्रश्न है । यह गंभीर प्रश्न है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह गोठान से संबंधित मुद्दा है, चारे के भुगतान का मुद्दा, गोबर का मुद्दा है । मैं सोचता हूं कि जब आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति को मामला संदर्भित करने वाले हैं, उसमें आप यह गोबर का प्रश्न भी जोड़ लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- उसको भी जोड़ लेंगे ।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का राशि आंवटन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

13. (*क्र. 2299) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021-2022 से प्रश्न दिनांक तक अनुसूचित जाति प्राधिकरण को कुल कितनी राशि का आंवटन प्रदाय किया गया, वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** प्राधिकरण द्वारा प्रश्नांश **(क)** अवधि में किस-किस प्रकार के निर्माण कार्य हेतु, किन-किन विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के दिये गये? इनमें कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं तथा कब तक पूर्ण किए जायेंगे समयावधि बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3550.00 लाख वर्ष 2022-23 में 3550.00 लाख एवं 2023-24 में 3550.00 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया। विस्तृत जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र अनुसार है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में कितनी-कितनी राशि मिली ? मंत्री जी ने जानकारी दी है कि 35 करोड़, 50 लाख रूपए प्रदान किया गया है । इसमें कितना काम पूर्ण हो चुका है, कितना काम अपूर्ण है और उसमें कितनी राशि अभी बची हुई है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसकी पूरी सूची दे दी है, वह बहुत लंबी सूची है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पुस्तकालय के माध्यम से पूर्ण-अपूर्ण कार्यों की सूची मिल चुकी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें कितनी राशि बची हुई है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 में 35 करोड़, 50 लाख रूपए स्वीकृत थी, उसमें से 727 स्वीकृत कार्य थे, पूर्ण कार्य 653, अपूर्ण कार्य 74 हैं और अपूर्ण कार्यों का प्रतिशत 10 प्रतिशत है । वर्ष 22-23 में भी 35 करोड़, 50 लाख रूपए दिए गए, उसमें 705 काम दिए गए । 509 कार्य पूर्ण हैं और 196 कार्य अपूर्ण हैं । 2023-24 में 35 करोड़, 50 लाख रूपए दिए गए, उसमें 634 काम दिए गए । उसमें से 102 काम पूर्ण और 379 काम अपूर्ण हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें अभी तक कितनी राशि बची हुई है, फिर मैं दूसरा प्वाइंट बताता हूं । 2022-23 में अपूर्ण कार्य पास होने के बाद अपूर्ण कार्य अप्रारंभ है, की स्थिति में विधान सभा चुनाव के पहले निरस्त कर दिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राधिकरण में अभी तक कितनी राशि बची हुई है, जिसे पास करना बाकी है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राधिकरण में 5 करोड़ रूपए की राशि बकाया है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि निरस्त कार्यों में मैंने प्रस्ताव दिया था कि मुंगेली विधान सभा क्षेत्र, मुंगेली जिले में लगभग 1 करोड़ का कार्य अप्रारंभ होने की स्थिति में उसे निरस्त कर दिया गया । मैंने जो नया प्रस्ताव दिया है, उसे आप जोड़ेंगे क्या ? मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में 27 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है तो प्रतिशत के आधार पर राशि स्वीकृत करेंगे क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- निश्चित रूप से। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय का जो प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव दे दें। अगर उसमें राशि बचेगी तो निश्चित रूप से जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र को प्राधिकरण के द्वारा ही वह राशि दी जाती है, वह राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि मोहले जी मुंगेली को लेकर बहुत संवेदनशील हैं।

<u>राज्य के जी.एस.टी. विभाग में पंजीकृत व्यवसायी</u>

[वाणिज्यिक कर]

14. (*क्र. 2457) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में जी.एस.टी. विभाग में कितने पंजीकृत व्यवसायी हैं? जी.एस.टी. लागू होने के उपरांत कितने व्यवसायियों द्वारा पंजीयन निरस्त कराये गये हैं? कुल पंजीकृत व्यवसायियों में से कितने व्यवसायियों द्वारा निरंक कर जमा किया जा रहा है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : 31 जनवरी, 2024 की स्थिति में जी.एस.टी. विभाग में कुल 1,76,777 पंजीकृत व्यवसायी हैं। जी.एस.टी. लागू होने के उपरांत 50,298 व्यवसायियों द्वारा पंजीयन निरस्त कराये गये है। कुल पंजीकृत व्यवसायियों में से वर्तमान वित्तीय वर्ष में (दिनांक 14.02.2024 की स्थिति में) 13,760 व्यवसायियों द्वारा निरंक कर जमा किया जा रहा है।

श्री कंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वाणिज्य कर विभाग से था। इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सन् 2024 की स्थिति में जी.एस.टी. विभाग में कुल 1,76,777 पंजीकृत व्यवसायी हैं। जी.एस.टी. लागू होने के उपरांत 50,298 व्यवसायियों द्वारा पंजीयन निरस्त कराये गये है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पंजीयन निरस्त कराने और जी.एस.टी. निरंक जमा करने से राजस्व का कितना नुकसान होता है ? यह बताने का कष्ट करेंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो प्रश्न किया था, उसमें विभाग न जवाब दे दिया है। कुल 1,76,777 करदाता हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के करदाता हैं। जो पंजीयन निरस्त कराने वाले हैं, उनका पंजीयन कई कारणों से निरस्त होता है। कई ऐसे फर्म हैं, जो 6 महीने से रिटर्न जमा नहीं करते हैं, उनका भी पंजीयन निरस्त किया जाता है। कुछ ऐसे फर्म हैं, जो अपना व्यवसाय बदल लेते हैं, उनका भी पंजीयन निरस्त होता है। हम ऐसे 6 कारणों से पंजीयन निरस्त करते हैं। यदि उसकी पृथक से जानकारी चाहते हैं तो पृथक से जानकारी दे सकता हूं।

श्री कंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि व्यवसायी पंजीयन तो करा लेते हैं और अंत में हिसाब नहीं देते, ऐसे कितने व्यापारी हैं ? साथ ही विभाग इन पर क्या कार्यवाही करता है, यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें राजस्व नुकसान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। टैक्स नम्बर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें अपना कोई राजस्व का नुकसान नहीं होता है, जो फर्म ऐसे सरेण्डर कर देते हैं। क्योंकि इसकी सीमा सन् 2019 से 40 लाख रूपये है। पहले 20 लाख रूपये थी। सामान्यत: जिनका 40 लाख रूपये तक टर्न ओवर नहीं होता, उनके द्वारा टैक्स पैड करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसलिए कोई नुकसान नहीं होता है ।

श्री कंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीकृत फर्म के लिए आयकर और पैन अनिवार्य होता है। आप बताते हैं कि आयकर विभाग में घरेलू कर के हिसाब से बिक्री कर मुनाफा कमाते हैं। इसी मुनाफे के आधार पर उसे मुनाफे के आधार पर कर जमा करना होता है। फिर भी यदि कोई व्यापारी जी.एस.टी. जमा नहीं करता है तो यह तकनीकी रूप से कर की चोरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इसे रोकने के लिए सरकार के द्वारा उपाय किया गया है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- कर चोरी रोकने का कोई उपाय कर रहे हैं क्या ? आप कर चोरी रोकने के उपाय करिये, यह उनका सुझाव है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय। हम कर रहे हैं। इन्होंने विगत 5 साल में जितना किया था, हमने उसका 20 प्रतिशत केवल दो महीने में किए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा, चलिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही की गई है, जिसमें 13 करोड़ 70 लाख रूपये वसूला गया है।

प्रश्न संख्या 15 : XX XX

प्रश्न संख्या 16 : XX XX

<u>अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से स्वीकृत व निरस्त कार्य</u>

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

17. (*क्र. 1365) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राज्य अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ से जनवरी, 2022 से दिसंबर, 2023 तक के मध्य निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? यदि हां तो प्रदेश में उक्त अवधि में कुल स्वीकृत कार्य की जिलेवार, विकास खंडवार, स्वीकृत राशि सहित कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्रदान करें। **(ख)** क्या उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने हेतु राज्य शासन से कोई निर्देश जारी किया गया है? यदि नहीं तो क्या बिना राज्य शासन के निर्देश केव बिना अध्यक्ष के अनुमोदन के सदस्य सचिव, कमिश्नर दुर्ग द्वारा अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने हेतु आदेश जारी किया गया है? यदि हां तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) जी हॉ। जानकारी **पुस्तकालय** में रखे प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 42/2023, क्रमांक/2520/एफ-2013-04-00224/ब-4 /चार, नवा रायपुर, दिनांक 20.12.2023 में इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से राज्य बजट से वित्त पोषित सभी अप्रारंभ निर्माण कार्यों को वित्त विभाग की पुनः सहमति के उपरांत ही प्रारंभ किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के परिपत्र क्र.2270/1883/2023/एक/6, नवा रायपुर दिनांक 15.12.2023 द्वारा राज्य में विगत वर्षों में जो राजनैतिक नियुक्तियां (विभिन्न निगम, मंडल, आयोग/सभा समिति आदि में) की गई है, उन्हें तत्काल प्रभाव से समाप्त किया गया है। चूंकि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में माननीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई थी, इसलिए जिलों से प्राप्त 153 अप्रारंभ कार्यों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1299,1301, 1303,1305, 1307,1309,1311,1313,1315, 1317, 1319, 1321, 1323,1325 तथा

1326, दिनांक 26.12.2023 को बिना अनुमोदन के निरस्त किये जाने की कार्यवाही की गई है। प्राधिकरण में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति पश्चात् उपरोक्त निरस्त कार्यों के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु आगामी बैठक में रखा जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.12.2023 एवं वित्त विभाग के वित्त निर्देश दिनांक 20.12.2023 में दिये गये निर्देश के उपरांत निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। अतः उक्त कार्यवाही हेतु कोई भी अधिकारी दोषी प्रतीत नही होता।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट शेष है। जल्दी-जल्दी प्रश्न पूछिये।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से प्रश्न पूछा था। राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण मद से जो जानकारी मांगी थी, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मेरा सवाल यह था कि क्या अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण मद से पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में स्वीकृत किया गया था, वह गलत है या सही है ? यह जानकारी दे दीजिये ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बताईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्राप्त जानकारी के अनुसार सही है।

अध्यक्ष महोदय :- अगला प्रश्न पूछ लीजिये।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि सही है। अगर वह सही है तो मंत्री महोदय यह बताये कि प्रारंभ कार्यों की स्वीकृति को किसके आदेश से निरस्त किया गया है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको निरस्त नहीं किया गया है। पुराने काम, जो प्रारंभ नहीं हुए थे, अभी उन कामों को प्रारंभ नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं, निरस्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय
12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारास-19 के अंतर्गत तेईसवॉ प्रतिवेदन वर्ष 2023

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारास-19 के अंतर्गत तेईसवॉ प्रतिवेदन वर्ष 2023 पटल पर रखता हूँ ।

(2) संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) 381/एफ2(3) /48/सं.का./2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023 एवं

(ii) 383/एफ 2(3)/48/सं.का./2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023

पटल पर रखता हूँ ।

पृच्छा

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौंडीलोहारा) :- अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामूहिक कन्या विवाह योजना रद्द होने के बारे में कहना चाहूंगी कि 19 तारीख को सामूहिक विवाह की तिथि निकलने के बाद 17-18 तारीख को वर-वधू का तेलमाटी, चुलमाटी की प्रक्रिया जो छत्तीसगढ़ में होती है, वह सब होने के बाद 19 तारीख को तय था और 19 तारीख को विभाग से आदेश आता है कि फण्ड के अभाव के कारण विवाह रद्द किया जाये । मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में मार्च, अप्रैल, मई में ही शादी की तिथि होती है और इसमें मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना है, यह मात्र योजना नहीं है...।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल की सूचना संक्षिप्त होती है, इसमें भाषण नहीं होता है, इन्फरमेशन होता है । आप जो बोल रही है, उसे मंत्री जी नोट करेंगे, मगर शून्यकाल इतना लंबा नहीं होता है । चलिये ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य रूप से भावनाओं से जुड़ा हुआ है, मैं इस तरफ ध्यान आकर्षण कराना चाह रही हूँ । जो योजना है, विभाग के द्वारा बंद करने के लिये सूचना दी गई है, इसलिये मैं कहना चाहती हूँ कि इसे वापस लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री व्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-विधान सभा विधान सभा क्षेत्र जो कि 100 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है । धान का भरपूर उत्पादन होता है । एक माह से अधिक समय हो गये हैं, हम किसानों के खाते पर अभी तक रकम नहीं आ पाया है । जांजगीर का जो बैंक है, जिसमें 17 हजार से अधिक खाताधारक है, लाईन लगाना पड़ता है, यह दोनों समस्या वहां है, कृपा करके खाता में पैसा आये और समय पर हमें रकम मिले ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे विधान सभा का एक गुरूर ब्लॉक है, उसमें रमतरा गांव हैं, वहां एक 30 साल का युवक है, वह कीटनाशक दवा का प्रयोग किया और उसे 12 बजे गुरूर के अस्पताल में भर्ती किये । धमतरी के जिला अस्पताल में 12 बजे से 2 बजे उनको रिफर किया गया और रिफर होने के बाद वहां दिन भर ट्रीटमेंट हुआ । रात को 12 बजे उनके परिजन को चिट थमाया गया कि आप इसको ले जाईये, कहीं भी ले जाईये, यह भी कहा गया कि इनको रायपुर ले जायेंगे तो वहां तक ले जाने में रास्ते पर ही मौत हो जायेगी । अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण करना चाहती हूँ कि ऐसे डॉक्टर पर कार्यवाही किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर जी ।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सुबह मनरेगा में काम करते वख्त ग्राम पंचायत सनौद के आश्रित ग्राम नवागांव निवासी दिनेश ठाकुर की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि परिवार के प्रति यदि कोई ऐसी सहायता बनती है तो उसे दिलाने के लिये प्रयास करने की कृपा करेंगे । इसी के साथ एक और है ...।

अध्यक्ष महोदय :- एक ही होता है, एक सूचना होती है, दूसरी कल देंगे । नेता प्रतिपक्ष जी ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख की बात है कि आपके जिले के ही प्रश्न मुझे बार-बार उठाने पड़ते हैं, आपके जिले में माननीय गृह मंत्री के गृह जिले में एस.पी. आफिस के सामने एक मकान में बदबू आई और देखा गया कि यहां कुछ सड़ी हुई लाश है, रायपुर में सूचना के बाद फॉरेंसिक के अधिकारी वहां गये, उन्होंने दरवाजा तोड़ा और जांच की तो अलग-अलग दो कमरों में, एक में मां की और एक में बेटी की लाश पायी गयी। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वह सही है

या गलत है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप गृह मंत्री जी को निदेर्शित कर दीजिये कि वे तत्काल जांच करें। इस तरह से लगातार दूसरे, तीसरे दिन कवर्धा जिले में हत्याएं हो रही है। इसमें आपका नाम खराब हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि मेरे प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 29 जनवरी को एक बच्चे का अपहरण हो गया था। दिनांक 24 फरवरी को यह पता चला कि उसकी हत्या 29 जनवरी को ही कर दी गयी थी और बहुत ही निर्ममतापूर्वक हत्या की गयी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि पीड़ित परिवार को कुछ अनुदान राशि देने की घोषणा कर दें।

अध्यक्ष महोदय :- लता जी।

सुश्री लता उसेंडी (कोंडागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पेशेंट को रात 8.00 बजे एम.एम.आई. हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, फिर रात 12.00 बजे ही उनके परिवार के सदस्य से यह कहा जाता है कि आपका पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, इसलिये हम उनको यहां नहीं रखेंगे, आप इन्हें इमिडियेट दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाईये। यदि कोई व्यक्ति रात को 8.00 बजे भर्ती हुआ है और आप रात को 12.00 बजे ही उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की बात कहेंगे तो वह रात को परेशान होकर हॉस्पिटल ढूंढता रहता है कि पेशेंट को कहां भर्ती कराया जाये। अधिकारियों के सही ढंग से निरीक्षण नहीं करने के कारण भी कहीं पर भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है और इससे पूरे परिवारों को, मरीजों को और परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सामरी में 20 फरवरी को एक पहाड़ी कोरवा जनजाति का लड़का नदी में डूब गया और आज दिनांक तक उसकी लाश नहीं मिली है। मैं आपका ध्यानाकर्षण कराना चाहती हूं कि उसकी लाश को ढूंढवाने की कोशिश करें।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गरियाबंद जिले के नगरपालिका, नगरपंचायत स्तर की बात बताना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र में 50 से 70 साल पहले से बसे हुए परिवार हैं, जो तालाब के आस-पास बसे हुए परिवार हैं, जिनको अभी तक पट्टे का वितरण नहीं हुआ है। जिसके कारण आज जो हमारे केंद्र सरकार की हमारे राज्य के लिये महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका लाभ उन गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उन गरीब परिवारों को पट्टा वितरण किया जाये, ताकि उनका आवास बन सके। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- रोहित जी, धन्यवाद।

श्री जनक ध्रुव (बिंद्रानवागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिला- गरियाबंद में एक हिना नेताम नाम की 4 वर्ष की लड़की है, जो डांग बंगला की निवासी है और एक कुमारी कुमकुम साहू नाम की 16 वर्ष 2 माह की लड़की है। यह दोनों लड़कियों का लगभग पिछले एक महीने से अपहरण हो गया है। एक लड़की का 14 जनवरी को और एक लड़की का 15 जनवरी को अपहरण हुआ है। अपहरणकर्ता एक लड़की को राजस्थान और एक लड़की को उत्तरप्रदेश ले गये हैं। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से तत्काल इन पर कार्रवाई की जाये।

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि शून्यकाल की सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिये मेरा मंत्री जी से और जो अधिकारी यहां बैठे हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया इसको गंभीरता के साथ नोट किया जाये और इस पर आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित हो।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने आपके सामने पहले भी इस विषय को उठाया है कि कल कवर्धा में फिर से पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने दो-दो हत्याएं होना, इससे पहले साधराम यादव की हत्या होना ,फिर वहां के जो बैगा आदिवासी हैं, उनकी हत्या होना। कानून व्यवस्था के ऊपर भी एक सवाल है कि इस तरह से वहां पर लगातार हत्याएं क्यों हो रही है ? एक बार फिर से दो-दो हत्याएं हुई हैं और वहां से अभी तक उसके बारे में मालूम न होना कि हत्याएं किसने की है और हत्याएं क्यों हुई है ? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। पटेल जी।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कवर्धा में हो क्या रहा है ? वहां लगातार खून पर खून होते जा रहे हैं और वह आपका स्वयं का क्षेत्र है और माननीय गृहमंत्री जी का गृह जिला भी है। कवर्धा में इतनी सारी हत्याएं हो रही हैं, इससे पूरे प्रदेश में एक अच्छा संदेश भी नहीं जा रहा है। लगातार दो महीने के अंदर खून हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही चाहूंगा कि इस पर सरकार की तरफ से वक्तव्य आये और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को यह आश्वस्त किया जाये कि कानून व्यवस्था ठीक की जा रही है।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्कूल हैं, वह ज्ञान का एक मंदिर है। उस मंदिर के ज्ञान की अलौकिक प्रकाश बिखेरने वाले हमारे गुरूजन हैं। खासकर सहायत शिक्षक हैं, जो कि लंबे समय से वेतन विसंगति को लेकर प्रयासरत हैं और उनके द्वारा कई बार आन्दोलन और धरना प्रदर्शन के जरिये ज्ञापन देकर, शासन और प्रशासन को अवगत कराया गया,

लेकिन अभी तक उनकी जो समस्या है, आज तक जस के तस है। मैं माननीय विभागीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वह इस पर जल्द ही कोई फैसला लें और इन वेतन विसंगतियों को दूर करें। उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना कर, 20 वर्ष पूर्ण पेंशन की ओर अपना निर्णायक कदम उठायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- श्री यादव जी। यहां सदन में दो यादव हैं रामकुमार जी को नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी):- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कवर्धा जिले में आये दिन मर्डर, कत्ल हो रहे हैं। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब शायद कवर्धा में निवास करने की स्थिति में नहीं हैं। जो वहां पर निवासरत हैं उनके साथ कब, क्या अप्रिय घटना घट सकती है या इस दुनिया से वह कब चले जाएंगे, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कवर्धा जिला में हर दो दिन और तीन दिन में एक न एक अपराध, हत्याएं हो रही हैं। मुझे इसलिए भी चिंता है क्योंकि अब तो पूरे हिन्दुस्तान ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग भी कवर्धा में रात रूकने से डरेंगे। यह स्थिति बनी हुई है। इसमें तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर क्षेत्र में कलमा अउ साराडीह जो बैराज हे ओ मे बहुत सारा किसान के अभी सर्वे नइ हो पाये हे, मुआवजा नइ मिले हे तेखर कारण ओ मन ला सरकार के प्रति बहुत रोष हे। एकर बहुत जल्दी सर्वे कराकर, ओ मन ला मुआवजा दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मोला बोले के मौका देव, ओकर बर आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद्।

(माननीय सदस्य श्री कुंवर निषाद द्वारा हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूँ। एक दिन में एक ही सूचना होती है । मैं, आपको कल मौका दूंगा।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जहां पर रहती हूँ। मेरा निवास खैरागढ़ अमलीपारा है। वहां पर मैंने एक बार और कहा था, लेकिन अभी तक इसमें कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वहां पर स्कूल है और स्कूल से कुछ ही दूर में, ज्यादा दूरी नहीं है वह 100 मीटर की दूरी से भी कम है। अभी तक वहां चखना दुकान संचालित है। अब वहां चखना दुकान के साथ-साथ शराब की बिक्री भी होनी शुरू हो गई है। वहीं पर स्कूल है। वहां पर स्कूल के बच्चे रोल खाने के लिए जा रहे हैं। आज वह रोल खाने जा रहे हैं और

कल के दिन वह शराब पीने भी लगेंगे तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन है कि वहां से उस चखना दुकान को हटाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री इन्द्रशाह मण्डावी (मोहला-मानपुर):- माननीय अध्यक्ष महोदय, कवर्धा का मामला बहुत संगीन है। एस.पी. ऑफिस के जस्ट 100 मीटर की दूरी पर दो-दो हत्याएं होना बहुत गंभीरता को प्रदर्शित करता है इसलिए इसमें सरकार का वक्तव्य आना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री बालेश्वर साहू (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां से नाबालिक लड़के, लड़कियों का भाग जाना, गायब हो जाना या अपहरण हो जाता है। उनकी थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी माता-पिता, खासकर जिसकी लड़की नाबालिक स्थिति में भाग जाती है या गायब हो जाती है और उनकी थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी हफ्ता महीना गुजर जाता है उनको अपनी बेटी या बेटे के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें पुलिस विभाग समय सीमा तय करें । उनकी हत्या हो गई, वह गायब हो गये या छत्तीसगढ़ प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले गये या किसी लड़के के साथ है तो उसकी तिथि तय कर उसके मम्मी पापा, परिवार को जल्द से जल्द बताया जाए, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से ऐसी मांग करना चाह रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती कविता प्राण लहरे (बिलाईगढ़):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलाईगढ़ विधान सभा से आथौ। मोर विधान सभा क्षेत्र में एक ताड़ापाड़ा गांव हे जहां कल नौ बजे एक 12 साल के बच्चा ला ट्रेक्टर कुचल के चले गे। बच्चा के समय में ही मृत्यु हो गे। ओ गरीब परिवार के बच्चा ए। आप थोड़ा मुआवजा के कुछ प्रावधान कर देतेव ता अच्छा रहितिस।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मोला बोले के मौका देव, ओकर बर आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा):- माननीय अध्यक्ष महोदय, महामाया की नगरी रतनपुर में कका पहाड़ के नीचे एक आश्रम में एक साधु महात्मा के ऊपर प्राणघातक हमला होता है। वहां अभी तक अपराधी फरार हैं। आप उस बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें क्योंकि इस छत्तीसगढ़ राज्य में साधु तक सुरक्षित नहीं है तो और कौन सुरक्षित रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

अध्यक्ष महोदय :- श्री बालेश्वर साहू जी, अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें।

समय :
12:18 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा दवाईयां वितरण में अनियमितता की जाना।

श्री बालेश्वर साहू (जैजैपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित संस्था छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरशन लिमिटेड, रायपुर (सीजीएमएससी) द्वारा प्रदेश के लिये सर्जिकल, उपकरण एवं अन्य सामग्रियों के क्रय की कार्यवाही शासन के नियमानुसार की जाती है। पूरे प्रदेश से दवाईयां क्रय कर 16 वेयर हाउसेस के माध्यम से जिलों में सप्लाई की जाती है। सभी वेयर हाउसेस में सीजीएमएससी के कर्मचारी कार्यरत हैं। क्रय की जाने वाली दवाईयों को आपूर्ति के बाद गुणवत्ता जांच के लिये विभिन्न लैब में भेजा जाता है, जहां से सही रिपोर्ट आने के बाद जिलों में भेजना होता है, परंतु सीजीएमएससी के वेयर हाउसेस के कर्मचारियों की मनमानी के कारण आपूर्ति करने वाले फर्मों से प्राप्त दवाइयों एवं अन्य सामग्री को वेयर हाउस में जगह नही है, कहकर 3-4 दिन तक गाड़ियों को खड़ा रखा जाता है, फिर वहां के कर्मचारी कुछ लेनदेन करने के बाद ही माल की आपूर्ति देते हैं। 16 वेयर हाउसेस में सब जगह अलग- अलग अधिकारी नही हैं, बल्कि 2-3 वेयर हाउसेस का जिम्मा एक अधिकारी को दिया गया है, जिसके कारण कार्यवाही नही होती है। जबकि एक अधिकारी को एक ही जगह का पदभार दिया जाना चाहिए। पिछले कई वर्षों से ये कर्मचारी एक ही जगह पर जमे हुए हैं, जिसके कारण वे मनमानी वसूली करते हैं। अभी तक एक बार भी इन कर्मियों का स्थानांतरण अन्य जगहों पर नही किया गया है। माल की आपूर्ति लेने के बाद गुणवत्ता टेस्ट के लिये मुख्यालय भी समय से नही भेजा जाता है। अभी वर्तमान में 1500 आईटम्स विभिन्न 16 वेयर हाउसेस में उपलब्ध हैं, जिसमें करीब 200 आईटम्स ही गुणवत्ता टेस्ट के लिए लंबित

हैं एवं 1300 आईटम्स की गुणवत्ता पास हो गयी है, उसके बावजूद भी उन आईटम्स को 16 वेयर हाउसेस के द्वारा 33 जिलों में नही भेजा जा रहा है, जिसके कारण सभी जिलों में दवाईयों की कमी हो गयी है। सीजीएमएससी के वेयर हाउसेस में दवाईयाँ रखी हैं, किन्तु जनता के काम नही आ रही हैं और उन सभी दवाओं को आम जन को बाहर से खरीदना पड़ रहा है और वे दवाईयों वेयर हाउसेस में रखे-रखे कालातीत (एक्सपॉयरी) हो रही हैं। वेयर हाउसेस के अधिकारियों-कर्मचारियों की मनमानी के कारण जनता को दवाईयां उपलब्ध नही होने से मरीजों एवं आम जनता में शासन के प्रति अविश्वास एवं आक्रोश व्याप्त है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां यह सही है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाली संस्था छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर जिसमें प्रदेश के लिये दवाईयो, सर्जिकल, उपकरण एवं अन्य सागक्रियों के क्रय की कार्यवाही शासन के नियमानुसार की जाती है जिसमें पूरे प्रदेश में दवाईयां क्रय का 16 वेयरहाउस के माध्यम से जिलों में सप्लाई किया जाता है। सभी वेयर हाउस में सीजीएमएससी के कर्मचारी कार्यरत हैं। क्रय की जाने वाली दवाईयों को आपूर्ति के बाद गुणवत्ता जांच के लिये विभिन्न लैबों में भेजा जाता है जहां से सही रिपोर्ट आने के बाद जिलों में भेजना होता है, परंतु यह कहना सही हीं है कि सीजीएमएससी के वेयरहाउस के कर्मचारियों की मनमानी के कारण आपूर्ति करने वाले फर्मो से प्राप्त दवाईयां अन्य सामग्री को वेयर हाउस में जगह नहीं है कहकर 3-4 दिन तक गाड़ियों को खडा रखा जाता है फिर भी वहां के कर्मचारी कुछ लेनदेन करने के बाद ही माल की आपूर्ति देते हैं, अपितु सत्य तो यही है कि सीमीएमएससी के वेयरहाउस के कर्मचारियों द्वारा निविदा नियमानुसार वांछित दस्तावेजों एवं फर्म द्वारा सॉफ्टवेयर में की गई प्रविष्टियों के परीक्षण पश्चात सभी दस्तावेज एवं प्रविष्टियां सही पाये जाने पर अविलंब सामग्री प्राप्त कर, प्राप्ति प्रमाण पत्र बना लिया जाता है।

यह भी कहना सही नहीं है कि 16 वेयर हाउस में सब जगह अलग अलग अधिकारी नहीं है, 2-3 वेयर हाउस का जिम्मा एक अधिकारी को दिया गया है जिसके कारण कार्यवाही नहीं होती है, जबकि एक अधिकारी को एक ही जगह का पदभार दिया जाना चाहिए। अपितु सत्य तो यह है कि वर्तमान में संचालित 16 दवा गोदामों में 10 सहायक प्रबंधकों को दवा गोदामों का प्रभारी बनाया गया है एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से 06 सहायक प्रबंधकों को 01-01 दवा गोदाम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसी भी सहायक प्रबंधक को 3 वेयर हाउस का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया गया है।

यह कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है कि पिछले कई वर्षों से ये लोग एक ही जगह पर जमे हुए हैं, जिनके कारण इनकी मनमानी वसूली आदि करते रहते हैं। अभी तक एक बार भी इनका स्थानांतरण

अन्य जगहों पर नहीं किया गया है। माल की आपूर्ति लेने के बाद गुणवत्ता टेस्ट के लिये मुख्यालय समय से नहीं भेजा जाता है। अपितु सत्य तो यह है कि वर्ष 2017 में 2 एवं 2020 में 2 सहायक प्रबंधकों का स्थानांतरण एक दवा गोदाम से अन्य दवा गोदाम में किया गया है। साथ ही यह भी कहना सही नहीं है कि माल की आपूर्ति लेने के बाद गुणवत्ता टेस्ट के लिये मुख्यालय समय से नहीं भेजा जाता। अपितु सत्य तो यह है कि माल की आपूर्ति लेने के बाद दवा गोदामों से सहायक प्रबंधकों द्वारा तत्काल त्वरित कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता परीक्षण के लिए नमूना (सेम्पल) मुख्यालय भेजा जाता है।

यह कहना सही नहीं है कि वर्तमान में 1500 आईटम विभिन्न 16 वेयर हाउस में उपलब्ध है, जिसमें करीब 200 आईटम ही गुणवत्ता टेस्ट के लिए लंबित है और 1300 आईटम का गुणवत्ता पास हो गया है, उसके बाद भी उस माल को 16 वेयर हाउस के द्वारा 33 जिलों में नहीं भेजा जा रहा है, जिसके कारण से सभी जिलों में दवाईयों की कमी हो गयी है। सी.जी.एम.एस.सी. के वेयर हाउस में दवाईयां रखी हुई है, जनता के काम नहीं आ रही है और उन सभी दवाओं को आम जनता को बाहर से खरीदना पड़ रहा है और ये दवाईयां वेयर हाउस में रखे-रखे कालातित (एक्सपायरी) हो रही है। अतः सी.जी.एम.एस.सी. के वेयर हाउस में दवाईयां रखी हुई है, जनता के काम नहीं आ रही है और उन सभी दवाओं को आम जनता को बाहर से खरीदना पड़ रहा है। अपितु सत्य तो यह है कि दिनांक 25.02.2024 की स्थिति में सी.जी.एम.एस.सी. के अधिनस्थ संचालित विभिन्न दवा गोदामों में 1594 प्रकार की दवाईयां एवं अन्य सामग्री उपलब्ध हैं, जिसमें से 1379 प्रकार का गुणवत्ता परीक्षण उपरांत पास पाया गया है एवं 223 प्रकार गुणवत्ता परीक्षण लंबित है। उक्त के अतिरिक्त सी.जी.एम.एस.सी. के अधिनस्थ संचालित 16 दवा गोदामों द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 25.02.2024 तक) में कुल 1698 प्रकार की दवाई एवं अन्य सामग्रियों का वितरण किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त सी.जी.एम.एस.सी. के वेयर हाउस में उपलब्ध एवं चालू वित्तीय वर्ष में वितरित गई दवाईयों एवं अन्य सामग्रियों की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.cgmsc.gov.in पर आम नागरिकों द्वारा देखी जा सकती है।

अतः सभी वेयर हाउस के कर्मचारी, अधिकारियों की मनमानी के कारण आम जनता को दवाईयां उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों एवं आम जनता में शासन के प्रति अविश्वास एवं आकोश व्याप्त नहीं है।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के मुख्यालय में विभिन्न जिलों में वेयर हाउस में कांट्रेक्ट बेसिक से रखे डेली विजेस के कर्मचारियों के भरोसे यह संस्था चल रही है। जिन कर्मचारियों के विरूद्ध कोई शिकायत या लापरवाही की बात आयेगी तो उन पर सरकार कोई कार्रवाई एवं जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर सकती। इसलिए यहां नियमित कर्मचारियों की भर्ती की जाये। बाजार दर से अधिक दर पर आवश्यकता से अधिक मेडिकल

औजार, मशीन, लैब टेक्निकल की 200 करोड़ रूपये से अधिक की खरीदी की गई है, जिसका उपयोग नहीं होने के कारण वह एक्सपायरी हो रहे हैं। वेयर हाउस में रखी दवाईयां, समस्त वेयर हाउस की जो 785 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जिसमें केमिकल के जो सामान हैं और उसको 517 मेडिकल टेक्निलिसिस्ट और 268 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ना डॉक्टर है और ना ही लैब टेक्निशियन है, वहां भी दवाई माल दे दिए गए हैं। उसको फ्रीज में रखना था, लेकिन आज दिनांक तक वहां पर फ्रीज की भी उपलब्धता नहीं है। यह सभी वहां दवाईयां रखे-रखे एक्सपायरी हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसका भुगतान कर दिया गया है? यदि भुगतान नहीं हुआ है तो इसका चेक का भुगतान रोका जाये और क्या इसकी जांच करवाई जाएगी?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आपने भुगतान किया है या नहीं किया है? यह बता दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस पर बड़ा ही विस्तृत बात किया है। इस पर इनकी चिंता बहुत हद तक जायज है और विगत दो महीनों में विभिन्न अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से सी.जी.एम.एस.सी. के बारे से जितनी भी खबरें छपी और हमने संज्ञान में लिया उसके आधार पर लगभग 400 करोड़ रूपये का भुगतान हमने रोका है और उसकी जांच हमारे विभागीय अधिकारियों के द्वारा की जा रही है । जांच में जो भी तथ्य आयेंगे उसके आधार पर...।

अध्यक्ष महोदय :- यह जो बता रहे हैं उसकी भी जांच करा लीजिये ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बोल रहे हैं उसी में है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विभागीय जांच चालू है । मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जांच के लिये कुछ लिखकर दे दीजिये ।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वेयरहाऊस है । वेयरहाऊस में आपने कहा कि आजतक किसी भी कर्मचारी को एक ही स्थान में नहीं रखा गया है । उनका लगातार स्थानांतरण होता है । मैंने यह जानकारी रखी है कि एक कर्मचारी को 1 या दो गोदाम का प्रभार दिया गया है और आज दिनांक तक उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है और मनमाने ढंग से दवाई की जो गाड़ी है, वहां जब तक उनका लेनदेन नहीं होता तब तक उनकी गाड़ी वहां खड़ी रहती है । मान लो हमारे मेडिकल में या हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई की जरूरत है और वहां मरीज आते हैं, वहां कोई बड़े आदमी ईलाज कराने के लिये नहीं जाते हैं जिसको ब्लड का टेस्ट कराना है उसको तो प्राईवेट बड़े हॉस्पिटल में जाना रहता है लेकिन हमारे गांव की जो गरीब जनता है वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं उसके पास न तो लैब

है, न फ्रीज है और न ही डॉक्टर है तो ऐसी स्थिति में हम जो करोड़ों रूपये की सामग्री खरीद रहे हैं तो क्या हम अपनी गरीब जनता को जो बीमार है क्या उसे धोखा नहीं दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है । आपका प्रश्न हो गया ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.जी.एम.एस.सी. कॉर्पोरेशन छत्तीसगढ़ का मेडिकल क्षेत्र में दवाईयां, उपकरण खरीदने वाली सबसे महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसी उद्देश्य से कि आमजन को कैसे सस्ती दवाईयां और किस प्रकार से गुणवत्तायुक्त दवाईयां मिले उसके लिये स्थापना की गयी थी लेकिन विगत् कुछ दिनों से 5 सालों में इस कदर सी.जी.एम.एस.सी. का नाम मतलब चलते के साथ एक ऐसा प्रतिबिम्बित होने लगा है इसलिये यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस सदन में उसके संदर्भ में कुछ बताना चाहूंगा जिससे मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्य संतुष्ट हो जायेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदस्य जिन प्रबंधकों की बातें कर रहे हैं ट्रांसफर की तो मैं आज सदन में घोषणा करता हूं कि पूरे के पूरे जो 10 प्रबंधक हैं जो 5, 8, 10 सालों से हैं उन सभी लोगों को उनके मूल विभाग में हम वापस करने जा रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा गोदामों में जो बातचीत आ रही है कि गाड़ियां खड़ी रहती हैं वह पहुंचती नहीं हैं तो उसके लिये हम फास्टट्रेक की अनिवार्यता कर रहे हैं ताकि उसकी जी.पी.एस. मॉनिटरिंग हो सके । कोई भी गाड़ीवाला एक भी इधर से उधर न जाये और खड़ा रहेगा तो जी.पी.एस. में हमको दिखता रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तीसरा सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं कि आपूर्तिकर्ता फर्म को अर्थात् उसमें साफ्टवेयर कर रहे हैं। अगर किसी की गाड़ी खड़ी होती है तो आपूर्तिकर्ता साफ्टवेयर में ऑनलाईन वह शिकायत रजिस्टर कर सकता है जिसको मैं भी देखूंगा और मेरे विभाग के अधिकारी भी देखेंगे । गोदाम से जो दवा स्वास्थ्य केंद्रों तक जाती है उसमें अनिवार्य रूप से जी.पी.एस. कर रहे हैं । सभी गोदामों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरा अनिवार्य कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा । ठीक ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा और जो भी पॉयलेट प्रोजेक्ट पर जो दवाईयां एक्पायर होने की स्थिति में हैं उसको जिस प्रकार से फीफो First Expiry First Out (FEFO) होता है इस पद्धति पर हम उसको बाहर भी करेंगे तो इस प्रकार से जो और भी माननीय सदस्य ने कहा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपने बहुत अच्छा कर दिया । मुझे लगता है कि इसके बाद कोई प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न है न ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी सारी शंका का समाधान...।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय :- इतनी कठोर कार्यवाही किये हैं । यदि कोई प्रश्न हो, चलिये एक छोटा प्रश्न कर लीजिये ।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि आज जो दवाई हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजी गयी है उसके लिये डॉक्टर नहीं है । क्या आप वहां डॉक्टर, लैब टेक्निशियनों की भर्ती करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, डॉक्टर का बता दीजिये भई । हो गया । क्या डॉक्टर भर्ती करेंगे ?

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, दूसरा । जो सामान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजे गये हैं उसके लिये फ्रीज भी नहीं है । उसका टेस्ट करने वाली जो मशीन है उसमें उस लैब के माध्यम से मरीज का टेस्ट होना है उस अस्पताल में वह मशीन नहीं है, क्या उसको क्रय किया जाना है ? चूंकि हमारी तमाम् गरीब जनता इसका उपयोग करेगी । क्या वहां डॉक्टर की भर्ती की जायेगी और लैब मशीन, फ्रीज यह सामग्री क्या हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपके माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वे धीरे-धीरे करेंगे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लगभग 600 से ऊपर फ्रीज खरीदने ही जा रहे हैं । उसको भी करने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- धीरे-धीरे करते जाईये । ठीक है । आप पूछ लीजिये ।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- छोटा प्रश्न करना।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- डॉक्टर भी उपलब्ध होने पर हम भेजते जा रहे हैं..।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा और सवाल है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका हो गया। आपका पूरा हो गया है। चलिए, आप पूछ लीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इसी सदन में 16 फरवरी को श्री राजेश अग्रवाल सदस्य जी द्वारा एक प्रश्न पूछा गया और दवा वितरण में नहीं, दवा खरीदी में भी व्यापक भ्रष्टाचार है और पूर्ववर्ती सरकार के 5 सालों में सी.जी.एम.एस.सी. भ्रष्टाचार का गढ़ था, ये इनके जवाब में सिद्ध होता है। स्वास्थ्य विभाग की 5 एजेंसियां हैं, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस

कार्पोरेशन लिमिटेड, राज्य मानसिक चिकित्सालय बिलासपुर, सिविल सर्जन, रायगढ़, सिविल सर्जन जगदलपुर और सिविल सर्जन, सरगुजा एक दवाई का नाम है..।

अध्यक्ष महोदय :- आप अलग से सूचना दें, क्योंकि यह ध्यानाकर्षण के संदर्भ से बिल्कुल उल्टा है।

श्री सुशांत शुक्ला :- यह दवाई के संदर्भ में ही है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, खरीदी अलग चीज है और वितरण अलग चीज है। राजेश जी, चलिए आपको पूछना है? इसी से संदर्भित मैं दूंगा।

श्री राजेश अग्रवाल (अंबिकापुर) :- महोदय जी, मेरा प्रश्न नहीं आ पाया था तो मैंने ध्यानाकर्षण लगाया है। खरीदी में बहुत ज्यादा अनियमितता हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- इस खरीदी में?

श्री राजेश अग्रवाल :- जी। बहुत ज्यादा अनियमितता हुई है और बहुत सी दवाइयां ऐसी खरीदी गई हैं..।

अध्यक्ष महोदय :- हां तो पूछ लीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- राजेश भैया, मैं पूछता हूं। मैं राजेश जी का ही बढ़ा रहा था। रि-एजेंट करके एक दवाई है, जो राज्य मानसिक चिकित्सालय..।

अध्यक्ष महोदय :- दो मिलकर एक प्रश्न नहीं कर सकते। या तो ये कर लें या तो फिर आप कर लें। आप बैठिए। ये सक्षम विधायक हैं। यदि ये प्रश्न नहीं कर पायेंगे तो मैं अवसर दूंगा। आप प्रश्न करिए। दोनों का अलग-अलग है। आप मिला नहीं सकते। कागज नहीं है तो उन्हीं को पूछने दीजिए।

श्री राजेश अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न लगाया था। रेज 197 ई.डी.टी.ए. टू एडल्ट एक ही कंपनी के द्वारा 2352 रूपये रेट दिया गया। दूसरी कंपनी का रेट है 8 रूपया 40 पैसा।

अध्यक्ष महोदय :- इतना बारीक प्रश्न तो मुश्किल पड़ेगा।

श्री राजेश अग्रवाल :- और 2352 रूपये वाले से करोड़ों रूपये की खरीदी की गई है।

अध्यक्ष महोदय :- आप जांच कराने के लिए लिखकर दे दीजिए। बहुत स्पेशिफिक प्रश्न है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, आपत्ति कर रहा हूं। आप बुरा मत मानिएगा। निवेदन है कि समय दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, स्पेशिफिक प्रश्न है।

श्री सुशांत शुक्ला :- यह बहुत बड़ी खरीदी है और पिछले 5 साल में एक ही कंपनी को हजारों करोड़ के काम दिये गये हैं। आपके माध्यम से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी, क्या इसमें जांच कराते हुए छत्तीसगढ़ में न्याय करेंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- क्या मंत्री जी इसे भी देखेंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि मैं तो समाचार-पत्रों को संज्ञान में लेकर जांच करा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बाकी आप लोग भी जानकारी दे दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- निश्चित रूप में हमारा ऑलरेडी जांच चल रहा है..।

अध्यक्ष महोदय :- प्रबोध मिंज जी, अपना ध्यानकर्षण पढिए। आपने पर्याप्त जवाब दिया। आपने अच्छा जवाब दिया है। प्रबोध मिंज जी।

(2) जिला-सरगुजा, थाना-लखनपुर में मेसर्स स्टार लाईट ग्रीड 36 लिमिटेड द्वारा एनर्जी स्टोरेज की स्थापना हेतु सर्वेक्षण कार्य बंद नहीं किया जाना।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

मेसर्स स्टारलाईट ग्रीड 36 लिमिटेड द्वारा 1200 मेगावाट क्षमता के पम्प्ड हाइड्रोस्टोरेज (एनर्जी स्टोरेज) की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ शासन के साथ दिनांक 04.10.2023 को एम.ओ.यू. का निष्पादन किया गया है, जिसके कारण पुलिस सुरक्षा एवं वन कर्मियों के साथ थाना लखनपुर, जिला सरगुजा के गांव डाडकेसरा, जामा, डोढाकेसरा एवं अरगोती के गांवों एवं जंगलों में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना ध्यानाकर्षण तो पढ़ दीजिए। पहले पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ दीजिए। बाद में प्रश्न उठेगा।

श्री प्रबोध मिंज :- सर, ध्यानाकर्षण की पढ़ रहा हूं। इन सर्वेक्षणों की वजह से पूरे क्षेत्र में भय एवं आतंक का माहौल है एवं लोगों को किसी अनहोनी की आशंका है। ग्रामवासी भयभीत होकर बैठकें कर रहे हैं। लोगों को इस संबंध में एम.ओ.यू. की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। लोगों में शांति व्यवस्था हेतु कार्य को तत्काल बंद भी नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रावासियों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कथन सही है कि मेसर्स स्टार लाईट ग्रीड 36 लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 1200 मेगावाट/2080 एम.यू. क्षमता का पम्पड हाइड्रोस्टोरेज (एनर्जी स्टोरेज) की स्थापना हेतु शासन के साथ दिनांक 04.10.2023 को एम.ओ.यू. का निष्पादन किया गया है।

तथ्य यह है कि सरगुजा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र लखनुपर एवं मैनपाट अंतर्गत स्टार लाईट ग्रीड 36 लिमिटेड, हरियाणा द्वारा 1200 मेगावाट/2080 एम.यू. पम्पड स्टोरेज निर्माण कार्य के गैर वानिकी उपयोग हेतु लगभग 1800 हे. संरक्षित वन भूमि में वन संरक्षण अधियिम 1980 अंतर्गत वनक्षेत्रों में टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कार्य करने की अनुमति हेतु स्टार लाईट ग्रीड 36 लिमिटेड, हरियाणा द्वारा दिनांक 02.02.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । मुख्य वन संरक्षण, सरगुजा वृत्त

अंबिकापुर के पत्र क्रमांक/765, दिनांक 06.02.2024 द्वारा वन परिक्षेत्र लखनुपर एवं मैनपाट के कुल 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य की अनुमति शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है, जिसके आधार पर सर्वेक्षण कार्य के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

जनपद पंचायत लखनपुर के तिरकेला, अरगोती, ढोढाकेसरा, लब्जी, डाडकेसरा में स्टर लाईट ग्रीड 36 लिमिटेड द्वारा 1200 मेगावाट क्षमता का पम्पड (एनर्जी स्टोरेज) की स्थापना के विरोध में उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच एवं जनपद सदस्य के साथ-साथ ग्रामवासियों के द्वारा संयुक्त रूप से आदेवन दिनांक 19.02.2024 को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2999/खनिज/2024 अंबिकापुर, दिनांक 21.02.2024 के द्वारा पुलिस विभाग, वन विभाग अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उदयपुर एवं मेसर्स स्टार लाईट को 1200 मेगावाट क्षमता का पम्पड (एनर्जी स्टोरेज) की स्थापना से संबंधित कोई भी कार्य, इस कार्यालय के आगामी आदेश तक सम्पादित नहीं किए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं । अत: यह कहना उचित नहीं है कि पूरे क्षेत्र में डर, भय एवं आतंक का माहौल है एवं किसी अनहोनी की आशंका है, ग्रामवासी भयभीत होकर बैठकें कर रहे हैं, बल्कि वर्तमान में संबंधित क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था पूर्णत: सामान्य है एवं क्षेत्र में पूर्णत: शांति का माहौल निर्मित है ।

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आया है । उन्होंने कहा है कि वहां शांति व्यवस्था है, भय का वातावरण नहीं है । मैं आपके माध्यम से यह जानना भी चाहूंगा और बताना भी चहूंगा कि आपने जवाब में टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण की अनुमति की बात कही है और टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण कैसा होता है, शायद आप बता पाएंगे । इन नक्शों को देखकर जो टोपोग्राफिकल एरिया बनता है, उसके हिसाब से उसमें सर्वेक्षण का काम किया जाता है कि कहां-कहां हाईएस्ट प्वाइंट है, कहां लोवेस्ट प्वाइंट है । उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से काम होता है और टोपोग्राफ के नक्शों में देखकर उसको किया जाता है । यहां सर्वेक्षण करने की बात तो स्वीकार कर रहे हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि ऐसा भय का वातावरण नहीं है तो आपने जवाब दिया है कि 19.02.2024 को सरपंचों ने, उप सरपंचों ने, जनपद सदस्यों ने और सारे ग्रामवासी कलेक्टर और वन विभाग को आवेदन दिया है। यदि उनमें भय नहीं है तो वे क्यों आवेदन दे रहे हैं ? दूसरी बात यह है कि पुलिस और वन विभाग ने इस कंपनी के सहयोग के लिए, उनके साथ पूरे क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम घूम घूमकर किया जा रहा है । टेप लेकर, चेन लेकर नापी की जा रही है और पुलिस संरक्षण में चल रहे सर्वेक्षण के चलते लोग डरे हुए हैं । बगल में अडाणी का इतना बड़ा कोल माइन्स है, जिसके चलते लोग भयभीत हैं । बतौली में चिरगा का प्लांट है, जिसके चलते 8-10 गांव के लोग लगातार आतंक के माहौल में उसको बनने नहीं दे रहे हैं । वहां इस प्रकार की भ्रांतियों के चलते वातावरण बन रहा है और दूसरी बात यह है कि यह एमओयू 04.10.2023 का है यानी ठीक चुनाव के तत्काल पहले और आचार संहिता लगने के समय का विषय

है । इतने आनन-फानन में चुनाव हुए और उसे तत्काल बाद जाकर सर्वेक्षण कर दिया जा रहा है और हमको पता भी नहीं है, विधायक तक को जानकारी नहीं है वह लोगों को क्या जवाब देगा ? मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- बताओ मत, पूछो ।

श्री प्रबोध मिंज :- अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस विभाग की चिट्ठी है । इसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि सर्वेक्षण के लिए लिखा गया है और उस परिप्रेक्ष्य में उस सर्वेक्षण कार्य के दौरान अपने अपने थाना क्षेत्र में मेसर्स कंपनी को नियमानुसार वैधानिक सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें । वन विभाग भी अपने अमले को लिख रहा है कि सर्वेक्षण कार्य के समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उपस्थित रहते एवं प्रस्तावित वन भूमि का कक्ष इतिहास अद्यतन करते हुए संदर्भित पत्र के उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए सुनिश्चित करें। क्षेत्र में लोग पूरी टीम के साथ सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपने बहुत सारा प्रश्न कर लिया। जवाब दे दीजिएगा। आपका प्रश्न ठीक है।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कंपनी के साथ एम.ओ.यू. हुआ है, वह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हुआ है। उनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। अगर उपयुक्त नहीं होगा तो कैंसल कर दिया जाएगा, वैसे भी पुलिस के माध्यम से संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। जब कलेक्टर से शिकायत हुई तो अभी संरक्षण के कार्य में रोक लगा दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय :- कार्य पर रोक लगा दी गयी है।

श्री लखन लाल देवांगन :- जी कार्य पर रोक लगा दी गयी है।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि यदि बंद हो गये हैं तो क्या बिना अनुमति के बिना जानकारी के आगे सर्वेक्षण कार्य होंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, वहां जो भी काम होगा, पूरे ग्रामवासियों को विश्वास में लेकर किया जाएगा। माननीय विधायक जी को भी विश्वास में लेकर किया जाएगा। पूरा काम उनके साथ होगा।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा। विधायक को विश्वास में लेकर काम करेंगे। धन्यवाद।

समय :
12:41

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. सुश्री लता उसेंडी
2. श्री बघेल लखेश्वर

समय :

12:41

वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या	**1**	**सामान्य प्रशासन**
मांग संख्या	**2**	**सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय**
मांग संख्या	**7**	**वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**12**	**ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**14**	**पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**16**	**मछली पालन**
मांग संख्या	**25**	**खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**32**	**जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**35**	**पुनर्वास**
मांग संख्या	**36**	**परिवहन**
मांग संख्या	**56**	**ग्रामोद्योग**
मांग संख्या	**60**	**जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**65**	**विमानन विभाग**
मांग संख्या	**71**	**इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग**

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 1 सामान्य प्रशासन के लिये - चार सौ पचहत्तर करोड़, उनचालीस लाख, इक्यासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये - चौहत्तर करोड़, अठारह लाख, उनतीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 7 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिये - चार सौ बत्तीस करोड़, तीन लाख, चवालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिये - तीन हजार नौ सौ नब्बे करोड़, छप्पन लाख, नवासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - पांच सौ तेरह करोड़, एक लाख, अठावन हजार रूपये,

मांग संख्या - 16 मछली पालन के लिय - एक सौ छः करोड़, उन्नीस लाख, उनचास हजार रूपये,

मांग संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये - एक हजार तीन सौ चालीस करोड़, बांसठ लाख, तिहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 32 जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये - चार सौ तिरालीस करोड़, सतासी लाख, बीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 35 पुनर्वास के लिये- दो करोड़, पचहत्तर लाख, चालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 36 परिवहन के लिये - एक सौ इक्यावन करोड़, आठ लाख, बीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 56 ग्रामोद्योग के लिये - दो सौ सत्रह करोड़, इकतीस लाख, चौहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिये - दो सौ आठ करोड़, तिरपन लाख रूपये,

मांग संख्या - 65 विमानन विभाग के लिये - दो सौ करोड़, अड़तालीस लाख, छत्तीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये - दो सौ पैसठ करोड़, पचहत्तर लाख, पन्चानवे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या- 1

सामान्य प्रशासन

1.	डॉ. चरण दास महंत	5
2.	श्रीमती अनिला भेंडिया	1
3.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
4.	श्रीमती शेषराज हरवंश	3
5.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1

मांग संख्या- 7

वाणिज्य कर विभाग से संबंधित व्यय

1.	डॉ. चरण दास महंत	3
2.	श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा	1

3.	श्री कुंवर सिंह निषाद	2
4.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
5.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1

मांग संख्या - 12

ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

1.	डॉ. चरण दास महंत	3
2.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
3.	श्रीमती शेषराज हरवंश	2
4.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	2

मांग संख्या - 14

पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

1.	डॉ. चरण दास महंत	1
2.	श्रीमती अनिला भेंडिया	1
3.	श्री कुंवर सिंह निषाद	2
4.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1

मांग संख्या - 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

1.	डॉ. चरण दास महंत	3
2.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
3.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1
4.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1

मांग संख्या - 32

जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय

1.	डॉ. चरण दास महंत	1
2.	श्री भूपेश बघेल	1
3.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या – 35

पुनर्वास

1.	श्रीमती अनिला भेंडिया	2

मांग संख्या - 36

परिवहन

1.	डॉ. चरण दास महंत	4
2.	श्रीमती अनिला भेंडिया	1
3.	श्री कुंवर सिंह निषाद	3
4.	श्रीमती शेषराज हरवंश	2
5.	श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह	1

मांग संख्या - 56

ग्रामोद्योग

1.	डॉ. चरण दास महंत	1
2.	श्री भूपेश बघेल	1
3.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1
4.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1

मांग संख्या - 65

विमानन विभाग

1.	डॉ. चरण दास महंत	1
2.	श्रीमती शेषराज हरवंश	1

मांग संख्या - 71

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

1.	डॉ. चरण दास महंत	3
2.	श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा	1
3.	श्री कुंवर सिंह निषाद	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री कुंवर सिंह निषाद।

समय :

12.47 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या - 1, 2, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 56, 60, 65, 71 की अनुदान मांगों के विरोध में बोलेने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, सरकार बनने के बाद सत्ता पक्ष के साथियों और मंत्रियों के द्वारा पूर्ववर्ती सरकार ने क्या-क्या किया और उनकी योजनाओं पर लगातार प्रहार किया गया। सबसे पहले तो आपको अपने विजन पर फोकस करना चाहिए। आप किस उद्देश्य को लेकर यहां पर सरकार में बैठे हैं और आपका विजन क्या है, इस पर बातें होनी चाहिए। ठीक है कि आप सत्ता में हैं और हम विपक्ष में हैं। बातें आती और जाती हैं और टकरार होती है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, नीयत साफ होनी चाहिए। क्योंकि जनता ने आपको जनादेश दिया है और जनतंत्र और लोकतंत्र के हिसाब से आपने पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मैं स्वयं उस समाज से आता हूं, जिसका प्रमुख व्यवसाय मछली पालन है। हमारी पूर्व की सरकार ने मछली पालन को कृषि का दर्जा देकर मछली पालन से जुड़े व्यवसायों को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाने का ओर प्रयास किया था। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-2023 में catch Assessment Survey योजना की शुरूआत भी हुई थी। वर्ष 2019 से राज्य में कृषि एवं उस पर आधारित व्यवसाय मछलीपालन, पशुपालन आदि को परंपरागत तरीके से करने हेतु शासन द्वारा महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी चलायी गयी थी। जिसपर हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत अलग सी बातें कहीं। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिससे गौठानों के परिवर्तन में स्थित तालाबों में गौठान के ताजे गोबर का उपयोग कर हम तालाबों में प्राकृतिक मत्स्य आहार के माध्यम से विकसित कर रहे थे, इससे मछली के उत्पादन में वृद्धि आई है क्योंकि हम लोग उस छोटे से तालाब जिनके पास बड़े-बड़े डैम हो तो अलग बात है, लेकिन छोटे-छोटे तालाब में गोबर और अन्य चीजों को डालकर मछली के उत्पादन को बढ़ाने का कार्य हम लोग कर रहे थे । पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा मछली पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने पर निश्चित ही राज्य के मछली पालन किसान चाहे वह छोटे हों या बड़े हों, उन्हें सुलभ ऋण एवं नगद प्राप्त करने के लिए दिसम्बर 2023 तक लगभग 3285 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे । मछली पालन कम लागत में अधिक आय, यह सहायक व्यवसाय के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यंत

लोकप्रिय हुई । यह ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी माध्यम है । यदि जिनके पास पर्याप्त जमीन है और खेती के साथ-साथ अन्य चीजें करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि मछली पालन का व्यवसाय उनके लिए बहुत बढ़िया साधन है । आप साल भर में खेती से जितना कमा लेते हैं, उससे दोगुना या तिगुना आय आप मछली पालन से अर्जित कर सकते हैं । मछली पालन से एक अच्छा लाभ कमाया जा सकता है । वैसे भी मछली में पौष्टिक ज्यादा होती है क्योंकि वह तालाब से निकाले हुए ताजा मछली होते हैं । हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे डेम हैं, जलाशय हैं, नदी-नाले हैं, लीज़ पर दिए जाने वाले तालाब हैं और बहुत से निजी तालाब हैं । पहले हमारे छत्तीसगढ़ में मछली के बीज का उत्पादन उतने ज्यादा मात्रा में नहीं होते थे तो हमें कोलकाता से या अन्य राज्यों से बीज मंगाना पड़ता था, लेकिन इस बार और पिछले समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी चाहे वह छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, शासकीय हेचरीज के माध्यम से मछली बीज की आपूर्ति लगातार की जा रही है । उसके बाद इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ से बाहर बीज निर्यात किये जा रहे हैं । यह निश्चित ही मछली पालन के उद्योग को लेकर छत्तीसगढ़ में एक नई क्रांति आई है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इस व्यवसाय के लिए मछली पालन विभाग में केन्द्र के अतिरिक्त राज्य मद से अधिक राशि का प्रावधान किया जाये, ताकि जो इस व्यवसाय से जुड़े कृषक हैं, वे इनमें लगातार प्रोत्साहित होते रहे और इस व्यवसाय को बढ़ाने का काम करें । बहुत से ऐसे कृषक हैं, जिनके पास छोटी जमीन है, हम लोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक क्राईटेरिया तय करते हैं कि यदि जिनके पास आधा एकड़ या एक एकड़ जमीन है, वह छोटी डबरी या छोटी जलाशय बनाकर भी इसमें मछली पालन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक बढ़िया सा मार्गदर्शन इस विभाग के माध्यम से होना चाहिए, ताकि वे छोटे-छोटे व्यक्ति जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी लाभ मिल सके । पिछली सरकार ने बजट में 360 करोड़, 54 लाख, 55 हजार रूपए का प्रावधान किया था, उसमें से लगभग दिसम्बर, 2023 तक 131 करोड़, 21 लाख, 5 हजार रूपए खर्च हुए हैं। बाकी इसलिए खर्च नहीं हो पाये क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लगा, फिर विधान सभा के चुनाव हुए । लेकिन वर्तमान बजट में केवल 239 करोड़, 01 लाख, 23 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है, जो हमारे शासन की तुलना में 112 करोड़ से कम है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज यदि हम खेती को बढ़ावा दे रहे हैं । आप कृषि में फसलचक्र परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, इसमें अब केवल मछुवारा परिवार ही नहीं, अन्य लोग भी इस ओर आकर्षित हुए हैं और इस व्यवसाय को बढ़ाकर राजस्व अर्जित करने के साथ-साथ बाहर राज्यों को बीज निर्यात में अब छत्तीसगढ़ एक समृद्धशाली राज्य बनने की ओर अग्रसर है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम नदी-नाले, पोखर में बीज डालते हैं, लेकिन एक पर्टिक्यूलर क्षेत्र होने के कारण यदि उस क्षेत्र के मछुवारे दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहां उन पर बंदिश लगाया जाता है। नदी-

नाले पर सब का अधिकार होता है। तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस पर किसी प्रकार का कोई बंदिश ना हो। सभी जगह पर मछुवारों को मछली मारने का अधिकार हो।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने बोनस का प्रावधान किया था। जो ज्यादा हैक्टेयर के जलाशय हैं, उसे नीलामी के माध्यम से देने की बात की गई थी। हमने विरोध दर्ज कराया था तब मछली नीति में संशोधन की बात की गई थी। मछली नीति में संशोधन हुआ। उसके बाद थोडी-बहुत कुछ और बातें रह गई थीं, तो अधिकारियों से बैठक कर, माननीय विभागीय मंत्री से चर्चा कर उसकी विसंगति को दूर करने की बात कही थी। हमने उसके बाद मछली नीति को लागू किया था। हमारे विद्वान साथी बड़े भैय्या अजय चन्द्राकर जी के माध्यम से इसमें जरूर बहुत सी बातें की गईं। अब आपकी सरकार है, यदि लगता है कि इसमें कुछ विसंगति है या कुछ सुधार किया जा सकता है, तो जरूर करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय निषाद जी, मैंने मछली नीति में वीडियो वायरल किया था। आपकी सरकार में आपने मछली नीति की विसंगतियों से सहमत थे या नहीं थे, यह बताईये ? आप सहमत थे या नहीं ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, आपकी अपनी सोच है और मेरी अपनी सोच है। सबसे पहली बात सरकार जो कभी नहीं कर पाई थी, पिछली सरकार ने उस मछली पालन को कृषि का दर्जा देकर छोटे से लेकर बड़े कृषकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया था, उसे फिर लगातार बढ़ाने का काम करना जरूरी है, उसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

सभापति महोदय, किसी चींज पर सबकी अपनी-अपनी सोच और नजरिया होता है कि हम कैसे करें, क्या करें, सबका दृष्टिकोण होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कुछ कुछ जगह विसंगति है, यह बात तो आई है। पूर्व में जिनका सोसायटी चल रहा है, जिनका पंजीयन हुआ है, उसके आधार पर आज भी उन्हीं लोगों को वह पट्टे दिए जा रहे हैं, तालाब और जलाशय दिए जा रहे हैं। लेकिन अब उस जल क्षेत्र की जगह बहुत से ऐसे मछुवारे परिवार हैं, जो निवासरत हैं, वहीं बस गये हैं। लेकिन पूर्व में पंजीकृत सोसायटी को प्राथमिकता दिए जाने के कारण उन परिवारों को आज भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि उन क्षेत्रों में पंजीकृत समिति में पुन: उन परिवारों को जोड़कर उसे लाभ दिलाने का प्रयास किया जाये ताकि उन परिवारों को भी उसका लाभ मिल सकें और उनका परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, बहुत से ऐसे संसाधन, उपकरण और सामान होते हैं, जो विभाग से द्वारा जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस विभाग के लिए जो बजट का प्रावधान किया है, उसमें और राशि बढ़ाई जाये। ताकि छोटे-छोटे जो मत्स्य कृषक हैं, जिन्हें आइस बाक्स देते हैं, सायकल देते हैं, जाल देते हैं, मोटर सायकल देते हैं, फोर व्हीलर देते हैं, मछली का बीज देते हैं, मछली का चारा देते हैं, आपने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए जो बजट का प्रावधान किया है, उतने बजट में बिलकुल

संभव नहीं है कि हम लोग इन किसानों या कृषकों को दे पाये। उन्नत कृषक के रूप में जो पुरस्कार मछुवारों को दिया जाता है , उसमें बड़े-बड़े व्यवसायी ही लाभान्वित हो पाते हैं । मैं चाहूंगा कि छोटे कृषकों को भी इस योजना के माध्यम से शामिल किया जाये, तभी उन्हें प्रोत्साहन भी मिलेगा और इसके प्रति उनकी सोच भी आयेगी और भावनात्मक बातें भी आयेंगी । सभापति महोदय, बड़े लोग तो हैं, उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं, वह कर लेते हैं, उत्पादन को बढ़ाने की बात हो या मछली बेचने में हो या अन्य चीजों में हो, लेकिन यदि हम छोटे कृषकों को, जिनके पास दो एकड़, तीन एकड़, चार एकड़, पांच एकड़ के तालाब हैं या जलाश हैं, उनके ऊपर यदि हमारी भावना अच्छी हो और उसको बढ़ाने का विभागीय स्तर पर कोई प्रयास हो तो निश्चित रूप से हम उन्हें योजना में शामिल कर लाभ दे सकते हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मछली कृषकों को जो आवास मिलता है, उस पर भी एक विचार होना चाहिये । आज हजारों परिवार ऐसे हैं, जहां 8-10 सदस्य हैं, मछुआ आवास के प्रति भी शासन की योजनायें विस्तृत रूप में होना चाहिये, बजट में भी बढ़ोतरी आवश्यक है, ताकि मछुआरों के परिवार को भी आवास का लाभ मिल सके । कई परिवार ऐसे हैं, जो तालाब में ही झोपड़ी बनाकर रह लेते हैं और जीवन उसकी वहीं पर खप जाती है, ऐसे मछुआरों को क्रियान्वयन के रूप में अतिरिक्त बजट दे सकते हैं तो उन परिवारों को भी लाभ मिल सकता है । माननीय सभापति महोदय, बड़े कृषक के लिये बड़े-बड़ें बांधों में कैचमेंट के माध्यम से मछली पालन के लिये नियम बनाये गये हैं, लेकिन छोटे किसानों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक के कैच कल्चर के रूप में व्यवसाय कर सकें, उन्हें समूह के माध्यम से प्राथमिकता मिले और सोसायटी के माध्यम से उसये बढ़ावा मिले, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम यह निवेदन करना चाहता हूँ । माननीय सभापति महोदय, हमारे विद्वान साथी के द्वारा लगातार गौठान में गोबर खरीदी को लेकर और गौमुत्र को लेकर सवाल किये जा रहे हैं, क्या यह नहीं चाहते हैं कि यहां के गौपालक या पशुपालक आर्थिक रूप से समृद्ध हो या मजबूत ? माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा गौठान के माध्यम से ग्रामों में कार्य करने वाले स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को एवं गौठान समिति को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया गया है । सभापति महोदय, चरवाहे से लेकर पशुपालक समूह की महिलायें एवं गौठान समिति आर्थिक रूप से मजबूत हो । विगत चार माह से गोबर खरीदी बंद होने से यह सभी कार्य लगभग बंद हो चुके हैं । माननीय सभापति महोदय, जब कोई सरकार योजना लाती है तो जनहित के उद्येश्यों को लेकर कार्ययोजना बनाती है, उसमें कुछ कमी हो तो उसमें सुधार कर पुन: उसे लागू करने की जरूरत होनी चाहिये । गौठान के माध्यम से हमने लाखों एकड़ जमीन जो अवैध कब्जे के रूप में लोग अपने पास रखे थे, उसे संरक्षित करने का काम पूर्व की सरकार ने किया है, जिसमें बहुत से रोजगारमूलक कार्य हो रहे थे और किये जा सकते हैं । गौठान के माध्यम से बहुत से कार्य जो पूर्व में संचालित हो रहे थे, वर्मी

कम्पोस्ड बनाने का काम, गौमूत्र से अर्क बनाने का काम, गोबर से पेंट बनाने का काम, साथ ही बाड़ी विकास के माध्यम से साग-सब्जी, गन्ना, पपीता एवं केला की सब्जी उत्पादन करने का काम हो रहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, 05 सालों में बाड़ी विकास में कौन से मद का कितना पैसा व्यय किया गया ? आप कह रहे हैं कि बाड़ी विकास हो रहा था तो बताईये कि बाड़ी विकास के लिये क्या योजनाएं बनी थीं और इसमें क्या विकास किया गया ? आप इसमें थोड़ा प्रकाश डालिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, आपको मदवार जानकारी मिल जायेगी लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा में।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, जिस योजना में कुछ नहीं हुआ है, आप उसमें जबर्दस्ती प्रशंसा क्यों करते हैं ? छत्तीसगढ़ राज्य तोर विधान सभा हे ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं दो-तीन उदाहरण दे रहा हूं, बाकी सरकार आपको पूरे प्रदेश की जानकारी परिशिष्ट के माध्यम से दे देगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, पूरे विधान सभा में सिर्फ दो-तीन ठन बाड़ी हे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- चल मे हर तेला दिखा दुहू कि कतका ठन बाड़ी कहां-कहां हे ? में हर आप ला 234 गांव में बाड़ी ला दिखा दुहू।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, सभी जगहों परा बाड़ी हैं। जब हम खैरागढ़ उप चुनाव में गये थे तो वहां भी बाड़ी है और लोग इसमें प्रोत्साहित हुए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- ते हर बाड़ी के विकास बर कै पैसा दे हस अउ का योजना बनाये हस, तेला बता ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- विकास होये हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- का होये हे तेला बता ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- में हर बतात हव। विकास ही बतात हव।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, चाहे गन्ना की खेती हो, चाहे केला की खेती हो या पपीता की खेती हो। खासकर मैं अपने विधान सभा की बात बता देना चाहूंगा कि गन्ना की खेती के ऊपर भी।

श्री अजय चन्द्राकर :- गन्ना भी बाडी में आथे ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, हमने अपनी जमीन संरक्षित की थी।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप अपनी बातें करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं अपनी बातें ही कह रहा हूं।

सभापति महोदय :- मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि काफी वक्ता हैं। कृपया सहयोग करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह विधान सभा है और यहां माननीय सदस्य जो भी कथन करें, वह सत्य करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं सत्य ही कह रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब यह बाड़ी का उदाहरण दूंगा कहते हैं और उदाहरण गन्ने का देते हैं। यही तो हाल है। अब आप कहेंगे कि इसको सुनते रहिये, तो हम कैसे सुनेंगे ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें पपीता भी लगाये हैं, केला भी लगाये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, पपीता और केला सब उद्यानिकी फसल में आता है, बाड़ी में नहीं आता।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, बाड़ी विकास योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग के संचालित है। मैं गौठान की बात कर रहा हूं कि हम लोग गौठान के माध्यम से जितनी भी योजनाएं संचालित कर रहे थे।

श्री रामकुमार यादव :- निषाद जी, ते जा तो एला गौठान के करमत्ता भाजी ला खवाबे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी लाहू। वहां कांदा भाजी घलोक हे।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आप जारी रखिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, जी। साथ ही उस गौठान योजना में हमने पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन और बटेर पालन का भी कार्य संचालित किया था। लेकिन अभी चार महीने से सरकार की तरफ से उनको जारी रखने का कोई भी आदेश नहीं आया है, जिसके कारण गौठान के सारे कार्य बंद है। आज समूह की लाखों महिलाएं बेरोजगारी का दंश झेल रही है, जिनके पास गौठान के माध्यम से कुछ पैसे आते थे, जिससे उनके परिवार का संचालन होता था। लेकिन योजनाएं बंद होने से, कार्य बंद होने से वह लगभग बेरोजगार बैठी हुई हैं। इस सरकार की तरफ से उनके लिये भी एक कार्ययोजना बननी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इसे पुन: प्रारंभ कर लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास किया जाये। केवल गोबर और गौठान कहकर विरोध करने से कुछ नहीं होगा। यदि आज हम जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो उसमें निश्चित ही हमारे वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट खाद है, हम लोग उसके माध्यम से एक बदलाव चाह रहे थे। पहले जब इतनी उन्नत कृषि और खेती नहीं होती थी तो लोग एक घुरवा बनाकर घर की चीजों को उस घुरवा में डालते थे और जब खेती-किसानी का समय आता था तो एक महीना पहले गाड़ा बैल से सुबह-सुबह उस खाद को खेत में ले जाकर डालते थे और जब बोआई का समय होता था तो एक सप्ताह पहले उसी गोबर खाद के माध्यम से खेती की जाती थी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और अन्य एक भी मंत्री उपस्थित नहीं हैं। एक मंत्री जी बैठे हैं और वह भी सो रहे हैं।

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- सभापति महोदय, मैं नहीं सो रहा हूं।

सभापति महोदय :- यहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनके अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, वह सोये नइ हे, वह प्रदेश की चिंता करत हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, यहां एक भी मंत्री उपस्थित नहीं हैं। उसके साथ ही सदस्य भी अनुपस्थित हैं। यह पहली बार हुआ है, आज तक मुख्यमंत्री जी के विभाग पर जब चर्चा चलती है तो सभी मंत्री एवं सदस्य विराजमान रहते हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पुन: उस योजना को शासन स्तर पर संचालित करने की जरूरत है क्योंकि आज केमिकल से बोआई हो रही है। चाहे वह सब्जी हो, चाहे फसल हो या जो भी उत्पाद हो, जो हम खा रहे हैं, उससे कम उम्र में ही लोग व्याधि के शिकार हो रहे हैं। लगातर ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक और कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं। हमें पुन: जैविक खेती की ओर अग्रसर होना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि एक बार पुन: इस गौठान के कार्य को संज्ञान में लेते हुए चालू करने की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि उसमें कुछ सुधार होना चाहिए तो आपकी सरकार है, आप उसमें जरूर अपने हिसाब से संशोधन करिये। हजारों, लाखों परिवार जो इनके माध्यम से अपना परिवार चला रहे थे यदि उन्हें आपने बेरोजगार कर दिया है तो उनके बारे में एक बार सकारात्मक सोचने की जरूरत है। वह लाखों परिवार जो समूह से जुड़कर, गौठान के माध्यम से रोजगार मूलक काम कर रहे थे, लेकिन वह आज बेरोजगार बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पुन: उस योजना को संचालित कर, उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास करें। विगत कई वर्षों से ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको कौन-कौन सी योजना को पुन: संचालित करना है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- में माननीय मुख्यमंत्री जी ला लिस्ट दूंहू, लेकिन निवेदन तो करे ला लगही।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे सरकार बदल गे हे हम हमर योजना बनाबो या तोर योजना ला चालू करबो। ते कार दिन में सपना देखत हस।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, में कहात हौं, में आपसे निवेदन करना चाहत हौं अउ माननीय हमर विद्वान अजय भईया जे बात करिस ओ जरूर मन में का बात हे, लेकिन विचार में अलग हे। में हा जानत हौं। छत्तीसगढ़िया आदमी कभी भी नइ सोच सके कि काखरो अहित हो। गौठान के माध्यम से ओखरो भी भावना जुडे हे कि जेन लाखों व्यक्ति ला काम मिलत रहिस हे, ओ काम मिले।

श्री अजय चन्द्राकर :- ओ मे एक झन ला काम नइ मिले हे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अजय भईया, ओ मे लाखों व्यक्ति ला काम मिलत रिहिस हे। ओ आपके सोच का हे तेला आप जानव, लेकिन पूरा प्रदेश में चाहे ओ गौठान समिति हो, चाहे समूह के मन हो ओ मन रोजगार मूलक काम करके, अपन परिवार ला संचालित करत रिहिस हे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यहां पशु चिकित्सा विभाग में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो सालों से चतुर्थ वर्ग के रूप में काम कर रहे हैं जिन्होंने बायोलॉजी विषय लेकर 12 वीं भी किया है और उन्होंने स्नातक भी किया है। शासन उसे पदोन्नत करता है और उसे दो सालों की ट्रेनिंग देकर, फील्ड में ए.बी.एफ.ओ. के तौर पर पदस्थ करती है, लेकिन उसमें देखा जाए तो विभागीय स्तर पर उन्हें पदोन्नत करने की संख्या या बात देखें तो यह बहुत कम है। वहां ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो इस आस में रहते हैं, लेकिन उनकी उम्र हो जाती है और वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में इसमें संगठन और कर्मचारियों के माध्यम से आवेदन दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जो मांग कर रहे हैं अगर उनके लिए 25 से 30 प्रतिशत भी आरक्षित कर दिया जाये तो उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। जो सेवानिवृत्त होने की कगार पर हैं उन्हें कम से कम इसका लाभ मिल सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त बजट नहीं आएगा। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी यह करना चाह लें तो वह ज्यादा लोग भी नहीं है। केवल 200-400 ऐसे कर्मचारी होंगे, जिन्हें उसका लाभ मिलेगा। अगर उनके लिए ऐसा कुछ काम कर दें तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी यह कहना चाहूंगा कि आपके पास ऊर्जा विभाग है। अभी किसान और आम जन लगातार बिजली की कटौती से परेशान हैं। कल बालोद जिला के किसानों ने इसी बिजली की कटौती को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया और यहां तक चक्का जाम की स्थिति निर्मित हुई थी तो मैंने निवेदन किया कि मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा, इसमें जो भी सुधार होगा, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। इस अटल ज्योति योजना के माध्यम से अभी जो फसलें लगी हुई हैं, उसमें आपके माध्यम से 5 बजे से 11.00 बजे तक लाईन काटी जाती है, लेकिन दिन में भी लगातर 4, 6 घण्टे बिजली की कटौती हो रही है। इससे परेशान होकर कल लगभग 25 गांवों के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से केवल चेतावनी देकर, चले गए । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो अटल ज्योति योजना के नाम से लगातार विद्युत की कटौती की जा रही है उस पर भी विराम लगाएं और साथ ही बिजली की आपूर्ति बराबर निर्बाध रूप से चले, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर विद्युत व्यवस्था को लेकर स्थानीय विद्युत कर्मचारियों का दंश झेल रहे हैं। फोन करने पर कर्मचारी न फोन रिसीव करते हैं

और जब विद्युत कार्यालय में शिकायत लेकर जाते हैं तो वहां कर्मचारी नदारत रहते हैं। जब ज्यादा परेशानी होती है तो दो-चार बार फोन लगायेंगे तो वह अपना फोन बंद कर देते हैं। माननीय सभापति महोदय, किसानों को और क्या चाहिए, पानी के लिए बिजली चाहिए। वह बिजली के लिए भटकते रहते हैं। हमारी पूर्व की सरकार में ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई थी। हमने लगातार सुचारू रूप से वह काम देने का प्रयास किया था। बिजली बिल हॉफ योजना के माध्यम से हमने प्रदेश की लाखों जनता को छूट भी दी थी। लेकिन वर्तमान में आपने बिजली बिल हॉफ योजना के लिए प्रावधान रखा है, लेकिन जब से आपने घोषणा की है तब से लगातार प्रदेश में बिजली व्यवस्था ठप्प पड़ी है। गावों में लगातार बिजली गुल हो रही है। लोग रात को 12-1 बजे फोन कर रहे हैं। गावों में बिजली व्यवस्था को लेकर परेशानी तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां पर बिजली सबंधी समस्या को लेकर जो-जो आवेदन आये हैं चाहे वह ट्रांसफार्मर के हों, वोल्टेज की समस्या का हो या कहीं पर सब-स्टेशन या अलग से वितरण केन्द्र स्थापना की बात हो, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसे अतिशीघ्र पूरा करें ताकि लोगों को और किसानों को उसका लाभ मिल सके। पूर्ववर्ती सरकार में मेला स्थल हो या प्रमुख चौक-चौराहों में क्रेडा के माध्यम से हाईमास्क लाईट, खेल मैदान, स्टेडियम में भी सोलर लाईट के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन अभी तक शासन पर स्तर पंचायतों, जनपद, नगरीय निकाय या किसी भी क्षेत्र में ऐसी जगहों लाईट व्यवस्था करने के लिए निर्देश नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अभी मेला, मड़ई का दौर चल रहा है। यदि ऐसी जगहों पर लाईट की व्यवस्था हाईमास्क लाईट या सोलर लाईट के माध्यम से हो जाये। आजकल बहुत से ऐसे युवा हैं, खेल के मैदान में बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण अपनी प्रेक्टिस नहीं कर पाते और गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मैं चाहूंगा कि जहां-जहां पर खेल का मैदान है और जहां पर बच्चे नियमित रूप से प्रेक्टिस करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने का संपना संजोये हैं, उसके लिए सोलर या हाईमास्क लाईट के माध्यम से उन खेल के मैदान में लाईट की व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आपको बोलने हुए आधे घंटे हो गये हैं। यदि अपने क्षेत्र की मांग है तो उसको बता दीजिए। काफी सदस्यो को चर्चा में भाग लेना है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से खनिज विभाग के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। खनिज विभाग में लगातार पिछली सरकार में रेत को लेकर जो बातें कहीं गई थीं, लेकिन यदि आप वर्तमान में देखें तो मेरे यहां लगातार बहुत से नेताओं के फोन सरपंचों को आ रहे हैं कि आपके यहां रेत खदान चालू करनी है, आपको स्वीकृति देनी है। कल भी दो जगह फोन आया था। मैं बताना नहीं चाहूंगा कि कहां से फोन आया था। वैसे लोगों का फोन आया था, जिनके बारे में वह लोग कभी सुने भी नहीं थे, यहां रेत घाट चालू करनी है

और आप लोगों की परमीशन चाहिए। आपको जनता ने जनादेश दिया है। जहां कभी रेत खदान की शुरूआत नहीं हुई थी, मैं समझता हूं कि वैसी जगह पर कभी न रेत को परिवहन करने का, न खनन करने की अनुमति दी जाये। माननीय मंत्री जी ने सदन में गांव में आवास निर्माण के लिए रेत देने की बात कही भी। गांव में छोटे-छोटे लोग घर बनाने के लिए रेत का उपयोग करते हैं। लेकिन उसकी आड़ में भू-माफिया सक्रिय हो गये हैं। रात-रात भर ट्रेक्टर के माध्यम से परिवहन हो रहा है, जे.सी.बी. लग रही हैं और वह सुबह फिर गायब हो जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिन पर आपको संज्ञान लेने की जरूरत है। ताकि जो अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन हो रहा है, उस पर भी अंकुश लग सके।

माननीय सभापति महोदय, जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार आई तो बहुत से ऐसे लोग सामान्य प्रशासन विभाग में कोटर मैनेज के माध्यम से काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उन्होंने निवेदन किया तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उन्हें उस विभाग में संलग्न करवाया और आज वह मंत्रालय में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के समय के बहुत ही कम 200-250 लोग हैं जो 5 साल काम करने के बाद आज फिर बेरोजगार हो गये हैं। वह आप तक भी निवेदन लेकर आये थे। उसमें यह बात कहने की जरूरत नहीं कि पूर्ववर्ती सरकार ने उन लोगों को रखा था । आपकी सरकार के समय के कर्मचारी को हमारी सरकार ने उसे नियमित रूप में काम करने की अनुमति दी थी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि लगभग 200 से 250 लोग हैं, जिन्होंने काम किया था। कोई मंत्री के बंगले में थे, कोई मंत्री के कार्यालय में थे, कोई उनके निवास में थे, कोई संसदीय सचिव के साथ में थे। लगभग ऐसे 200 से 250 कर्मचारी थे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन्हें पुन: वापस लाकर संलग्न कर रोजगार देने का काम करें। साथ ही मैं अंतिम में यह कहना चाहूंगा कि ग्रामोद्योग विभाग की बात करते हैं तो निश्चित ही गांवों की जो शिल्पकलाएं हैं और हम सबसे ज्यादा शिल्पकलाएं आदिवासी अंचल में देखते हैं। पूर्व की सरकार ने उसे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया और ग्राम शिल्प को लगातार एक ऊंचाई मिली, एक प्रसिद्धी मिली। चाहे सी-मार्ट के माध्यम से हो या अन्य योजनाओं के माध्यम से हो, हमने उसे जनता तक मार्केट एवं बाजार तक उपलब्धता कराने का काम किया, जिसका उन्हें प्रतिषाद मिला और उनकी आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार हुई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुम्हार गांव में रहते हैं और आजकल घड़ा के साथ-साथ मूर्तियों से लेकर अन्य चीजों का निर्माण करते हैं। वे बीच में निवदेन करने आये थे कि शायद अब उनको जो जमीन उपलब्ध कराई जाती थी, उन पर टैक्स नहीं लिये जाते थे। अब उस पर शायद ऐसा प्रावधान कर रहे हैं, ऐसा कह कर उन्होंने मुझ तक आवेदन लेकर आये थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- शायद।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा मत हो। उसके पहले में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे छोटे-छोटे परिवार के हैं। उसके माध्यम से उनका जीवन चलता है। वह निर्विवाद रूप से चलता रहे। उनको किसी प्रकार की परेशान ना हो, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय :- निषाद जी, आपके क्षेत्र की कोई मांग हो, कृपया उसे रखते हुए समाप्त करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बस यही निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक तो विद्युत की बड़ी समस्या है। इधर राजनांदगांव जिला भी, इधर मोहला-मानपुर जिला, इधर बालोद जिला, हम लोग इन तीनों जिला से घिरे हुए हैं और मैंने एक बड़ी विद्युत परियोजना 132 के.व्ही. के लिए मांग की है। खामबाट में सब स्टेशन यदि स्थापति कर दिया जाये तो लगभग पांच विधान सभा को उसको लाभ मिलेगा। वहां से खुज्जी विधान सभा भी लगा हुआ है, डोंरगांव विधान सभा भी लगा हुआ है, माननीय अध्यक्ष जी का स्वयं विधान सभा लगा हुआ है, डोंडीलोहारा विधान सभा भी लगा हुआ है। इन पांच विधानसभाओं को उसका लाभ मिल सकता है। वहां पर पर्याप्त जगह है। लगभग 40 से 50 एकड़ जमीन है, जो सब स्टेशन के लिए जगह खाली है। वहां पर उसका विस्तार किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैंने भाठागांव-आर के लिए सब स्टेशन के लिए भी मांग की है। यदि संभव हो सब स्टेशन स्थापित किया जाये, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने बजट में बहुत-से ऐसे स्वीकृति की है। यदि वह व्यवस्था हो जाता है तो वहां पर आसपास के 8-10 ग्राम पंचायतों के लोगों को उसकी सुविधा मिल सकती है और जो विद्युत के दाब बन रहे हैं, उस परेशानी से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए बस अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रथम वक्ता के भाषण को सुनकर लगता है कि कांग्रेस पार्टी सदमे में है। वह जितने समय बोले, उतने समय में आधा से ज्यादा समय मछली पालन में बोले, फिर चलते-चलते अर्जुन्दा, गुण्डरदेही में आकर समाप्त कर दिये। उनको धोखे से पता नहीं चला कि विष्णु सरकार जो कदम उठाने जा रही है, उसकी आलोचना के लिए कोई शब्द नहीं है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैंने सीधे सरकार को कहा कि यदि आपका विजन है तो आप अपने विजन में काम कीजिये। आलोचना करना आपका काम है और आईना दिखाना हमारा काम है। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आप उम्मीद के हिसाब से खतम करिये। आपने केवल सरकार को गोबर के लिए, चारा के लिए कोसने का काम किया है, लेकिन इसका जवाब जनता भी देख रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोला बोलन दे न।

सभापति महोदय :- निषाद जी, बैठ जाईये। अजय जी, आप अपनी बात को रखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मिट्टी की जमीन एलॉट किए हैं, शायद उसमें टैक्स लगेगा। फलाना योजना है, उसको जारी रखने का कष्ट करेंगे। क्या हमको इनकी योजना को जारी रखने के लिए मेंडेट मिला है क्या? क्या हमको इनकी तरह पैसा खाने के लिए मेंडेट मिला है?

हमें किन्हीं और कामों के लिये और जनता की सेवा के लिये मेंडेट मिला है । माननीय सभापति महोदय, पाप के कारण पृथ्वी रसातल में चली गयी, उसको बाहर निकालने के लिये, उसका उद्धार करने के लिये विष्णु भगवान ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को फिर से ऊपर लाये । छत्तीसगढ़ का प्रशासन और प्रशासनिक शैली एवं प्रशासन के जो मापदंड हैं वह बिल्कुल रसातल में चले गये हैं और जब भगवान विष्णु फिर से अवतार लिये हैं तो सबसे पहले प्रशासन को दुरूस्त करने के लिये बडा उपक्रम करना पडेगा । मैं आपको कुछ चीजों में बधाई दूंगा और कुछ चीजों में मांग करूंगा । मैं सामान्य प्रशासन और आपने जितने विभागों की मांगें रखी हैं, मैं उन सभी का समर्थन करता हूं । आपने मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिये कदम उठाये हैं उसमें एक गारंटी महत्वपूर्ण थी कि हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया की सी.बी.आई. जांच करेंगे । माननीय सभापति महोदय, मैं आपको उसकी पृष्ठभूमि में अवगत कराना चाहता हूं कि जब तत्कालीन, चूंकि नाम नहीं लेते लेकिन मैं किसी बुरे उद्देश्य से नाम नहीं ले रहा हूं । मैं केवल नाम बता रहा हूं टामन सिंह सोनवानी जी । आप सुन लीजिये, चूंकि आप प्रथम वक्ता हैं । आपके दोनों लोग, मैं दोनों को तो नहीं बोलता । पर्यटन में एक इसलिये गायब हैं कि उनमें इस सदन का सामना करने का नैतिक साहस नहीं है । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- ऐसा नहीं है । काम है, वह गये हैं । (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- ऐसा मत बोलिये वे किसी काम से गये हैं ।(व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- प्रतिदिन उनके 5 सालों के कारनामों की परत उधड़ेगी । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हमने इधर भी देखा है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आज भी दो विषयों में प्रश्न संदर्भ की जांच की घोषणा हुई । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हमने इधर भी देखा है कि लगातार आपके मंत्रियों की उपस्थिति कितनी रहती है । हमने ट्रेजरी बेंच की जवाबदारी भी देखी है ।

श्री अजय चंद्राकर :- हमको वह मालूम है । इनको पर्यटन में कुछ बना लिये हैं । माननीय सभापति महोदय, जब उसकी नियुक्ति के लिये प्रस्ताव भेजा गया तो यह बात छिपा दी गयी कि उसके खिलाफ जांच है और वी.आर.एस. लेकर जांच को समाप्त किया गया और उसको पी.एस.सी. में नियुक्ति दी गयी । मैं आपसे मांग करूंगा चूंकि दो साल नहीं हुए हैं और उन्हें वी.आर.एस. लिया था इसलिये उस जांच को फिर से संस्थित की जानी चाहिए । छत्तीसगढ़ की जनता के साथ एक षड़यंत्र किया गया कि

एक दागी अफसर को, एक दागी व्यक्ति को जांच को समाप्त करके हम पी.एस.सी. की चेयर में बैठायें और बाजार भाव में पदों को बेचें या अपने लोगों के पास उनकी नियुक्ति करें । (शेम-शेम की आवाज) यह प्रशासन को पंगु बनाने के लिये, जब योग्य लोग नहीं आ रहे थे चाहे वह किसी भी संवर्ग से आयें । जो लोग पैसे में खरीदकर आयेंगे तो वह प्रशासन कैसा होगा ? छत्तीसगढ़ का प्रशासन किधर जायेगा ? इसीलिये मैंने कहा कि वह नीचे चला गया तो इसलिये आप इसमें अवश्य जांच की घोषणा करें कि उनके ऊपर जो जांच थी वह जांच फिर से संस्थित की जायेगी ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वर्ष 2003 की भी जांच हो जानी चाहिए । वर्ष 2003 की जो पी.एस.सी. भर्ती हुई थी उसमें भी जो बात आयी थी उसकी भी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- भाई, आप 5 साल थे न । आपने क्यों नहीं किया ? 5 साल कुछ नहीं कर पाये । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- क्या आप बोलते समय भूल गये थे ? (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- मुख्यमंत्री जी 5 साल खोजते-खोजते रह गये । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मैं यह बोल रहा हूं कि आपके पास अभी जितनी भी एस.आई.टी., सी.बी.आई. हैं उसकी भी एक बार घोषणा कर दीजिये, उसकी भी जांच होगी करके । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- आप सुनिये न । जितनी क्षमता पर जितनी बैठायेगी, जितनी जांच करानी है करा लेना । आप 5 साल कुछ नहीं कर पाये । (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप लोग कराईये न । सरकार में आप बैठे हैं । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- आपके मुख्यमंत्री 5 साल में कुछ नहीं कर पाये । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, बीच-बीच में टोका-टाकी अच्छी बात नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जब सरकार में आप बैठे हैं तो आप करा लीजिये । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब आपको फिर से दोबारा मौका देने की अर्थात् मेरे बाद आपको दोबारा मौका दिया जाये ऐसा मैं आग्रह करता हूं ताकि सोच-सोचकर ये फिर से मेरी बातों को काटें । आप लिखते जाईये, आपको दोबारा मौका दिलवाने का आग्रह करेंगे । माननीय सभापति महोदय, आज पेपर में छपा है । मैं पेपर की बात का उल्लेख कर रहा हूं । एक लज्जाजनक बात छपी है, राष्ट्रीय एजेंसी की बात छपी है, स्थानीय एजेंसी ने कार्यवाही की । प्रशासन का नाम क्या है सिंडिकेट । मैं इन लोगों को बोलता हूं कि देश की सर्वोच्च प्रतिभाएं, देश के सर्वश्रेष्ठ एग्जामिनेशन से चुनकर आते हैं, उनके लिये क्या शब्द उपयोग हो रहा है सिंडिकेट । सिंडिकेट के सरदार एक थे, रिटायर हो गये उनका नाम है कि साहब ये उन लोगों को लाभ देते थे और सबसे लज्जाजनक बात क्या छपी कि एक मंत्री को 50 लाख रूपये दिये जाते थे और एक सचिव को 50 लाख रूपये महीने दिये जाते थे

इन लोगों को सुनने में कैसा लगता है और हम निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सुनने में कैसा लगता है, पढ़ने में कैसा लगता है और छत्तीसगढ़ की छवि कैसी बनती है? अब आप सिंडिकेट में कुछ बोलेंगे? माननीय सभापति महोदय, ये सिंडिकेट मामले में ई.डी. को पूरी मदद मिलनी चाहिए। ये सिडिंकेट जो बना था, दोबारा प्रशासन में सिंडिकेट न बने और इन लोगों को तो आपके माध्यम से कहूंगा कि साहब, अमीन सयानी जी हमारे सामने अब नहीं हैं। बिनाका की खनकती आवाज गुंजती थी, लोग सोये रहते थे वे जाग जाते थे। 5 साल में 1 साल छोड़ दीजिए, सवा साल से तो जेल में हैं। ये लोग भी एकदम नूरजहां की खनकती आवाज सुनते थे तो सोये रहते थे तो जाग जाते थे। नियम-कानून के परे सेस के पैसे से पैरा धुलाई कर दिये। 15वां वित्त आयोग से पैरा धुलाई कर दिये। ये आदत सुधारनी पड़ेगी कि संवैधानेत्तर सत्ता की इच्छाओं का पालन करना भारत का संविधान नहीं है कि 4 सलाहकार नियुक्त कर लिये और कांग्रेस शासन के पैसे पर मणिपुर, असम और उत्तरप्रदेश के चुनाव में सरकारी पैसे से प्रचार पर जा रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं और ऐसा प्रशासन चलता है। सरकारी पैसे में कांग्रेस पार्टी का काम करे, जिसके सामने लिखा है, ये सलाहकार, वो सलाहकार, वो सलाहकार, वो सलाहकार। माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर इस तरह के सरकारी कर्मचारी चाहे जिस किसी स्तर पर हो, यदि वो अपना स्तर खोते हैं तो छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाएं और मैं आग्रह करूंगा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रश्रय दीजिए। संविधान के अनुसार चल रहे हैं, उन्हें प्रश्रय दीजिए। (मेजों की थपथपाहट) अच्छा काम करें, पुरस्कृत कीजिए, लेकिन ये नूरजहां की खनकती आवाज में कोकिलकंठी लता मंगेश्कर की आवाज में प्रशासन नहीं चलेगा। प्रशासन चलेगा बिजनेस रूल्स से, संविधान से, नियम से, कानून से, निर्देश से। खनकती आवाज से प्रशासन नहीं चलेगा। सिंडिकेट नहीं बनेगा। माननीय सभापति महोदय, एक आदमी को उपकृत करने के लिए नवाचार आयोग बनाया गया। 33 बैठकें हुईं, 2 सुझाव आये। अब खर्चा कितना हुआ, भाई साहब खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जान जायेंगे। आप ई.ओ.डब्ल्यू. में 5 साल में केवल दो चालान प्रस्तुत कर पाये। लखेश्वर जी, आप सामने आकर बैठ जाइए। आप तीसरी बार के हैं। मात्र दो चालान प्रस्तुत कर पाये न? ए.सी.बी. में 5 साल में एक प्रकरण दर्ज हुआ। भ्रष्टाचार संस्थागत मान्यता प्राप्त हो गई। उस ऑफिस में ताले लटक गये। उसमें दो दरवाजे हैं। पिछले दरवाजे से फोन आता था कि साहब आपके खिलाफ complaint है, आप आकर सेटल कर लीजिए। वह ब्लैकमेलिंग की संस्था बन गई। पूरा हिन्दुस्तान में 33 राज्यों में कहीं पर भी केन्द्र शासित राज्यों को मिलाकर यह स्थिति नहीं थी कि ए.सी.बी. जैसी संस्थाएं ब्लैकमेलिंग का माध्यम बनकर सरकारी ब्लैकमेलिंग करे। यह छत्तीसगढ़ में आपके राज में हुआ। एक प्रकरण दर्ज हुआ। माननीय सभापति महोदय, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड अभी भी शायद वह कार्यरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 5 साल में कितनी भर्ती की? आप नोट करते रहिए, मेरे बाद आपको और मौका दिलवाउंगा। कितनी भर्ती हुई? बस्तर की, सरगुजा की, कहीं की एकाध भर्ती। कुछ नहीं।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, कनिष्ठ चयन बोर्ड में बस्तर जिला में 2100 लोगों की भर्ती हुई है।

श्री रामकुमार यादव :- प्रोफेसर के भर्ती होये हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें हैं। ये तो जनरल बातें हैं, जिस तरह नूरजहां के निर्देश पर, खनकती आवाज पर प्रशासन चला और सिंडिकेट बने, वसूली हुई आगे के विभाग में और होंगे। आपके बहुत सारे विभाग हैं। आपके बोलने के पहले बहुत सारे लोगों को बोलने होंगे। अनुकंपा नियुक्ति एक मानवीय आधार है। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में कैबिनेट से आपको छूट देना पड़े तो विकलांगों के मामले में भर्ती शत-प्रतिशत हो, गरीबों को, पीडितों को न्याय मिले। विभागीय जांच कितने के ऊपर लंबित हैं? भूपेश बघेल जी के राज में या कांग्रेस regime में सिर्फ जो काम नहीं कर रहा है, जो वसूली नहीं कर रहा है, जो नई पद्धति ठेका पद्धति का शासन विकसित हुई कि बड़े-बड़े पदों पर पैसा लेकर नियुक्ति की जाने लगी, उस ठेका पद्धति के शासन में जो फिट नहीं बैठ रहा था तो उसके खिलाफ जांच संस्थित कर दो। (शेम-शेम की आवाज) जो जांच संस्थित हुई है वो सही है या गलत है ? मैं चाहूंगा कि उन्हीं लोगों की अध्यक्षता में समिति बने, जो बेचारे कर्मचारी पीड़ित हुए हैं, उनको न्याय मिले और गलत थे उनके निपटाकर उनको उचित स्थान में भेजा जाए । माननीय सभापति महोदय, प्रशासन की इतनी बुरी हालत थी कि सी.एस. का आवास ही खाली करवा दिया गया । सी.एस. एक इंस्टीट्यूशन होता है । इन लोगों ने स्वीकार भी कर लिया, खनकती आवाज़ के सामने, नूरजहां की आवाज़ के सामने इन लोगों ने एक लाईन नहीं कहा कि यह गलत हो रहा है, एक इंस्टीट्यूशन के साथ अन्याय हो रहा है ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, ये नूरजहां कौन है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो कांग्रेस शासन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो नूरजहां की खनकती आवाज बोल रहा हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- जहांपनाह, नूरजहां कौन है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप समझते हो तो गलत समझते हो कि आपका कोई मुख्यमंत्री था । सिंडीकेट ही था । सिंडीकेट ही शासन चलाता था और नूरजहां की खनकती आवाज चलाती थी ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नूरजहां नहीं थी, यह सही है । आप बार बार नूरजहां बोल रहे हैं, नूरजहां नहीं थी । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि व्यवधान न करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इस भ्रम को निकाल दीजिए कि आपने कोई मुख्यमंत्री चुना था । सिंडीकेट प्लस नूरजहां की आवाज इज इक्वल टू कांग्रेस शासन नाम दे दिया गया ।

श्री राजेश मूणत :- कौन है नूरजहां ?

श्री द्वरिकाधीश यादव :- बताएंगे वे ही ।

श्रीमी संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, नूरजहां की कहीं नहीं चली है, वह भूपेश बघेल जी की सरकार थी ।

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी ही बता सकती हैं, उनको पूरा अनुभव है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो वसूली नहीं करेगा, वह ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बड़ी देर से याद आया कि भूपेश बघेल की सरकार थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीयय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों की पदोन्नति, क्रमोन्नति, वेतन विंगति को लेकर बिना मतलब के हड़ताल होती रहती है । मैं यह चहूंगा कि एक ऐसा आयोग बने जो कर्मचारियों की बातों को पूरी तरह सुने, जो विसंगति है यदि उनकी सेवा भर्ती नियम में विसंगति है तो उसको सुने, वार्ता असफल हो जाए, तब वे हड़ताल पर जाएं । यदि वे सीधे हड़ताल में जाएं तो हड़ताल अवैध घोषित हो। पहले वार्ता हो, कोई आयोग बने जो इस तरह की विसंगतियों को सुने और वे भी हमारे लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ता है तो प्रशासन की क्वालिटी सुधरेगी । जो उनका अधिकार है उनको मिलेगा तो प्रशासन ऊपर आएगा । जनहित के कार्य होंगे, नीति-निर्देश ये लोग बनाएंगे । अभी तो ऐसा कोई फोरम नहीं है, वो विभाग वाले जाएं, वो विभाग वाले जाएं, इतने संगठन है, इतने सारे विभाग हैं, एक फोरम बने जहां वे अपनी बात रख सकें । जब वार्ता असफल हो तब वे हड़ताल पर जाएं । हड़ताल करके वे हमको बुलाएं, ऐसा नहीं हो सकता, फिर उस पर कार्रवाई हो । लेकिन यदि उनकी मांग है तो उसे सुनने के लिए फोरम होना चाहिए । महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मैं बार बार शासन प्रशासन में महारानी की आवाज को सुनते सुनते ऐसी आदत पड़ गई है कि सम्माननीय 50 विधायक नये चुनकर आए हैं । विधायकों के फोन का जवाब देना, कॉल बैक करना, पत्रों का जवाब देना, उचित समय में देना, यह प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई, जो भी सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं, वे इस बात को सुन लें कि यह शिकायत तो मुझे भी है । इसको लेकर मेरी भाषा कभी-कभी विद्रुप होती है । 50 विधायक नये चुनकर आए हैं, उनकी बातों को सुना समझा जाए ।

सभापति महोदय, दिल्ली में छत्तीसगढ़ के जो तीन आवासीय परिसर हैं । तीनों की हालत अच्छी नहीं है । खासकर सफाई, स्वच्छता के मामले में । वह अवांछित लोगों का आरामगाह बन गया है । वहां कोई भी अवांछित आदमी जाकर रह सकता है । यदि कभी बड़ी दुर्घटना घट गई तो गड़बड़ हो जाएगी । हमारे पास तीन आवास हैं तीनों आवासों के लिए दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है कि कौन लोग, कितने दिन ठहर सकते हैं ? अभी जो दृश्य है वह अच्छा नहीं है । सभापति महोदय, लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 60 हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित है । लोक सेवा गारंटी अधिनियम अपना अर्थ खो देगा । मैं चाहता हूं कि जन-सामान्य को लाभ मिले । एक जन-समस्या निवारण शिविर और जन-

शिकायत निवारण शिविर इस विभाग के अंतर्गत है। माननीय सभापति महोदय, यह दुर्लभ काम हो गये हैं। प्रशासन में क्या काम है मुझे नहीं मालूम। दौरा करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे नहीं मालूम। जन-समस्या निवारण या जन-शिकायत निवारण के लिए कोई शिविर इस तारीख को लगेगी जिसमें सब काम छोड़कर अधिकारी उपस्थित रहेंगे, इस गांव में लगेगा, इस क्षेत्र में लगेगा या इस जिले में लगेगा, यह दुर्लभ हो गया। लुप्तप्राय प्राणी टाईप हो गया, संरक्षित कार्य हो गये हैं, शासन की दृष्टि में इसका महत्व समाप्त हो गया है। मैं चाहता हूं कि ये जो सामान्य प्रशासन की चीजें हैं, वह होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन में खास तौर पर एक ही लाईन बोलना था, प्रशासन नवाचार का काम करें, नीति-नियम बनाने का काम करे, जो अच्छे उद्देश्य हैं, जिसके लिए विष्णु सरकार गठित हुई है, उसमें काम करें। सबसे ज्यादा शिकायत इसी बात से है कि प्रशासन को सिंडिकेट कहा जाने लगा। यह एकमात्र राज्य है, जहां आई.ए.एस. और अखिल भारतीय सेवाओं तक के अधिकारी 22 करोड़ की बिल्डिंग में बंद हैं। हम छत्तीसगढ़ में लाख अच्छा काम कर लें, जब ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं तो हमको उसका स्पष्टीकरण देते बनता नहीं है। मैं यही आग्रह करूंगा कि अच्छे अधिकारी जो नियम कानून से काम करते हैं जिसके खिलाफ गलत-सलत कार्रवाई की गयी, उन सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त करके, आप पृथ्वी से निकालिए, जो विष्णु अवतार हुआ है, दूसरा बड़ा अवतार हुआ था, उसको लीजिए और छत्तीसगढ़ की धरा को पाप से मुक्त कीजिए।

सभापति महोदय, मैं खनिज संसाधन में एक लाईन पढ़ता हूं। वर्ष 2021-22 में 413.13 लाख का उत्पादन हुआ था और राजस्व प्राप्ति 423.93 करोड़ की हुई थी। वहीं वर्ष 2022-23 में 441 लाख उत्पादन होने के बाद आमदनी 360 करोड़ हुई। ज्यादा उत्पादन होने के बाद आमदनी कैसे कम हुई। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह प्रतिवेदन बोल रहा है। यह आखिर कैसे हुआ ? यह तो जांच का विषय है, क्योंकि अंतर लगभग 800 करोड़ का है। उत्पादन ज्यादा होने के बाद आमदनी कैसे कम हुई। दूसरी बात, खनिज का मतलब क्या होता है ? छत्तीसगढ़ में खनिज का मतलब लेवी वसूली होती है। कालिख पूत गयी, कोयले की दलाली से छत्तीसगढ़ में बस हाथ काले नहीं होते, कोयले की दलाली से गांधी निकलते हैं, यह छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने या नूर जहां की खनकती बलखाती आवाज ने इस बात को साबित किया है, 25 रूपए चाहिए, 50 रूपए चाहिए, इतना रूपए चाहिए [xx], दो अखिल भारतीय सेवा के अफसर ने मुझे आकर बताया कि मेरे लिए [xx] शब्द का उपयोग हुआ है। आप यदि कक्ष में समय दें तो मैं नाम ले दूंगा। मेरा कहना, मुख्यमंत्री का कहना है। यदि आप नाम जाहिर नहीं करेंगे तो मैं आपको नाम बता दूंगा। कोयले की दलाली से गांधी जी छपते हैं, यह छत्तीसगढ़ में साबित हुआ। जेल में गये हैं। वर्ष 2018-19 से 2023-24 तक जो कोयले में राजस्व मिलता है, उसमें भी राजस्व कम प्राप्त हुआ है।

सभापति महोदय, अब DMF में आ जाते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की। DMF में 9 हजार से उपर करोड़ का घोटाला हुआ है, यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने यह आरोप लगाया कि 9 हजार करोड़ रूपए से उपर का DMF घोटाला हुआ है। DMF घोटालें में ED ने रिपोर्ट दर्ज की, उसके बाद ACB ने रिपोर्ट दर्ज की। DMF मतलब क्या है ? ATM सरकार दिल्ली पैसा भेजे यही DMF है। 9 हजार करोड़ रूपए गये पानी में। पैरा ढुलाई में गये या स्कूल पोताई में गये। आपके प्रतिवेदन में कई चार्ट भी लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जिन जिलों में असंतुलित राशि और अत्यधिक राशि मिलती है तो एक अनटाइट फण्ड है। मैंने एक उदाहरण दिया कि मैं अभी कोण्डागांव गया था तो ज्ञात हुआ कि वहां की लाइब्रेरी D.M.F. से बनी है। मैंने कहा कि यदि मुझे धमतरी जिले में ऐसी लाइब्रेरी बनानी है तो मैं अपने जीवन में नहीं बना सकता। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं उसको कौन से मद से बनवाऊं। ऐसे कई कार्य हैं। वह लाइब्रेरी इनके शासनकाल में नहीं बनी है। आप गर्व मत पालना, क्योंकि वह लाइब्रेरी आपके समय में नहीं बनी है। यहां रायपुर का नालंदा परिसर बहुत प्रसिद्ध है। यदि हमको बनवाना हो या अलटाइड फण्ड से कुछ ऐसे कार्य करने हों या नॉन बजट के हों तो 10 जिले ऐसे हैं, जिनमें कोई भी बजट नहीं है। असंतुलित विकास न हो, इसके लिए आप कोई न कोई राशि का प्रावधान कीजिए। केन्द्र सरकार के D.M.F. के नये निर्देश जारी होंगे। उनके जो भी निर्देश जारी हों, लेकिन आप अपने अधिकारियों और मंत्रिमण्डल के साथ बैठकर इस बात की चिंता जरूर करें कि उसमें लिकेज ही लिकेज हैं। उस राशि का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में जितना प्रतिशत होगा, उसके अतिरिक्त जनहित के ये क्षेत्र। खास तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थाई अधोसंरचना विकसित हो। जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, उनको प्राथमिकता दी जाए। यदि आप प्राथमिकता तय करेंगे तो सप्लायर नहीं कूदेंगे। अभी D.M.F. के लिए सप्लायर घूमते हैं। यदि हम लोग किसी गैप फीलिंग के लिए लिखेंगे तो बोल देंगे कि हम इसमें नहीं दे सकते। मैं आपको एक कलेक्टर का उदाहरण बता दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने रेत की बात कही। इनके पास फोन आ रहे हैं। 300 से अधिक खदानों का झण्डा तो आपने ही गड़ाया है। जो अभी गायब हैं, उनका नारा होता था - छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया। रेत खदान के माफिया में कौन छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़िया है? मैं तो छत्तीसगढ़ी की बात नहीं करता हूं। मैं तो हमेशा कहता था कि आप एक डोमिसाइल नीति बनाइये और कौन छत्तीसगढ़िया है और कौन नहीं है, उसको परिभाषित कीजिए। फिर आप इस बात को किसी को बोलना। उनका नाम लेकर और भावनात्मक शोषण करके अपने गुर्गों को रेत खदान में बैठाकर दादागिरी, लठैतगिरी, शोषण के काम और आम ग्रामीण की पिटाई भी हुई तो इनके शासन में हुई। मैं अपना उदाहरण दे देता हूं। मैंने साफ कह दिया है और मुख्यमंत्री जी से भी मांग की है कि नयी नीति बनने तक लीगल खदान ही चलें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उसमें एक संशोधन की मांग करूंगा कि मेनुअल करने से रेत के भाव तो बढ़ते हैं। मशीन से करने से इलीगल खदान वाले भी ब्लैक

मेलिंग के शिकार होते हैं। अभी आपदा विभाग की चर्चा में आया था कि जो रेट होल वाले फंसे थे, वैसे ही रेत के लदान करने वाले भी कुछ ही श्रमिक होते हैं। उसमें ज्यादा श्रमिक नहीं होते हैं। सब श्रमिक रेत नहीं भरते हैं। मेरे यहां तो रेत खदान की लाइन है। वह ब्लैक मेलिंग और दादागिरी के शिकार बंद होंगे। उनको बोलिये कि जो काम मांगने आते हैं, उसको आप 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 मेनुअल कीजिए और बाकी मशीन से कीजिए। इससे रेट सस्ती होगी। यदि पूरा मेनुअली करावाएंगे तो रेट हमेशा महंगी ही होगी। इसको इनको भी स्वीकार करना पड़ेगा और पूरे सदन को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए यदि खदान मान्यता प्राप्त है और नयी नीति आने तक इसमें कोई बुराई नहीं है कि वह मशीन से रेत भरते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आप गरीब के मजदूरी ला खरम करना चाहत हो उऊ मशीन मा भरवाना चाहत हो। सभापति जी, कई जगह में गरीब आदमी मन अपन झोड़ा-झाड़ा में जाकर नदिया में काम करत हें। अब ओला मशीन ला देना चाहत हें। आप सोच लो कि एमन कतका बड़े गरीब के आदमी हें।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको जो समझना है, समझिये।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आपका भी इस विषय में नंबर है। आप बाद में बोलियेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैंने आपको सुझाव दिया है। आपकी बारी आएगी तो आपको जो अच्छा लगे, आप वह सुझाव दे देना। माननीय सभापति महोदय, कोल माफिया। मैंने तो सिर्फ लेवी वसूली में बोला था कि जो लोग समानांतर सत्ता चलाते हैं, उनके लिए माफिया नाम का शब्द है। लखेश्वर जी, वैसे माफिया शब्द की उत्पत्ति ईटली से हुई है। आप राम नाम वाले तो नहीं हैं। आप रोम नाम वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इटली का कोई सांस्कृतिक प्रभाव छत्तीसगढ़ में न दिखें। खनिज विभाग में हीरा खदान में जहां पर भी लिटीगेशन है, उसके लिए जितना बड़ा भी वकील लगाना पड़े। लेकिन वह जल्दी सुधरे। चोरी के बजाय उसकी एक नंबर में माइनिंग हो। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे खदान अभी ऑक्शन नहीं हुए हैं। अपने खनिज संसाधन के बलबूते में आपने जो मोदी जी की गारंटी का लक्ष्य रखा है, वह हम पा सकते हैं । पुन्नूलाल जी के मुंगेली में तो कोई खनिज है ही नहीं, पर महासमुन्द में डायमंड दिख रहा है । जहां गैर विवादास्पद हैं, वहां माईनिंग में तेजी आये, मैं इसकी बात करता हूं ।

सभापति महोदय, आप इस प्रतिवेदन में पढ़ेंगे तो इसमें तीन प्रकार के शेष हैं- विशेष आबकारी शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क और गौठान शुल्क । गौठान शुल्क अभी भी जारी हैं, यदि ये तीनों सेश अभी भी जारी हैं । इनके समय में जो सेश लगा, अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री नहीं बैठे हैं, लेकिन कोरोना के सेश का एक भी पैसा स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिला, यह जांच का विषय है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि आप सेश के जांच की घोषणा करेंगे तो सेश में मेरा पी.आई.एल. है, मैं पी.आई.एल. को वापस लेने की घोषणा करता हूं, लेकिन जिन कारणों से सेश लगाया

गया, वह पैसा उन विभागों तक नहीं पहुंचा । पैरा ढुलाकर उन पैसों को कागज में खा दिया गया, यह मेरा आरोप है । यह खुला भ्रष्टाचार है, कहीं पर पैरादान नहीं हुआ है । कोई एक आदमी बता दे, हम सत्यापन करते हैं कि मेरे गांव में पैरादान हुआ है, यह मैं कांग्रेस के लिए भी बोल रहा हूं, भाजपा के लिए भी बोल रहा हूं । तो सेश का उपयोग ऐसा ही हुआ है । मेरा पी.आई.एल. है । यदि सेश के जांच की घोषणा करेंगे तो मैं उसे वापस लेता हूं । प्रदेश के सहृदय, सरल, सहज मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि सेश के पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। यदि वे तीनें सेश लगाए रखते हैं, जैसा प्रतिवेदन बोल रहा है कि तीनों सेश लगे है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लगे । छत्तीसगढ़ में यदि गरीब किसान, गरीबों की योजनाओं के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है, अतिरिक्त राशि लगती है तो सेश में हम शिक्षा और स्वास्थ्य को ही दें, प्राथमिक क्षेत्रों के लिए दें ।

सभापति महोदय, एक साल का घोटाला 2000 करोड़ रूपए से ऊपर का है । हिन्दुस्तान में पहली सरकार है, जो अपने करों को चोरी करती थी । यही सिंडीकेट का काम था, इसी में जेल में घुसे हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक साल में ये अंदर गए हैं, बाकी चार साल जो समानान्तर सत्ता चलती रही, समानान्तर दुकान चलती रही, कितने का घोटाला हुआ और अपने कर को चोरी करने वाली आजाद भारत की पहली सरकार बनी, ऐसे लोगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए और आपने मोदी की गारंटी की बात कही है । सामान्य प्रशासन विभाग के कामों में जांच आयोग की भी घोषणा है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हर कामों को तेजी से कर रहे हैं, वैसे ही जांच आयोग की भी घोषणा करें, उसके बिन्दु तय करें, जिसमें शराब घोटाले की एक साल की नहीं, चार साल की पूरी जांच होगी । यह तय होना चाहिए, जांच आयोग हमारे घोषणा-पत्र में भी है । आज ही प्रश्न एवं संदर्भ समिति को जांच के लिए गोबर खरीदी और परिवहन के दो विषय गए हैं । ऐसे सारे विषय की जांच होनी चाहिए । उस दिन आत्मानंद स्कूल की जांच की घोषणा हुई । वह ऐसे सारे विषय उस जांच में आने चाहिए । वह सामान्य प्रशासन के दायरे में है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उसको आप करेंगे ।

सभापति महोदय, लखेश्वर जी, कहां से बुद्धि लाते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता । नशामुक्ति में 10 करोड़ रूपए खर्च हो गए । कहीं पर एक जगह कोई कैम्प नहीं, कोई इंडोर नहीं, कोई आईपीडी में ईलाज नहीं, किसी का ईलाज नहीं हुआ, पर व्यसन मुक्ति केन्द्र के नाम से 10 करोड़ रूपए बुक हो गए । ममा, बागबाहरा में बता सकथस का कि व्यसन मुक्ति के एकाध जगह कैम्प लगे रिहीस होही ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- कई जगह कला जत्था चला है न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बागबाहरा के बात पूछथौं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, बालोद में कैम्प किया गया है।

सभापति महोदय :- संगीता जी, इनके बाद आपका ही नम्बर है, आप बोलिएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मुख्यमंत्री उन्नयन विकास प्राधिकरण के लिए सेश लगाया गया । 1212 करोड़ रूपए एकत्र कर लिए गए, उसमें से 625 करोड़ रूपए व्यय किए । वह तत्कालीन मुख्यमंत्री का जेब खर्च था । क्या नियम, क्या कानून, कौन से विभाग को कौन से कार्य के लिए दिया गया ? कोई नियम नहीं, जो वे बोलेंगे, वह नियम है । ऐसे प्राधिकरण की जरूरत नहीं है । जो सेश आप लगाते हैं, मैं फिर से आग्रह करता हूं कि सेश सभी सरकारें लगाती हैं । यदि आप सेश लगाते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय में लगाएं, 5 साल की शराब बिक्री की जॉच होनी चाहिए और वह कलंख मिटना चाहिए कि कोरोना कॉल में हम घर पहुंच सेवा देते थे । मेरे प्रश्न में है कि कितने पैसे की शराब बेची गई, सप्लाई ब्वाय की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए ? अजीब सरकार थी । मालूम है राजा साहब ? कोरोना में घर पहुंचकर दारू पिलाने वाली हिन्दुस्तान की एक मात्र सरकार थी, वह भूपेश सरकार थी। गर्व से कहो कि हम उस सरकार के ..।तै उंघा मत भइया।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन दारू ला बंद करवा देवा ना भईया।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो बिना देखे एक-एक विभाग को उठा-उठाकर पढ़ रहा हूं, यार। मैं मछली विभाग भर में नहीं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप अपने भाषण में बोलियेगा। अजय जी, आधे घण्टे हो गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जनसम्पर्क विभाग में 4 प्रकार के ईनाम हैं। जनसम्पर्क सचिव कौन हैं ? उनको बोलिये कि 4 ईनाम देने के बजाय एक ही बढ़िया ईनाम किसी काम के लिए दें। दूसरा, क्या है कि अब बहुत सारे न्यूज पोर्टल आ गए हैं। चंदूलाल चन्द्राकर, मधुकर खेर, पंडित माधव राव सप्रे और छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि, बाप रे, 4 प्रकार के सम्मान हैं। यह पहला जनसम्पर्क विभाग है, जिसमें एक ही विषय के लिए 4 प्रकार के सम्मान हैं। उन्हें ज्यादा पैसे, ज्यादा सुविधा के साथ एक ईनाम दीजिये या तो श्रेणी में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, वेब पोर्टल में दीजिये। जन सम्पर्क विभाग ऐसा मत बने। मेरा प्रश्न था, जनमन ने छापा, पत्रिका ने छापा कि 6 लाख लोगों को नौकरी मिली। मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा था कि 4 लाख 51 हजार लोगों को नौकरी मिली। मैंने डी.पी.आर. को फोन किया कि आपने इस समाचार को कहां से छापा ? तो कहा गया कि विभाग ने दिया, हमने छाप दिया। फिर 2 करोड़ रूपये के विज्ञापन दे दिया गया, सी.एस.एम.आर ऐसा क्या बोलते हैं, उसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में 1 प्रतिशत बेरोजगारी है। 6 लाख लोगों को नौकरी मिली, वही छाप रहे हैं और वही छाप रहे हैं कि 1 प्रतिशत बेरोजगारी है। 2 करोड़ रूपये का विज्ञापन वही विभाग दे रहा है।

माननीय सभापति महोदय, संवाद में आउट सोर्सिंग हुई। संवाद के आउट सोर्सिंग में संवाद में कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता घुस गये। यानि मीडिया हाउस, स्ववित्त पोषित संस्था है, आउट सोर्सिंग करके उसको पूरा पंजा छाप का बना दिया। तो आउट सोर्सिंग संस्था कौन है ? किसने नियुक्त किया ? कौन-कौन कितने दिन तक रहे कितने पैसे में रहे, यह जांच तो होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, अब वेब पोर्टल भी आ गया है। अधिमान्यता के जो मापदण्ड हैं, विज्ञापन के जो मापदण्ड हैं, अभी वेब पोर्टल छोटे लोग चलाते हैं। मात्र छः साढ़े छः सौ के आसपास अधिमान्य लोग हैं। अधिमान्यता के मापदण्ड बदलने चाहिए। जन सम्पर्क विभाग सिर्फ विज्ञापन देने का काम मत करें, जागरूक आयोजन भी हो। एक अच्छा आयोजन हो, साहित्यक आयोजन भी हो। राजस्थान के साहित्यक आयोजन का देश इंतजार करता रहता है कि राजस्थान जनसम्पर्क विभाग साहित्यिक मेला कब लगायेगा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा होता है। कोई भी प्रकाशन हो सकता है। जनमन के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के लेखक, साहित्यकार, पत्रकार जितने लोग हैं, उनकी कृति, हमने हिन्दी ग्रंथ अकादमी बनाई थी। पहले कोदूराम दलित थे, अभी भी दलित साहित्य या आदिवासी साहित्य को प्रकाशन के लिए कोई पैसे का मापदण्ड नहीं है। तो जनसम्पर्क कम से कम हिन्दी ग्रंथ अकादमी के पुनर्जीवित होते तक इस काम को करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग जनसम्पर्क सलाहकार बनाये थे। पूर्ववर्ती सरकार चुनाव में गई थी तो सरकार का पैसा गया है, उसकी वसूली होनी चाहिए। जनसम्पर्क विभाग विज्ञापन देने के बजाय सरकार की छवि के साथ प्रदेश की छवि को, मुख्यमंत्री जी की छवि को, और कौन सी चीज है..।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, अगर मीडिया, प्रेस के बात किए जाय तो टी.व्ही. ला खोलिहा तो भगवान के दर्शन नइ होवय, देश के प्रधानमंत्री दिखथे। जेन चैनल ला खोला ओही-ओही दिखावत हे। ओमा काबर निष्पक्ष नइ दिखाय ?

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप भी बोलने वाले पैनल में हैं, आप अपने समय में अपनी बात रखियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- इहां जब ले सरकार बने हे टी.व्ही. खोलत हन तो इहीच मन दिखत हे, अउ कोन दिखत हे ? ओमा कोनो गरीब के बात आवत हे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सिर्फ जांच।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, ऐसा है कि मोदी जी जैसे जनसेवक को आदर के साथ नाम ले सके, कभी सीख नहीं सकते हैं। कांग्रेसी उनको गाली बकने के लिए पैदा हुए हैं। इनकी निष्ठा राष्ट्र के प्रति नहीं है, रोम के प्रति है। इसलिये अपनी ओर से उनकी टिप्पणी को माफ करता हूँ ।

श्री रामकुमार यादव :- थोड़ा सा बोल ले भईया । मोदी जी के बारे मे पूरा देश जानथे । जहां देखबे तिहां, टी.वी. ला खोलबे त विष्णु भगवान कस वोही निकलथे । कोनो पेपर वाला अगर छाप दिस, त वोखर घर में छापा । वोला ई.डी., सी.डी. वोला अंदर । कांपथे ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मोर हाथ मे जेन आथे तेन बोलथंव। सुनथस के नई ? सभापति महोदय, मैं प्रशासकीय प्रतिवेदन में देखा तो जाना कि मछली विभाग आपके पास है ? इसके पहले सही में नहीं जानता था कि आपके पास मछली विभाग है ? माननीय मोदी जी ने देश के सामने पहली दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि अब समय आ गया है कि हम नीली क्रांति करें । हमारे जो जल क्षेत्र हैं, उससे इकॉनामी कैसे मजबूत हो सकती है, इस बारे में सोचें, उसमें साईंटिफिकली क्या-क्या काम किये जा सकते हैं, इस बारे में विचार करें । सभापति महोदय, मछुआरा नीति की बात कर रहे थे कि मैंने एक रील जारी किया था, मछुआरा नीति में मछुआरा के हक को छोड़ कर जल क्षेत्र किसी को भी दिया जा सकता है, नीलाम किया जा सकता है, यह शामिल था । मैंने दसों जगह मछुआरा सम्मेलन को लेकर यह बात कही थी कि छत्तीसगढ़ के मछआरो के, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, यह पहली बार नहीं प्रमाणित तौर पर छत्तीसगढ़ के मछुआरों का हक मार रहे हैं । आज भी कांग्रेस का कोई आदमी अपने भाषण में खुद स्वीकार कर रहे थे, मैं सब सुधारने के लिये, फिर से लिखने के लिये, आवेदन दिया, प्रार्थना किया, हो सकता है अब हो गया होगा, करेंगे, कान्फिडेंस नहीं था कि सुधर गया कि नहीं सुधरा। माननीय सभापति महोदय, आप एक केंवटीन पुरूस्कार देते हैं, बिलासा बाई केंवटीन पुरूस्कार दो बार भर दिया गया है । तत्कालीन मंत्री थे, दोनों बार अपने धमधा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को दिये । मैं इसलिये माननीय संस्कृति मंत्री से व्यक्तिगत चर्चा से लेकर सात्विक चर्चा में इस बात को कहता हूँ कि हमारा ईनाम है जो मजाक मत बने । हम एक ईनाम दें, श्रेष्ठ ईनाम दें, विवेकानंद जी के नाम से दें, किसी के नाम से दें, छत्तीसगढ़ रत्न नाम रख दें, कुछ भी नाम दें, लेकिन चूंकि मैं उस विभाग का भारसाधक मंत्री हूँ, कोई आदमी नहीं मिला तो अपने निर्वाचन क्षेत्र के दो लोगों को वह ईनाम दे देता हूँ । अब मैंने जल क्षेत्र की बात कही है, छत्तीसगढ़ के जल क्षेत्र में आपने बड़े जल क्षेत्र को जो उसका आबंटन ही नहीं हुआ है, गंगरेल या सारे बड़े बांध है, उसको जोड़ ले, बांगों-वांगों गंगरेल से 11 हजार स्कवेयर मीटर का है, जल क्षेत्र का उपयोग नहीं होना, यह चिंताजनक बात है, जल क्षेत्र के लिये नई मछुआरा नीति बनें, यह प्रदेश की आवश्यकता है । वह जल क्षेत्र में हमारे मछुआरा बंधु हैं, प्रशिक्षित मत्स्य कृषक हैं या उसके पास स्व-सहायता समूह हो, तब कोई व्यापारी इस प्रदेश में आये, तब वह ऑक्शन की स्थिति आये या दस स्व-सहायता समूह या दस लोग मिलकर ले सकते हैं, किसी बड़े डैम को 10 मछुआरा समिति मिलकर ले सकते हैं । यदि उनको किसी तरह के समर्थन की आवश्यकता हो, वह समर्थन करे । बृजमोहन जी जब कृषि मंत्री थे, डॉ.रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पहला मछुआरा कॉलेज, मत्स्य कॉलेज छत्तीसगढ़ में खुला कि उसकी कैपिसिटी बिल्डिंग हो । बोलिये ।

श्री उमेश पटेल :- आपने तो इसके लिये पूरा विडियो बनाकर वायरल किया था । मुख्यमंत्री जी को दे दें ?

सभापति महोदय :- उमेश जी, आप लोग आपस में अनुमति ले लेते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखते तो जाओ, विष्णु अवतार है, आज वराह अवतार में भाषण हो रहा है । समझे । माननीय जल क्षेत्र का 10 प्रतिशत भाग ही आबंटित है । उसके बाद मछुआरा समिति जितनी है, कोर्ट लगाकर फॉस्ट ट्रैक में लाकर, वह अकार्यशील क्यों है ? उसको कार्यशील बनाने के लिये, उसके पूरे विभाग को, निपटाया जाये और जितनी समितियां है, उसको क्रियाशील किया जाये । जल क्षेत्र का उपयोग किया जाये, मत्स्य पालन नीति नई बनाई जाये और आपके प्रतिवेदन में छपा है । वह कौन अधिकारी है, मैं पढ़कर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, औपचारिकतावश तो नहीं बनाये हैं ? इन लोग समझते होंगे कि ये पढ़ते नहीं होंगे, इन लोगों की भाषण देने की आदत है ।

श्री रामकुमार यादव :- अधिकारी मन के हाथ धोके पीछे पड़े हस भईया । सभापति महोदय, अभिनव योजना में लिखा है, मत्स्य पालक हितग्राहियों के तालाब में प्लेकांटन वृद्धि कर मछली उत्पादन बढ़ाना, यह भी ठीक है। लेकिन तीसरे नंबर में अभिनव योजना में नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी लिखा है। क्या अभी-भी नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना चल रही है ? इसके कौन-कौन से कंपोनेंट चल रहे हैं ? मुख्यमंत्री जी, जब आप भाषण देंगे तो अधिकारी महोदय से पूछकर जरूर बतायेंगे कि वह अभी नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी में क्या कर रहे हैं ?

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पशुधन में हैं। अभी नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी चलत हे।

सभापति महोदय, मेरे हाथ में जो विषय आते जा रहा है, मैं उस विषय में बोलते जा रहा हूं और मैं जल्दी-जल्दी बोल रहा हूं। मैंने पशुधन की गौवंशी, भैंसवंशी, सबकी जनगणना को पढ़ा। लेकिन एक जनगणना में मुझे आश्चर्य हुआ कि यह पक्षी धन की जनगणना किये हैं और 01 करोड़ 87 लाख 12 हजार पक्षीधन हैं। एक बार बीरबल ने आसमान के तारे गिन लिये थे और अकबर को बता दिया था कि जहांपनाह इतने तारे हैं। उन्होंने पूछा कि तुमने कैसे गिना ? बीरबल ने कहा कि यदि आपको मेरी गिनती में शंका है तो आप गिनकर देख लीजिये। (हंसी) यह पक्षीधन की गिनती इतनी एक्यूरेट कैसे हुई ? मैं इसमें थोड़ा आश्चर्यचकित हूं। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ होगा। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मामा जी, मैंने कहा न कि आपने प्रशासन को नूरजहां की खनकती आवाज में चलाने की जो प्रैक्टिस डाल दी है, इसलिये कुछ भी लिखा जा सकता है। यह छत्तीसगढ़ में कुछ भी संभव है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सभापति महोदय, यहां का बीरबल कौन है, यह भी बता दीजिये ?

श्री रामकुमार यादव :- साहब, मोदी जी जो बघुवा लाये हे, ओ हा मरे जात हे। आप ओखरों भी तो देख लेव।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं इसमें दो-चार सुझाव देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। छत्तीसगढ़ में जो ब्रीडिंग पॉलिसी है, जो पशु प्रजनन नीति है, मैं उस समिति में था। मैंने पशु प्रजनन नीति में कुछ सुझाव दिये थे। मैं आपको बता देता हूं कि मेरे घर में करीब 100 लीटर दूध होता है। लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। हमारे जो देशी नस्ल के जानवर हैं, हम यहां के मौसम के हिसाब से कौन से नस्ल में उनको परिवर्तित करें और उसके लिये पैसे हो ताकि एक अच्छा कार्यक्रम चले और जो एलाईट सेक्टर है, जिसमें मोदी जी ने कृषकों की आय को दुगुना करने की बात कही है। उसके कांग्रेसी यह समझ लेते हैं कि वह धान खरीदी से ही दुगुनी होगी और रबी फसल खरीदने की घोषणा कर दिये और एलाईट सेक्टर में कृषि का दर्जा दिये। कृषि के दर्जे में पशुपालन को और कृषि को क्या लाभ दिये ? यह लोग एक लाभ बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। परंतु उनको ताली बजवाना है और इन लोगों को वाह-वाह करना है। मैंने कहा न कि खनकती आवाज है या डर है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप बताईये न तो।

श्री उमेश पटेल :- सुनिये तो। आप भी नस्ल सुधान समिति में थे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तत्कालीन सरकार में था। आपकी पांच साल की सरकार में कोई पालन नहीं हुआ।

श्री रामकुमार यादव :- वह जतका सांड हा किंदरथे, ओ हा तुंहर देन हे। ओकर से गांव-गांव के धरती ला पटवाथे। पूरा नस्ल सुधार ला गड़बड़ कर दे हव।

श्री उमेश पटेल :- आप भी नस्ल सुधार समिति में थे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पशु प्रजनन नीति समिति में था।

श्री उमेश पटेल :- हां, मैं वही बोल रहा हूं। आपने कितने पशुओं का नस्ल सुधार किया ? और उसमें कितना खर्च हुआ ? आपको याद है ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- यह नस्ल सुधार करने जायेंगे तो अपराध कर देंगे। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं यह बता देता हूं कि मैं नस्ल सुधार समिति में नहीं था और मैं पशु प्रजनन नीति समिति में भी नहीं था। एक बार केबिनेट में यह विषय आया था तो मैंने कुछ दिन रूकवा दिया कि रूकिये मैं कुछ सुझाव बनाकर, लिखकर दूंगा। फिर मैंने दूसरी केबिनेट में बनाकर, लिखकर दिया। मैं उसमें विधिवत् सदस्य नहीं था।

श्री उमेश पटेल :- उस समय बृजमोहन जी भी थे न ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हां थे।

श्री उमेश पटेल :- उनका डर अब समझ में आ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, दूसरा, छत्तीसगढ़ में नस्ल सुधार के कार्यक्रम के अतिरिक्त जो फोडर डेव्हलपमेंट, चारा विकास का कार्यक्रम है। चारा विकास के लिये कोई नीति कार्यक्रम नहीं है। यदि हम एलाईट सेक्टर को प्राथमिकता देते हैं, दूध उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं । इसी तरह आपने भेड़-बकरी नस्ल की भी गिनती कराई है परंतु उसके उत्तम नस्ल की ब्रीडिंग के लिये छत्तीसगढ़ में कोई व्यवस्था नहीं है। यह नये क्षेत्रों की चीज है। नई नस्ल, नई चीजें बाजार में आ रही है। यदि छत्तीसगढ़ विकसित भारत में अपनी भूमिका निभाना चाहता है तो आदिवासी बंधु या जो लोग भेड़-बकरी पालन करते हैं, आप उनके लिये नई नस्लों की ब्रीडिंग करवाईये ताकि वह भेड-बकरियों की नई नस्लें पायें। छत्तीसगढ़ में उसकी व्यवस्था ही नहीं है। चौथी बात यह है कि पशु चिकित्सा ग्राऊण्ड लेवल में, गांव में जीरो है। में हा गलत बोलत हव कि सही बोलत हव ? ए मा हव बोल देवव न या आलोचना करव। उसकी भर्ती, उसके इक्विपमेंट या दवाई, जो भी चीजें हैं, उसमें आप ध्यान दीजियेगा।

सभापति महोदय, वैसे तो मैं कुरूद के बारे में कभी बोलता नहीं हूं लेकिन आज एक लाईन बोल देता हूं। मैं 15-20 सालों से लगा हूं। सभापति महोदय, यदि आपकी नज़र-ए-इनायत हो जायेगी तो बड़ी कृपा हो जायेगी। मेरे लिए एलाईट सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है मैं उद्यानिकी, धान की भी खेती करता हूँ। मैंने दूध उत्पादन के बारे में बताया। मैं कभी आपको तीनों, चारों जगह में ले चलूंगा। मैंने कुरूद में नक्शा बनाकर, सब करके दिया कि वहां यह मिल्क रूट बनाना है और वहां पर मिल्क रूट बनाकर, एक चिलिंग प्लांट स्थापित करना है। तो मैंने एक बार उसे बनाकर दिया तो माननीय मंत्री महोदय जी अपने क्षेत्र में उसे ले गये । आप इसको मेरे क्षेत्र में एज इट इज बनाईये। जैसे बिलासा बाई केविटन पुरस्कार दे दिया, यह वैसा ही है। अभी जब मैंने यह मांग की तो इन लोगों ने 5 सालों में कुछ नहीं दिया। मान लीजिए कि माननीय बृजमोहन जी थे, माननीय अरूण साव जी थे। तो उन्होंने केवल दो जगहों, दो गांवों एक गातापार और एक सेमरा में प्लांट लगा दिया। ऐसा नहीं है। उसके लिए समितियां गठित हों, एकत्रीकरण हो और एकत्र होकर एक जगह जाएं और वहां पर चिलिंग प्लांट बने फिर चिलिंग प्लांट से देवभोग जाए। साहब, मैंने ही यह देवभोग नाम रखा था। यह हमारा क्षेत्र भी है और देवताओं के भोग की चीज है। जब हम मध्यप्रदेश के सांची से अलग हुए तो हमारे ब्राण्ड का नाम देवभोग रखेंगे, यह मेरा रखा हुआ नाम है। आप से अनुरोध करता हूँ कि आप हर बार पुन्नूलाल जी के मुंगेली को क्या-क्या बहुत सारा मान लेते हैं। वहां पर एक मिल्क रूट के साथ, चिलिंग प्लांट लगे। इसके लिए नई समिति गठित हो, जब यहां आप खड़े होंगे तो आप इसकी घोषणा कर दीजिएगा। मैं अभी तक पहली बार बोल रहा हूँ। यह 25 वां साल लग रहा है। मैंने अपने संसदीय कार्यकाल में पहली बार "कुरूद" नाम के शब्द का उपयोग किया। मैं कुरूद के लिए कुछ मांगता ही नहीं हूँ और मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ।

सभापति महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, आप समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, साहब, आप ऊर्जा विभाग में किसानों को छूट दे रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है जो कम पैसा है, लेकिन यहां पम्पों के ऊर्जीकरण के लिए पर्याप्त पैसे रहे। उस समय एक लाख से 11 हजार से ज्यादा के क्यू थे। कांग्रेस के शासन में वहां 55 हजार पंप इसलिए नहीं लग पाये क्योंकि बजट में उनको ऊर्जीकरण के लिए पैसे नहीं थे। यदि किसान के हाथ में ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित सिंचाई है तो आप यह जान लीजिए...।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भांजा जी, ए प्रदेश मा किसान के धान मरत हे। आप बिजली कटौती बर भी थोड़ा निवेदन कर देतेव। आपके निवेदन ला मान लिही।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बोलत हौं। तें पूरा ला तो पूरा सुन लें। में एको कनिक नइ छिपाववं।

माननीय सभापति महोदय, यहां ऊर्जीकरण की जो बात होगी, यदि यहां सुनिश्चित सिंचाई से रकबा बढ़ता है तो आप फसल चक्र परिवर्तन की बात कर सकते हैं । अगर इस प्रदेश में धान खरीदी कम होगी तो हमारा राजस्व बचेगा और अगर यहां राजस्व बचेगा तो हम प्राथमिक क्षेत्रों में व्यय कर पायेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस प्रदेश में पम्पों के ऊर्जीकरण के लिए पर्याप्त पैसे दें। पिछला जो बकाया है, जो कांग्रेस शासन ने नहीं दिया। यह लोग नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी से बाहर ही नहीं निकल पाये तो क्या करेंगे। यह लोग केवल धान खरीदी करते हैं। यह नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी करते हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया:- आप भी तो नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी से नहीं निकल पा रहे हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप ऊर्जीकरण के लिए दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आप नरवा, गरूआ, घुरवा, बाड़ी के बारे में इतना बोलते हैं। आप उसका विकल्प तो प्रस्तुत करें । 5 साल हो गये, हम आपसे मांगते रह गये कि आप उसका विकल्प बताईये, आपने कभी नहीं बताया।

सभापति महोदय :- माननीय उमेश जी, उन्हें बोलने दीजिए। आप ज्यादा टोका-टाकी न करें। अभी बहुत सारे सदस्य हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुमन टोकहूं तहान बहुत देर हो गे कहिके।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार से मिलकर आर.डी.एस.एस. में जो काम कर रहे हैं। वह बहुत ही अच्छा है। यहां बिजली सुधार होगा। आप इसे तेजी से लाएं। मैं आपको दूसरी दो तीन चीजें कह दूं। यदि हम उन्नत प्रदेश, उन्नत भारत बनते हैं तो यहां पर 24X7 की सप्लाई हो। यदि वास्तव में किसानों की बिजली कटौती हो रही है, यह रबी का सीजन है। दूसरा, लो वोल्टेज के लिए आप जो सुधार कर रहे हैं उसमें तेजी आए। आप लोगों के सुझाव भी लें और यहां एक कार्ययोजना बने। यदि यहां पर उस कार्ययोजना के हिसाब से लो वोल्टेज की समस्या दूर होती है यदि बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होते हैं तो उद्योग, कृषि से लेकर सर्विस सेक्टर, चाहे होटल हो या बड़े मैदान हों, वहां आयोजन हो, सबके लिए अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम् संकीर्णताओं से उठकर, रायपुर हमारा शहर है और

हम सब की राजधानी है । आज भी स्थिति यह है कि यदि कभी एक बार झोंका आया तो यहां लाईट गोल हो जाती है। यहां पर कहां-कहां पर निम्न दाब है, यहां कहां पर लो वोल्टेज की समस्या है, कितने ट्रांसफार्मरों की जरूरत है, कितने सब स्टेशन की जरूरत है, चाहे 132 के.व्ही. की जरूरत है या 440 के.व्ही. की जरूरत है या यहां लाईन को अण्डर ग्राउण्ड करने की जरूरत है । मैंने जब अधिकारियों से यह पूछा तो इसके लिए हमें कम से कम 200 करोड़ रूपये चाहिए। यहां रायपुर शहर के दो विधायक महोदय सुन रहे हैं इसके लिए बजट में 1 रूपये भी नहीं है। रायपुर शहर की बिजली व्यवस्था को भारत, दिल्ली या विश्व स्तर कहें। इस जुड़वा शहर, नया रायपुर और रायपुर की बिजली व्यवस्था को आज उस स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। किसानों के लिए जो कर रहे हैं, उत्पादन का जो गैप है, आपका लगभग 37 प्रतिशत गैप है। यदि 37 प्रतिशत का गैप है और वह यदि आप सेन्ट्रल सेक्टर की बिजली से करते हैं, तब तो अच्छी बात है। यदि हो जाता है तो कटौती नहीं होनी चाहिए। यदि गैप को कम करने के लिए, लारा-2 का शिलान्यास हुआ है तो अपनी कोई योजना लाते हैं, हम तेजी से विकसित होने वाले राज्य हैं, बिजली जो सबसे जरूरत वाली चीजें हैं, उसके उत्पादन में हम कम से कम सरप्लस रहें। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बना, आज यदि प्रति व्यक्ति यूनिट की खपत को देखेंगे तो 04 गुना खपत हो चुकी है, पर बिजली का उत्पादन चार गुना नहीं हुआ है। मैं व्यक्ति का उत्पादन बोल रहा हूं। उद्योग का, सेवा क्षेत्र का, दूसरे क्षेत्रों का बाटेंगे, वह अलग है। दूसरी बात आपसे एक छोटी सी मांग यह है हम कहते हैं कि टेरिफ की दर आयोग तय करती है। लेकिन आप दो चीजों के लिए एक तो मंदिरों का टेरिफ और दूसरा राजनीतिक दल के कार्यालय का टेरिफ के लिए सरकार की ओर से प्रस्ताव जाना चाहिए कि इसकी जो टेरिफ की दर है, वह व्यवसायिक दर पर न लगें, मंदिरों के लिए, राजनीतिक दल के कार्यालय के लिए एक अलग टेरिफ बनाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इलेक्ट्रानिक सूचना प्रौद्योगिकी, आपने आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेस बढ़ाने के लिए बजट में 266 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। भारत नेट परियोजना के तहत 5804 पंचायतों के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखे हैं। भारत नेट परियोजना में मेरा प्रश्न कई वर्षों से लगता है। यह हरि अनंत हरि कथा अनंता है। यह परियोजना कब से शुरू हुई है, कब पूरी होगी, इसको कोई नहीं जानता। उसको कितनी बार एक्सटेंशन दिया गया, यह पूछो तो अधिकारी घूमा-घूमा कर जवाब देंगे। उसकी 200 करोड़ रुपये की पेनाल्टी बिना अनुमति के वापस कर दी गई। आपने पी.एम. वाणी योजना के हॉट-स्पॉट, वाई-फाई लगाने के लिए बजट में प्रावधान रखा है। हॉट-स्पॉट को परिभाषित कैसे करेंगे? योजना में लिखे तो जरूर हैं, हॉट-स्पॉट वैसे तो नहीं होगा जो खनकतीदार आवास है, आपको इस पैसे से पैरा खरीदना है तो खनकतीदार आवाज का फोन आयेगा कि हॉट-स्पॉट जेल है, हमको जेल में वाई-फाई की सुविधा दो तो जेल में वाई-फाई की सुविधा हो जायेगी। इसको थोड़ा क्लीयरीफाई किया जाये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहत हवं कि मोला अच्छा तब लगतिस, जैसे सरकारी कंपनी के जो टॉवर है, ओला जगह-जगह तुमन प्राइवेट के टॉवर लगा थौ, जियो के टॉवर गांव-गांव में लगावत हे, आप सरकारी खोला, सरकार के तंत्र ला आगे बढ़ावा, ओखर के लिए कुछ बोला न भैया।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा बोलन तो दे। मैं मछलीपालन भर में नई बोलवं न, आगे भी बोलहूं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप ला मछली पालन से तकलीफ हे का ?

सभापति महोदय :- निषाद जी, आपने समय लिया है, आप बोल चुके हैं। माननीय अजय चन्द्राकर जी को बोलने दीजिए, अजय जी, कृपया जल्दी समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, चिप्स को इस कार्य प्रणाली से मुक्त करना पड़ेगा। आरीडोंगरी में फलाना भरेगा, बाकी नहीं भरेंगे। यदि ऑफलाईन करना है तो ऑफलाईन कर दो, ऑनलाईन करना है तो ऑनलाईन कर दो। पैसा वसूली हो गई, उसका बिल भुगतान करना है तो सर्वर डाउन हो गया। राइस मिलर्स को यदि धान देना है तो कार्यालय रात को 12.00 बजे खुल जायेंगे, उसको एलाट करने के लिए जिसका पैसा मिल गया। यह बोलते हैं कि ऑनलाईन भुगतान होता है, तीन-तीन साल तक ऑनलाईन भुगतान नहीं हो रहा है। आरीडोंगरी एक उदाहरण बता दिया। उस दिन घोषणा की अब नीलामी ऑनलाईन होगी। पिछली सरकार ने क्या उत्तर दिया था, ऑफलाईन करने से इनकम बढ़ी और उससे 05 साल में क्या इनकम बढ़ी है यह नहीं बता पाये। ऑनलाईन का मतलब ऑनलाईन होता है, वह राजनीतिक कारण से नहीं होता। पारदर्शिता आज की जरूरत है। वही सरकार सही मानी जाती है जो पारदर्शी होती है। प्रक्रियाओं में यदि इस तरह की चीजें दिखती हैं तो आरीडोंगरी साबित हो चुका है। लेकिन भूपेश बघेल जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं, अपने मित्रों को, संवैधानेत्तर सत्ताओं को ऐसा सरंक्षण दिया, ऐसे-ऐसे कामों में लगाया, आप समझ रहे हैं न, कोई जेल में है, कोई बेल में है, कोई फरार है। समझ गयेस न मामा (माननीय सदस्य श्री द्वारिकाधीश यादव को संबोधित करते हुए) दो-तीन जन हमर पुराना विधायक साथी मन भी चेपट में हैं, तय बांच गयेस मामा, अच्छा होईस, मोर पुण्य प्रताप हे, तैहां भांजा के आशीर्वाद में बाचे हस। नई जोय रहितस तहूं हां। बहुत कूदत रहेस। माननीय सभापति महोदय, यह टैबलेट खरीदे हैं, उसमें 90 प्रतिशत टैबलेट बंद हैं। आप टैबलेट खरीदी की जांच करवा लीजिये। आप जैम पोर्टल की पूरी खरीदी की जांच करवा लीजिये। मतलब जो चिप्स है ..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके समय का मोबाईल तो फट जाता था।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर नाम बोले बर हावय? मैं अभी ओला बोले हौ। मैं बोलहूं तेखर खंडन बर तैं लिख कर रखे रइबे। निषाद राज ला अउ मौका देवाहौ कइके ओला आग्रह करे रहेओ। निषाद राज अउ मोर गांव एके गांव हे। ओला पूछ लें।

सभापति महोदय :- अजय चन्द्राकर जी, समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चहता हूं कि यह संस्था जिन कामों के लिए बनी थी, यह पांच साल में अपने उद्देश्यों से भट गई और करप्शन में सहायक बनी, लेटलतीफी में सहायक बनी, किसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता को पूरा करने में सहायता बनी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पारदर्शिता लाने में, चिप्स को ठीक करने में, Connectivity बढ़ाने में सहयोग करें और अभी इस विधान सभा से निकलकर मंदिर हसौद से रायपुर जायेंगे तो बीच में टावर नहीं पकड़ेगा। जितने टावर लगने हैं, वह लगा दीजिये। मेरे ख्याल से चिप्स ही स्टार्टअप की नीति बनाती है। छत्तीसगढ़ की स्टार्टअप की क्या नीति है? माननीय भूपेश बघेल जी ने पांच साल में एक रूपये के एक स्टार्टअप को वित्त पोषण नहीं किया। पांच साल तक जब ऐसी बातें होती थी तब लखेश्वर बघेल जी ऐसे ही सोने लगते थे, जैसे वह अभी सो रहे हैं। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आपके भाषण को मुख्यमंत्री जी नहीं सुन पायें।

श्री अजय चन्द्राकर :- मत सुने न। मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही है।

श्री उमेश पटेल :- आपकी तरफ न सभापति दे जी देख पा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी आपकी तरफ नहीं देख पा रहे हैं। लखेश्वर बघेल जी अपने सर को नीचे कर लिये हैं। अब सोच लीजिये कि आपके भाशण में क्या चल रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- ये हर तुमन ला चिंतन करत हे, मनन करत हे। अइसनहे नई बइठे हे। सोए हे कइके फोन कर दे न। अभी रहा तो, ये हर अपन त्रिनेत्र ला खोलही। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- वह देखिये। माननीय मंत्री जी सो रहे हैं।

सभापति महोदय :- अजय जी, आप बोल रहे हैं और बहुत लोग सो रहे हैं, इसलिए आप समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मेरा भाषण ही वैसी है।

श्री उमेश पटेल :- अब तो सभापति जी ने ही कह दिया कि आपके भाषण में सारे लोग सो रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- साहब, ओ हर सोए नइ हे। ओकर भाषण ला देख कर ओहा चित्त पड़ गे हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वास्तव में पांच साल में एक भी स्टार्टअप को वित्त पोषण नहीं हुआ। इसलिए स्टार्टअप की नीति बने। भिलाई में एक कमरा लिये थे, उसका किराया भर चिप्स पटा रही है। नगर निगम के बिल्डिंग को लिये हैं तो नगर निगम को किराया देते हैं। ई-पार्क बनाने के लिए भी नहीं मालूम की वह पार्क कब बनेगा, कैसे बनेगा? उसका कुछ नहीं मालूम। यह स्थिति है। दूसरी बात, कुटीर उद्योग के संबंध में है। बृजमोहन जी उस बात के गवाह हैं, राजेश मूणत जी उस बात के गवाह है। हम लोग पुरानी केबिनेट में थे। कुटीर उद्योग की नीति बनाने के लिए आग्रह किया

गया। उस कमेटी में मुझसे भी सुझाव लिया गया, क्योंकि यह प्रस्ताव मेरा था। छत्तीसगढ़ में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना लांच की कि हम 3 लाख रूपये तक उनको वित्तीय समावेशन करेंगे। ठीक है कि आप वित्तीय समावेशन करेंगे, वहां तक तो व्यवस्था हो गई, लेकिन लोहार को यदि कोयला और लोहा चाहिए तो उसको कहां से मिलेगा? बांस की क्या स्थिति है? वह उसको कहां से मिलेगा ? डोकरा शिल्प के कुम्हारों को माटी चाहिए और चॉल्क चाहिए तो उसको हम मुफ्त में देते हैं, उसके बाद जो ट्रेनिंग चाहिए। एक बार कलकत्ता से कलाकार बुलवाया था, उनके लिए अलग-अलग तरीके के बनाये। इनके लिए यह व्यापक नीति बने। उनको वित्तीय समावेशन तो मिल गया। वित्तीय समावेशन में भी उन 18 लोगों में छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से विषय छूटे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना में 18 लोगों को कहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थितियों से यदि 25 लोग होते हैं तो 7 लोगों के लिए राज्य से योजना बननी चाहिए कि हम यह 7 लोगों को और जोड़ेंगे और उसके बाद उनके लिए कच्चे माल की, बाजार की, व्यवसाय की व्यवस्था हो और साथ में रूरल डेव्हलमेंट की, चिप्स की ग्रामीण उद्योग से ऐसे लोगों के लिए शहरी क्षेत्र में दुकानों का आरक्षण हो। जैसे पूर्व सैनिकों के लिए, दिव्यांगों के लिए और किसी के लिए आरक्षण करते हैं तो ऐसे कुटीर उद्योग के लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स में दुकानों का आरक्षण होना चाहिए। वह रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या भिलाई में जितने पैसों में शहरी क्षेत्रों में दुकान बिकते हैं, वह जीवन में नहीं खरीद सकते। वर्ष 2018-2019 में बुनकरों की आय लगभग जो 67 करोड़ रूपये थी।

समय :

2.25 बजे

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेंडी) पीठासीन हुईं)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ निवेदन करूं ?

सभापति महोदय :- जी ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आज की कार्यसूची में माननीय विष्णुदेव साय जी की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिये 3 घंटे निर्धारित हैं । एक घंटे से यह महाशय बोले जा रहे हैं । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- क्या आप व्यवस्था देने लगे हैं ?

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं-नहीं । महाराज, मैं व्यवस्था नहीं दे रहा हूं । मैं आपसे व्यवस्था चाह रहा हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- तो फिर आपके बोलने का मतलब क्या हुआ ? साहब, यदि आसंदी मुझे कहेगी तो मैं बैठ जाउंगा ।

डॉ. चरणदास महंत :- आपके दूसरे सदस्य बोलेंगे या नहीं बोलेंगे ? या हम लोग बोलना बंद करवा दें, आप कुछ तो करिये । आपकी ही सरकार है, आप कितनी गाली देंगे ? हमारी सरकार में गाली देते थे तो चलता था । अब कहां से नूरजहां ले आये, कौन नूरजहां है ? आप कुछ तो बता दीजिये कि किसकी खनकती आवाज है ?

श्री अजय चंद्राकर :- यह बता देता हूं । आप शौकीन आदमी हैं, आपने बोला तो मैं जरूर बताउंगा ।

श्री राजेश मूणत :- अजय जी, अब नेता जी की भी इच्छा जागरूक हो गयी है कि नूरजहां कौन है ।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं-नहीं, ये एक घंटे से बोले जा रहे हैं । माननीय सभापति महोदय जी भी थककर चले गये, इनको बुलाया । अध्यक्ष जी को तो पहले ही पता था कि एक घंटे से पहले छोंड़ेगे नहीं । मान जाओ भैया, बंद करो ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपके अमूल्य सुझाव को मान लेता हूं । मैं जल्दी खत्म कर देता हूं । माननीय सभापति महोदय, बुनकर लोगों की आय वर्ष 2018-19 में 67.87 करोड़ थी वह वर्ष 2021-22 में 44 करोड़ आ गयी और वर्ष 2020-21 में 29 करोड़ रूपये थी । गरीबों के साथ, बुनकरों के साथ आपकी दृष्टि क्या थी, यह प्रतिवेदन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं । अब आप मत पढ़ो बोलते हैं तो मैं नहीं पढ़ता भई । खादी उत्पादन में कारीगरों की संख्या घट रही है, बांस शिल्प में घट रही है, हस्तशिल्प में घट रही है इसको संरक्षण की जरूरत है । बुनकर समितियां इसलिये अक्रियाशील हो रही हैं कि उनको कच्चा धागा मिल नहीं रहा है । (माननीय सदस्य, श्री कवासी लखमा जी के सदन में प्रवेश करने पर) माननीय कवासी लखमा जी हमारे बीच में आये हैं उनकी तबीयत खराब थी । हम लोग उनके स्वास्थ्य लाभ की, दीर्घ जीवन की कामना करते हैं । (मेजों की थपथपाहट) मैं राजस्व विभाग में कुछ नहीं बोलता । माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पुनर्वास है तो पुनर्वास में एक पत्ता है । ले-देकर यह प्रतिवेदन मुझको मिला है । माना कि कुछ घटनाओं का उल्लेख है, वहीं ऑफिस है तो एकाध दिन माना जाकर पुनर्वास में घूमकर आ जायेंगे । आपके साथ चल देंगे । आपने कहा ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य जल्दी करेंगे ।

डॉ. चरणदास महंत :- जो बचा हुआ है उसको मेरे लिये छोड़ दीजिये । मैं भी पहली बार बोलूंगा । आप जो-जो लेकर आये हैं वह मुझे दे दो, मैं बोल देता हूं । दादा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं । मेरे हाथ में जो आ रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं । मैं जल्दी खत्म कर देता हूं । ताली बजाने के लिये इन लोगों ने इतना काम किया और सुनने का इतना काम किया जिसकी हद नहीं है । मैं परिवहन विभाग में बोल रहा हूं । छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं । मेरा 139 है, मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि मेरे 139 को स्वीकृत कर लें । आज के पेपर में है कि रायपुर के 2 हाटस्पॉट

ठीक हुए तो 4 हाटस्पॉट और बढ़ गये करके । चूंकि मैं रायपुर में पला-बढ़ा हूं इसलिये इन विधायकों जैसे मैं भी इस शहर को प्रेम करता हूं। मैं यही पढ़ा हूं लेकिन उसके लिये प्रदेश में कोई परिवहन विभाग कहीं पर ओवरलोडिंग की जांच तो नहीं करेगा । परिवहन विभाग का इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईविंग एण्ड ट्रैफिक रिसर्च नया रायपुर आज तक शुरू नहीं हुआ । जब उसकी घोषणा विधानसभा में की गयी तो इतने टेबल ठोके गये, इतने बजाये गये जैसे छत्तीसगढ़ बदल गया, दुर्घटनारहित हो गया और ओवरलोडिंग बंद हो गयी तो गाड़ियों के फिटनेस, ड्राईवरों के फिटनेस, ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ जीरो, परिवहन विभाग को सुधारने की जरूरत है । विष्णु अवतार इसीलिये हुआ है । साहब, मैंने इसको इतने में ही खत्म कर दिया अब विमानन बचा है । मैं एक-दो विभागों को छोड़ दूंगा । मैं जब विमानन में शुरू कर रहा था तो विमानन उद्योग विभाग का एक ही काम था । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, रेगुलर फ्लाईट से आपके तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार यात्रा की थी उसको बता दीजियेगा और आपने कितनी बार कितने करोड़ रूपये केवल विमान किराये में व्यय किये ? माने लग्जीरियस जिसको बोलते हैं न । जेला हमन कथन न कि जेला पूरा अपन जिंदगी के मजा लेना हे । हवई जहाज मा उड़-उड़के पूरा जिंदगी के मजा लिस हे । कम से कम एकाध झन ला लटका लेतिस । ऊपर में रामकुमार ला चढ़ा लेतिस । माननीय सभापति महोदय, इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है । मैं 2-3 बातें ही कहूंगा । विभाग को यह प्रयत्न करना चाहिए कि रायपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा बने । उसमें जो-जो कमी है और राज्य सरकार की ओर से उसमें जो योगदान हो सकते हैं, वह योगदान जरूर करने चाहिए । रायपुर में निर्यातकों के लिये कोई सुविधा नहीं है, समुद्र तल हमारे पास नहीं है । विशाखापट्टनम सड़क बन रही है, मेरे क्षेत्र से ही शुरू हो रही थी, बाद में उसको रायपुर से शुरू किया गया । ड्राई एयरपोर्ट की तरह रायपुर विमानतल को हम शुरू करें। छत्तीसगढ़ की इकानॉमी को यदि मजबूत करना है तो ड्राई एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। कार्गो का संचालन नियमित हो। निर्यात की जो संभावनाएं हैं, तब बढ़ेंगी। आयात-निर्यात hospitality सेक्टर का एक बड़ा विषय है। निर्यात करने का, आयात करने का लाइसेंस छत्तीसगढ़ में एकाध दो लोगों के पास होगा, वो भी मेरे ख्याल से चावल का होगा। और भी जो चीजें मैं बस्तर के बेलमेटल का, कोसा का निर्यात करना चाहता हूं, आपके चांपा-जांजगीर का या किसी अच्छी चीज को भेजना चाहता हूं, फर्नीचर जो बन रहे हैं, उसको भेजना चाहता हूं। तो इसके लिए न कोई प्रशिक्षण है, न कोई इंस्टीट्यूट है। यह आगे तब आयेगा जब इसकी सुविधा हमें मिलेगी। तो ड्राई एयरपोर्ट के लिए भी क्या किया जा सकता है ? 10 जिले में लगभग एयरपोर्ट हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में केवल दंतेवाड़ा में एयरपोर्ट नहीं है। जशपुर में हो गया, रायगढ़ में हो गया, भले वह प्राइवेट स्ट्रिप हो, अंबिकापुर में हो गया तो अंबिकापुर के स्ट्रिप को बिलासपुर का जो हवाई अड्डा है वह नियमित संचालन के लायक बड़े विमानों के उतरने के लायक बने। इसके लिए भी राज्य सरकार जो सहयोग दे सकती है, उसे देना चाहिए। अंबिकापुर में हमारे छोटे विमान कम से कम उतर जाये, इस स्तर का वह हवाई अड्डा बने। ये कोशिश हम सबको

मिलकर करनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से यह बोलता हूं, आग्रह करता हूं और अंत में मैं पुन्नूलाल मोहले जी की तरफ से एक आग्रह कर देता हूं। वे बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मैं नहीं जानता। मुंगेली में हो सकता है तो एक हवाई अड्डा बनाना चाहिए। उसी की कमी है, बाकी सब हो गया है। राम विचार जी की तरफ से बोल देता हूं। सनावल में बहुत सारी चीजों की घोषणा हुई थी तो बलरापुर के हवाई अड्डा को भी अच्छे हवाई जहाज के लायक बना दें। सक्ती में भी है क्या साहब? आपकी ओर से बोल देता हूं। अब समाप्ति की ओर हूं। आप आये और मैं समाप्त कर रहा हूं न।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं सक्ती में बनाने का निवेदन दे चुका हूं। आपके साथ-साथ मैं यह बोल देता हूं कम से कम एकाध हेलीकॉप्टर खरीद लें। एकाध जहाज खरीद लें, जो इनके हाथ में है। फिर उसमें परसेंटेज का भी मामला है। ये बाकी चीज से कुछ नहीं मिलने वाला, जो आप छत्तीसगढ़ को सपने दिखा रहे हैं न।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सपने दिखा नहीं रहा हूं। मैं तो मांग कर रहा हूं। इस ओर सोचना चाहिए, कह रहा हूं।

सभापति महोदय :- आप जल्दी समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तो इसे छोड़ दिया है। ये है तो भी नहीं देख रहा हूं। एक ठोक रखा है, ऐसा रख दिया। ये खाली हाथ हो गया। मैंने जितने विभागों में बातचीत की है, मैं जानता था कि समय की एक सीमा है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है तो सबसे जो जरूरी काम है वह प्रशासन के मनोबल को बढ़ाना और यदि प्रशासन का मनोबल बढ़ गया, हमने उसे सही कामों के लिए संरक्षण देना शुरू किया, गलत कामों के लिए प्रोत्साहित करना बंद किया, ठेका पद्धति के शासन को जीरो किया कि कलेक्टर, एस.पी. बनने के लिए भी पैसे लिये जाते थे, हमने अपने राजनीतिक जीवनकाल में पहली बार सुना, 15 साल सत्तारूद्ध में रहे भी, हम ईमानदारी से बोल रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो ये चीजें समाप्त होकर प्रशासन की इतनी उच्च प्रतिभाएं यदि काम करेंगी, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नीतियां बनाएंगी तो चाहे वह ऊर्जा का क्षेत्र हो, विमानन का क्षेत्र हो, कुटीर उद्योग का क्षेत्र हो, हस्तशिल्प हो, चाहे वह मछली पालन हो या एलाइड सेक्टर के जो भी विषय हों, सब आप ही आप उठने लगेंगे। इसलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ को इस रसातल से उठाकर स्थापित करने के लिए ही विष्णु का बराह अवतार हुआ है, अच्छा प्रशासन, अच्छा शासन छत्तीसगढ़ को मिलेगा। सब अच्छी चीजें मिलेंगी, इस अपेक्षा के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष के सुझाव को स्वीकार करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- श्रीमती संगीता सिन्हा।

डॉ. चरण दास महंत :- सभापति जी, एक मिनट, ये शासन के मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं। इनका भाषण सुनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं हैं। सिर्फ 4 मंत्री बैठे हुए हैं। मंत्री ही यहां नहीं आयेंगे, मुख्यमंत्री यहां नहीं आयेंगे तो मनोबल कैसे बढ़ेगा प्रभु?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तो प्रशासन के मनोबल को कहा। शासन का नहीं कहा।

डॉ. चरण दास महंत :- प्रशासन के मनोबल को चढ़ाओगे। फिर कहोगे कि रिमोट कंट्रोल से चल रही है। प्रशासन के मनोबल को बढ़ाओगे, जिसमें मंत्री शामिल नहीं हैं, प्रशासन के कहने से आप काम करोगे तो फिर रिमोट कंट्रोल नहीं होगा?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके कहने से चले। आप भी केबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त हैं। आपके कहने से चले, नूरजहां की खनकती आवाज से न चले।

डॉ. चरण दास महंत :- मतलब, नूरजहां क्या है भाई? (हंसी)

सभापति महोदय :- आप वह बाद में पूछ लीजिएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नूरजहां शाहजहां की बीवी थी। (हंसी)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय नेता जी, शाहजहां इनके पास हैं।

श्री अजय चन्द्रकार :- नूरजहां जहांगीर की बीवी थी। एक बार सुधारकर बोल देते। (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- आप कुछ भी कहते रहो।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- संगीता जी, एक मिनट। श्री कवासी लखमा जी, सदस्य स्वास्थ्य लाभ लेकर सदन में आये हैं। संसदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए उनकी उपस्थिति का स्वागत है।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत समस्त मांगों का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं । सभापति महोदय, विष्णुदेव साय जी की सरकार है । कहां चले गए चंद्राकर जी ?

सभापति महोदय :- आप बोलिए, समय कम है, चंद्राकर जी सुन लेंगे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- विष्णुदेव साय जी की सरकार है और विष्णु भगवान से समानता व्यक्त कर रही हूं । चंद्राकर जी ने बहुत सारी बातें कही, उनकी बात सुनने से ऐसा लगा कि 100 प्रतिशत सही है । विष्णु भगवान और विष्णुदेव जी की सरकार में बहुत सारी समानता है । विष्णु भगवान के हाथ में हमेशा कमल फूल रहता है और हमारे विष्णुदेव साय जी को कमल ने ही खिलाया है ।

श्री राजेश मूणत :- वाह, आ जाओ इधर ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी हम लोग आपको इधर बुलाने की तैयारी कर रहे हैं । अभी मैंने दोनों में समानता बताई है और इसके बाद जो पेश करूंगी उससे आप लोग इधर आ जाएंगे । विष्णु

भगवान के हाथ में कमल फूल था और इन विष्णुदेव साय जी को कमल फूल ने खिलाया है । कमल फूल ने उनको ऊपर उठाया और आज सर्वोच्च पद पर आसीन है । विष्णु भगवान शेष नाग पर सोए हैं, मैं विष्णुदेव साय की सरकार को जगाना चाह रही हूं । ये सरकार अभी तक सोई है । हमारे राज्य की जनता के लिए जागिए और उठिए और अपने विराट रूप को दिखाइए।

श्री राजेश मूणत :- मोहले जी जाग गए ।

श्री उमेश पटेल :- कोई और जागे या न जागे, मोहले जी जाग गए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- विष्णु भगवान के साथ कौन थी, लक्ष्मी माता थी । उधर लक्ष्मी भी है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- लक्ष्मी भी है मैं मानने को तैयार हूं लेकिन राज्य की जनता की सेवा के लिए जागिए, अपना विराट रूप दिखाइए, आप सोए मत रहिए । शेष नाग में सोए हैं, अब जागने का समय आ गया है । समय हो चुका है, हमारे राज्य की जनता देख रही है, जागिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति जी, यह बताना जरूरी है कि शेष नाग का अवतार कौन थे, लक्ष्मण थे, लखन थे । तो यहां लखनलाल मंत्री जी भी हैं ।

सभापति महोदय :- समय कम है, टीका टिप्पणी करते रहेंगे तो देर हो जाएगी।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अजय चंद्राकर जी जब बोल रहे थे तो आप सो रहे थे । जैसे ही संगीता जी ने बोलना शुरू किया, आप हर मिनट खड़े हो रहे हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार 2019 से 2023 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारी सरकार थी और हमने सिर्फ राज्य की जनता के हित का ही काम किया है और लगातार करते रहे । मैं छठवीं विधान सभा में यह सरकार जनहित की बातें न करके सिर्फ नरवा, गरवा, घुरूवा, बारी की जांच के पीछे पड़ी हे । आप रिकॉर्ड निकालकर देख लीजिए कोई भी जनहित का काम नहीं हुआ है । यह सरकार केवल नरवा, गरवा, घुरूवा, बारी के पीछे दौड़ रही है, पिछली सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है सिर्फ जांच की मांग कर रही है।

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी, आप कह रही हैं कि जनहित का काम नहीं हुआ । महतारी वंदन योजना के लिए 12 हजार करोड़ का प्रावधान किसने किया । 18 परिवारों को मकान देने का काम किसने किया ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मूणत जी बैठेंगे, संगीता जी आप अपने विषय पर आएं ।

श्री रामकुमार यादव :- 1000 कहिके 500 रूपए मा महिला मन ला ठग दे हवव, अभी लोक सभा चुनाव में जाहू ता पता चलही ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, मुझे तो आश्चर्य तब होता है जब हमारे विद्वान साथी ने आज पूछा कि संविधान के कौन से नियम मे तहत पैरा खाए। सभापति महोदय, यह क्या है ? आपको याद होगा, रायपुर में कंटेनर से 100 गायों को पकड़ा गया, कटाई के लिए जा रही थीं । उनको पकड़ा

गया है और आनन फानन में गौठान में रखा गया है, अब उसके चारे की व्यवस्था के लिए क्या संविधान आएगा या संविधान से पूछकर उसको खाना देंगे । उनको तुरंत पैदा दिलाया जाता है और वह पैरा दान से होता है, उसमें कोई पूछकर नहीं होता है कि संविधान ने इसको खाने का नहीं दिया है तो गाय को पैरा न दिया जाए।

श्री उमेश पटेल :- संगीता जी, मैं पांच साल अजय जी से पूछता रहा कि आप गौठान का इतना विरोध करते हैं, इसका अल्टरनेटिव तो प्रस्तुत करें, आज इनकी सरकार है, आज फिर से वही बात कर रहा हूं, यह पांच साल जाने के बाद भी अल्टरनेटिव प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, 15 साल की बातों का एक-एक रिकॉर्ड है, आप कहेंगे तो मैं पटल में रखने को तैयार हूं। इन्होंने 36 हजार करोड़ की गरीबों का चावल खाया है। बहुत सारे घोटाले हैं, मैं सबको लाईन से रख दूंगी। आज महोदय जी के विभाग में चर्चा करने का विषय है।

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी, आप अच्छी बात बोल रहे हो। चावल खाया, ये खाया, वो खाया। आप पांच साल क्या कर रहे थे ? जनता ने आपको मेंडेट दिया था। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने पांच साल क्या किया? आप अभी पांच साल में आए नहीं हो। फिर दोनों वही कहानी पढ़ेंगे। अजय चंद्राकर जी आ रहे है, पुन्नूलाल मोहले जी हैं।

सभापति महोदय :- मूणत जी, उनको बोलने दीजिए, आपकी बारी आएगी तो आप अपनी बात रखिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हमने कार्य किया। हम बता रहे हैं, आप बैठिए और सुनिए। हमने क्या किया है।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, वे एक घंटा तक बोल रहे थे, वे पूरे सत्र भर पांच साल में ही अटके हैं। आप भी वही 5 साल का प्रश्न लगा रहे हैं, धरमलाल कौशिक जी भी वही 5 साल का प्रश्न लगा रहे हैं। वह चर्चा हो ही रही है, ये 15 साल की चर्चा कर रही हैं तो क्यों टेंशन ले रहे हैं।

सभापति महोदय :- संगीता जी आपको 5 मिनट हो गया। आप जल्दी समाप्त करिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हमारे अजय जी एक घंटा बोले हैं तो कम से कम हमको आधा पौन घंटा दिया जाए।

सभापति महोदय :- आपके एक साथी भी बोल चुके हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हमारे साथी ने कहा कि सभी कार्य किये हैं, मैं दिखा देना चाहती हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने जब राशि ट्रांसफर की, उसी दिन घोषणा किए कि एक लाख नौकरियां देंगे। मेरे पास इसकी कॉपी है। आज तक क्या किए ? घोषणा किए एक महीने हो गये ? कोई भी प्रावधान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। एक लाख नौकरियां देने की बात करते हैं, मेरा यह मानना है, हमारे लोगों का मानना है कि सबसे पहले रिक्त पदों को भरा जाए। यहां तो 40 प्रतिशत

नौकरी में हैं, जो पद पर हैं, बाकी तो बस ऐसे ही चल रहा है। 60 प्रतिशत रिक्त है। आप सबसे पहले रिक्त पदों को भरिए। फिर आप एक लाख लोगों की नौकरियों की घोषणा किए हैं, उसकी बात कीजिए। सबसे पहले 60 प्रतिशत रिक्त पदों को भरने का काम कीजिए। आप दंतेवाड़ा, सुकमा, सरगुजा, बालोद चाहे रायपुर देखिए, आप कहीं भी जाइये। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। वहां पर स्कूल है, टीचर नहीं हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- आदरणीय महोदया जी, तीन महीने में ही डॉक्टर, टीचर गायब हो गये। बताने के हिसाब से पांच साल में व्यवस्था पूरी थी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, जब भी हम लोग जनता की बात करते हैं, ये पीछे चले जाते हैं। आपको जनता ने चुना है, आप उस पर काम कीजिए। आप उसको करके दिखाईए।

श्रीमती भावना बोहरा :- आप उसकी चिंता मत करिए। उसके लिए महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। ढाई महीने में ही बहुत सारी योजनाएं पूरी हुई है। संगीता जी, आप चिंता मत करिए। अभी और समय दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जो जनता की मांग है, उसको करके दिखाईए। सरकार को बने इतने महीने हो गये, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, न ही धान का पैसा आया है, न 3100 रूपये मिला है। कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आज लोग देख रहे हैं, ताक रहे हैं, कब घोषणा होगी, कब पूरा होगा। आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उस पर विचार कीजिए।

श्री राजेश मूणत :- मेरी तरफ देख रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मंत्री जी नहीं हैं। (हंसी) सभापति महोदय, छात्रावास की स्थिति बहुत खराब है। वहां रातभर लाईट गोल रहता है, वहां छात्रावास अधीक्षक नहीं हैं। मैंने आज सुबह शून्यकाल में एक घटना बताई है, जैसे ही आपकी सरकार आई, सरकारी अस्पताल का क्या हाल हो गया। एक युवक जहर सेवन कर लिया है, उसको हास्पिटल में रात में भर्ती किए, उनको रात में ही पेपर थमा दिया जा रहा है, यह यहां ठीक नहीं हो सकता ले जाईए। यह आपकी सरकार है। यह सच्चाई है। वहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, प्राईवेट हॉस्पिटल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, सेटिंग चल रहा है। इसको आप ठीक कीजिए। इसमें ध्यान दीजिए। अगर सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो उसको पहले बताएं। वह गरीब लड़का है, निचले स्तर का है, वह कहां पर दौड़कर जाएगा। उसके घर वाले मरने के लिए देख रहे हैं, मेरा बेटा कब मरेगा। यह इस सरकार की स्थिति है। आदरणीय सभापति महोदय, मेरी एक राय है, इसको जरूर नोट कर लें कि जो रिक्त पद हैं, उनको पहले भरा जाएं। उनको भरकर आपने जो 1 लाख नौकरी देने का वायदा और घोषणा की है, वह 1 लाख नौकरियां आप तुरंत के तुरंत बेरोजगार साथियों को दिलाइये। जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग में आरक्षण होता है। कोई भी भर्ती होती है तो उसमें ओ.बी.सी. व महिलाओं को आरक्षण मिलता है। लोक सेवा आयोग में 30 प्रतिशत महिलाएं रहती हैं। जो आऊटसोर्सिंग को काम दिया जाता है, उसमें कोई भी आरक्षण नहीं है। आप उसमें आरक्षण दें। वहां

किसी से भी काम करवा लिया जाता है। वहां पर लोग बेरोजगार घूमते रहते हैं, हमारी महिलाएं घूमती रहती हैं और हमारे युवा साथी घूमते रहते हैं। उसको आऊटसोर्सिंग के जरिये ठेकेदार को दे दिया जाता है और वह अपने तरीके से मनमानी करके और कमाकर लोगों को कहीं भी रोजगार का अवसर नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आऊटसोर्सिंग में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए। लोक सेवा आयोग में यह नियम है। वह नियम आऊटसोर्सिंग में भी जारी किया जाना चाहिए और नियम का सरलीकरण होना चाहिए। आप आऊटसोर्सिंग के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए नियम बना दीजिए कि इसमें महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए और बाकी ओ.बी.सी. व अन्य के लिए होना चाहिए। मैं आपको विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि इसमें महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं किसानों के मोटर पम्प के बारे में कहना चाहती हूं। किसानों को मोटर पम्प के जो अस्थाई कनेक्शन दिये जाते हैं, उसमें शासन के द्वारा सुरक्षा निधि राशि के तहत् 3,800 रूपये लिये जाते हैं। उस 3,800 रूपये को उनको वापस किया जाता है। जब कनेक्शन दिया जाता है तो उसको बिल के साथ शामिल कर-करके दिया जाता है। लेकिन जो 3,800 रूपये की सुरक्षा निधि की राशि ली जाती है, उसको आज तक वापस नहीं किया गया है। 40 या 50 नहीं, बल्कि 70-80 करोड़ रूपये की राशि सरकार के पास जमा है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जनता की वह राशि जैसे पहले बिजली बिल के तहत् वापस की जाती थी, उसके जरिए उसको वापस किया जाए।

सभापति महोदय :- संगीता जी, जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, अभी तो मेरे बहुत सारे विषय शेष हैं।

सभापति महोदय :- आप जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी। सभापति महोदय, मैं जल्दी-जल्दी बोल देती हूं। जो 50 या 60 करोड़ नहीं, बल्कि 70-80 करोड़ रूपये की राशि है, शासन को जनता के उस पैसे को वापस करना चाहिए। आप उनको वापस दें और उनके खाते में डालें। चाहे आप बिजली बिल के तहत् दें या किसी भी तरीके से शामिल करके उस पैसे को वापस करें। किसानों के जो बिजली पम्प होते हैं, उसमें एक मीटर होता है। उस मीटर से वह केवल सिंचाई करते हैं। यदि उनको एक बल्ब भी लगाना है तो उसके लिए उनको अलग से मीटर लेना पड़ता है। जो संभव नहीं है। वह बहुत ही मुश्किल काम रहता है। मैं आप लोगों को ध्यान दिला देना चाहती हूं कि और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जो 1 बल्ब के लिए हैं तो यदि आप उसी में सेट कर देंगे तो उनको परेशानी नहीं होगी। यह होना चाहिए कि आप जो बिजली लेने के लिए एक मीटर ले रहे हैं, उसमें एक बल्ब जला सकते हैं। आप नियम में इसका सरलीकरण कर दीजिए। साथ में किसानों की सिंचाई के लिए पानी जाता है, उसका समय 5 से 11 रहता है। लेकिन कभी वह 6 बजे चालू होता है तो कभी 7 बजे चालू होता है तो कभी 8 बजे चालू होता है। आप पूरे

छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए समय तय कर दीजिए कि इतने से इतने बजे तक बिजली आइगी और इतने से इतने बजे तक पम्प चालू होगा। आपको पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह नियम लागू कर देना चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, मैंने एक चीज और महसूस किया है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। कल मेरे पास एक फल दुकान वाली महिला आई, उसने कहा कि उसके छत के बिल्कुल नीचे से तार गयी है। वह कपड़ा भी सूखाते हैं तो वह तार टच होती है। उसका कहना था कि मैंने ऑफिस में 4 चक्कर लगा लिये, लेकिन वह लोग पैसे की मांग करते हैं। उसमें एक राशि जमा करनी होती है। लेकिन जो गरीब तथा निचले स्तर की महिलाएं व पुरूष हैं, उनके पास उतनी राशि नहीं रहती है। वह स्वयं अपना जीवन-यापन इतनी मुश्किल से करते हैं। मेरा मंत्री जी के लिए एक राय और निवेदन भी है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अगर उनको अपना पोल चेंज करवाना है या तार बदलवाना है तो उनसे कोई राशि न ली जाये। वे बेचारे गरीब हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं तो उनसे राशि न ली जाये, यह निर्णय लेना चाहिए ।

सभापति महोदया, किसान से बिना पूछे उनके खेत में पोल लगा दिया जाता है । किसानों का खेत है तो वे रात को सोते जाते हैं, सुबह जाते हैं तो उनसे बिना पूछे उनके खेत में पोल लग जाता है । मैं निवेदन करती हूं कि जिनका खेत है, उनसे राय ले ली जाये, परमिशन ले लिया जाये तो बहुत अच्छी बात है । सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक मांग है । दरगहन ढोकला जहां बिजली की व्यवस्था अत्यंत दयनीय है और गुरूर मुख्यालय से सिर्फ तीन किलोमीटर है तो वह धानापुरी साल्हेटोला से होते हुए लगभग 10 किलोमीटर घूमकर वह लाईन गया है । लाईन जंगल क्षेत्र से घूमकर जाता है तो वहां बहुत ज्यादा परेशानी है । अगर उसको मोखा से डायरेक्टर कर दिया जाये और गुरूर से डायरेक्ट जोड़ें तो तीन किलोमीटर जुड़ जाएगा, यह मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं ।

सभापति महोदया, अभी खनिज की बात चली, उसमें चन्द्राकर जी ने बहुत सारी बात रखी, घोटाले की भी बात की । रेत खदान थोड़ा जल्दी चालू करवा दें, लोग इधर-उधर भटक रहे हैं तो रेत को आम जनता के लिए जल्दी उपलब्ध करवाईए, ताकि उनको परेशान न हो । मैं ईंट भट्ठा के बारे में भी कहना चाहूंगी । ईंट भट्ठा में अवैध कारोबार चालू हो चुका है, अवैध कारोबार चल रहा है । उस ओर ध्यान दीजिए । उनके पास अनुज्ञा है या नहीं, उनको अधिकार है या नहीं, इसकी जांच करवाईए, वह अवैध चला रहे हैं और वैसे ही ईंट भट्ठा चल रहा है ।

सभापति महोदया, मैं आर.टी.ओ. के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है । मेरा बालोद विधान सभा जो क्षेत्र है, उसमें दुर्ग उड़नदस्ता भी रहता है, जगदलपुर उड़नदस्ता भी रहता है और रायपुर उड़नदस्ता भी रहता है । इन तीनों उड़नदस्ता से हमारे क्षेत्र के लोगों को सामना करना पड़ता है । अगर दुर्ग तरफ से आये तो दुर्ग उड़नदस्ता पड़ा । फिर अंदर घूसे तो वहां जगदलपुर का उड़नदस्ता खड़ा रहता है, उसके

बाद इधर आते हैं तो रायपुर का उड़नदस्ता खड़ा रहता है । उड़नदस्ता से आम जनता को बहुत परेशानी है । आप फिक्स कर दीजिए कि इस एरिया में एक उड़नदस्ता रहेगा और वही उसकी जांच करे, यह निवेदन है । आम जनता परेशान होकर हमें फोन करते हैं । एक व्यक्ति तीन-तीन जगह रूकता है । आपसे सनम्र निवेदन है कि आप उसका ख्याल रखें, मंत्री जी को इसके बारे में जानकारी हो ।

सभापति महोदया, यह मेरी आखरी मांग है । गुरूर मुख्यालय में जो उप संभाग का कार्यालय है, उसकी स्थिति बहुत जर्जर है । हमारे यहां पूर्ववर्ती सरकार ने 40 डिसमिल जगह दी थी । आपसे निवेदन है कि कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उसको बहुत जल्द प्रारंभ किया जाये । अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो इन सबकी ओर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा । उसमें जो भी कार्य है, उसमें नियमों में सरलीकरण लाकर कार्य करें और महोदय जी की अनुदान राशि को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा । मैं अनुदान मांगों का घोर विरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं । सभापति महोदया, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदया, हमारी सरकार ने प्रशासन में अधिक कसावट के लिए दुर्ग जिले में एंटी करप्शन ब्यूरों कार्यालय की स्थापना की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । उस आर्थिक अपराध अन्वेशन ब्यूरों में 6 नवीन पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । अपर सचिव एवं अन्य पदों की भी स्वीकृति कर 140 नवीन पदों के सृजन के लिए भी स्वीकृति का प्रावधान रखा गया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदया, अगर मैं खनिज विभाग की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में खनिज की संपदा भरपूर है और इसके अंतर्गत रायपुर में कार्यालय हेतु भवन निर्माण के लिए स्वीकृति, बिलासपुर में भी कार्यालय की स्वीकृति हेतु बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाईन व्हाया मुंगेली, भू-अर्जन के लिए 245 करोड़ का प्रावधान किया गया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाईन कार्य प्रांरभ किए जाने हेतु 55 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा और उन्हें बताना भी चाहूंगा हूं कि पिछले समय भारतीय जनता पार्टी की डॉ. रमन सिंह की सरकार थी, उस समय मंत्रिमण्डल की बैठक में बिलासपुर-उसलापुर-डोंगरगढ़ व्हाया मुंगेली प्रावधान किया गया था, जिसमें 49:51 अनुपात का एम.ओ.यू. हुआ था। लेकिन मुझे इसमें डोंगरगढ़ के ऊपर शंका है। यह कटघोरा-डोंगरगढ़ की लाईन है, उसमें देखे कि व्हाया मुंगेली है या नहीं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस लाईन का सर्वे भी हो चुका है, कार्य प्रगति पर है, भू-अर्जन की प्रक्रिया चालू है, उसमें पहले से रेल लाईन के लिए जगह भी उपलब्ध है। तो इस पर ध्यान देंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। जिससे डोंगरगढ़ जाने में यात्रियों को सुविधा मिलेगी, इससे लाखों लोगों को काम भी मिलेगा। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी हो चुकी है। टेण्डर होने की

प्रक्रिया में है। आप उसको देखें, मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने उसको बदलने की कोशिश की थी। आप इस पर ध्यान देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूर्व की डॉ. रमन सिंह की सरकार थी, जिन्होंने एम.ओ.यू.भी किया, आप उसको जरूर ध्यान देंगे, ऐसी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा करता हूं। सभापति महोदय, चिरमिरी-हाल्ट रेल लाईन के लिए 120 रूपये नवीन मद में प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, मैं उर्जा विभाग के बारे में बात करूं तो 5 एच.पी. के कृषि पंपों के लिए 7,500 यूनिट तक बिजली का बिल माफ किया गया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। 6 लाख 56 हजार कृषि पंप किसानों को लाभ मिलेगा। मैं बिजली बिल हाफ योजना के बारे में बताना चाहूंगा कि 43 लाख 34 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को 4 सौ यूनिट तक वालों को हाफ बिजली योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह योजना पूर्व की सरकार की योजना थी, इससे कम लोगों में लागत भी ज्यादा आ जाता है और 4 सौ यूनिट बिजली का बिल नहीं हो सकता है। हाफ बिजली का मतलब आधा होता है। लोग समझते हैं आधा। इस सरकार ने कहा है कि हम हाफ बिजली बिल का फायदा देंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पूरा बिजली माफ के मांग कर दे ना।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी करना चाहूंगा कि 4 सौ यूनिट बिजली में जितना हाफ बिजली का है, उस बात को रखे उसको हाफ बिजली में दो। कई लोगों के यहां मीटर नहीं लगा है। मीटर नहीं लगने से अनुमान होता है कि इसने इतनी बिजली का खपत किया। तो जहां मीटर नहीं लगा है, ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है।

श्री उमेश पटेल :- ददा।

सभापति महोदय :- उमेश जी, उनको बोलने दीजिये। समय कम है। फिर आप ही लोग बोलेंगे।

श्री उमेश पटेल :- अभी तो ये स्मार्ट मीटर लगाने वाले हैं। जब स्मार्ट मीटर का टेस्टिंग हुआ तो जहां मैकेनिकल मीटर चलता है वहां 200 यूनिट बता रहा था और स्मार्ट मीटर 400 यूनिट बता रहा था।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- वह दिखा रहा था, वह अलग विषय है और मेरा विषय अलग है। 4 सौ यूनिट की जगह कम से कम 500 यूनिट हो। मैं इस कारण से बोल रहा हूं क्योंकि उपभोक्ताओं का स्लैब निर्धारित है, परन्तु उपभोक्ता बहुत लोग हैं, कई लोग दो महीने, तीन महीने तक बिल नहीं देते हैं, उन लोग गरीब आदमी हैं। वह जब तक बिजली का बिल नहीं भुगतान कर देता तब तक उसका बिल हाफ नहीं होता है। जब उपभोक्ता बिजली का बिल पटा रहा है तो उसको पत्येक माह बिजली के आधार पर उपभोक्ता से राशि ली जाये और उनसे फाइन भी ना लिया जाये, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं, जिससे आम लोगों को फायदा हो।

श्री उमेश पटेल :- हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। आप पूरा बिजली बिल हाफ करवाईये।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- मैं जितना मांग कर रहा हूं, अपने अनुसार कर रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- तै मांग दे ना बबा, तै सीनियर अस।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- सभापति महोदय, कृषि पंपों के उर्जीकरण हेतु 200 करोड़ रूपये का प्रावधान है। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। सिंचाई सुविधा के लिए सोलर पंप की स्थापना हेतु 607 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं एक और मांग करता हूं। बी.पी.एल. परिवारों को प्रति माह 30 यूनिट बिजली का बिल माफ है। इस योजना को चलते बहुत समय हो गया है। यह कम से कम 25 साल पहले की योजना है।

श्री उमेश पटेल :- दिग्विजय सिंह सरकार के समय का है।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- वही तो बता रहा हूं। यह पुरानी मांग है। इसके उपभोक्ता गांव वाले हैं, गरीब लोग हैं, बी.पी.एल. वाले हैं, वह बिल नहीं पटा पाते हैं। इसलिए उसको कम से कम 50 यूनिट किया जाये, जिससे लोगों को फायदा भी होगा। सरकार के प्रति सद्भावना भी उत्पन्न होगी, किसानों के प्रति आपकी सोच क्या है ? यह सभी के क्षेत्र के लिये है ।

श्री दिलीप सिंह लहरिया :- आप पूरा माफ का भी मांग कर दीजिए ? आदरणीय आपको धन्यवाद देंगे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, माननीय सदस्य ध्यान दें । यह 50 यूनिट होने से हो जायेगा यानी उतनी ही खपत होगी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम लोग इसका समर्थन करते हैं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप लोग मेरा समर्थन कर दो । सभापति महोदय, सौर उर्जा सिंचाई योजना में 95 करोड़ रूपया है, जिसमें सिंचित क्षेत्र के लिये 30 करोड़ का प्रावधान है । मैं इसमें सौर उर्जा के बारे में बात कहूंगा कि सौर उर्जा में लग गया और चोरी हो गयी । यदि चोरी हो गई तो उसको समय में मिलता नहीं है। जब चोरी हो गयी, एफ.आई.आर.दर्ज करेंगे, 15 दिन के अंदर उसको दूसरा पंप दें, जिससे किसानों करो पंप की सुविधा मिले । किसानों के पंपों में सिंगल कनेक्शन और आर्डिनेरी कनेक्शन दिया जाता है । जब पंप लगाया जाता है, उसे 43 हजार, 35 हजार और 25 हजार अनुदान दिया जाता है, यह छूट तब मिलता है, जब किसान पंप लगा लेता है । जब स्वीकृति है तो अस्थायी कनेक्शन की बात ही नहीं है, 6 हजार को लगेगा तो स्थायी कनेक्शन एक साथ दिया जाये । यह भावनात्मक होता है, अस्थायी और स्थायी में रहता है, इसमें चोरी का भी डर रहता है । कई लोगों के अस्थायी कनेक्शन के नाम से बिजली डायरेक्ट चलाते रहते हैं, जिससे गांव के लोगों का ट्रांसफारर्मर जल जाता है । हर समय ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है । पिछले समय की हमारी डॉ.रमन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने एक जिले में लगभग 14 से 20 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्टेपनी टाईप रखा था । जब भी आपका ट्रांसफार्मर खराब हो, तत्काल किसानों को 24 घण्टे में उपलब्ध कराया जाता था । आज की

स्थिति में ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण किसानों को काफी दिक्कतें आ रही है, मैं मुख्यमंत्री जी से फिर मांग करूंगा कि कम से कम एक जिले में 20 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर हो । ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है तो तत्काल उनको ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो । सभापति महोदय, क्षेत्र में खंबे हैं, खंबे पुराने हो चुके हैं, यह बेकार हो चुके हैं, इसमें तार बदलने की आवश्यकता है । तार के लिये अतिरिक्त राशि का प्रावधान हो। यहां 20-30 वर्षों से लगे हुये खंबे खराब हैं, टेढ़ा-मेढ़ा हो गये हैं, पारे-टोले-मुहल्ले-मजरे में खंबा लगाने की इस बजट में मांग करता हूँ । सभापति महोदय, मंदिरों में, हाई स्कूल भवन, कॉलेज, मिडिल स्कूल, ग्राम पंचायत भवन या अन्य सार्वजनिक स्थलों में वहां तक बिजली नहीं जाने के कारण, बिजली खंबे देने का प्रावधान नियम में नहीं आता है, इन सभी स्थानों के लिये बिजली खंबों की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूँ, जिससे यह सब कठिनाईयां दूर हो जाये । जहां छोटे मंदिर हैं, पुजारी नहीं है, उनमें सिंगल बत्ती कनेक्शन हो । किसी के नाम में नहीं होगा तो बिल कौन पटायेगा ? यदि मंदिर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है या आर्थिक स्थिति के कारण उनके पास पैसा नहीं है, सिंगल बत्ती के रूप में 50 या 100 बत्ती तक माफी हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ । सभापति महोदय, मैं सामान्य प्रशासन विभाग की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार में अनुसूचित जाति के लगभग 37 हजार पद रिक्त हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं और अन्य विभाग में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक सरकार रिक्त पदों का विशेष भर्ती अभियान चलाये, जिससे रिक्त पदों की पूर्ति हो जाये । सभापति महोदय, मैं परिवहन विभाग की बात करूं तो ...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, 33 हजार यूनिवर्सिटी में था और दो हजार पद भर्ती होना था, उसको जल्दी करवायेंगे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मैं परिवहन विभाग की बात करूंगा तो एक्सीडेंट हो जाता है...।

सभापति महोदया :- माननीय मोहले जी, जल्दी समाप्त करिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मैं तो अभी बात समाप्त कर दूंगा लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूं वह आम लोगों के लिये आवश्यक और गंभीर है, इस कारण मुझे बोलने दीजिये। मैं बताना चाहता हूं कि यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके परिवार वालों को 25 हजार रूपये मुआवजा राशि मिलती है। वे कितने दु:खी रहते हैं। जबकि अन्य प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर जैसे ओला गिरने पर, पाला गिरने पर, बिजली गिरने पर, करेंट लगने पर, सांप काटने पर, जलने पर, 04 लाख रूपये मुआवजा राशि की सुविधा है। जबकि एक्सीडेंट को प्राकृतिक नहीं माना जाता है। एक्सीडेंट को भी प्राकृतिक घटना मानी जाये और इसमें भी 04 लाख रूपये की मुआवजा राशि दी जाये क्योंकि यदि मृत्यु होने वाले इंसान का परिवार बेघर हो, तो उनके परिवार का क्या होगा ? उनको जो 25 हजार रूपये की मुआवजा राशि दी जाती है, वह दो महीनों तक मिलती ही नहीं। जब तक एस.डी.ओ., तहसीलदार लिखकर

नहीं देंगे, जब तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होगी, यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने पर ही मुआवजा राशि मिलती है। उसके लिये तत्कालिक रूप से कलेक्टर मद में पर्याप्त राशि दी जाये जिससे मृत इंसान के परिवार को तत्काल सुविधा मिले। दूसरा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पिछले समय गया था तो मैंने उनसे मांग की थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं जरूर घोषणा करूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि मुंगेली जिले के कनतेली में एक कॉलेज खोला जाये और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करें।

सभापति महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ग्रामोद्योग विभाग भी है । गावों में पर्याप्त मात्रा में उद्योग खोलने के दो प्रकार है । एक, बुनकरों के लिये और दूसरा, रेशम बनाने वालों के लिये, कुटीर उद्योग, हाथकरघा उद्योग और शिल्प कला उद्योग है, इन शिल्पकला उद्योग के लिये अनुदान राशि दी जाये। गांव का बाजार हो, शहर में भी बाजार हो, जैसे रायपुर में तत्कालीन मंत्री ने हाट बाजार योजना चालू की थी तो हमने हाट बाजार का उपयोग किया था तो गांव में हाट बाजार का उपयोग हो, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिये 33 प्रतिशत राशि की छूट हो।

सभापति महोदया :- मोहले जी, समाप्त करियेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदया, यदि मैं यह कहूं कि हस्तशिल्प को बाहर विदेशों में व्यापार के लिये भेजा जाये। विदेशों में यहां की कोसा साड़ी और हस्तशिल्प जाते हैं और विदेश में यहां की अपेक्षा तीन गुना और पांच गुना ज्यादा राशि मिलती है। जैसे आपका माटी कला बोर्ड है, उसकी वस्तुएं रेलवे के सामान के उपयोग के लिये दिया जाये। यहां तक कि जो आपके एयरपोर्ट है, वहां भी उनकी सुविधा हो और वहीं से विदेशों के लिये भी उसका निर्यात किया जाये, जिससे बुनकरों को, हस्तशिल्पों को, हस्तकला के लोगों को और शिल्पकला के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। यहां छत्तीसगढ़ में उसके बाजार हो, विदेश में भी ऐसी ही व्यवस्था हो और पूरे अन्य राज्यों में भी उसकी व्यवस्था हो। मैं ऐसी मांग करता हूं।

सभापति महोदया, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया :- माननीय श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदया, मैं यहां मांग संख्या 1, 2, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 56, 60, 65 और 71 के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदया, जब हमारा बजट आया तो उसमें करों की भी बात हुई और यह बताया गया कि हम कोई नया कर नहीं लगायेंगे। यह भी बात हुई कि हम जब कर नहीं लगा रहे हैं तो हम ऐसी व्यवस्था बनायेंगे कि उससे कहीं न कहीं व्यापारी भी लाभान्वित होंगे और हमारे पास राजस्व भी आयेगा। वर्ष 2022 में लगभग 17 हजार ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय सभापति महोदया, मेरी एक और मांग है। मैं खनिज विभाग के डी.एम.एफ. फण्ड की बात करना चाहता हूं। अधोसंरचना मद में 20 प्रतिशत राशि दी जाती है, जिससे ग्रामीण विकास का कार्य नहीं होता, वह बाहर दूसरे कार्यों में दिया जाता है। डी.एम.एफ. फण्ड की राशि को 35 प्रतिशत किया जाये, जिससे आम लोगों का, गांव का विकास होगा। यदि सरकार चाहती है कि पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो तो उस विचाराधारा में आप जरूर काम करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं।

सभापति महोदया :- व्यवस्था की दृष्टि से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री के अनुदान मांगों पर चर्चा के लिये वक्ताओं की लम्बी सूची है। समय-सीमा को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सभी सदस्यगण 10-10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति जी, धन्यवाद। हमें वर्ष 2022 में लगभग 17 हजार 350 करोड़ रूपये का राजस्व और वर्ष 2023 में 19 हजार 390 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। हमने छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में 22 हजार करोड़ का जी.एस.टी. का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसकी तुलना में हमारे पास दिसंबर, 2023 तक लगभग साढ़े चौदह हजार करोड़ रूपये, 64-65 प्रतिशत जी.एस.टी प्राप्ति हो गयी है। मैंने अपने बजट भाषण में ही कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह वसूली बहुत तेज होगी और यहां व्यापारियों में डर का माहौल है। उस समय सरकार का एक प्रेस नोट आया था कि 21 से 23 फरवरी के बीच में रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, जांजगीर, मनेन्द्रगढ़ में करीब 11 जगहों पर छापे पड़े। अगर कहीं कोई गलत कर रहा है तो वहां पर छापे पड़ें, वहां से वसूली हो, यह एक अच्छी चीज है, लेकिन कहीं न कहीं यहां के छोटे व्यापारियों में डर का माहौल है। जो व्यापारी जी.एस.टी. के दायरे से बाहर हैं वह राज्य कर अधिकारियों से डरे हुए हैं कि हमें उस सीमा में लाकर, कहीं फिर से हमसे भी वसूली न की जाये तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि यहां पर व्यापारियों को डर के माहौल में न दिया जाये । अगर उनसे वसूली करनी है तो उनको टैक्स के बारे में बताना है तो कहीं न कहीं काउंसलिंग के जरिये से हम छोटे व्यापारियों को बता सकते है। न ही वहां पर रेड करके, वहां पर जाकर, वसूली न करें। इससे कहीं न कहीं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो हम लोग वन विंडो सिस्टम की बात करते हैं या हम यह बात करते हैं कि यहां हम व्यापारियों को अच्छा माहौल देंगे, इससे यह माहौल खराब होने की स्थिति में आता है।

माननीय सभापति महोदया, जहां तक एक्साईज की बात है। इसमें करीब 29 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है। हमने कोरोना में यह देखा कि जब यहां पर शराब नहीं मिल रही थी तो यहां लोग किस तरह से सेनेटाईजर पीकर मरें। इस प्रदेश में युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है और इसके बारे में छत्तीसगढ़ को सोचना भी होगा और एक नीति भी बनानी होगी। नशे की इतनी आदत, इतनी निर्भरता की कोई व्यक्ति दवाई खाने लगे या उसकी जगह वह सेनेटाईजर पीने लगे तो यह किसी पार्टी विशेष की बात

नहीं है। इस पर सारे सदस्यों को बैठकर, सोचने का भी विषय है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर कोई एक कठोर निर्णय लेकर, एक नीति बनाने का भी विषय है कि आने वाले समय में हम युवा पीढ़ी को आखिर किस तरफ ढकेलना चाहते हैं। आज कल कोविड के बाद कहीं न कहीं हार्ट अटेक, मधुमेह यह बहुत युवावस्था में लोगों को हो रहा है। समाचार पत्रों में यह बहुत आसानी से सुनाई दे देता है कि किसी की जिम जाते हुए या बैडमिंटन खेलते हुए, मृत्यु हो गई। जब कोविड के बाद, इस तरह की बात सामने आयी है तो हमको इसमें कहीं न कहीं शराब की भी मात्रा को चेक करना होगा। यहां अवैध शराब बिक्री से जैसे ही यह तीन विषय आतें हैं यहां पर सारे सदस्य उसके बारे में बोलते हैं चाहे वह कोयला, राखड़ हो या अवैध शराब की बात हो तो कहीं न कहीं अवैध शराब पर कार्यवाही हो और यहां एक कठोर नीति की आवश्यकता है। आने वाले समय में जो अवैध शराब बिक रही है, हमें उस पर रोक लगाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदया, छत्तीसगढ़ एक परिवर्तनशील राज्य है। यहां कृषि, जंगल, पयर्टन, उद्योग और हमारे पास खनिज संपदा भी बहुत है, लेकिन जब हम लोग उद्योग और खनिज की बात करते हैं तो कहीं न कहीं पुनर्वास पीछे चला जाता है। यहां पुनर्वास का पहला मतलब यह है कि जहां पर वह लोग हैं वहां से एक बेहतर जिंदगी की ओर जाएं और वहां पर एक बेहतर जिंदगी व्यापन करें, लेकिन आम तौर पर यह देखा जाता है कि जब प्लांट आते हैं या वहां पर खनिज होता है तो उसके बाद वह एक खराब जीवन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा कि हमारे यहां वर्ष 2008-2012 के बीच में आदिवासी भूमि का अधिग्रहण हुआ था। वहां कुछ जमीनें खरीदी गईं थीं, वहां पर उन पर केवल इतना लिख दिया गया है कि मैं यह मानता हूँ कि मैं यहां से जाने के बाद दूसरी जमीनें खरीदूंगा। आज तक वहां के आदिवासी भूमिहीन हैं। न उसके पास मुआवजा आया है, वहां कई मामले ऐसे हैं कि न उन्हें नौकरी देने की बात है, कई मामले ऐसे हैं, न उन्हें पेंशन आ रही है । अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था उस पर मुझे जानकर यह अचम्भा हुआ कि वहां प्लांटों के परिसर के अंदर कुछ जमीनें हैं और न अभी तक उनमें मुआवजा मिला है और न ही उन्हें नौकरी मिली है। माननीय सभापति महोदय, यहां पर एक समिति गठित करने की आवश्यकता है ताकि कलेक्टर उसकी मॉनिटरिंग कर पायें कि वहां ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने आदिवासी या कितने लोग हैं जिन्हें न नौकरी मिल पायी, न मुआवजा मिल पाया और जो आज उन्हें, पुनर्वास नीति बेहतर जिंदगी बनाने के लिए दी गई है उससे वह वंचित रह गये हैं। वहां कुछ जगहों पर जमीनें ले ली गईं हैं, लेकिन वहां पर प्लांट डले नहीं हैं, उद्योग नहीं डले हैं। जब वहां पर उद्योग नहीं डले हैं तो आज भी उस पर किसान खेती जरूर कर रहा है, लेकिन खेती के साथ-साथ वह अपनी ही जमीन पर धान भी नहीं बेच पाता है। चूंकि वहां प्लांट नहीं लगा है तो वहां पर नौकरी, बाकी पुनर्वास, स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल की कोई बात ही नहीं रह जाती है।

माननीय सभापति महोदया, मैं, आपका जिला खनिज न्यास और गौण खनिज मद की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस गांव में खनिज संपदा है, कहीं न कहीं वह गांव धूल, राखड़, प्रदूषण, ट्रक के आवागमन से प्रभावित रहते हैं। हमारे कई गांव ऐसे हैं जहां पर गौण खनिज की राशि बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा इस हिसाब से नहीं है, लेकिन जब हम दूसरो से तुलनात्मक करते हैं तो वहां पर गौण खनिज की राशि है। अभी मेरे से पहले माननीय सदस्य गौण खनिज के लिए कह रहे थे, मैं उनके विपरित अपना एक सुझाव दूंगा। हमारे यहां कई गावों में, 2 से 3 करोड़ रुपये की एक गांव में गौण खनिज की राशि है और वह पूरी राशि 2011-12 की नीति की वजह से अधोसरंचना में चली जाती है। गांव वाले बार-बार यह कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं खनिज न्याय की तरह हम इस राशि को एच.आर. में दे सकते हैं। क्यों नहीं हम लोग अपने स्कूलों में टीचर रख सकते हैं, हम लोग हॉस्पिटल खोल सकते हैं? कहीं न कहीं इस पर एक नीति बनानी होगी कि हम लोग गौण खनिज के पैसे को सिर्फ अधोसंरचना में उपयोग न करके एच.आर. की तरफ भी हमें देखना होगा। मेरे विधान सभा में लगभग दो साल से न गौण खनिज की राशि आई है, न उसकी ब्याज की राशि आई है। मैं आपके माध्यम से इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, यह विषय बार-बार हमारी विधान सभा में आया है, जिसके लिए इस बजट में प्रावधान करना चाहिए था, लेकिन शायद नहीं हो पाया है। इसको करना अत्यंत आवश्यक है। पूरे प्रदेश में करेंट से वन्य प्राणियों की जान जा रही है। अभी एक युवा बाघ की बात आई है जिस पर ध्यानाकर्षण भी लगा था और सवाल भी लगा है। करेंट से अब तक लगभग 45 हाथी भी मारे जा चुके हैं। अगर करेंट से वन्य प्राणियों की मौत के सिलसिले को रोकना है तो यह जो बिजली की नंगे तारें निकली हुई हैं, इसमें insulated cable लगाने की आवश्यकता है और इसका बजट में प्रावधान होना बहुत ही जरूरी है। बिलासपुर में एक जनहित याचिका माननीय उच्च नयायालय में लगी थी। क्रमांक 5/2018 दिनांक 5.11.2018 को एक आदेश भी आया है कि जल्दी insulated cable जंगलों मे लगाये जायें ताकि इस तरह के अवैध शिकार के जो प्रकरण है, वह खत्म हो पायें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बजट में इसका प्रावधान होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, परिवहन विभाग राजस्व संग्रहण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। प्रतिवर्ष लगभग 2 हजार करोड रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है। इस राजस्व की वसूली तंत्र को और अच्छा करके इसको ढाई से तीन हजार करोड़ रुपये तक भी ले जाया जा सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनने पूर्व कार्यकाल में सीमाओं पर जितने भी चेकपोस्ट, उड़नदस्ते थे, वह उस समय बंद किये गये थे। हालांकि वह 2020 के आसपास चालू किये गये हैं। लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली जैसी चीज है। इसको सुदृढ़ करने के लिए हमको लगभग 7 को बढ़ाकर 40 करने की आवश्यकता है जिससे राजस्व में लगभग 1 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हो

जायेगी। ओवरलोड गाड़ियों की सभी सदस्य बात करते हैं। दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं, बिना फिटनेश की गाड़ियां चल रही हैं, हेल्पर नहीं रहते हैं, इन सभी पर अंकुश लगाने के लिए हमको कहीं न कहीं इनमें बजट में प्रावधान में करना होगा ताकि यह flying squad और बाकी जितने भी इस तरह के तंत्र हैं, इससे राजस्व की भी वसूली होगी और दुर्घटनायें और बाकी जितने भी हमारे यहां इस प्रकार से हो रहे हैं, उसमें कमी आयेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां की जो गौण खनिज की राशि है, उसकी ब्याज की राशि जो अभी भी नहीं आई है, वह राशि आ जाये। ताकि आने वाले समय में उसका पालन हो सके, लोग उसका उपयोग कर सकें। मैं प्रशासकीय प्रतिवेदन में एक बात पढ़ रहा था- "बिजली लग गई स्कूल मा, चले लागिस कम्पयूटर, सपना देखै दाई-ददा, लड़का बनय कलेक्टर।" आपके माध्यम से मैंने एक सवाल विधान सभा में उठाया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने स्कूल विद्युतविहीन हैं ? सभापति महोदय, मुझे यह जानकार आश्चर्य और दुख भी हुआ कि मेरे क्षेत्र के 16 स्कूल विद्युतविहीन हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस पर तुरंत ही आदेशित होना चाहिए। जब हम ऐसे क्षेत्र में रहे हैं जहां पॉवर प्लांट लगे हुए हैं, वहीं हमारे बच्चों को बिजली नहीं मिल पा रही है। अकलतरा विधान सभा में जहां-जहां पुनर्वास नहीं हो पाया है, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि वहां कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित हो, ताकि ऐसे जितने भी मामले हैं, उनका निराकरण तुरंत हो पाये। राखड़ प्रबंधन .. ।

सभापति महोदय :- समाप्त करेंगे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- जी। बस दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, राखड़ प्रबंधन हमारे जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बड़ी समस्या के रूप में है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने स्केप रूट और ईमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम हैं। विधान सभा में भी जवाब दिया गया है कि वहां पर स्केप रूट और ईमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात आकर्षित करना चाहूंगा कि चूंकि वर्ष 2016 में वहां पर पानी ज्यादा गिरा था, वहां राखड़ पूरा फैल गया था और किसानों को मुआवजे दिये गये थे। यदि स्केप रूट और इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है तो आखिर राखड़ खेतों तक कैसे पहुंचा? यदि हम लोग ग्रामोद्योग में रीपा से लोगों को जोड़ना चाहे तो, उससे बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ग्रामोद्योग विभाग में सरकार की जो नीति है, जो शुरू से चली आ रही है, हमें उसका फायदा मिलेगा और जितनी महिला समूह और महिलाएं हैं, ग्राम के लोग हैं, उनको इससे आगे फायदा मिलेगा। मैं बस यही कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदया, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री नीलकंठ टेकाम जी।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मांगें हैं, उन सभी शीर्षों पर अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं सामान्य प्रशासन विभाग, जोकि कार्मिक प्रबंधन का सबसे बड़ा विभाग होता है और सरकार के जो नियम-निर्देश होते हैं, उनको लागू करना और उनकी मॉनिटरिंग करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग की होती है। मैं उसमें अनुभव के आधार पर भी कहना चाहूंगा कि एक तो कलेक्टर और उसकी जो संस्थाएं हैं, चाहे हम अपर कलेक्टर की बात करें, डिप्टी कलेक्टर की बात करें, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, आर.आई., पटवारी और उससे नीचे चले जायें तो चैन मेन की बात करें तो इसमें अभी भारी संख्या में पदों में भर्ती करने की आवश्यकता है। मैं केवल सुझाव की बात करूंगा, क्योंकि आप समय का लिमिटेशन रखेंगे। इसलिए मैं यह सारी मांगों का समर्थन करते हुए केवल सुझाव और मांगें आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह सारे लोग आम जनता से सीधे जुड़े हुए लोग होते हैं। चाहे सीमांकन की बात हो, नामांतरण की बात हो, बंटवारा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो और अक्सर यह माना जाता है कि जब सारा सिस्टम बंद हो जाता है तो उस समय कलेक्टर की यह जो एजेंसी होती है, जिसको हम राजस्व अमला के नाम से जानते हैं, वह किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में पुलिस और राजस्व प्रशासन ही एक अंतिम विकल्प के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इसमें लगातार जो कमी महसूस की जा रही है, इसमें भर्तियां भी हो रही हैं, लेकिन इसमें और अधिक भर्ती करने की जरूरत है। लेकिन आप इसी के समांतर देखेंगे तो कुछ मिस मैनेजमेंट भी देखने को मिलेगा। आज की तारीख में हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला क्षेत्र एजुकेशन और हेल्थ है। लेकिन एजुकेशन में लोग एक अच्छे शिक्षक कहलाने के बजाय एक स्त्रोत समन्वयक कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, बी.आर.सी. कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, सी.आर.सी. कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। यह बड़ा ही चार्मिंग पोस्ट हो गया है और अभी से कुछ साल पहले, पांच साल पहले तो कम से कम 20-20 स्कूलों के बीच में एक संकुल हुआ करता था, लेकिन आजकल हर 3-3, 4-4 स्कूलों के बीच में सी.आर.सी. बना दिये गये हैं और यह गैर-शिक्षकीय कार्य करने में लोगों का जो इंट्रेस्ट है, इसको समझने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि चुनाव के कुछ ही समय पहले स्कूल जतन योजना के नाम से योजना लाई गई थी और उस योजना के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से शासकीय धन का स्वार्थपूर्ण बंटवारा हुआ । जो आवंटित राशि है उसका बमुश्किल 20 से 25 परसेंट राशि ही स्कूल मरम्मत के काम में आया बाकी पूरा का पूरा पैसा किसी न किसी तरीके से लीकेज में चला गया है । इसी प्रकार हम शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग को भी देखते हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि आप कलेक्टर रहे हुए हैं । ऐसी कोई भी राशि बगैर प्राक्कलन के स्वीकृति और प्राक्कलन के आधार पर ही मूल्यांकन हुआ, भुगतान हुआ और

विधिवत् टेंडर हुआ है । आपको यह बोलना उचित नहीं है, चूंकि आप कलेक्टर रहे हुए हैं और नहीं तो केवल 25 परसेंट हुआ है तो जांच करवाईये और अगली बार सदन में बताईयेगा कि कहां पर 75 परसेंट भ्रष्टाचार हुआ है । केवल और केवल भाषण में बोलना उचित बात नहीं है विशेषकर आपको चूंकि आप कलेक्टर रहे हैं । आप और अच्छी बात बोल सकते हैं ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, जब हाथ में तथ्य है तभी बोला जा रहा है । अभी इसका मौका नहीं है, जब मौका आयेगा तो वह भी दिखा दिया जायेगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं तो बोल रहा हूं न । माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जांच हो और जांच में सदन में 75 परसेंट आना चाहिए । यह संभव ही नहीं है ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, यह प्रोसिडिंग में आ गया होगा, जब भी मौका लगेगा तो इसका भी जवाब आ जायेगा ।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- द्वारिकाधीश जी, थोड़ा कम होगा तो नहीं चलेगा ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, केवल भाषण में हुआ है। आप सख्त जांच कराईये न, क्यों एक-एक वक्ता बोलते हैं ? माननीय मुख्यमंत्री पूरे 5 साल की एक साथ जांच करवाईये, अलग-अलग बोलकर सदन का समय क्यों नष्ट हो रहा है ? स्पष्ट हो, माननीय मुख्यमंत्री जी दो लाईन का आदेश दे दें कि 5 साल में हर विभाग में पूरा एक-साथ जांच करके और कितने दिन में हो जायेगा ।

सभापति महोदय :- टेकाम जी कंटीन्यू करें ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के साथ-साथ मेन पावर का जो सदुपयोग होना चाहिए उसमें स्वास्थ्य विभाग में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी । स्वास्थ्य विभाग में भी खासकर के चिकित्सा ड्यूटी के अलावा जो काम है उसमें भी बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिलता है और मेरा तो अनुभव रहा है कि इन दिनों बहुत सारे अधिकारी-कर्मचारी मिलकर के क्षेत्र की राजनीति को भी प्रभावित करने का काम करते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी शिकायत जो जनशिकायत निवारण शिविर के माध्यम से लगातार आपके डेस्क बोर्ड में आते रहते हैं उनकी एक समय-सीमा में निराकरण किया जाना बहुत आवश्यक है ।

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय पुन्नूलाल मोहले जी भी बता रहे थे और उसके पहले मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे कि एक विशेष अभियान चलाकर के बैकलॉग की भर्ती करना बहुत आवश्यक है । मैं आग्रह करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता से यह भरोसा इसीलिये प्राप्त किया है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो उनके साथ नइंसाफी हुई, उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया गया उसका जवाब आम जनता ने विधानसभा चुनाव में दिया है और हमारे ऊपर भरोसा किया है, विष्णुदेव की सरकार के ऊपर भरोसा किया है तो हम सब विश्वास करते हैं कि उनके

साथ न्याय होगा । 2000 फर्जी जाति को लेकर के लोग आज भी सरकारी नौकरी में बने हुए हैं । छत्तीसगढ़ के इतिहास में और शायद पूरे भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला होगा जब एस.सी. और एस.टी. वर्ग के बेरोजगार नौजवान फर्जी जाति प्रमाण पत्रधारी लोगों को नौकरी से बाहर निकालने के लिये, उन पर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिये निर्वस्त्र होकर के नया रायपुर की सड़क पर प्रदर्शन किया था और उस समय तत्कालिक रूप से आम जनता को यह मैसेज भी देने की कोशिश की गयी थी कि कांग्रेस सरकार के द्वारा इसमें सख्त कार्यवाही की जायेगी लेकिन तत्काल उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि एक समय-सीमा निर्धारित की जाये और यह फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के माध्यम से जो लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं, उनकी तत्काल सेवा समाप्ति की जाये और उन्हें जेल के अंदर भेजा जाये और उनसे पूरी राशि वसूल की जाये। उतनी संख्या में तत्काल आदिवासियों और हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की भर्तियां की जायें ताकि उनके साथ न्याय हो सके। आदरणीय सभापति महोदय, मैं विष्णु देव सरकार के बजट भाषण का जो सबसे ताकतवर पेज है कि सरगुजा और बस्तर की ओर देखें, उस पर मैं ध्यान केन्द्रित करना चाह रहा हूं। हम अगर सिंचाई की व्यवस्था को देखते हैं तो आज बस्तर और सरगुजा में सिंचाई का जो परसेंटेज है वो हमारे मैदानी क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है और इसलिए सरकार ने जो प्रावधान पंपों के विद्युतीकरण का रखा हुआ है, इसमें सबसे अधिक प्राथमिकता बस्तर और सरगुजा संभाग को मिलना चाहिए ताकि इस क्षेत्र में सिंचित रकबा की बढ़ोत्तरी हो सके। ये मैं आग्रह करता चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, आज कोण्डागांव जिले में आपका भी विधान सभा है, मेरा भी विधानसभा केशकाल है, पिछले दो से तीन महीने हो गये हैं, लगातार लो-वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं और लोग उनको गुमराह करने में लगे हुए हैं कि इसको आंदोलन की शक्ल दी जायेगी। वर्ष 2018 में केशकाल के लिए 132 किलोवाट का ट्रांसमिशन प्लांट स्वीकृत हुआ है, लेकिन आज तक वन विभाग के एन.ओ.सी. नहीं मिलने के कारण अभी तक ये काम चालू नहीं हो पाया। अभी जब से विधान सभा का रिजल्ट आया, मैंने लगातार इस विषय को सामने लाने की कोशिश की है। फॉरेस्ट विभाग से यह मामला निपटकर आगे बढ़ गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि केशकाल में स्वीकृत 132 किलोवाट का जो ट्रांसमिशन ग्रीड है, उसे तत्काल मंजूरी दी जाये ताकि न केवल कोंडागांव जिले को, बल्कि कांकेर जिले को सरप्लस बिजली का जो फायदा है, वह मिल सके।

सभापति महोदय :- समाप्त करें।

श्री नीलकंठ टेकाम :- सभापति महोदय, बहुत छोटे-छोटे 1-2 मुद्दे और हैं, जिनको बताना बहुत जरूरी है। परिवहन को लेकर..।

श्री उमेश पटेल :- टेकाम जी, एक मिनट। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों पर चर्चा हो रही है, बमुश्किल 3 मंत्री बैठे हैं। सदस्य भी पूरे नहीं हैं। अधिकारी दीर्घा भी पूरा खाली है

और मुख्यमंत्री जी भी नहीं हैं, उन्हें काम होगा और इनका सचिवालय भी खाली है। देखिए, ट्रेजरी बेंच। कुछ व्यवस्था बनाइए, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट पर चर्चा हो रही है तो थोड़ी उपस्थिति बढ़ाएं। अधिकारी भी यहां पर उपस्थित हो जाये।

श्री रामकुमार यादव :- महाज्ञानी मन भी नहीं हे। महाज्ञानी चन्द्राकर भी नहीं है।

सभापति महोदय :- उमेश जी, बैठेंगे। टेकाम जी जारी रखेंगे।

श्री नीलकंठ नेताम :- सभापति महोदय, अंतिम प्वाइंट में बात रखना चाह रहा हूं। परिवहन को लेकर है। परिवहन पर भी मेरा यही कहना है कि जब अंग्रेजों ने विदेशों में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बस्तर से साल के बड़े-बड़े झाड़ काटने के लिए केशकाल के पहाड़ी तक रेलवे लाइन का विस्तार किया था। अभी रावघाट तक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया है। क्या इसे जगदलपुर तक नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हम देखते हैं कि अकेले कोंडागांव जिले में एक साल में एक्सीडेंट के कारण 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और जवान बच्चे, नौजवान जो मोटरसाइकिलों से आना-जाना करते हैं, रायपुर से जगदलपुर तक की जो दूरी है, वह बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसलिए ये दोनों रेलवे लाइनों को तत्काल प्रारंभ करने के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन किया जाना चाहिए, इसके अलावा आयरन ओर बैलाडीला से रायपुर और राजनांदगांव के लिए सप्लाई हो रहा है । आमदई के खदान से जो आयरन-ओर कांकेर होकर अंतागढ जा रहा है उसकी वजह से हमारे सड़कों की हालत, केशकाल घाट की हालत बद् से बद्तर होती जा रही है । अनफिट गाड़ियां चल रही हैं, ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं । इसमें तत्काल रोकथाम करने की आवश्यकता है। रात के समय बेतहशा ट्रकें चलती हैं, बसें चलती हैं । जिससे एक्सीडेंट होता रहता है, इस पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग संख्या 1, 2, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35,36, 56, 60, 65, 71 पर चर्चा के लिए खड़ा हूं । सभापति जी, जब ले छत्तीसगढ़ में भाजपा के सरकार बने हे अउ हमर विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हे, अइसना संजोग हे कि ओखर मंत्रिमंडल मा भी भगवान जैसे नाम के बहुत सारा मंत्री हे । मैं आज जइसे ही शपथ लिस ता पूरा प्रदेश में एक माहौल बनाए के प्रयास करिन कि अब भगवान के राज आ गे । भगवान के राज आ गे अब गरीब घर के लइका बड़े आदमी बनही, सबके ख्याल होही, सबके चिंता होही, अइसने सोचके जब चर्चा करे गिस । लेकिन आज के बजट ला देखत हौं । चूंकि मैं अंतिम छोर के गरीब घर के व्यक्ति हौं तो मैं मोर हिसाब से, मोर नजर से बजट ला देखथौं । मैं का देखथौं, ठाकुर साहब। मैं देखथौं गरीब आदमी के का हे, ओखर कुकरी, ओखर भेड़ी, ओखर छेरी के रहे के व्यवस्था करे हे कि नइ करे हे सरकार हा या केवल बड़े बड़े आदमी, के महल अउ अटारी के चिंता करिस । जंगल मा रहने वाला वो आदिवासी समाज जे हर बिहनिया उठथे तो सूर्य भगवान ला प्रणाम

करथे, हे भगवान तिहिंच हर हस । जब रात के सोथे तो कहिथे भगवान तिहिंम हर हस । अइसन सोचकर प्रणाम करके अपन जीवन ला जीथे । लेकिन आज हम देखत हन ए बजट में । गरीब के खुशी अउ अमीर के खुशी ला मैं कभी तुलना करथौं । जैसे कि कोई धीरू भाई अंबानी के नाती, मुकेश अंबानी के बेटा 5 करोड़ के एक ठ मर्सीडीज कार लेथे ता ओला जतका खुशी होथे, ओते कन एक गरीब घर के लइका एक ठ छेरी पिला, भेड़ी पिला पाथे तो खुशी होथे । आज ओ गरीब के ज्यादा सपना नइ राहय, वो गरीब के सपना रथे कि कुछु करके मोर जिंदगी चल जाए । लेकिन आज पशुपालन, ए जतका सदन में ज्ञानी बइठे हे, कहां चल दिस हमार चंद्राकर जी हा । जब भी बात करही तो उद्योगपति के बात करते, अरब खरबपति के बात करथे लेकिन गरीब के बात कभी नइ करय । सभापति जी, हम छोटे रहेन तो देखे हन, गांव में पशुधन कहे जाथे । गौठिया मन ला भी कोनो दुख परय तो भइसा ला बेच देवय ।

श्री राजेश अग्रवाल :- अरे, चंद्राकर जी तोर ले ज्यादा दूध पैदा करे हे । कइसे ओला कहत हस ।

श्री रामकुमार यादव :- जम्मो दूध पीके तू मोटा गे हे, बइठा । आज गरीब आदमी मन के मेहनत, अउ मलई का खाने वाला आने । सभापति जी, मैं बात करना चाहत हौं पशुधन के । हम गांव मा देखे हन, जब घर मा कोनेा दुख पड़य तो गरवा बछरू ला बेचके वो समय ला चलाए जाए । लेकिन जइसे ही आज देखना चाहत हन, आज बजट मा वो पशुधन के मोला तब खुशी होतिस जब पशु ला धन बनाकर गांव मा कोई ला गाय बांटे के, कोई ला भैंस बांटे के योजना बनाए जातिस तो मोला खुशी होतिस । लेकिन एमन नइ करिन । आज मैं कहना चाहत हौं, मैं सामान्य प्रशासन मा दू मिनट चर्चा करिहौं, बाकी हमर बड़े-बड़े वक्ता मन बोल चुके हे। सामान्य प्रशासन के जतका अधिकारी मन सुनत होही, जब सामान्य प्रशासन विभाग कोई आर्डर करथे, चाहे चपरासी से लेकर प्रोफेसर तक हो, ए मन बड़े-बड़े शहर नगर मे आर्डर करथे। जैसे आप रायपुर के कॉलेज में जा के देखव, उहां अतका कन प्रोफेसर हे कि जान देव। लेकिन कोई गांव में कॉलेज खुले हे, वहां जा के देखव, अगर मान ले 30 झन प्रोफेसर के जरूरत हे तो लटपट 5-7 झन चलावत हे। जब भी अगर सामान्य प्रशासन विभाग कोई भी चीज में भर्ती करथे, चाहे वो कोई भी पद के रहाय, मोर आपसे निवेदन हे, सदन से निवेदन हे, मोर सभापति से निवेदन हे, अपन अधिकारी ला निर्देश करे। जैसे हमन छोटे रेहेन ता आलू पलोय ला जान, गोंदली पलोय ला जान ता अंतिम छोर ला पलोत-पलोत आए, एक नारी, दू नारी बचे त ओ टेड़ा ला बंद कर देवन, अतका अकन धार में पल जाही कहन। उसी प्रकार से जब सामान्य प्रशासन भर्ती करे तो बड़े-बड़े शहर में तो प्राइवेट कॉलेज हे, अंतिम छोर ला भर्ती करत आवए ताकि गांव के जो कॉलेज खुल हे, छोटे कस्बा में कॉलेज खुले हे, बड़े-बड़े ऑफिस खुले हे, ऊहां अधिकारी मन रहे, ऊहें ज्यादा जरूरत हे।

सभापति महोदय, मैं पुनर्वास के बात करना चाहत हौं। जहां-जहां कंपनी आथे एमन हमन ला हसीन सपना दिखाथे। एमन ऐसे-ऐसे माया जाल फंसाथे, ऐसे अधिकारी बनाथे, अऊ ओमन जा के का कथे, बताओ भाई और बहनों, आपके गांव में कंपनी खुलेगा तो आपका कंपनी स्वर्ग हो जाएगा। गांव के

व्यक्ति का सोचथे, मोरो गांव हा, बंबई, कलकत्ता कस हो जही कथे। अउ गांव के जमीन ला बेचारा ह, उद्योगपति के झांसा में आ के दे देथे। जमीन तो चल दिस, मैं दिल में हाथ रख कर कहात हो, मैं झूठ नई बोलत हौं, चाहे आपके सरकार हो या मोर सरकार हो। बहुत सारा कंपनी खुले हो, आप जा के देखव, ओमन ला किसी प्रकार के कोई अधिकारी नई मिलत हे, अउ ए मेरे आ के सब लच्छादार भाषण मारत हन कि ओ रामकुमार अइसे हे, भूपेश बघेल जी अइसे हे, ता तुमन कइसे हो। तुमन 15 साल करके गे हो तिही ला तो हमन भोगत हन। कंपनी तुंहर समय में खुले रिहिस हे कि हमन खोलेन। कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। जैसे मैं मोर एरिया के बात करत हौं। हमन ठाकुर साहब बैठे हे, बहुत ज्ञानी हे। कल या परसों ए देश के मजबूत प्रधानमंत्री, 15 लाख खाता में भेजने वाला प्रधानमंत्री, एनटीपीसी आरा के एक ठन अउ प्लांट के उद्घाटन करिस हे। हमन ताली बजायेन, लेकिन कभू ओला पूछ के देखिस का, कोई कंपनी खोले के लिए कोयला लागथे, कंपनी खोले के लिए जमीन लागथे, अउ कंपनी ला चलाय के लिए पानी लागथे। लेकिन तुंहर सरकार रिहिस हे ता आप मन बैराज बनाय हो, ओमे जमीन डूबान में चले गिस, मोला खुशी तब होतिस जब प्रधानमंत्री जी हा वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पूछतिस ए एनटीपीसी आरा के मैनेजर, वहां पर पुनर्वास का सब मिला है या नहीं मिला है, रामकुमार यादव कांग्रेस के हरे तभो ले ताली बजा देतिस। लेकिन खाली फीता कांटना हे, गरीब ला का मिलिस पुनर्वास के का मिलिस, मैं ए सदन के माध्यम से कहात हौं, आप जाकर देखव, कलमा बैराज, साराडीह बैराज, उहें के पानी एनटीपीसी आरा जात हे, ऊहां ले डूबान जमीन गे हे, ओला पुनर्वास के एको ठन फूटी कौड़ी नई मिलत हे। ए बात के कतका तकलीफ होत होही।

सभापति महोदय, मैं कुटीर उद्योग के बारे में कहना चाहत हौं। कुटीर उद्योग का ए। हमन छोटे रेहने ता हमर किसान मन बढ़ईगिरी के काम करे। चार महीना खेती करे ओखर बार किसान कर समय बचतीस तो ओमन बौंसला में गाड़ा बनावए, ठईका बनावय, लेकिन जब से ऐ आधुनिक दुनिया आए हे, किसान ला कुटीर उद्यो गा भुला गेन। ओ लोहार ला भुला गेन, आजकल बड़े-बडे कटर मशीन आत हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- तैं कुल मिला के ए बता, मुख्यमंत्री जी के विभाग के मांग ला मंजूर करना है या नई करना हे। ऐला बताना भैया, तैं हा इतना गुस्सा-गुस्सा में बोलत हस।

श्री रामकुमार यादव :- मैं जानत रेहेव, हमर ठाकुर साहब अतका कलाकार ए, एक भारत में अगर सबसे बड़े डबल रोल करे वाला हे ता मोर ठाकुर साहब हे। हमन जंजीर फिल्म में देखे हन।

श्री अनुज शर्मा :- तोर मोर झगड़ा हो जही में बतात हों।

श्री रामकुमार यादव :- हमन हेमा मालिनी के डबल रोल वाले देखे हन। लेकिन अगर ठाकुर साहब कोई फिलिम में डबल रोल करही कि कइसे कांग्रेस में रहना है, कइसे भा.ज.पा. में रोल करना है अऊ कभु-कभु जोगी के पार्टी में कइसे रोल करना है, अगर कोई ला सीखना है तो मोर ठाकुर साहब से सीखना चाहिए। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- तैं शौक मत पाल। बहुत खतरनाक रहिथे। जहां हस, वहीं रह। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- ठाकुर साहब, मोर गरीब के का नठाही?

श्री धर्मजीत सिंह :- सुनना। ए सबके बस के बात भी नहीं हे।

श्री रामकुमार यादव :- देखो। मैं एक गरीब हर गरूवा चरा के दू घाव विधायक बन गेव। अब रामकुमार यादव के का हे, मैं तुंहर भूथियारी करके जी जाहूं। मोला डर नहीं हे। कल का होही, लेकिन मैं दिल के बात करथो। मैं कोई बनावट बात या अकड़ के बात नहीं करो।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं अभी मुख्यमंत्री जी करन तोर तारीफ करके आए हो कि रामकुमार यादव जी के क्षेत्र मा विकास करना है अऊ ते इंहा धाय-धाय हमर खिलाफ में बोलत हस। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- ओखर कहना वही हे कि मैं कहे हव, तेला काट दिहूं कहात हे। मुख्यमंत्री जी हा बइठे-बइठे सुनत होही। ओ मुख्यमंत्री हा मोर बड़का भाई कस हें। आप चिंता झन करीहो। आज कुटीर उद्योग अऊ लोहार के बात करत रहे हन। पहिली जमाना में लोहार के घर में जातेओ तो लोहार के घर मा भीड़ लगे रहाय। दूरिया ले जान डरे कि लोहार घर हे। लेकिन आज के डेट में ओ लोहार के घर मा जाहूं तो ओहा सुन्ना पड़े हे। एखर चिंता कोन करही? सिर्फ बड़े-बड़े कारखाना, जेन कारखाना हा मोटर-साइकिल अऊ हवाई जहाज बनात हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, समाप्त करें।

श्री रामकुमार यादव :- बहिनी। माननीय सभापति महोदय, एहा जरूरी हे। (हंसी) ऐ बात ला करन देओ। ऐ सब मन तो माया जाल के बात करथे। लेकिन मैं जो कहत हो, एहा जरूरी बात हे। तेखर खातिर मोला समय दो। हमन एक घण्टा ले सुनत रहे हन कि ओ ऐसा है, ओ ऐसा हे। ए जरूरी बात हे। मैं कहना चाहत हो कि हमन ला ओ लोहार के भी चिंता करना चाहिए। आप गांव-गांव में योजना बनाओ अऊ आप लोहार ला खोजो।

श्री आशाराम नेताम :- रामकुमार भैया, विश्वकर्मा योजना लागू होहे।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ी में कहावत हे। भैया, आप सुन लो -

उलट-पुलट भय संसारा,

अऊ नाऊ के मुड़ ला मुड़े लोहारा। (हंसी)

माननीय सभपति महोदय, जेन पहिली लोहा के काम करत रीहिस। जेहा पहिली बढ़ई के काम करत रीहिस, ओहा तुमन के दु:ख में ओला छोड़ के आने काम करत हे। ओखरे खातिर कहात हो कि लोहार हा आने काम करत हे। बढ़ई हा आने काम करत हे। सब उलट-पुलट भय संसारा हो गेहे। आप ओला फिर से खोजो अऊ खोज के ओला फिर से व्यवस्थित करो, तब जाके छत्तीसगढ़ में पूर्व में हमर मन के जो व्यवसाय रीहिस हे, फिर ओहा आगे बढ़ही। हमर महाज्ञानी आत हवें। ऐला देख के मोर आधा बल हा अइसने भाग जाथे। (हंसी)

सभापति महोदय, मैं खनिज विभाग के बात करथो। ए प्रदेश मा 32 प्रतिशत आदिवासी समाज रथे। ए प्रदेश में आधा से थोकन कम मा जंगल हे अऊ जंगल में कोन रथे? आदिवासी समाज रथे। ओ मन कोयला के रखवाली करथे। जब तक कोई उद्योगपति हा कोयला ला नहीं लेवे, ओमा अपन निशान नहीं लगावे, तब तक ओ आदिवासी समाज हा कोयला ला राखत-राखत ओमा बइठे रथे। जइसे ही हमर विष्णु देव साय जी के वर्तमान सरकार बनीस तो हमर विष्णु देव जी के चक्र हा विकास में नहीं घुमीस। ओ जो गरीब आदिवासी हैं, तेमन घर तरी घुसर गे। आज ओमन ला जतका घर कुरिया ले बेघर करे के काम करत हे। कोयला ला खनथे तो आदिवासी समाज ऊंहा ले ओमन ला भगाथे। आदिवासी समाज कहां-कहां भागे? मोर आपसे प्रार्थना हे कि जेन आदिवासी समाज हा कोयला ला जिंदगी भर राखे रहिथे, वही कोयला ला अगर ओहा एक झउंहा में धर लेथे, तो पुलिस जाके का कथे। ऐ, चोरी करते हो, डाका डालते हो। वही आदिवासी समाज के सात पुरखा हा बइठे-बइठे कोयला ला राखे हे। कोयला हा ट्रेन में जोराए रथे। गरीब आदमी हा बेचारा रूक ला चुनत हे तो वन विभाग वाले मन हा ओला पकड़त हे। आप गैस सिलेण्डर के रेट ला 1,200 रूपये कर देहो। ओखर ओला भरवाये के क्षमता नहीं हे तो ट्रेन में चघ के कोयला ला एको झउंहा धर डारथे तो पुलिस हा जाके डण्डा देके ओला अंदर कर देथे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, समाप्त करें।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मोर आपसे प्रार्थना हे कि आप अइसे कोई योजना बनाओ। तुमन तो महाज्ञानी हों। मैं आपसे निवेदन करना चाहत हो कि आप मन कोयला के रखवाला आदिवासी समाज ला कोयला देके कुछु न कुछु प्रावधान बनाओ। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, ऐला कहे जाथे। जतका फोन आथे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, समाप्त करें।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, केवल 5 मिनट।

सभापति महोदय :- 5 मिनट नहीं, आप 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामकुमार यादव :- आप हमन ला संरक्षण नहीं देहौ त कौन दिही ।

सभापति महोदया :- एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री रामकुमार यादव :- पॉच मिनट में मोर बात पूरा करिहौं । इलेक्ट्रानिक्स विभाग से फोन आथे अउ जाथे । हमन छोटे रेहेन त एके ठन फोन चलय । जब क्रिकेट देखन, कोई चौका मारय तो बीएसएनएच चौका, बीएसएनएच छक्का अईसे होवय, लेकिन जब ले अम्बानी आए हे, तब ले टावर ला बदल दिस, सरकारी कम्पनी ला बंद करके उद्योगपति के कम्पनी ला आगे कर दिन । मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करथौं, मोला तब खुशी होही, जब गांव-गांव में, शहर-शहर में बीएसएनएल कंपनी के टावर लगावय, काबर के ओ पइसा सरकार के खजाना में जाही । कोई प्राईवेट ला बढ़ाए के काम करिहौ त ओ पईसा ह बढ़का उद्योगपति के खजाना मा जाही । तेहर खातिर मैं आपसे निवेदन करना चाहथौं ।

सभापति महोदया, परिवहन विभाग में बोलना चाहथौं । मोर एरिया में बढ़का-बढ़का ट्रक ह जाथे । ओ मन के 10-20 टन में परमिशन रहिथे । अउ 30 टन के जोरथे, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी ह ओला कभू नहीं रोकय । कोन ला रोकथे ? ट्रैक्टर वाला ला । कौन सा रोकथे ? जे ह गरीब आदमी ए, ट्रेक्टर मा बारात जावथे, तेला जाके रोकथे अउ कथे-ए, ट्रैक्टर में बारात जाते हो । तो गरीब आदमी ह ट्रेक्टर मा बारात नहीं जाही त जहाज में बारात जाही ? मोर आपसे प्रार्थना हे कि आप परिवहन विभाग के अधिकारी ला अच्छा से निर्देश करौ, ताकि गरीब आदमी ला कम सताय करै अउ उद्योगपति के बड़े-बड़े गाड़ी ह रोड़ ला तोड़थे, ओला पकड़े के काम करै ।

सभापति महोदया, ऊर्जा विभाग में बोलना चाहथौं । एक समय रहिसे, लाईट ला देखन त जगजग ले अंजोर रहाय । अब तो लाईट ला देखना हे तो कंडिल ला धरके जाए ला लागथे कि बलब ए कि काहे ए कहिके । तुमन के लाईन मा ओतके अकन प्रकाश रहिथे कि कंडिल ला धरके लाईल ला देखेबर जाए ला लगथे । आपसे प्रार्थना हे कि आप अईसे निर्देश करौ, ताकि ए मन ऊर्जा विभाग ला बढ़िया से सम्हालैं ।

सभापति महोदया, अंत में आपके भावना ला समझते हुए मोर क्षेत्र के मांग कर देथौं । बिलाईगढ़-चन्द्रपुर में नया सब स्टेशन के जरूरत हे, काबर कि ओ ह अंतिम छोर पड़थे । ओकर खातिर बिलाईगढ़ में एक ठी नया सब स्टेशन । सपिया हमर क्षेत्र के बहुत बड़े गांव हरे, उमेश पटेल जी के विधान सभा से लगे हुए हे । आए दिन ऊंहा से सिर्फ लाईट के लिए 20 ठी फोन आथे । ऊंहा एक ठी नया सब स्टेशन के जरूरत हे, सिंघरा गांव बहुत बड़े हे, ऊंहा एक ठी नया सब स्टेशन अउ शक्करा में जे.ई. स्तर के एक ठी आफिस खोल दिए जाये, ताकि बिजली बिल पटाए बर सुविधा मिलय अउ डभरा में डी.ई. स्तर के एक ठी बड़े साहेब के कार्यालय बना दिया जाये, ताकि बिजली के पूरा देखरेख ला कर सकय । अंत में मोर गांव में बीएसएनएल के कोई टावर नहीं हे, तेखर खातिर आज सदन के माध्यम से मोला मांग करेबर लगथे कि बीएसएनएल के टावर होवय, काबर कि कोनो अधिकारी फोन करथे त हमर फोन लगबे नहीं करय । काबर के हम तो वईसने गांव के विधायक अन, जहां अंतिम छोर के रहवैया अन त ऊंहा बीएसएनएल के टावर लगा देवय । माननीय मुख्यमंत्री जी ह बजट के अनुदान मांग करे हे, एमा गरीब के बात नहीं हे, छेरी पिला के बात नहीं हे, भेड़ी के बात नहीं हे, मछरी कोतरी धरैया के बात नहीं हे, गांव के जंगल के रहवैया के बात नहीं हे, तेखर खातिर मैं ए बजट के घोर विरोध करत हुए मैं अपन वाणी ला विराम देवथौं ।

सदन को सूचना

सभापति महोदया :- विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन हेतु 4 बजे का समय निर्धारित है । चूंकि अभी अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी है । अत: मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2024 - 2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(आसंदी से श्री धरम लाल कौशिक का नाम पुकारे जाने पर)

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- सभापति महोदय, आप लोग फिक्र मत करिए। जब मैं कांग्रेस पार्टी में था, कौशिक जी भाजपा में थे तो मैं जब भाजपा के खिलाफ बयान देता था तो इनका फोटो छप जाता था और कौशिक जी हमारे खिलाफ बयान देते थे तो मेरा फोटो छप जाता था ।

सभापति महोदया, सबसे पहले मैं लखमा दादी को देखकर बहुत खुश हो गया हूं । ईश्वर आपको स्वस्थ्य रखे । आपकी तबीयत खराब थी तो अच्छा नहीं लग रहा था । आप हमारे दोस्त हो । भगवान आपको अच्छा रहे । आप भी खाने-पीने में अपना थोड़ा ख्याल रखिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें मुझे आपत्ति है । आप सिर्फ खाने की बात करें। खाने का ख्याल रखें करके, आप जबरदस्ती पीने की बात कर रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसमें क्या दिक्कत है ? सभापति जी, खाने-पीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज पीने के लिए बना है। जिसको भी पीना है, कन्ट्रोल में पीओ, कौन मना कर रहा है ?

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाई, आपको कैसे पता चला, पहले यह बताओ ? कन्ट्रोल में पीते हैं या बिना कन्ट्रोल में पीते हैं, आप माननीय सदस्य हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- देखो, तबीयत तो तभी गड़बड़ होता है। मेरी भी तो तबीयत खराब हो चुकी है, तो मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। हम सब लोग 98 माडल वाले हैं। आप भी हैं। तो दादी के लिए थोड़ा हमारा प्रेम तो है। आपको कोई टेंशन नहीं पालना है। होही वही जो राम रची राखा, कोई टेंशन मत पालिये। दादी, टेंशन पालने से कुछ होने वाला भी नहीं है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी बेहद सरल, सच्चे, अनुभवी और गरीबों के बीच पैदा हुए व्यक्ति हैं। उनके हाथ में इतने बड़े-बड़े विभाग है तो निश्चित रूप से विभाग में काम अच्छे ही होंगे। मैं थोड़ी दो-तीन बात कहना चाहता हूं। मैं आबकारी विभाग के बारे में बात करना चाहता हूं। उसमें पहले ब्रेवरेज कार्पोरेशन था, बाद में खरीदी-बिक्री वाला एकाध कार्पोरेशन

अलग से बन गया था। मुख्यमंत्री जी, आप इसको खत्म करके थोड़ा सिस्टम को देख लीजिये, पुराना अनुभव अच्छा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप इस पर जरूर विचार करेंगे।

सभापति महोदय, राम कुमार जी, आप परिहवन के बारे में बोल रहे थे। परिवहन में क्या-क्या होता था, जब आप बैठोगे तो मैं बताऊंगा। यहां कोई एक ड्रायवर था, वह पूरा परिवहन विभाग चलाता था। बता दूंगा, नाम ले दूंगा तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए बता रहा हूं। परिवहन में भी ब्लेक स्पाट को भी देखना है, आप थोड़ा पारदर्शी रखिये। छत्तीसगढ़ में पहली बार अजीत जोगी जी एम.पी.एस.आर.टी.सी. को खत्म किया। उन्होंने बेरोजगारों को मोटर परमिट दिया है तो उनको कैसे आगे बढ़ाना है, मोटर की व्यवस्था कैसे ठीक होना है, आप कर दीजियेगा।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक मांग करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। मैं तो अभी थोड़ा लेट हो गया। आज प्रधानमंत्री जी ने 554 रेल्वे स्टशनों के पुनरोद्धार कार्यक्रम का शिलान्यास किया है और डेढ़ हजार अण्डर पास का शिलान्यास किया है, उसमें दो तखतपुर विधानसभा को मिला था। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में था।

श्री रामकुमार यादव :- ठाकुर साहब, बहुत अच्छा बात हे। लेकिन ट्रेन चालू तो करवा देवा। जब ट्रेन ला बंद कर दे हे। बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर आय बर बंद कर दे हे। ओला चालू करवा देवा।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या है कि आप लोग बस इसी में ही खत्म हो गये । अभी ट्रेन लाईन और डिस्टर्ब रहेगा, अभी और बंद रखेंगे। बोलो क्यों ? चार-चार लाईन बनाना है तो ट्रेन चलाकर किसी मरवाओगे क्या ? बनने दो, उसके बाद चकाचक चलना, बैठकर आराम से जाना।

श्री उमेश पटेल :- मतलब ट्रेन कितने घंटे लेट चल रही है, आपको पता है ? छत्तीसगढ़ में पैसेंजर ट्रेन बंद होने की स्थिति में है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, बंद हो जाये ना।

श्री उमेश पटेल :- बंद हो जाये ?

श्री धर्मजीत सिंह :- लाईन बन रही है न। लाईन बनने के बाद चलायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- क्या पहली बार लाईनें बन रही है ?

श्री रामकुमार यादव :- कोयला वाला गाड़ी तो बंद नइ होवत हे साहब, कोयला वाला घर्र-घर्र भागत हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आकड़ें बताता हूं। 30 हजार किलोमीटर नया रेल लाईन बनी है और 40 हजार किलोमीटर लाईन इलेक्ट्रेफाई हुआ है। तो काम करोगे तो रहना पड़ेगा। आप घर का रेनोवेशन कराओगे और ज्यादा बड़ा काम रहेगा तो घरके बाहर निकलकर रहना पड़ेगा।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले भी रेल्वे लाईन बढ़ी है। उसमें भी आल्टरनेटिव लाईन से ट्रेनें चलाई जाती है।

सभापति महोदय :- समय कम है, कृपया आपस में संवाद ना करें। विषय पर आयें।

श्री उमेश पटेल :- आप पैसेंजर ट्रेन को जानबूझकर लेट कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपकी गति बहुत धीमी थी और देश को बहुत फास्ट ले जाना है। विकसित भारत बनाना है। तीसरी इकानॉमी बनाना है। इसलिए हम तेज चल रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- अभी जो पांचवी इकानामी हुई है, उसकी नींव आज के कारण नहीं हुई है। सन् 1991 में मनमोहन सिंह जी ने नींव रखा था, तब जाकर आज पांचवी इकानामी बनी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है, मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद तो दिये है। नरसिम्हाराव जी को तो भारत रत्न दिए हैं। आप लोग तो नहीं दिये थे। तो इन सब बातों को छोड़िये।

माननीय सभापति महोदय, मैं तखतपुर से पहली बार विधायक निर्वाचित होकर आया हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यह संदेश भेज रहा हूं कि वहां की विद्युत व्यवस्था कुछ एरिया मुंगेली जिले से, कुछ एरिया का पेण्ड्रा-गौरेला जिले से और कुछ एरिया का तिफरा और चकरभाठा से से बिजली प्रदाय हो रहा है। तीन-तीन जगह से सप्लाई है। मैं विधायक होने के नाते कहां-कहां, किस-किस जिले से बात करूंगा। इसलिए मेरी सिर्फ और सिर्फ एक मात्र मांग है कि तखतपुर में कार्यपालन अभियन्ता की जगह डिवीजनल इंजीनियर का आफिस खोल दिया जाये तो तखतपुर के 280 गांव के लोगों को विद्युत की व्यवस्था ठीक होगी और हम सरकार की नीतियों को क्रियान्वित कर सकेंगे । सभापति महोदया, इससे ज्यादा मेरा कोई और न मांग है और न ही मैं भाषण देने के लिये खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने मुख्यमंत्री जी की मांगों का समर्थन कर रहा हूँ । वह बहुत ही अच्छे अनुभवी नेता हैं, हमारे विभाग में जो भी काम होगा, हम जाकर बोल लेंगे, काम हो जायेगा । रामकुमार जी, मैं तो आपकी तारीफ करके आया था, आप इतना खिलाफ में क्यों बोलते हो ? अपने को काम करना है ना भई ? मुख्यमंत्री जी सभी का काम करते हैं, वह बहुत दयालु हैं।

श्री राजेश मूणत :- इधर से कुछ सीखो ।

श्री उमेश पटेल :- राजेश जी, आप क्या सिखाना चाह रहे हो ?

श्री रामकुमार यादव :- बहुत कलाकार है, मैं मांगे हंव, तेनला अइसने बोल-बोल के कटवाही । मोला भरोसा है, जब वोला दिही ना, महु ला दिही ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मेरे चक्कर में तुम मत पड़ो । बार-बार मत बोला करो कि मैं कांग्रेस, फिर जोगी कांग्रेस, उसके बाद भाजपा में हूँ । मेरे टाईप चक्कर में पड़ोगे तो साफ हो जाओगे । एक झन यहां से चक्कर में पड़ने का प्रयास भी किया था । टकराना मत । हम दोस्त हैं, दोस्ती निभाते हैं । जनता से प्यार करते हैं । जनता का सम्मान करते हैं । जनता की सेवा के लिये दिन-रात हाथ जोड़ते हैं, जैसा कि हाथ जोड़ रहे हैं । यह सीखिये । जनता का काम होना नहीं है, 20 साल से अंडर पास नहीं बना था...।

श्री अजय चन्द्राकर :- 5 साल कांग्रेस में विधायक बने तो वह क्या सीखे ? यह ऊंच के दिखे । (हंसी) वही सीखे बस । तीन चार जगह रखा था, उतना तो हम लोग पिक्चर में देखें हैं और आजू-बाजू कितना था, नहीं मालूम ?

श्री धर्मजीत सिंह :- वह तो सब देखे थे ।

श्री रामकुमार यादव :- ए दारी हाईट अऊ बढ़ गे हे, चिन्ता मत कर ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदया, बढ़िया है, बढ़िया है, काम अभी चलेगा। ठीक है । सभापति महोदया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ । मेरी एक ही मांग है, मेरे तखतपुर विधान सभा क्षेत्र के तखतपुर में डिविजनल इंजिनियर का आफिस चाहिये । मैं मांगों का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ, अब आप आगे बुलवाईये, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदया :- श्री द्वारिकाधीश यादव जी ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अनुदान मांगों पर मांग संख्या 1, 2, 7, 12, 14, 16, 25, 32 से लेकर 71 तक जो मांग संख्या है, उसके विरोध में चर्चा में भाग लेने के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदया, मैं विरोध में इसलिये नहीं बोल रहा हूँ कि विपक्ष में हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की जनता के हित में खड़ा हूँ, उनके हितों का ख्याल नहीं रखा गया है । सभापति महोदया, जब से विष्णु देव जी की सरकार बनी है, पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बनने के पहले वह छत्तीसगढ़ की सारी जनता, मतदाता सब जानते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छे नेता के रूप में जानते थे, मुझे लगता है कि आज भी वह छत्तीसगढ़ के विकास के लिये विवेक से काम लेंगे । आज वह अदृश्य शक्ति है, उससे काम करवा रहे हैं । सभापति महोदया, आज छत्तीसगढ़ के एक सुंदर जंगल को केवल एक अधिकारी ने उजाड़ दिया है, विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री के बगैर निर्देश के यह कारनामा हो गया । सभापति महोदया, आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री इतने विवश क्यों है कि एक अधिकारी जंगल उजाड़ दिया और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । जिस जंगल के लिये इस सदन में सर्वसम्मति से संकल्प पारित हुआ था । सभापति महोदया, केवल इतना ही नहीं, जब गरीब सड़क के नीचे शराब भट्ठी के करीब चखना सेंटर चला रहे थे, तब चखना सेंटर को सेंट्रलाईज्ड करने के लिये गरीब के ठेले में बुलडोजर चला और आज बड़े से बड़ा आदमी चखना दुकान को कब्जा करके बैठे हैं।

श्री मोतीलाल साहू :- सभापति महोदया, कोई गरीब चखना सेंटर नहीं चला रहा था, कांग्रेस के नेता चखना सेंटर चला रहे थे। आपको इसी बात की पीड़ा है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदया, क्या कांग्रेस के लोग चखना सेंटर चला रहे थे, इसीलिये आपने बुलडोजर चला दिया ? यही है सरकार ?

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदया, आप लोगों ने तो शराब तो शराब, खोखे को नहीं छोड़ा। खोखे में भी इतनी बड़ी धांधली हुई है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- खोखा ? अभी तो आप लोग ढक्कन को भी नहीं छोड़ेंगे। आप जैसे चलायेंगे तो ढक्कन भी नहीं बचेगा।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदया, खोखे में धोखा हुआ है। मैं उसको भी बताऊंगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हम अगले सदन की बैठक में मिलेंगे।

श्री अनुज शर्मा :- इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया कि पिछली सरकार में ढक्कन तक को नहीं छोड़ा गया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदया, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव से पहले इस सरकार ने कर्जा माफी की बात कही थी। आज वह सदस्य इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री जी का वीडियो चला कि किसानों का 02 लाख रूपये तक का कर्जा माफ करेंगे ।

समय :

4.06 बजे **(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए)**

लेकिन उन किसान भाइयों को छला गया। मैं उस बात को याद दिलाना चाहता हूं जो हमारी सरकार के ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे थे। इस सरकार के पहले जो 05 साल तक सरकार थी। इसी सदन में दो घण्टों में 09 हजार 500 करोड़ रूपये की कर्जा माफी के लिये यदि किसी ने हस्ताक्षर किया था तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, श्री भूपेश बघेल जी ने किया था। धान 1870 रूपये के दाम पर बिक रहा था। जब हमारी सरकार बनी तो धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये प्रति क्विंटल किया गया। बात यहीं नहीं रूकी जो किसान 1870 रूपये में अपना धान बेच चुके थे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, यह कृषि विभाग का मामला कहां से आ गया ? यह मुख्यमंत्री जी के विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ओ हर मुख्यमंत्री हन तहान ओ हर सब विभाग के मंत्री हन। मुख्यमंत्री हर प्रदेश के मुख्यमंत्री हन, ओकर पास सब विभाग आथे।

श्री राजेश मूणत :- एकर मतलब द्वारिकाधीश यादव हर सपोर्ट के जरूरत हे। ओव्हर ऑल आप कल विनियोग पर बोल लीजियेगा। यह अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। आप विभाग पर बात करिये।

सभापति महोदय :- चलिये, विषय पर आईये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, हमारे कार्यकाल में आपके विद्वान सदस्यों ने भी बोला है। ऐसा कोई विभाग नहीं है, जिसके खिलाफ वह नहीं बोले होंगे। मैं अब वहीं से बात शुरू कर रहा हूं।

श्री राजेश मूणत :- इसका मतलब आप अभी तक शुरू नहीं किये थे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के कोई भी माननीय सदस्य खड़े होते हैं तो सदन का ऐसा कोई दिन नहीं है, जिसमें हर समय अलग-अलग परिस्थिति में जांच की घोषणा करते हैं। आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगली बार सदन का समय बचे, उसके लिये एक साथ जो-जो जांच करवाना चाहते हैं, वह पूरी जांच करवा लें। मैं उस 15 साल की सरकार को भी याद दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- आप विषय पर आईये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, मैं विषय पर ही आ रहा हूं। अब उधर के सदस्य थोड़ा बोले हैं, तो उनको भी बोलना जरूरी है।

सभापति महोदय :- नहीं, उसके लिये समय नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हीरो होण्डा और स्कूटर में धान ढुलाई हुआ करती थी। यह भुला दिये हैं।

सभापति महोदय, मैं पशु पालन विभाग से अपनी बात शुरू करता हूं। हमारे सम्माननीय रामकुमार यादव जी गरीब लोगों की बात कर रहे थे। वास्तव में पशुपालन विभाग में जैसे मछली का और मुर्गी का काम है। इसमें केंद्र सरकार ने बड़े व्यापारियों के लिये सब्सिडी दी है। इसमें 50 लाख से ऊपर, 02 करोड़ से 04 करोड़ रूपये तक का व्यवसाय करने वालों को सब्सिडी दी जाती है। यदि आज कोई गरीब व्यक्ति 02 लाख का या 05 लाख का काम करना चाहता है तो उसमें सब्सिडी नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे व्यापारी व्यापार करना चाहते हैं, उनको पर्याप्त सब्सिडी दी जाये, जिससे उनको रोजगार मिले।

सभापति महोदय, खनिज विभाग के बारे में बोलना चाहूंगा। आप 05 साल में डी.एम.एफ. मद में घोटाले की बात करते हैं। आपकी 15 साल की सरकार में कलेक्टर साहब अपने बंगले में स्वीमिंग पुल बनाते थे।

श्री राजेश मूणत :- अच्छा, स्वीमिंग पुल कब बना, वह आपको पता है या नहीं है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपकी सरकार में बना है।

श्री राजेश मूणत :- नहीं। फिर आपको गलत, कन्फ्यूजन है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं। आपकी सरकार में दंतेवाड़ा में बना है, मैं कन्फ्यूज नहीं हूँ।

श्री रामकुमार यादव :- आप ही के सरकार में बने हे।

सभापति महोदय :- आपस में बात न करें। आप विषय पर आईये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, खनिज विभाग में खनिज संसाधन ...।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय यादव जी सही कह रहे हैं । वह दंतेवाड़ा में नहीं बना था, सुकमा में बना था मैंने ही उसे तगाड़ी ले जाकर पाटा था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, खनिज विभाग में कुछ जिले ऐसे हैं, जहां पर डी.एम.एफ. का फण्ड बहुत कम है। जैसा कि हमारा महासमुंद जिला है तो जिस जिले में जहां पर डी.एम.एफ. की धनराशि ज्यादा है, उस जिले की राशि मात्र 10 करोड़ रूपये में बलौदा बाजार से बहुत कम आ रहा है। चूंकि रायगढ़ की तरफ से हमारे महासमुंद जिले से लगा हुआ है और वहीं से गाड़ियां गुजरती हैं तो निश्चित रूप से हमारे जिले को भी डी.एम.एफ. फण्ड की राशि मिले। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं परिवहन विभाग के संबंध में कहना चाहता हूँ। यहां परिवहन विभाग तो ऐसा चल रहा है कि आप हाईवे में जाएंगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है और आप दूसरी सड़क में जाएंगे तो आपको परिवहन विभाग को टैक्स देना पड़ रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में परिवहन विभाग को छोड़कर, खल्लारी थाने में नया टी.आई. आया है उनको बगैर शुल्क दिये, वहां से एक गाड़ी भी नहीं जा रही है। वहां ज्यादा वालों के लिए उन्होंने गाड़ी के अंदर एक झोला रखा है, वह हाथ में नहीं लेते हैं। वह कहते हैं कि आप इस झोले में डालिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वहां उस खल्लारी थाने में झोले की व्यवस्था बंद हो और सबसे वसूली भी बंद हो। मैं यह देखता हूँ कि इस सरकार में यह झोले का सिस्टम कब तक बंद होगा। अगर यह व्यवस्था बंद नहीं होगी तो मैं आपसे अगली बार फिर से निवेदन करूंगा...।

श्री उमेश पटेल :- आपने यह कोई नया सिस्टम बना दिया है।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात और कहना चाह रहा हूँ। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी पंचायत विभाग से आये हैं और मैं भी पंचायत विभाग से छोटे जनप्रतिनिधि के रूप में यहां तक पहुंचा हूँ। आज निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों का अधिकार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत का अधिकार कम होता जा रहा है। आज हमने उन्हें 50 लाख रूपये तक के राशि के अधिकार दिया है, लेकिन उन्हें धरातल में नहीं मिल रहा है। अन्य विभागों के जो बजट का काम है..।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें 50 लाख रूपये तक का जो काम है, यहां अन्य विभागों के बजट का होता है, वह भी सरपंचों को दिया जाये। अब अधिकार के मामले में तो केवल नामांतरण बच गया है। उनको हर विभाग में व्यापक रूप से अधिकार दिया जाये। मैं इसी बात का निवेदन करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की चर्चा में मांग संख्या 1, 2, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 56, 60, 65 और 71 के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए अवसर दिया है। उसके लिए मैं, आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यहां एक संतुलित बजट आया है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि आज जितनी जांच करानी है, आप करा लीजिए। हम लोगों ने उसकी तैयारी कर ली है। यहां प्रशासन में और अधिक कसावट लाने के लिए छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरों की नई इकाई कार्यालय दुर्ग में खोल रहे हैं। इसके लिए 35 नवीन पदों को भी सृजित किया जा रहा है। इसके लिए एक करोड़ रूपये का प्रावधान है। इसमें माननीय सदस्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां-जहां घोटाले हुए हैं, वहां-वहां हर एक बात की जांच करायी जाएगी। सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है और हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। मंत्रालय में भी 140 नवीन पदों का सृजन किया गया है उसके लिए 5 करोड़ 30 लाख रूपये का बजट का प्रावधान किया गया है। मैं इसका भी समर्थन करता हूँ। राज्य में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों में 6 नवीन पदों को सृजित किया जायेगा, इसके लिए 20 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, संचालनालय के अंतर्गत रायपुर के जो भवन हैं यानी खनिज विभाग के जो भवन हैं। साथ में क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में खोला जाएगा, उसका भी प्रावधान किया जा रहा है। कटघोरा, डोंगरगढ़ जो रेल लाईन है उससे हमारी जो माईनिंग है उसमें काफी गति आएगी और खनिज संपदा का काफी आसानी से खनिज सपंदा का परिवहन हो पायेगा, उसके लिए भू-अर्जन के लिए बजट में 245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह एक नई राह बनाने वाला कदम है। कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाईन के लिए नवीन मद में बजट में 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चिरमिरी-नागपुर हाल्ट की नई रेल लाईन के लिए भी बजट में 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में काफी खनिज संसाधन भरे हैं, उनको सही तरह से कैसे यूटीलाईज किया जाये, उसके लिए पूरा चैनल तैयार किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा विभाग की बात करना चाहूंगा। 5 एच.पी. तक के कृषि पंपों को वार्षिक 7500 यूनिट तक नि:शुल्क विद्युत प्रदाय करने हेतु 05 हजार 500 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। इस योजना में 06 लाख 96 हजार कृषि पंपों को लाभ मिल रहा है। इसका मैं समर्थन करते हुए यह भी कहूंगा कि हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत 43 लाख 34 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट की खपत तक हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलेगा, इसके लिए बजट में 01 हजार 274 करोड़ रुपये के प्रावधान का मैं समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कृषकों को सिंचाई की सुविधा हेतु सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना हेतु बजट में 670 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस देश में Grid Connected Solar Rooftop एक नया कांसेप्ट आया है। अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनें। हम हर मकान से इतनी ऊर्जा का निर्माण करें कि अपने घर में ही बिजली की व्यवस्था कर लें। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत आगे की सोच है जो देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारी राज्य सरकार ने इसके लिए योजना बना ली और इसको क्रियान्वित किया जायेगा, उसका मैं अभिनंदन करता हूं।

माननीय सभापति जी, आबकारी विभाग की बात करना चाहूंगा। सेन्ट्रलाईज्ड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर हेतु बजट में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि आबकारी के क्षेत्र में चीजों को नियंत्रित किया जाये, नियंत्रण बढ़ सके। तकनीकी आधारित प्रयोगों के माध्यम से हम सरकार के खजाने के लीकेज को कम करना चाहते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की बात करना चाहता हूं। इस बजट में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासनिक कार्यों में तेजी और शासन के धन के कपटपूर्ण संव्यवहार पर रोक तथा प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए आई.टी. अधोसंरचना का तेजी से विकास होगा। राजधानी रायपुर से लेकर हर ग्राम पंचायत को जोडने का काम किया जायेगा। इसके लिए बजट में 266 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका मैं अभिनंदन करता हूं, समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राज्य की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि 1 हजार गावों को वाई-फाई से जोड़ा जाये। इसके लिए बजट में 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस तरह की ढेर सारी योजनायें हैं। चूंकि समयाभाव है तो मैं कुछ बिन्दुओं की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं पहले माईनिंग विभाग की बात करना चाहूंगा। पिछली सरकार में छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटने का जो काम हुआ है, उसका उदाहरण यह है कि माईनिंग विभाग पिट-पास जारी नहीं करता है। इसमें इतना बड़ा खेल हो रहा है कि पिट-पास जारी किये बगैर वहां से अवैध उगाही की जाती है। उसकी ओर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और बाकी हमारे माननीय मंत्री जी लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें अगर 10 हजार क्यूबिक फिट के लिए पिट-पास जारी हुआ तो माईनिंग 20 हजार क्यूबिक फिट की जाती है। डी.एम.एफ. फंड में जो पैसा आना चाहिए, गौण खनिज का जो पैसा आना चाहिए, वह कुल मिलाकर पिछले 05 सालों की सरकार ने सरकार को नुकसान करते आई है। उससे छत्तीसगढ़ महतारी के खजाने को इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा रहा। आज भी अगर ये चीज जारी है तो इसका परीक्षण कराकर ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने की लीज मिलती है, उससे ज्यादा की माईनिंग की जाती है और सरकारी खजाने को नुकसान होता है। मैं अपने क्षेत्र में जानता हूं कि कितने सारे माईन्स हैं और यहां यह खेल हो रहा है।

सभापति महोदय :- चलिये, कृपया समाप्त करिये।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अभी बाकी है। मंदिर तक को खोद दिया गया है। इस पर अधिकारी, कर्मचारी चुप्पी साधे रहते हैं। पिछली सरकार में रेत का ऐसा उत्खनन हुआ है कि नदियों का रूख मोड़ दिया गया। नदियों की दिशा बदल गई, इतना भ्रष्टाचार हुआ है । इस ओर भी मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आबकारी विभाग की बात करूं तो हम लोग शराब में परेशान थे। शराब के ऊपर कार्रवाई हुई। जिन लोगों ने इसमें किया, खोखे में धोखा हुआ है। जिस खोखे को 76 रूपये किलो में बेचा गया, उसको 12 रूपये किलो में भी बेचा गया है। पिछले साल किलो के हिसाब में बेचने पर अगर डेढ़ करोड़ रूपये की वसूली हुई तो अगले साल उसको नग के हिसाब से बेचा गया, जिससे एक करोड़ रूपये की आमदनी हुई, जिससे खोखे में धोखे का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं माननीय मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इसमें भी जांच होनी चाहिए। जब यह सामने आयेगा तो यह बहुत बड़ा घोटाला है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से परिहवन विभाग के लिए एक आग्रह करना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे बनने के बाद जो सड़कें गांव से गुजरती थी, वहां से सभी बस भी गुजरा करती थीं, लेकिन अब नेशनल हाईवे गांव के बाहर से गुजरती है तो जो गांव के छात्र, छात्राएं और लोग हैं, उनको बस पकड़ने के लिए सड़क तक आना पड़ता है जो उनके गांव से एक-डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि छात्राओं की सुरक्षा और गांव वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिहवन विभाग यात्री बसों का रूट गांव के अंदर से बनाने का कष्ट करें और प्रदेश स्तर में यह नियम बनाया जाये कि जो यात्री बस है, वह गांव से गुजरे और ट्रांसपोर्टेशन में जो दूसरे माध्यम ट्रक वगैरह है, उनको बाहर से गुजारने दिया जाये ताकि गांववासियों को लाभ मिल सकें। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- लालजीत सिंह राठिया।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में भी वह सांसद रहे हैं और आज मुख्यमंत्री बने हैं। उनके विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारी कोयला की खदानें हैं, वहां पर बहुत सारी खनिजें हैं, पूरा रायगढ़ क्षेत्र कोयला से भरा हुआ है। पूरा देश-दुनिया को वहां से कोयला जाता है। आज वहां पर यह स्थिति बनी हुई है कि चारों तरफ से ट्रेफिक जाम है। यदि कोई व्यक्ति रायपुर से अम्बिकापुर, जशपुर जाना चाहे तो उस रूट से जाम में फंस जाते हैं, वहां इतनी खराब स्थिति है। वहां की गरीब आदिवासी किसान लोग हैं, जो गांव के गांव उजड़ गये हैं। आज हमारा तिलाईपाली और

एन.टी.पी.सी. का जो प्रोजेक्ट है, वहां पर पूरे 8 के 8 गांव के पूरे जंगल के जंगल उजड़ गये हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वहां पर आज के आधुनिक युग में सिर्फ मशीनों से काम हो रहे हैं। वहां बड़े-बड़े पोकलेन, ट्रेलर मशीनें चल रही हैं, लेकिन वहां के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और ना ही पुनर्वास पर लोगों को सही ढंग से मुआवजा दिया गया है। आज आप वहां की स्थिति को देखेंगे तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। सभापति महोदय, हमारे यहां जो बरौद की कालरी कोयले की खदान है, वह आजादी से पहले सन् 1938 की खदान है, जो अब तक संचालित है। वहां पर इतना ज्यादा कोयला उत्पादन हो रहा है, लेकिन वहां के रहने वाले लोगों को न किसी प्रकार की सुविधा, न कोई पुनर्वास की व्यवस्था, न रहने, खाने-पीने, न चलने और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आज वहां के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, जिससे बड़ी-बड़ी मशीनें चल रही हैं, उसको वहां के लोग चला सके, उससे अपना जीवन जीविका कर सकें, लेकिन सरकार के द्वारा खनिज विभाग के द्वारा वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज सरकार को इन सब चीज की चिंता करने की आवश्यकता है कि वहां इन सबके लिए आई.टी.आई. केन्द्र खोला जाये, कंपनियों को निर्देश किया जाये कि इनको उस लायक बनाया जाये, उन लोगों को सक्ष्म जाये और जो जैसा पढ़ा-लिखा है, वैसा उनके लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाये। आज हमारे कोरबा कोल माइन्स के हरदीबाजार का कुसमुण्डा का जो एस.सी.सी.एल. की प्लांट है, वहां पर किसानों को डबल कीमत पर मुआवजा दिया जाता है और हमारे यहां फारेस्ट होने के कारण कम कीमत पर पुनर्वास की योजना का मुआवजा दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि समान स्तर पर चूंकि हमारे कोयले की ग्रेडिंग भी वही है और वहां के कोयले की भी ग्रेडिंग वही है, दोनों का ग्रेड समान है इसलिये वहां जो रेट निर्धारित होता है वही रेट हमारे यहां के लोगों को भी दिया जाये, पुनर्वास की जो कीमत है, जमीन की जो कीमत है, उस मकान की जो कीमत है, जैसा है वह व्यवस्था की जाये । चूंकि आज इससे बहुत नुकसान हो रहा है । हमारे गरीब आदिवासी लोग हैं, वे नौकरी करना चाहते हैं । नौकरी के नियम में भी हमारी जो पुनर्वास नीति है । नौकरी की जो नीति है उसमें भी सरकार के द्वारा थोड़ी शिथिलता लायी जाये चूंकि गरीब आदिवासी लोग हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह समय पर पूरा जल्दी से जल्दी हो सके और उनको जल्दी रोजगार मिल सके ।

माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा विभाग में कहना चाहूंगा । हमारे यहां ऊर्जा विभाग में, मेरे यहां हाटी में 220 के.व्ही. सबस्टेशन की घोषणा हो चुकी है और उसके लिये जल्दी से जल्दी काम को चालू किया जाये ताकि वहां किसानों की बिजली में जो कटौती हो रही है अर्थात् बिजली कटौती हो रही है, बिजली में समस्या आ रही है, किसानों को खेती-बाड़ी करने के लिये सही समय में पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है उस समस्या से निजात मिल सके और किसानों को आगे बढ़ाने के लिये

हमारे क्षेत्र में कृषि हेतु पम्प कनेक्शन के जो आवेदन आये हुए हैं, उन सभी को स्वीकृत किया जाये ताकि जल्दी से जल्दी कार्य प्रारंभ किया जा सके और किसान खेती-बाड़ी में आत्मनिर्भर हो सकें ।

माननीय सभापति महोदय, यह हमारे यहां की मांग थी । मैं हमारे यहां रायगढ़ में विमानन विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी यह कहना चाहूंगा कि वहां पर काफी दिनों से हवाई सेवा की मांग की जा रही है, हम लोग लगातार उसकी मांग करते आ रहे हैं । वहां जो चक्रधर कोड़ातराई हवाई-पट्टी है उसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाये ताकि वह हवाई सेवा से जुड़ सके और देश-दुनिया में समय पर जल्दी पहुंचा जा सके । माननीय सभापति महोदय, मैं ग्राम उद्योग विभाग में कहना चाहूंगा क्योंकि मैं जंगल में रहता हूं । जंगल में कोसा पालन करने वाले लोग मुझसे मिलते रहते हैं वहां पर कोसे की जो कीमत है वह बहुत कम है । उससे उनको सही ढंग से फायदा नहीं हो पाता, वे खाली मजदूरों की तरह काम करते हैं, उसको उद्योग की दृष्टि से देखा जाये, चूंकि कोसा उद्योग के नाम से उसको कहा जाता है ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें । बाकी लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, इसलिये उसमें वृद्धि की जाये और इसमें शासन की जो योजना है ।

सभापति महोदय :- चलिये । आप मुख्यमंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं किसान के विषय में बोल लेता हूं । हमारे यहां वेटनरी विभाग में किसान लोग गाय, मुर्गी-बकरी पालन आदि करते हैं उनको भी अनुदान देने की आवश्यकता है । पहले नाबार्ड की योजना से किसानों को बहुत सारा अनुदान मिलता था ।

सभापति महोदय :- आप लिखित में दे दीजिये । श्रीमती भावना बोहरा ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा बोल लेता हूं । मुझे एक मिनट बोलने दीजिये । मैं कभी-कभार तो बोलता हूं । मैं किसानों की मुद्दे की बात करता हूं ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, मछली पालन विभाग। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मछली पालन विभाग भी है तो इसके लिये किसानों को ज्यादा से ज्यादा अनुदान देने का निर्देश करें । खेती के साथ-साथ मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन यह भी करें ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें । श्रीमती भावना बोहरा । आप लिखित में दे दीजियेगा ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं लिखकर तो दूंगा। हमारे यहां जंगल है, जंगल में हाथी है और जब गांव में हाथी आता है तो हमारे यहां लाईट को बंद कर दिया जाता है । इसके लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? ऊर्जा विभाग क्या उपाय कर रहा है ?

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा । ऐसी कोई योजना बनायी जाये ।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री नहीं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- हां, मुख्यमंत्री जी । भई, वह भी हमारे वहां के सांसद रहे हैं, उनके क्षेत्र में भी पूरा जशपुर, पूरा सरगुजा आता है ।

सभापति महोदय :- चलिये ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट । क्योंकि पूरे प्रदेश में वह हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यह अकेले मेरे जिले का प्रश्न नहीं है। आपके बालोद और बस्तर में भी हाथी पहुंचने वाले हैं, पहुंच गये हैं। आपके यहां भी लाइट कटिंग होगी तो आप कैसे करेंगे? उसकी आप चिंता कीजिए।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- इसलिए मैं पूरे प्रदेश की चिंता कर रहा हूं। यह अकेले की समस्या नहीं है। पूरे सरगुजा में भी मेनपाट में भी हाथी चढ़े हुए हैं।

सभापति महोदय :- चलिए हो गया। क्षेत्र की मांग हो तो रखिए और समाप्त करें।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- पीने के पानी की समस्या हो जाती है। आजकल बोरिंग कोई नहीं टेरता है। कुआं कोई नहीं तिरता है। सब बिजली से पानी निकालते हैं। पूरा घर में बर्तन मांजने, खाना बनाने, चाय नाश्ता पीने के पानी तक के लिए 3-3, 4-4 दिन तक लाइट कट जाती है।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करें। हो गया।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- इसलिए सब लोग परेशान रहते हैं। अंधेरे में रहते हैं। इसके लिए सरकार को सोचने की और इसके लिए केबल और तार करने की योजना बनाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय :- चलिए, हो गया।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- अब जल्दी-जल्दी बोलते हैं। यहां हाथी वाली समस्या है। नहीं तो अमरजीत भैया मुझे बोलते थे, हमारे बैज साहब बोलते थे। हाथी वाले महावत बोलते थे। उसी तरह सब लोग महावत हो जाओगे तो मुश्किल हो जायेगा। ये हाथी जी के लिए हमें चिंता करनी चाहिए।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करें।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- उनके रहने खाने-पीने के लिए व्यवस्था करने की आवश्कता है। सभापति महोदय, आप बस-बस कह रहे हैं तो बस करता हूं। आपने बोलने का समय दिया धन्यवाद।

सभापति महोदय :- चलिए, भावना बोहरा जी।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- सभापति महोदय, राठिया जी को सदन में पहली बार बोलते हुए सुनी हूं तो इतना हक बनता है। मैंने आपको अपने में से दो मिनट दिया है। आदरणीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के विषय पर बोलने के लिए अवसर दिया है तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी के अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए मुझे अवसर मिला।

सभापति महोदय :- ज्यादातर अपने क्षेत्र की बात रखें।

श्रीमती भावना बोहरा :- जी, सभापति महोदय जी, मैं बहुत कम शब्दों में ही अपनी बात खत्म करूंगी। जिस तरीके से हमने पहले भी कहा है..।

श्री उमेश पटेल :- संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। क्या उपस्थिति है, देखिए। अधिकारी दीर्घा भी नहीं भरा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विपक्ष को बोलना है। विपक्ष का क्या हालचाल है, जरा देखिए।

श्री उमेश पटेल :- ये तो बोलेंगे ही।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या हालचाल है?

श्री उमेश पटेल :- ये बोलेंगे। आप तो बुला लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, तो विपक्ष की जरूरत है।

श्री उमेश पटेल :- खुद मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं है।

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय जी, ये मेरे टाइम में included नहीं होगा। ये टाइम से बाहर लिया जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विपक्ष कितना गंभीर है, देखो।

श्री उमेश पटेल :- खुद मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। आप बैठे हैं, आपका कहीं और ध्यान है। सारे मंत्री का भी ध्यान नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विपक्ष कितना गंभीर है, जरा देखिए।

श्री उमेश पटेल :- अधिकारी दीर्घा भी नहीं भरा हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विपक्ष कितना गंभीर है, जरा देखिए।

सभापति महोदय :- प्लीज, बैठिए-बैठिए।

श्री उमेश पटेल :- आप जरा गंभीरता से लें। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुदान मांगों पर चर्चा है।

सभापति महोदय :- पटेल जी, बैठिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय जी, ये मेरे समय से कट नहीं होगा। इतना समय एडिशनल रहेगा। सभापति महोदय, जैसे हम जानते हैं छत्तीसगढ़ को हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि संसाधनों

से भरा हुआ हमारा प्रदेश है, लेकिन फिर भी जो संसाधन है, उनकी अपनी एक क्षमता होती है। मुझे लगता है कि उसका दोहन करने का भी उसकी एक सीमा होती है। तो उसी लिए सोलर की हम बात करें, लगातार प्रधान मंत्री जी के विषय में भी बोलें या फिर हमारे छत्तीसगढ़ का जो बजट है, उसमें सौर ऊर्जा को लेकर काफी अच्छा प्रावधान किया गया है तो मुझे लगता है कि इसे बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी सोलर ऊर्जा के जो प्लांट्स लग रहे हैं तो कहीं न कहीं हम जो घर बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की योजना है कि घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर विद्युत का उत्पादन है, मुझे लगता है कि इसमें हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और इसे प्रमोट करने के लिए हमें ये न सिर्फ बजट में बल्कि इसको लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए भी हमें अलग से गांव वाले क्षेत्रों में कैंप लगाना चाहिए। मेरा ऐसा सुझाव है। दूसरा विषय आदरणीय मैं परिवहन को लेकर कहना चाहूंगी। मैं वही विषय सामने ला रही हूं, जिसको क्षेत्र में हमने जो चीजें देखी हैं परिवहन को लेकर बहुत सारी अनियमितताएं अभी भी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। हम सबसे पहले सी.सी.टी.वी. कैमरे की बात करते हैं। महोदय जी, मैं बताना चाहूंगी कि स्कूल में जो बसें चलते हैं, सारे स्कूल से प्राइवेट स्कूल में यह नियम है कि आपके बच्चे जहां बैठे, तो बस में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना बहुत compulsory है और मुझे लगता है कि 99 परसेंट स्कूल इस चीज को फॉलो करते हैं, लेकिन अंदर गांव में जो बसें चलती हैं, जो प्राइवेट बसें हैं, जो परिवहन का काम हो रहा है, उसमें हम पाते हैं कि सी.सी.टी.वी. कैमरे की बात है, वहां जाकर वह नियम ध्वस्त हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से स्कूल बसों में जो सी.सी.टी.वी. कैमरे को compulsory किया गया है, उसी तरीके से जो प्राइवेट बसें हैं, उसमें भी सी.सी.टी.वी. कैमरे होने चाहिए ताकि बच्चियों की सुरक्षा की जो बात हम लगातार करते हैं, जो विषय आता है, मुझे लगता है कि काफी गंभीर विषय है। दूसरा विषय महिलाओं और बच्चियों को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि जो परिवहन में जो प्राइवेट बसें चलती हैं आज भी हम उसमें सीट आरक्षित जरूर बोलते हैं कि ये महिलाओं के लिए दो सीट आरक्षित किया गया है, लेकिन जब आप स्थिति देखेंगे तो महिलाएं खड़ी रहती हैं, उसमें युवा हैं या अन्य जो भी पुरूष वर्ग हैं, उसमें वही बैठते हैं। तो महोदय जी, आपसे निवेदन है कि ये जो 33 परसेंट उसमें बस में सीटों पर बैठने के लिए जो आरक्षण है, वह compulsory हो। तीसरा विषय, कॉलेज वाली बच्चियां जब बस का परिवहन के लिए बस का उपयोग करती हैं तो उनको दिक्कतें ये आती हैं कि बच्चियों के लिए अलग से बस स्टॉप की व्यवस्था नहीं की गई है । बस वालों की मनमानी है कि वे कहीं पर भी बसें रोकते हैं फिर चाहे वह बाजार हो या मार्केट वाला एरिया हो । कॉलेज की बच्चियों के लिए हर शहर और कस्बे में बस स्टॉप की व्यवस्था होनी चाहिए । मैं तीसरा विषय आबकारी विभाग का लेना चाहूंगी । जिस तरह से पिछले पांच सालों में लोगों में शराब की लत बढ़ी है, शराब का कारोबार फैला और अवैध शराब के कारोबार में नियंत्रण करने के लिए सरकार जागरूक है । लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी कुछ नियम होना चाहिए । सबसे पहला नियम यह होना चाहिए कि जिस तरह से

नेश्नल हाईवे में सिस्टम है कि नेश्नल हाईवे से निश्चित दूरी पर दुकान होनी चाहिए उसी तरह स्टेट हाईवे में भी निश्चित दूरी के अंतराल में शराब भट्टी होनी चाहिए । स्टेट हाईवे से लगी हुई शराब भट्ठियां अभी भी संचालित हो रही हैं । जब हम इस विषय को लेकर गांव में जाते हैं । कल ही मेरे क्षेत्र का एक उदाहरण बताउंगी । पांडातराई शहर में नयापारा मोहल्ला है, जैसे ही हम अंदर आते हैं सामने में ही शराब भट्ठी तीन साल से संचालित है, जिसका लगातार विरोध होता आ रहा है । जब बच्चियां वहां से निकलती हैं तो यह स्थिति होती है कि जो लोग वहां शराब पिए रहते हैं, वे उनके कपड़े तक खींचने लग जाते हैं । निवेदन यह है कि पहले इन स्थानों से शराब भट्ठी हटाई जाए । उसको जहां भी स्थानांतरित करें तो उसकी बाउंड्री की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि बाहर से आवागमन करने वालों को अंदर की गतिविधियां दिखाई न दें, बाउंड्री के साथ उसमें गेट का लगना भी जरूरी है। वहां शराबियों के चलते बहुत दर्दुशा है । मुझे लगता है कि इस दिशा में पहल की जरूरत है । महोदय, मैं ग्रामोद्योग के विषय में कहना चाहूंगी । आज हम लगातार बुनकर समितियों की बात करते हैं, कोसा को बढ़ाने की बात करते हैं, हाथकरघा की बात करते हैं । हर सरकार ने उसमें बजट जरूर रखा है । चूंकि मैं एक जिला पंचायत सदस्य भी हूं और लघु उद्योग मेरे डिपार्टमेंट में ही आता है, मैं सभापति हूं। मैंने देखा है कि इसे लेकर लोगों में अवेयरनेस नहीं है । अधिकारी भी यह मानकर चलते हैं कि यह सिर्फ एक खानापूर्ति वाला डिपार्टमेंट है । जो सरकारी जरूरतें होंगी, जो डिमांड वहां से आएगी उसी को सप्लाई करेंगे । लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि सरकारी विभाग के साथ साथ छत्तीसगढ़ में निवास करने वालों को भी इसमें जागरूकता लानी चाहिए । छोटे-छोटे कैम्प के माध्यम से, समूहों के माध्यम से बुनकर और हाथकरघा को बढ़ावा देने की जरूरत है । मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा उठाए गए तीनों मसले गंभीर हैं इसलिए मुख्यमंत्री जी आगे अच्छी पहल करेंगे । सीमित समय में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद् ।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- अपने क्षेत्र का विषय रखिएगा ।

श्री ब्यास कश्यप :- क्षेत्र का नहीं, प्रदेश का भी नेतृत्व करते हैं । कुछ बात मन में है उसे सुन लीजिए, क्षेत्र की बात भी उसमें शामिल है । सभापति जी, मैं सामान्य प्रशासन से प्रारंभ करूंगा । कल ही जांजगीर में प्रदेश स्तरीय कर्मचारियों का एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में अतिथि बनकर जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ । उस पर बातें आई, सरकार चाहे किसी की रहे, शुरू से यही रही है कि राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत डी.ए. इस सरकार के द्वारा भी नहीं दिया गया । जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो भाजपा वाले भाई बोलते हैं और आज भाजपा की सरकार है तो हम कांग्रेस के लोग इस बात की मांग करते हैं कि उनको 4 प्रतिशत डी.ए. दिया जाए । इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी अनुमति दे दी गई है । कर्मचारी हित हेतु छत्तीसगढ़

शासन को ध्यान देना चाहिए और मैंने देखा कि भारत की वर्तमान वित्त मंत्री जी के द्वारा आज सातवें वेतनमान और आठवें वेतनमान नहीं लेने की बात कही है । तो निश्चित रूप से भविष्य में कर्मचारियों के हित पर हमें ध्यान देना होगा । सामान्य प्रशासन विभाग में मैं कहना चाहूंगा कि सरकारें आती रहती है, जाती रहती हैं । सरकार चलती है कलेक्टर से, जब नेतागण जाते हैं तो उनको अपने ऑफिस, सर्किट हाऊस में बुलाकर निर्देश देते हैं परंतु इस बात का खेद है कि हमारे देश के माननीय गृहमंत्री का कार्यक्रम 22 तारीख को था, 21 फरवरी को भाजपा के नेताओं के द्वारा प्रथम श्रेणी अधिकारियों को भाजपा कार्यालय में बुलाकर निर्देश देना उचित बात नहीं है । भविष्य में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए । सामान्य प्रशासन विभाग में मेरी यह आपत्ति है ।

सभापति महोदय, मैं ऊर्जा विभाग की बात पर आ रहा हूं। हमें विद्युत के दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं एक किसान हूं और मेरा यह अनुभव है कि सरकार के द्वारा हम किसानों को बिजली दी जाती है। हम भी उसका कैसे दुरूपयोग करते हैं, मैं सबकी संज्ञान में लाने के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूं। हमारी संगीता बहन चना के बारे में बात कर रही थी। मुंगेली क्षेत्र पहले चना का क्षेत्र हुआ करता था परंतु जब से धान का समर्थन मूल्य या धान का मूल्य बढ़ने के कारण अन्य फसलों की अपेक्षा हमारा ध्यान धान के उपर गया है। हम धान के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। हम बिजली लेते हैं, ऊर्जा सरकार की रहती है, हम लोग भू-जल धरती मां की तरफ से लेते हैं, उसमें बिजली का भी दुरूपयोग हो रहा है और भू-जल का भी दुरूपयोग हो रहा है। अगर हम धान की बोनी के लिए विद्युत न दें तब जाकर सरकार की जो नीति रहती है कि फसल चक्र परिवर्तन करेंगे, वह सफल होगी। दलहन, तिलहन की ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इस विषय में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। हम किसान भाई जो बिजली से धान उत्पादन करते हैं, उसमें हमारी ऊर्जा की भी खपत होती है और भू-जल का भी दोहन होता है। अभी मैं शहरी क्षेत्र में निवास करता हूं। शहर विस्तार कर रहा है, जब शहर विस्तार कर रहा है तो उसके नये-नये मकान बन रहे हैं, जब उनको विद्युत कनेक्शन देने का रहता है तो विद्युत विभाग के पास खंभे के लिए पैसे नहीं है। वे एक खंभा लगाकर एक-एक खंभे में 100 से ज्यादा मीटर लगा देते हैं, वह मीटर अस्थायी रहता है, अस्थायी मीटर में पैसा भी ज्यादा लगता है। वे दुर्घटना को भी आमंत्रित कर रहे हैं। कम से कम ऐसे चिन्हांकित जगहों पर विद्युत कनेक्शन के लिए विस्तार किया जाए। उसके लिये राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन उस पर पैसे लगाकर इस व्यवस्था को सुधारने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं पुनर्वास के विषय में बोलना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत ताप संयंत्र स्थापित है। भू-स्थापित को पुनर्वास निति के तहत संविदा पदों पर न्यूनतम वेतनमान पर नियोजित की जा रही है। नियमित पदों पर भी भू-स्थापितों को नियोजित नहीं

किया जा रहा है। उनको अवसर मिलना चाहिए। मैं यह पूरे प्रदेश के लिए बात कर रहा हूं। यह बातें पुनर्वास नीति के तहत आनी चाहिए।

सभापति महोदय, खनिज संसाधन की बात है। DMF के माध्यम से विकास कार्य के लिए अधोसंरचना का जो मद होता है, वह मद कम मिल रहा है। हम जनप्रतिनिधि हैं, जब हमको देने की बारी आती है, तब यह बात आती है। यह विकास का विषय है, जिससे अधोसंरचना मद का निर्माण होता है। अधोसंरचना मद का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को भेजना चाहिए। छत्तीसगढ़ पिछड़ा क्षेत्र है, हमको राशि मिलती है लेकिन राशि का उपयोग अन्य मदों पर कर लेते हैं। अधोसंरचना मद पर हमारा बजट कम रहता है। इस विधान सभा से, माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से केन्द्र सरकार के पास बात जानी चाहिए। जब DMF की बैठक होती है, तो कब किसको-किसको क्या देना रहता है, खाली लालीपॉप पकड़ा दिया जाता है, कई विधायकों की इस बात की शिकायत है, जब कलेक्टर महोदय पूरी बात करते हैं तो एक आग्रह है कि जो भी बात हो, उसी बैठक में क्लीयरकट आ जाये, इसको यह राशि इस काम के लिए देना है, जैसे बजट बनता है, वह पूरा हो। वह दस्तखत होकर जारी हो ताकि किसी के द्वारा मनमानी न की जाये। मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। जांजगीर जिले में क्रेशर उद्योगों के द्वारा अधिक जमीन को संग्रहित कर ली गयी है। अधिक जमीन को संग्रहित करने के बाद वहां से गौण खनिज, गिट्टी या जो भी पदार्थ निकलता है, उसका वह दुरूपयोग कर रहे हैं। उसको ब्लास्ट करना है तो आजकल नये-नये मशीन आ गये हैं, बोर करते हैं और बोर करने के बाद उसमें ब्लास्ट करते हैं और ब्लास्ट करने के बाद अत्यधिक मात्रा में खनिज निकलता है, उनको तो लाभ होता है, पर वहां पर जो आस-पास रहने वाले मकान हैं, वह मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कृपा करके इस व्यवस्था को भी सुधारना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं मत्स्य विभाग की बात करना चाहूंगा। प्रदेश में बारहमासी तालाब हमारे पूर्ववर्ती जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत है। प्रदेश में लगभग 14 हजार तालाब ऐसे हैं जो लबालब भरे रहते हैं। हमको हसदो का पानी लगातार नहरों के माध्यम से मिलता रहता है। लगातार पानी बहने के कारण हमारे यहां का तालाब पहले भी भरा हुआ था और आज भी भरा हुआ है। धान की खेती हो रही है, अभी भले ही बायीं-दायीं तरफ नहीं हो रही है।

सभापति महोदय :- ब्यास जी खत्म करिए। अपने क्षेत्र की बात रखिए।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मेरी दो चार बिन्दु है, मैं कह देता हूं। मैं सुझाव दे रहा हूं, कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। यह तालाब पहले और वर्तमान में भी भरे हुए हैं। मछली की बात है, मैं एक बात बता दूं। सभापति महोदय, मेरे 2-4 बिंदु हैं। मैं इनको कह देता हूं। मैं केवल सुझाव दे रहा हूं। मेरी कोई शिकायत नहीं है।

सभापति महोदय :- आप अपने क्षेत्र की बात रखिये।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि पहले और वर्तमान में भी तालाब भरे हुए हैं। मछली की बात हो रही है तो मैं एक बात बता दूं कि जब मेरे पास ट्रैक्टर था तो मैं तालाबों में नेटिंग करने के लिए जाता था। जब हम नेटिंग करके रेलवे स्टेशन आते थे तो रेलवे स्टेशन से हमारे यहां की मछली अन्य राज्यों में जाती थी। परंतु दुर्भाग्य है कि आज हम मछली उत्पादन में उस प्रगति से नहीं बढ़ पाये। हमारे माननीय तरूण चटर्जी जी भी हमारे जांजगीर में जाकर वहां की तालाबों का ठेका लेते थे और पर्याप्त मछली उत्पादन करते थे। मछली उत्पादन का स्तर गिरा है और हमें अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ा है। इसलिए हमें ऐसे तालाब, जो कि बारहमासी भरे रहते हैं, हम प्रयास करके उन सफल कृषकों को मत्स्य सेवा सहकारी समिति के माध्यम से अच्छा उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षण दें, ताकि वह उसका लाभ ले सकें। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि मैंने स्वयं अनुभव किया है कि पहले हमारे बंगाली भाई रेलवे में अफसर रहते थे और हमारे यहां की मछली कलकत्ता, राऊकेला और टाटानगर जाती थी। उनकी अपनी सुविधा के लिए बंबई-हावड़ा मार्ग पर स्टेशन होने के नाते एक्सप्रेस का ठहराव दिया गया। उन अफसरों के द्वारा यात्रियों के लिए कम और मछली की ट्रांसपोर्टिंग के लिए वह ठहराव दिया गया था। मैं कह रहा हूं कि हमें मछली पालन को बढ़ावा देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे यहां इतने तालाब हैं तो कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षा में मत्स्य कॉलेज की भी स्थापना हमारे जिले में होनी चाहिए।

सभापति महोदय, पशुधन विकास के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि पशुधन तेजी से घट रहा है। उसके घटने का एकमात्र कारण है कि हम ठीक से संधारण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कोसली गाय के संवर्धन के लिए काम होना चाहिए। मुझे पता है कि बृजमोहन भैया ने मुझे कामधेनु विश्वविद्यालय के कार्य परिषद का सदस्य बनाया था। डॉ. रमन सिंह जी उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे। मुझे पता है कि जब कामधेनु विश्वविद्यालय की बैठक होती थी तो उस बैठक में कोसली गाय के संवर्धन और उनको ज्यादा दूधारू बनाने के लिए 10 करोड़ रूपये की राशि दी गई थी। परंतु आज तक हम उसमें सफल नहीं हो पाये हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की कोसली गाय को हम कैसे दूधारू बनाये, इस विषय पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे जो नरवा, घुरूवा बने हुए हैं, उनपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ताकि हम पशुधन को संरक्षित कर सकें और उनके चारे की व्यवस्था कर सकें।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करें।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मेरा एक और विषय है - ग्रामोद्योग विभाग। लघु उद्यागों के लिए रीपा बनाये गये हैं। रीपा के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। उसकी संख्या बढाई जाए, ताकि हम ग्रामोद्योग की ओर बढ़ सकें। ऐसे ग्रामोद्योग के लिए जो ऋण का प्रावधान है, उसका सरलीकरण किया जाए। ताकि समय पर हमें ऋण मिल सके। ऋण स्वीकृति के पश्चात् उन्हें

प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाया जाए। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाए।

सभापति महोदय :- आप समाप्त करें। श्री राजेश मूणत जी।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं एक अंतिम विषय कहना चाहूंगा कि भारत का सातवां और छत्तीसगढ़ का एकमात्र कॉलेज चांपा में स्थित है जो वर्ष 2007 से प्रारंभ हुआ है। वहां पर शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर हो गया है। न वहां पर बच्चे दाखिला ले पा रहे हैं और न वहां के बच्चे पास हो रहे हैं। वहां पर स्थाई प्राचार्य नहीं हैं। वहां पर अभी भी 30 पदों में से 13 पद खाली हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस संस्था को तकनीकी शिक्षा को जोड़ा जाए। वह दूसरे माध्यम से हथकरघा चलाती हैं तो मैं चाहता हूं कि वहां पर तकनीकी लाकर शिक्षा के स्तर को सुधारें। ताकि वहां के पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार मिल सके। सभापति महोदय, भले जी आपने मुझे टोका, लेकिन मैंने अपनी बात पूर्ण की। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद।

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- सम्माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने हेतु खड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ राज्य में नई सरकार माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में बनी है। जिसकी दूरदृष्टि, एक सोच, एक कल्पना और एक विजन के साथ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य तरक्की और प्रगति की ओर कैसे आगे बढ़े। जब माननीय वित्त मंत्री जी ने एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ अपने विभाग की अनुदान मांगों पर अपनी बात रखी तो उन्होंने एक विजन रखा। वह विजन इस बात को साकार करता है कि जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की तो उन्होंने एक छोटे, समृद्धशाली और खुशहाल राज्य की परिकल्पना की। 15 साल तक डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में बी.जे.पी. की सरकार ने चलते-चलते ऐसे कई आयाम खड़े किये, जिनसे गरीब, किसान और मजदूर के हित में काम हुए हैं। उसी प्रकार से विष्णु देव साय जी की सरकार ने अपने विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से किसान, बहन, मजदूर, व्यापारी, बेरोजगार नौजवान के हित में कई विषय लेकर आये हैं । मैं ज्यादा भूमिका भी नहीं बाँधूगा, मैं प्वाइंट टू प्वाइंट बात करूंगा । एक विषय लेकर शुरू दिन से इस प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी और डबल इंजन की सरकार के साथ में विकास की गति को बढ़ाना, आमजन को वह सुविधा पहुंचाना, जिसका हक वह रखता है । इसीलिए हमने गरीब परिवार के प्रति, किसान के प्रति ध्यान दिया । छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, जहां धान की पैदावार होती है और किसान के हित में जब सरकार 31 सौ रूपये प्रति क्विंटल में 21 क्विंटल धान खरीदी का निर्णय करती है । यह फैसला कोई छोटा-मोटा फैसला नहीं है । जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट्स की घोषणा की, हम संकल्प-पत्र लेकर आये कि हम किसान को 3100 रूपए देंगे और हम 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे । हमारी सरकार

आते ही पहली किस्त में धान खरीदी की स्वीकृति, दो साल का बोनस, महतारी वंदन योजना में 12 हजार करोड़ का प्रावधान किया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, आपके घोषणा-पत्र में दो लाख रूपए के कर्ज माफी और 500 रूपए में सिलेण्डर देने की बात भी है ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए, टोका-टाकी मत करिए ।

श्री राजेश मूणत :- चिन्ता मत करिए, पिछले पॉच साल के इतिहास का पन्ना पलटकर देखिए, चेहरा अपना भी दिखता है । प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने काम तो कुछ नहीं किया, पी.एम. को आईना भेंट करने गए थे और पॉच साल खाली लिख-लिखकर बीता दिए । कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि किसान के दो साल को बोनस हम देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दी । दो साल में जनता ने वापस निपटा दिया । 500 रूपए में सिलेण्डर देने की बात आपने की थी। मैं रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब विजन हो, सोच हो, कल्पना को साकार करने की क्षमता हो, यह विष्णु देव सरकार के अंदर है और उन्होंने करके दिखाया । सत्ता में बैठते ही किसानों के हित में निर्णय किये, महतारी वंदन योजना के हित में निर्णय किए, 18 लाख परिवारों को पक्का घर देने का वादा किया, उसके सपनों को साकार किया । आपने नलजल योजना की टंकी तो नहीं बनाई, सिर्फ पाईप बिछाकर चले गए। यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि टंकी नहीं बनी और पाईप लाईन बिछा दी गई । टेण्डर किए और चल दिए । टंकी बनेगी, तभी तो पानी आएगा । पहले टंकी भरी जाएगी, उसके बाद में पानी आएगा । नलजल योजना का केन्द्र सरकार का 70 प्रतिशत तो आपने खर्च कर दिया, लेकिन अपने बजट में प्रावधान करके 30 प्रतिशत देना था, वह देने की व्यवस्था कर ही नहीं पाये ।

सभापति महोदय, एक-दो चीजों की ओर मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं । बहुत छोटे-छोटे उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं । जनसंपर्क विभाग बहुत बड़ा विभाग है और मैं कहता हूं कि यह पूर्व मुख्यमंत्री जी का आदर्श विभाग रहा है । चांद सुहाना लगता है, तेरे आगे । आगे कुछ नहीं कहना है । जनसम्पर्क विभाग में 800 करोड़ रूपए का जिस प्रकार से [xx] किया गया, यह हिन्दुस्तान के इतिहास में रिकार्ड बनेगा । चुनाव नहीं हुआ और सितम्बर में जनवरी का कैलेण्डर छाप दिया गया । चुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री तय हो गए । दो करोड़ रूपए खर्च कर दिए । वाह भई । ऐसा कौन सा विभाग है, जहां मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ा, लोकतंत्र की परम्परा चालू नहीं हुई, उसके पहले ही कैलेण्डर छाप दो । पूरा विभाग प्रत्याशा में चल रहा है । यह एक नया इतिहास है । कोई फाईल चलती है, कोई बजट आता है, कोई अनुमोदन होता है । अनुमोदन होने के बाद में उसकी प्रक्रिया है कि वर्क आर्डर दिया जाता है । बिना उसकी प्रक्रिया किए हो गया । एक होल्डिंग लगी तो चार होल्डिंग का बिल आ गया । 56 करोड़ पाम्पलेट छपे । कितने ? 56 करोड़ पाम्पलेट छपे । और प्रदेश की आबादी कितनी

? 3 करोड़ । कहां बॉटने गए थे मेरे भाई, किसको बांटे ? किन योजनाओं में गए ? यानि ऐसी [xx] जहां इच्छा है, वहां होर्डिंग्स लगा दो। अभी एक चीज बताया कि आपने 5 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया। आपने एक जगह 5 लाख लोगों को रोजगार देने वाली होर्डिंग्स लगा दी थी, दूसरी जगह 6 लाख लोगों को रोजगार देने की होर्डिंग्स लगा दी थी। श्री धरम लाल कौशिक जी के प्रश्न में सरकार उत्तर दे रही है कि 19,200 लोगों को नौकरी दी गई थी। तो यह 5 लाख, 6 लाख किसका था ? यह सोचने का विषय है। इसके अंदर मुख्यमंत्री जी है, नहीं। नीचे जो अधिकारी बैठे हैं, वह सालों से एक जगह बैठकर [xx] कर रहे थ, यह चिंता का विषय है। ये एजेंसियां कौन थी ? कहां जाकर काम करती थी ?

श्री विक्रम मण्डावी :- दिल्ली की सरकार ने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे कहा था, उसका क्या हुआ ?

श्री राजेश मूणत :- वह भी देंगे। आप चिंता मत करो। दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनेगी। मोदी सरकार, छत्तीसगढ़ में भा.ज.पा. की 11 की 11 सीट आ रही है, आप चिंता मत करो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, 36 हजार करोड़ रूपये का राशन घोटाला हुआ था। उसका थोड़ा हिसाब दे देते, एक एक चीज का हिसाब दे देते तो ज्यादा अच्छा था।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये।

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी, आप 5 साल रही हैं। आपकी तो चलती नहीं थी, बोल ही नहीं पाते थे। इनोवा का किश्त पट जाये, वह ही बहुत था।

श्री विक्रम मण्डावी :- अभी तो पट रहा है न, अभी आपका चल रहा है न ?

श्री राजेश मूणत :- अपन मिलकर चलायेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी तक सायलेंट हैं। आपके यहां की स्थिति को चन्द्राकर जी से अच्छा कोई नहीं बता सकता।

श्री राजेश मूणत :- बैठिये, बार-बार खड़ा होना ठीक बात नहीं है।

श्री राजेश मूणत :- अब क्या करेंगे ? मोहले जी देख ही नहीं रहे हैं। माननीय सभापति जी, आप जनसम्पर्क विभाग के अंदर पंजीयन करते हैं। लोकल पोर्टल चलता है, लोकल मैगजीन चलती है, लोकल पेपर चलते हैं, इनका हिन्दुस्तान में पंजीयन है। यहां तो प्रत्याशा में विदेश के लोगों को भी विज्ञापन दिया गया था। 19 लाख कुछ हजार रूपये का विज्ञापन, 12 लाख रूपये का विज्ञापन दिया गया था, मेरे पास दस्तावेज है। यह क्या है भाई ? अंधा बांटे रेवड़ी चुन-चुन के दो। क्या है ? यानि आपने उस विभाग को अपनी बफौती समझ ली। सभापति महोदय जी, मैंने पहले और विभागों में बातचीत की। मेरा जनसम्पर्क विभाग के 4 ध्यान आकर्षण लगा है। जितना लूट खसोट किया, छत्तीसगढ़ के प्रिंटिग वाले को छोटा-छोटा आर्डर मिला था। जैसे दिल्ली के अंदर एक स्कैण्डल निकल आया था- "कामनवेल्थ घोटाला", उस कामनवेल्थ घोटाले में कहा गया था कि अगर आपने टाईल्स फिटिंग की है तो वह आपको

मिलेगा। ये यहां पर भी ऐसे ही कर रहे थे। आपने इतना का काम किया है ? भाई, छत्तीसगढ़ के आदमी ने छोटी-मोटी प्रेस लगाया, छोटा-मोटा काम किया, फैल्क्स की मशीन लगाई, वह कहां से करोड़ों का टर्न ओव्हर ले आयेगा। यह प्रिंटिंग वाले कहां से ले आये ? कोई छत्तीसगढ़ वाला नहीं था, जिसने कभी जिन्दगी में काम नहीं किया। आपने इतने का काम किया है क्या ? तो वह कहां से करेगा ? एक फोटो यहां लगाओ, उसको उखाड़कर आगे ले जाओ, फिर आगे लगाओ, एक फोटो का तीन बिल बनाओ, ऐसा चलता था। इसीलिए इस विभाग को माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की पूरी टीम से आग्रह करूंगा कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्री राजेश मूणत :- मान्यवर, मैं अभी चालू हुआ हूं। थोड़ा सा मोहब्बत रखें। सभापति महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब छत्तीसगढ़ियां की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नवजवानों को रोजगार के नये नये आयाम खड़े करने के लिए अवसर मिलता है। सरकार किसकी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब छत्तीसगढियां की बात करते थे तो इस बात का भी ध्यान रखना था कि लोकल लोगों को रोजगार कैसे मिले ? इसीलिए खाली अनियमितता हुई थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और बताता हूं। एक फोटो छपा था। आपने 7 सौ रूपये का एक कैलेण्डर सुना है क्या ? साहब, जनसम्पर्क विभाग से 7 सौ रूपये का एक कैलेण्डर छपा था। अब आप बताओ ? चलिये, खत्म करो, इस विभाग को। मेरा इतना ही सुझाव है कि जो पूर्व में गलतियां हो गई थी, वह कम से कम ठीक हो जाये। जो गलत काम करने वाले हैं उनको सजा मिल जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं खनिज के ऊपर बात कर रहा हूं। जो रायल्टी-वायल्टी, दुनिया की बात छोड़िये। सभापति महोदय, अगर मेरी बात आपके माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाती है, मैं जी.ए.डी. के एक नियम पर अपनी बात रख रहा हूँ, सिर्फ सिंगल प्रश्न है । आज मान लीजिए, यदि किसी विभाग के पालिसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी अनुमोदन करेंगे, उसके विभाग का कोई डायरेक्टर उसे बदल सकता है क्या ?

श्री कवासी लखमा :- यह बीजेपी सरकार में हो सकता है ।

श्री राजेश मूणत :- सुनो ना दादी, आगे चालू हो रहा हूँ ।

श्री कवासी लखमा :- एक मिनट, जब धान ले रहे थे तो आपके मुख्यमंत्री जी का टी.वी. में, अखबारों और होर्डिंग्स में छपता है कि 3100 रूपये में धान खरीदी होगी । मोदी से लेकर सभी नेताओं ने यह बात कही है, हमारा कलेक्टर सोसायटी में घूम-घूम कर कहता है कि 15 क्विंटल नहीं, 14 क्विंटल धान खरीदेंगे । मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का राज अलग चल रहा है और कलेक्टर का राज अलग चल रहा है ।

सभापति महोदय :- दादी आप भी बोलेंगे, आप भी वरिष्ठ हैं । आप भी अच्छे से बोलियेगा । मैं तो इतना बता रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो ना, यह आपकी सरकार और आपके कार्यकाल में हुआ । सभापति महोदय, उस समय भारसाधक मंत्री के रूप में खनिज विभाग में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह जी थे, उन्होंने ऑनलाईन परमिशन के लिये नये रूल्स रेगुलेशन बनाये, तब तक लगातार चल रहा था । पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसके भारसाधक मंत्री माननीय भूपेश बघेल जी थे, अगर एक मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है तो क्या विभाग का डायरेक्टर उसको चेंज कर सकता है क्या ? यह विषय मेरे ध्यानाकर्षण में आया है । जी.ए.डी. के अंदर बैठे हैं और नियम कानून की बात करते हैं, अगर मान लीजिए डायरेक्टर है, उसके ऊपर विभाग का सचिव होगा, सामान्य प्रक्रिया में उसके ऊपर पी.एस.होगा, उसके ऊपर सी.एस.होगा, एक डायरेक्टर कैसे चेंज कर सकता है ? सभापति महोदय, अब मैंने प्रश्न में पूछा तो उत्तर आ गया कि वह डायरेक्टर तो अंदर चला गया है, अंदर चला गया तो नियम खत्म हो गये क्या ? उसके बाद दूसरा फिर आ गया, वही उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, गजब यार ? वह भी लाईन में है, दादी कई लोगों के लिस्ट में नाम है । वेट एण्ड वॉच ।

सभापति महोदय :- चलिये, आदरणीय समाप्त करिये ।

श्री राजेश मूणत :- नहीं, नहीं, मैं इस चीज को ऊपर ध्यान दिला रहा हूँ । कुछ चीजें की ओर कमी-बेशी है, जिन अधिकारियों ने इन नियमों को त्याग में रखकर किया है, क्या उनको ऐसा करने का अधिकार है ? यदि नहीं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही होना चाहिये, ताकि कोई भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न कर सके । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज के विषय में गांव के अंदर है, आप बात करते हो, हम बात करते हैं, उत्तरप्रदेश वाले कौन आते थे, किनके निर्देश पर वहां खदानें मिलती थी, यह आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कौन-कौन चलाया, कैसे चलाया, उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ । सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर अगर खनिज में गांवों के लोगों का योगदान रहेगा तो गांवों का विकास भी होगा, यह मेरी प्राथमिकता है, यह मेरा आपसे आग्रह है ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये ।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, छोटा-छोटा दो-तीन है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब परिवहन विभाग की बात करूंगा, इसमें मेरा दो निवेदन है । गाड़ी का फिटनेस किसे कहते हैं, गाड़ी को चेक करो, सही चलती है कि नहीं चलती है, गाड़ी का चक्का जाम तो नहीं है, उसके फिटनेस कहते हैं । अब एक लैपटाप लेकर फोटो खींच दे, फिटनेस जारी कर दे । अपना प्रायवेट सेक्टर का इन्वाल्वमेंट कर दिया । प्रायवेट सेक्टर में फिटनेस कौन चेक कर रहा है, किसी का कोई लेना-देना नहीं है, अधिकारियों का कोई साईन नहीं है, उस में सील ठप्पा लगा हुआ नहीं है । हम भी थे, उसी समय के अधिकारी आज भी हैं । आज वह सी.एस. है, मैंने परिवहन विभाग के अंदर भंग किया था । आपकी सरकार आई और आपने

चेकिंग तय कर दिया। चेकिंग के नाम पर जो अवैध काम हो रहे हैं, उसकी चिन्ता करो । परिवहन विभाग आय का स्त्रोत है, इसे आपने प्रायवेट दुकानों में बांट दिया है । कौन चला रहा है ? मैंने रायपुर परिवहन कार्यालय में फोन करके पी.एस. को बोला कि वहां एक समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया है और खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। जब हमारी सरकार थी, तब हमने पूरी प्रतिनियुक्तियां बंद कर दी थी। बाहर से कोई भी विभाग के अंदर नहीं आयेगा, जो विभाग का आदमी है, वही काम करेगा। इनकी सरकार में लगातार प्रतिनियुक्तियां हुई हैं।

सभापति महोदय, आप तो बस्तर से हैं। आप तो जानते हैं कि बस्तर परिवहन संघ का क्या हाल है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में जो धंधा चल रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। यह जितने लोग प्रतिनियुक्ति में आये हैं, इन सब का पेट बहुत भर चुका है, आप इनसे मुक्ति दिलवाईये। यह तो सी.एम. साहब का विभाग है, सी.एम. साहब तो नहीं देखेंगे, उनके जो पी.एस. हैं, कम से कम वह इस विभाग को देखें। क्योंकि सी.एम. साहब पूरे प्रदेश की चिंता करेंगे। लेकिन जब यह चीजें जानकारी में है और उसके बाद यदि यह हरकत कर रहे हैं तो यह चिंता का विषय है।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, ग्रामोद्योग एक ऐसा विभाग है जो प्रदेश के गांव-गांव से जुड़ा हुआ है। हम हाथकरघा के नाम पर स्कूल में ड्रेस बांटते हैं, सरकारी अस्पतालों में चादर और टॉवेल देते हैं। मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहता हूं कि ग्रामोद्योग विभाग के अंदर जो हाथकरघा सोसायटियां हैं, हम बजट में उन बच्चों को ड्रेस बांटने का मटेरियल पहले ले ले और उनको मटेरियल का पैसा दे दें क्योंकि उस विभाग के पास कम पैसा है। हम उनको शिक्षा विभाग से एडवांस दे कर हजारों बहनों को सिलाई का काम दे सकते हैं। इस माध्यम से उनको कार्य मिलेगा और एक बड़ा रोजगार खड़ा हो सकता है। इसी में हमारे यहां चाक, जो खासकर कुम्हार लोग होते हैं। यह मिट्टी का पैरा लेकर सब काम करते हैं। मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाये और उनके लिये विस्तारपूर्वक कार्ययोजना बने।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से और एक विभाग के संदर्भ में आग्रह करना चाहता हूं कि जो गरीब परिवारों को बी.पी.एल. कार्ड के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान दिया गया है। उन गरीब परिवारों को पता नहीं लगता है कि उनका 300 यूनिट जल गया कि 500 यूनिट जल गया। जब उसका बिल आता है तो कई बार ऐसा होता है और वह कहते हैं कि साहब, हमारा इतना बिल कैसे आ गया ? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि जब हम उनको एस.एम.एस. भेजते हैं तो क्यों न ऐसा हो कि हम उनको कॉल एस.एम.एस. भेज दें कि आपकी मुफ्त बिजली का जो 300 यूनिट था, वह खत्म हो गया है, अब इसके बाद आपको चार्ज लगेगा, इससे वह सचेत हो जायेंगे और जो आये दिन शिकायतों का दौर है, इससे राहत मिल जायेगी।

सभापति महोदय, अब सबसे बड़ा एक विभाग है, जो राजस्व का विभाग भी है और जिसके ऊपर बहुत बड़े-बड़े देशों में चर्चा हो गयी। नेता प्रतिपक्ष जी भी आ गये हैं। अब बचा हुआ तो वह बोल ही देंगे।

सभापति महोदय :- चलिये, 20 मिनट हो गये।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, अभी 20 मिनट कहां हुए हैं ?

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति जी, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि मैंने सुना है आज माननीय मुख्यमंत्री जी सिरपुर जाने वाले हैं और वह इनको कह नहीं पा रहे हैं कि मैं जल्दी जाना चाहता हूं। इसलिये उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूं कि अब जितने सदस्य बचे हैं, सबका नाम हटा दीजिये और मुझे और मुख्यमंत्री जी को सुन लीजिये।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, मैं आपकी बातों से सहमत हूं और मैं संक्षिप्त में दो-तीन विषयों पर अपनी बात कह रहा हूं, जो कि सुझाव है। जब डॉ. रमन सिंह जी की 15 सालों की सरकार थी तो हमने आबकारी नीति में एक निर्णय लिया था कि 2500 की आबादी के नीचे वाले शहर में कोई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। वहीं हमने भारत माता की एक समिति बनाकर उसके अंदर जागरूकता का कार्य किया था।

समय :
5.09 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक निर्णय हुआ था, उस निर्णय की समीक्षा करके जो हाईवे के किनारे शराब की दुकानें खुल गयी। आप मानिये इस शहर के बीच में पहले एक भी शराब की दुकानें नहीं थी, वहीं आज सरोना में लाईन से तीन भट्ठी खुल गई हैं। पहले वहां एक शराब की दुकान नहीं थी। क्योंकि वहां हाईवे है, बाईपास है। अब वहां तीन शराब की दुकानें खुल गईं हैं। वहां पर ऐसा मेला लगता है कि जैसे फ्री में प्रसाद बंट रहा हो। शहर के बीचों बीच राजकुमार कॉलेज के सामने पुरानी बस्ती में भट्ठी की स्वीकृति है। वहां पर भट्ठी खोलकर, रखा है मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसे चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरें करें, जैसे आपकी मंशा स्पष्ट है। मैं किसी काण्ड के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, होलोग्राम में किसने क्या किया, कितने जेल, रेल में है, अभी कितनी जमानत में है, यह 2200 हजार करोड़ रूपये का घोटाला किसने किया, मैं इन सब में नहीं जाना चाहता हूँ। ई.डी. अपना काम कर रही है और वह करती रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी शांत रहने वाले हैं यह कुछ बोलते नहीं हैं। कल ही रात को इन्होंने ईशारा कर दिया है कि चले जाओ तो कई लोगों का धुक-धुक हो गया है। कल दो चार दिन में और कोई दो चार हो जाएं तो मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। जिसने कुछ किया है वह भरेगा, इन दो तीन सुझावों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं छोटी-छोटी बातों पर अपनी बात कही है। मुझे यह

उम्मीद है कि आने वाले समय में एक परिवर्तन आएगा। हमारी राजधानी रायपुर है। मैं आखरी में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ । यहां 5 सालों तक इस राजधानी की उपेक्षा हुई, ऐसा समझें। इसकी उपेक्षा रही। यह हमारी राजधानी है यह केवल रायपुर शहर नहीं है। कोई इस बात को अपने मन से निकाल ले कि यह किसी एक का विधान सभा क्षेत्र है, किसी का एक वार्ड है, किसी का एक मोहल्ला है। यह छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी, राजधानी रायपुर है। यहां सी.एस.ई.बी. के माध्यमम से शहर के चारों तरफ तार का जाल फैला हुआ है । पूर्व की सरकार की यह अव्यवस्थित प्लानिंग थी। जिस प्रकार से माननीय ओ.पी चौधरी जी ने कहा है कि हम तीन जिलों को मिलाकर, इसे ग्रैण्ड सिटी बनायेंगे। मेरा आग्रह है कि रायपुर के प्रबुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों की एक मिटिंग लेकर, कम से कम राजधानी के रूप में कुछ दिखे। आप राजधानी में इन चीजों की एक प्राथमिकता तय कर दें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना आग्रह है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री रोहित साहू। आप 5 मिनट में बोलिएगा। आप अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए क्योंकि अभी बहुत से लोग बोलने वाले हैं।

श्री रोहित साहू(राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, जी। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने आई.टी. के उपयोग द्वारा प्रदेशवासियों के जीवन को और अधिक सरल बनाने के लिए नवीन योजनाएं प्रारंभ कीं हैं। राज्य के सभी नागरिकों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से देने के लिए संकल्पित है । मुझे आपको यह बताते हुए, बड़ा हर्ष होता है कि हमारी सरकार ने गत वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बजट में 109 करोड़ रूपये की वृद्धि की है, जो लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि है।

माननीय सभापति महोदय, मैं, आपको सर्वप्रथम नवाचार प्रोत्साहन योजना के संबंध में बताना चाहूंगा कि आज टेक्नालॉजी का दौर है। कहीं न कहीं हर दिन एक नई तकनीक का ईजाद हो रहा है। इसका विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि में उपयोग हो, जहां तक स्वास्थ्य, कुपोषण की बात है। नवीन तकनीक जैसे ड्रोन, ए.आई. और फाईव जी का उपयोग करने के नवाचार को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारी सरकार ने 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् दूंगा। हमारी सरकार डिजिटल इंडिया की तर्ज पर डिजिटल छत्तीसगढ़ की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही है। इसके लिए पंचायत में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए हमारे वर्ष 2024-25 के बजट में 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जिससे हमारे प्रदेश के सुदूर अंचलों में निवासी देश दुनिया से जुड़कर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार राज्य की पंसदीदा निवेश गंतव्य बने, इसके लिए आई.टी. अधोसंरचना एवं आई.टी. इनेबल्ड सेवाओं के निवेश प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार ने 2024-25 के बजट में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्य की भारत नेट परियोजना के अंतर्गत अधोसंरचना के संचालन एवं रखरखाव हेतु राज्य बजट से राशि 66 करोड़ रुपये की पूल निधि के रूप में प्रावधान किया है। इससे हमारे गांव-गांव तक इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी सुचारू रूप से संचालित होने में मदद मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं ग्राम पंचायतों के बारे में बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत स्तर पर हमारी सरकार पी.एम. वाणी योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से वाई-फाई के माध्यम से हॉट-स्पाट स्थापित करने प्रदेश भर में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई एक्सचेंज पाईन्ट के साथ इंटरनेट प्रदान करने की योजना बनाई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बजट में किये गये प्रावधान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- साहू जी, अब आप अपने क्षेत्र की मांग कर लीजिए।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, इसी बीच में मैं अपनी मांग भी रखना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पशुधन विकास के संबंध में बताना चाहूंगा कि इसके पहले पूर्व में पशुधन विकास योजना में जो योजना बनी हुई थी कि हर जिले में इस विभाग में नियुक्ति करने की प्रक्रिया जारी की थी। जिला स्तर पर जो डी.एम.एफ. फंड होता है, मैं गरियाबंद जिला राजिम विधान सभा की बात बताना चाहूंगा कि वहां लगभग पशु चिकित्सा अधिकारी के 74 पद स्वीकृत हैं। गांव एरिया में पशु चिकित्सा अधिकारी की कमी के नाम से हमारे पशुपालकों की चिंता बनी हुई है, गंभीर समस्या है। हमारी गौ-माताओं की अच्छे से देखभाल नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले में पूर्व में डी.एम.एफ. फंड से इस पद पर नियुक्ति करने का आदेश हुआ था, अभी तक मेरे गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा में पशु चिकित्सा अधिकारी के 74 पद में 40 पद अभी भी रिक्त हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि डी.एम.एफ. फंड से नियुक्ति करने का आदेश हुआ है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं होने का कारण क्या है ? अब हमारी सरकार बनी है और गौ-माता की सेवा करने का हमारा बहुत ही पुराना अनुभव भी रहा है। हमारी सरकार इसमें प्रमुखता से काम भी कर रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पद के लिए गरियाबंद जिले में जो पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, वह नियुक्ति तुरंत हो जाये। इसमें लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय :- साहू, मैं आपको बार-बार इसलिए टोक रहा हूं कि आप सीधे अपने क्षेत्र की दो-चार मांग करिये और समाप्त करिये। बहुत से लोग बाकी हैं, विनियोग विधेयक भी पेश होना है तो थोड़ा आसंदी को सहयोग करिये।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, यही मेरी मांग है।

सभापति महोदय :- आप यह आंकड़ें मत पढ़िये न। वह तो सबको मालूम है। आप सीधे अपनी मांग में आ जाईये।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि यह पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति प्रारंभ हो जाये। बस और ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया,उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्रीमती शंकुतला सिंह पोर्ते।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (प्रतापपुर) :- आदरणीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आदिवासी समुदाय से, किसान परिवार से, साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री चुने गये हैं। इसके लिए मैं अपने भाजपा संगठन को, सरगुजा संभाग की जनता एवं अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं दो लाईनें कहना चाहती हूं। "राहें जहां तक जायेंगी, राहगीर वहां तक जायेगा।" विपक्ष के सम्मानित सदस्यजनों के लिए कहना चाहती हूं कि "आप दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जायेगा।" मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि "खींच धनुस का डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जायेगा।" (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने प्रशासन को और अधिक कसावट लाने के लिए छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो के नई इकाई कार्यालय, जिला दुर्ग में खोलने का निर्णय लिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं सामान्य प्रशासन विभाग के बारे में अपनी बात रख रही हूं। छत्तीसगढ़ मंत्रालय के लिए अनेकों पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसमें कुल 140 नवीन पदों का सृजन हेतु 5 करोड़ 30 लाख रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। खनिज संसाधन विभाग के अंतर्गत माननीय मोदी जी की गारंटी के तहत जहां पूरे भारत देश में रेल लाईन का ऐतिहासिक विस्तार हो रहा है, वहीं हमारे छत्तीसगढ़ भी मोदी जी की गारंटी से अछूता नहीं है। जहां हमारी विष्णु देव की सरकार के द्वारा रेलवे लाईन की विस्तार के लिए कार्य किया जा रहा है, जिससे अनेकानेक औद्योगिक लाभ होगा। वहीं धार्मिक उपलब्धि के रूप में कटघोरा-डोंगरगढ़ रेलवे लाईन को स्वीकृति प्रदान की गई है। कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल लाईन के बनने से माँ समलेश्वरी के दर्शन में जनता को सुविधा मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा विभाग के बारे में भी कहना चाहती हूं। हमारा विष्णु देव सरकार का बजट ज्ञान के आधार पर तय किया गया है, जिसमें 'A' से अन्नदाता होता है। हमारी सरकार ने किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अहम रोल निभाया है। किसानों के लिए दो साल का धान का बोनस देकर हमारी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। महोदय, किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए 5 एच.पी. तक के कृषि पंपों में 7,500 यूनिट तक नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 3,500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय :- शकुंतला जी, सुनिये न। आप वैसा मत पढ़िये। वह सबको मालूम है। आप अपने क्षेत्र की बात कर लीजिये।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- जी। माननीय सभापति महोदय, मैं जनसंपर्क विभाग के बारे में अपने ही क्षेत्र की समस्या बताना चाहती हूं। जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया है, जिससे हमारे जीवन स्तर में बदलाव आया है। हम कैशलेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया एक ऑनलाईन मंच है, जो व्यक्तियों के सामग्री को साझा करने में मदद करता है। मैं प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, जहां 15-20 गांव ऐसे हैं, जहां पर मोबाईल टॉवर नहीं है, जिसकी वजह से जनता की कनेक्टिविटी लोगों तक नहीं है, जिससे वहां पर काफी लोग परेशान है। मैं चाहती हूं कि जजावल, गोरगी, ठुठी झरिया, यह कुछ ऐसे गांव हैं, जहां पर मोबाईल टॉवर लगाना अति आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, मैं आबकारी विभाग के बारे में बोलना चाहूंगी। जहां पिछली सरकार में नशा को बहुत ही बढ़ावा मिला, वहीं हमारी सरकार नशा को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार है। पिछली सरकार के समय सार्वजनिक जगहों पर शराब की दुकानें खोली गई हैं, जिसमें नगर पंचायत जरही में हनुमान मंदिर के पास शराब की दुकान है, जिसे मैं सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करती हूं कि उसे वहां से तत्काल हटाया जाये।

सभापति महोदय :- ठीक है। अब समाप्त करिये।

श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते :- प्रतापपुर बस स्टैण्ड में सार्वजनिक स्थान पर शराब की दुकान संचालित है, इसे भी मैं हटाने की मांग करती हूं। सभापति महोदय, मुझे थोड़ा सा बोलना है। पिछली सरकार में रेत खनन को बहुत ही बढ़ावा मिला था। परिहवन, आर.टी.ओ. में चेकिंग की व्यवस्था दुरूस्त की जाये, जहां से अवैध परिवहन, लकड़ी की तस्तकी और गौ तस्करी को रोक लगाया जाये। अवैध रेत खनन के मामले में मैं बहुत ही पीड़ित हूं। पिछली सरकार में हम लोगों ने अवैध रेत खनन को रोकने का प्रयास किया था तो स्वयं मुझ पर और हमारे 18 कार्यकर्ताओं पर फर्जी एफ.आई.आर. दर्ज किया गया था, जिससे चुनाव में जब मैंने नामांकन दाखिल किया तो अपराधिक छवि बताना पड़ा था। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस सरकार में सारी व्यवस्थाएं दुरूस्त की जाये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बजट का समर्थन करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्री धरम लाल कौशिक।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने देखा है कि माननीय कौशिक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठे थे तो वे मांग का समर्थन कर लेते और जो मांग थी उसको वहीं मांग लेते । सार्वजनिक रूप से यहां मांग कर रहे हैं तो यह समझ में नहीं आ रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, क्या है कि मैं उनको बताने के लिये गया था कि आपने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है और विपक्ष वाले भी उसका समर्थन कर रहे हैं । आप समर्थन नहीं करेंगे तो आपको विकास के लिये राशि नहीं मिलेगी तो इसका समर्थन करना पड़ेगा ।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछली सरकार में आप भी किसानों के लिये लड़ रहे थे और मैं भी लड़ रहा था । चूंकि उनके पम्प के कनेक्शन देने की स्थिति में सरकार नहीं थी और इसके कारण उनका बहुत समय तक लंबित रहा । लंबित रहने के बाद मुझे एक बात समझ में नहीं आयी कि जब-जब कांग्रेस की सरकार आयी तो पम्प कनेक्शन के लिये लाईन में खड़ा रहना पड़ा । मध्यप्रदेश में भी जब दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी उस समय हम लोग विधायक थे तो उस समय केवल 3 जिलों को मिलता था । एक जिला वह है जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं । एक जिला वह है जहां से वित्त मंत्री जी आते हैं और एक जिला वह है जहां से विद्युत मंत्री जी आते हैं । 3 जिला को बाकी छत्तीसगढ़ जैसी स्थिति थी और यहां भी जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनी तो कनेक्शन देना है तो कनेक्शन देने के लिये लाईन में आप खड़े रहिये और जब लाईन में खड़े रहेंगे तो आपका नंबर आयेगा । भाजपा की सरकार 15 सालों तक रही, एक दिन वेटिंग में नहीं आना पड़ा । जैसे ही उनका डिमांड नोट कटता था और उसके बाद में टेंडर हुआ और उनके खेत में पम्प के कनेक्शन लग जाते थे । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने 5 हॉर्सपावर तक के कृषि पम्पों को नि:शुल्क प्रदाय करने के लिये 3500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है और उससे हमारे 7 लाख 42,000 हितग्राहियों को उसका लाभ मिलेगा । (मेजों की थपथपाहट) यह सरकार है जो किसानों की चिंता करती है । यह सरकार नहीं कि उनको स्टॉलमेंट में दे रहे हैं, पिछली सरकार 5 साल में भी पम्प कनेक्शन नहीं दे पायी । यह सरकार चली है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, पम्प का तो कनेक्शन दे रहे हैं । 5 एच.पी. का मोटर जितना समय आप बिजली कटौती कर रहे हैं तो खेत में 2 एच.पी. का पानी नहीं जा रहा है । जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चूंकि किसान 5 हॉर्स पॉवर के हिसाब से खेती कर चुके हैं । आप बिजली कटौती करते रहे, किसान की फसल चौपट हो रही है । इस पर भी विचार होना चाहिए ।

सभापति महोदय :- हो गया । आपकी बात समझ गये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय ।

सभापति महोदय :- इनका भी सुनकर जवाब दे दीजिये । इनका भी सुन लीजिये ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, कल मेरे विधानसभा में लगभग 20 गांव के किसानों ने एक जगह इकट्ठा होकर रोड जेवरतला के सबस्टेशन में धरना-प्रदर्शन किया था कि लगातार अघोषित बिजली कटौती से किसान परेशान हैं, खेतों को पानी नहीं मिल रहा है और यह एक तरफ बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं ।

सभापति महोदय :- कौशिक जी ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह हमारा आरोप नहीं है ।

सभापति महोदय :- देखिये यादव जी ऐसे बार-बार खड़े होने से तो नहीं बनेगा। आपको बोल दिया, मौका दिया ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार की जो हालत रही न । हम लोग छत्तीसगढ़ में जितना उत्पादन करते थे और बिजली मिलती थी । कांग्रेस की सरकार आने के बाद में उत्पादन भी कम हो गया, ये बड़ी-बड़ी बातें न करें। उसको मेंटेन भी नहीं कर पाये और जो पावर उत्पादन होता था, उत्पादन भी कम हो गया । उस कारण को बता नहीं पायेंगे कि उत्पादन कम क्यों हुआ ? हमको ऊपर चढ़ाई चढ़नी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए लेकिन यह सरकार रिवर्स गियर में लाकर खड़ी कर देती है और आज विष्णुदेव जी की सरकार है जो लगातार छलांग लगा रही है और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसलिये हम उनके बजट की तारीफ करते हैं । आपने एकलबत्ती कनेक्शनों के लिये भी प्रदाय किया । 15 लाख 72,000 हितग्राहियों को उसका लाभ मिलेगा । इसके लिये 539 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । इसके साथ ही 400 यूनिट उसमें सब्सिडी देने के लिये 1274 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार को बिजली बिल हाफ के लिये धन्यवाद दे देना चाहिए ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए । वह दे देंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, राज्य के 28 लाख 48,000 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा । इसी प्रकार से आज जो टंकी बनाकर पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, पंचायतों की जो स्थिति है और बाकी की जो स्थिति है, उसमें मैं पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- कौशिक जी एक मिनट आज की कार्यसूची के पद 5 तक का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री धरम लाल कौशिक :- शुद्ध पेयजल के लिए सोलर पंपों की स्थापना हेतु 670 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 20 हजार सोलर पंपों की स्थापना होगी। सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना प्रारंभ की है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली। हम केवल इस बिजली पर निर्भर न रहें, बल्कि हम अपने घरों के छत में सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन करें और लगभग 1 करोड़ लोगों के घर में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए इस बजट में राशि का प्रावधान किया गया है और उसमें पैनलों की लागत का लगभग 40 परसेंट तक कवर करेगी। ये जो इसमें बड़े प्रावधान हैं, मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे स्कूल के छात्र हैं..।

श्री उमेश पटेल :- उस योजना में कौन-कौन लोग आयेंगे, आपको कुछ क्राइटेरिया पता है क्या? कितना होगा, वह भी बता दीजिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- क्राइटेरिया आपको बता दूंगा न। क्योंकि वह लंबा-चौड़ा होगा तो उसे बताने में सभापति महोदय टोक देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- तोर भाषण ला सुनके चन्द्राकर जी हा चुप होगे हे।

सभापति महोदय :- एक मिनट। बैठिए न। दो-दो लोग कैसे खड़े हो रहे हैं? एक मिनट, इनकी बात सुन लीजिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि पिछले समय से हम लोग यह देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। जलने के बाद बिजली ऑफिस में जाकर शिकायत करते हैं और शिकायत करने के बाद उन्हें लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं उसमें यह चाहता हूं कि एक बार यह पूरा सर्वे हमारे पास होगा कि एक साल में हमारे कितने ट्रांसफार्मर जलते हैं और जलने के बाद उसके रिप्लेसमेंट के लिए हमें कितना ट्रांसफार्मर चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने यह देखा है कि जिन कंपनियों को दिया गया है, सीमित दो-तीन कंपनियों के ऊपर में पूरा प्रदेश आश्रित है और उसके बाद में उन्हें फाइन भी किया गया है, पेनाल्टी भी लगायी गई है, लेकिन वह कंपनी सुधरने वाली नहीं है। इसलिए कि हम 72 घंटे मान लें, 48 घंटे मान लें कि हम रिप्लेसमेंट करने की स्थिति में रहे। जब हमें मालूम है कि साल में इतने ट्रांसफार्मर की हमें आवश्यकता है और यदि इतनी आवश्यकता है तो हमें साल भर में जो हमारी डिमांड है, उसके अनुसार हमारे पास रहना चाहिए। अभी कई जगह फोन करोगे तब मुश्किल से ट्रांसफार्मर मिल पाता है और ये जो बिगड़े हुए हालात है, उसको सुधारने की जवाबदारी मुख्यमंत्री जी आपकी है कि हम किसानों को कैसे समय पर ट्रांसफार्मर उपलब्ध करायें। मैं समझता हूं कि इस विषय पर बहुत गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात स्मार्ट मीटर के बारे में है। अभी स्मार्ट मीटर की बात आ रही है कि स्मार्ट मीटर लगायेंगे। मैं जहां तक समझता हूं कि स्मार्ट मीटर का मतलब यह है कि जैसे हमारे पास फोन है और फोन का पैसा खत्म हो गया तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा और आप रिचार्ज नहीं किये तो आपका कनेक्शन

disconnect कर दिया जायेगा। क्या छत्तीसगढ़ में वो हालात अभी है? हमारा बहुत बड़ा वनवासी क्षेत्र है। अनुसूचित जनजाति का एरिया है और यदि वे बिजली बिल की भरपाई नहीं कर पाये तो अपने आप disconnect हो जायेगा। उसके बाद प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी? मैं समझता हूं कि हाहाकार की स्थिति बनेगी। लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आपके बिल से मतलब नहीं है। लोग बोलेंगे कि हमारे मीटर की लाइन आपने कटवा दी। इसको आप कैसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे और पायलेट प्रोजेक्ट में कहां से चालू करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप एक उसे हमारे आदिवासी क्षेत्र में शुरू करें। आप इसे 5 सेक्टर में बांटिए न। शहर में भी आप करिए। सामान्य एरिया में भी आप करिए और उसके बाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ये दोनों क्षेत्र में आप करें।

श्री उमेश पटेल :- कौशिक जी, शायद यह ऑलरेडी डिसाइड हो गया है कि कहां-कहां पायलेट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मैं आपका पूरा समर्थन करता हूं कि अभी छत्तीसगढ़ इसके लिए तैयार नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन के घर में लगाववव न बस। गरीब मन ला छोड़ देवव।

श्री धरम लाल कौशिक :- तो मैं यह समझता हूं कि इसे जब हम पायलेट प्रोजेक्ट में लेंगे तो मुझे लगता है कि 3 महीने, 4 महीने के अंदर हमारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि हमको स्मार्ट मीटर लगाना है या नहीं लगाना है ? प्रदेश उसके लिए तैयार है या नहीं है? इस बारे में निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है ।

सभापति महोदय :- थोड़ा जल्दी करेंगे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- जन सम्पर्क विभाग । केन्द्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, बहुत सारी राज्य सरकार की योजनाएं बनती हैं । उन योजनाओं का प्रचार-प्रसार, खास तौर पर रिमोट एरियाज़ में लोगों को जानकारी मिले, इसके लिए आदिवासी क्षेत्रों सूचना केन्द्र, शिविर का आयोजन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि बहुत से लोग इसलिए लाभ से वंचित हो जाते हैं क्योंकि उनको योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है । हितग्राहियों को जानकारी मिलेगी तो उन्हें योजनाओं का लाभ भी मिलेगा । सभापति महोदय, 25 जून 1975 से लेकर 31 मार्च 1977 तक जो लोग मीसा में रहे । जब हमारी सरकार थी तो हमने लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि बनाई थी और वह सम्मान निधि उनको मिल रही थी । लेकिन कांग्रेस सरकार आई तो 2019 से यह राशि देना बंद कर दिया गया । क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मीसा बंदियों को राशि मिले । इसलिए कांग्रेस की सरकार द्वारा जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए यह राशि बंद कर दी गई । इसके बाद 23 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी कर उसको निरस्त कर दिया गया । उसके बाद मीसाबंदी कोर्ट में गए और हाईकोर्ट के द्वारा फैसला उनके पक्ष में हुआ तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई । मीसा बंदियों को जो राशि मिल रही थी, वह राशि प्रारंभ होनी चाहिए । मुझे लगता है कि सरकार को, सुप्रीम

कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की जरूरत नहीं है । सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील को वापस ले और आज ही मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री जी बजट भाषण का जवाब देंगे तो मीसा बंदियों को पुन: राशि प्रारंभ की जाए, इस बात की घोषणा सदन में होनी चाहिए, यह मांग मैं मुख्यमंत्री जी से करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, रेत घाट के बारे में बहुत चर्चा हुई । आपकी जानकारी में है कि बिलासपुर में नदी से पूरी रेत निकाल ली गई और बीच में बिजली का टावर वैसे ही खड़ा हुआ है । विभाग के द्वारा खर्च किया गया, सेंदरी में गहराई में जाकर डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई । हमारे खनिज विभाग की इतनी स्थिति भी नहीं है कि वहां रेत घाट चला रहे माफियाओं पर कार्रवाई कर सके । प्रदेश की अन्य घटनाओं की भी यहां चर्चा हुई है । मैं उन सारी घटनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस समय हमारी सरकार थी उस समय उसको लीज़ देने के बजाय, पंचायतों को सौंप दिया गया था । आज मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे रेत घाट को पंचायतों को सौंप देना चाहिए इससे पूरे प्रदेश में शांति का वातावरण स्थापित होगा । जिस प्रकार का माफिया राज यहां चल रहा है, इसे समाप्त करना चाहिए । रेत माफियाराज को समाप्त करने के लिए वापस से पंचायतों को सौंपना चाहिए, मैं यह मांग करता हूं । सभापति जी, मंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास में छूट दी गई थी । लेकिन मैं समझता हूं कि केवल छूट देना ही पर्याप्त नहीं है । बल्कि उसके बजाय पंचायतों को सौंप दिया जाए तो अच्छा रहेगा ।

श्री उमेश पटेल :- भइया, एक चीज । माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास में रेत फ्री करेंगे । क्या सिस्टम बनाया है आपने ? भंडारण कर रहे हैं । कैसे मुफ्त में दे रहे हैं, क्या सिस्टम से दे रहे हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- उल्टा फांदा हो गे हे, रोज टैक्टर मन ला पकड़त हे। एक भी व्यक्ति ला फायदा नई मिलत हे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी बैठिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, बजट सत्र में बात आई है, जब किसी बात की घोषणा करते हैं तो उसकी क्रियान्वयन की भी योजना बनाते हैं। अभी हमारा सत्र चल रहा है। आप पांच साल में कुछ नहीं कर पाए। आप दो दिन पहले की बात करते हैं कि क्या कर लिए ?

श्री उमेश पटेल :- एक सेकंड।

सभापति महोदय :- आपस में बात मत करिए।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि ऐसा कर दिया है। इसलिए मैंने यह प्रश्न किया। अगर ये बोलते कि सिर्फ घोषणा हुई है तो यह प्रश्न उठता ही नहीं।

श्री धरमलाल कौशिक :- जब हमारे मंत्री जी ने घोषणा की है तो योजना बनेगी। मैंने घोषणा की ही तो बात की है।

सभापति महोदय :- अभी तो घोषणा ही हुई है।

श्री रामकुमार यादव :- घोषणा तो 15 लाख के करे हो, तुमन कुछु दिहो।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी बैठिए, मैंने आपका भाषण सुना है। आपने बहुत जोरदार भाषण दिया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, जो पूर्ववर्ती सरकार डूबी, वह तीन कारणों से डूबी। एक कोयला से, दूसरा शराब से और तीसरा रेती से डूबी। इन तीनों वजहों से पूर्ववर्ती शराब डूब गयी। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पहले हमारी सरकार थी तो हमने कोचिया सिस्टम को समाप्त कर दिया था। तीन हजार की आबादी की गांव में शराब बंद कर दिए थे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार तीन कारणों से डूबी, आप बता रहे हैं। आपकी 15 साल की सरकार 15 सीट में कैसे आई और कैसे डूबी, उसको भी थोड़ा सा बताईए ना।

श्री धरमलाल कौशिक :- 15 साल की बात का फर्क नहीं पड़ेगा क्या ? 15 साल की बात का फर्क पड़ेगा ना। आप पांच साल में डूब गये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- 15 साल की सरकार की स्थिति यह बनी कि 15 सीटों में रह गये। उसको भी बताईए ना।

श्री उमेश पटेल :- अच्छा यह बताईए, वह सिस्टम खत्म हुआ या नहीं हुआ। आज भी तो कहीं से नहीं चल रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- बात कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, कोचिया सिस्टम तत्काल बंद हो जाना चाहिए। गांव में अराजकता का सबसे बड़ा कारण शराब की अवैध बिक्री है। घर-घर में परोसने की योजना है। उसके कारण गांव में मारपीट हो रहे है, अराजकता की स्थिति बन रही है। उसका प्रमुख कारण यही है।

सभापति महोदय :- आगे बोलिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात, मैं उसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमने उसको नियंत्रित करने के लिए 3 हजार की आबादी में शराब को बंद किया था। आज तो 100 घर की आबादी है, वहां भी पहुंचा रहे हैं। 3 हजार की आबादी में बंद करने के बाद उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उस पर सरकार विचार करे। उससे ज्यादा की आबादी में हम दुकान को बंद करें। हमारी जो प्लेंसमेंट एजेंसी है, उनके द्वारा नकली शराब, पानी मिलाने, की बात है, ये कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देते हैं, उनको टर्मिनेट कर देते हैं, लेकिन जो

प्लेसमेंट एजेंसी चला रहे हैं, इनके उपर कोई कार्रवाई नहीं होती। चलाने वाले ये हैं, अवैध धंधा करने वाले ये हैं। प्लेसमेंट एजेंसी में जो गांव के लगे हुए हैं, उनको निकालकर खाना पूर्ति करते हैं। इस पर भी विचार होना चाहिए। उसके साथ ही साथ मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शराब और करप्शन के मामले आए हैं, उनको कैसे नियंत्रित करेंगे, उस बात की ओर विचार करें। सभापति महोदय, गौठान में प्रति नग के हिसाब से जो सेस लगाया गया था, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। सेस की राशि का उपयोग कहां करें, उस गौठान में कहां लगायेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में भी विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी हमारे हेलीकाप्टर भी खराब हो गये है और आपके प्लेन भी खराब हैं। लगातार किराये के हेलीकाप्टर और प्लेन लेकर यात्रा हो रही है, खर्च भी अधिक हो रहा है। दूसरी बात, इस बीच में एक प्रश्न भी लगाया गया था कि हमारे मुख्यमंत्री के लिए डबल इंजन की हेलीकाप्टर चाहिए, प्राइवेट हेलीकाप्टर वाले उतने सुरक्षित नहीं हैं, जितना खुद के हेलीकाप्टर में रहेगा। इसलिए मैं मांग करूंगा कि आने वाले समय में जो हमारे हेलीकाप्टर और प्लेन हैं, उसको सेल किया जाए और सेल करने के बाद नई हेलीकाप्टर और नये प्लेन की खरीदी के लिए प्रावधान रखा जाए, योजना बनाई जाए। माननीय सभापति महोदय, पशुधन विकास की बात है।

श्री राजेश मूणत :- सभापति महोदय, बीच में बोल रहा हूं। उमेश जी, पूर्व सरकार ने 268 करोड़ रूपये केवल हैलिकॉप्टर और प्लेन के किराये पर दिये।

श्री विक्रम मण्डावी :- राजेश भैया, हमारे पास पहले से डबल इंजन है तो फिर नई हैलिकॉप्टर लेने की क्या जरूरत है? (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। माननीय सभापति महोदय, जहां तक पशुधन विकास और डेयरी की बात है तो हमारे यहां नदियों में एनीकट और एनीकट के कारण सभी जगहों में बहुत अच्छी सड़क की व्यवस्था हो।

सभापित महोदय :- कौशिक जी, आपको 20 मिनट हो गये। शॉर्ट कीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, केवल दो मिनट। मैं चाहता हूं कि आप जो सब्सिडी में डेयरी के लिए अनुदान देते हैं। उस अनुदान की राशि और वह डेयरी नियमित रूप से कैसे चल जाएं और हम उसकी यूनिट कैसे बढ़ा सकें, इसके लिए विचार होनी चाहिए। इसके साथ में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि पहले जो परिवहन विभाग में परमिट जारी करने का सिस्टम था, वह संभागीय कार्यालय था। उसको कमिश्नर करते थे और वह कमिश्नर के द्वारा संचालित होता था। जिससे प्रदेश भर के बस मालिकों को ठीक से रूट मिल जाता था। अभी उसकी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था रायपुर में हो गई है। रायपुर में जिनकी धमक है, उनको तो ठीक से परमिट जाती है। पूरे प्रदेश के बाकी बस वाले मेरे पास आये थे और उन्होंने मुझसे कहा कि पहले की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। वह व्यवस्था जारी नहीं होने के

कारण धमक वाले तो अपने हिसाब से परमिट ले लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं समझता हूं कि इसको सेन्ट्रलाइज्ड करने के बाद विकेन्द्रीकरण करना चाहिए और उसके लिए पुन: कमिश्नर को अधिकार देना चाहिए। जिससे उनकी परिमट जारी हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह रिवर्स गेयर का बजट नहीं है। यह प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। किसानों की चिंता करने वाला बजट है। युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है और उसके साथ महिलाओं के सम्मान से लेकर उनके विकास के लिए यह बजट है। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इसके लिए उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है तो मैं मुख्यमंत्री जी की मांगों का समर्थन करते हुए और उनको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। डॉ. चरण दास महंत जी। (मेजों की थपथपाहट)

समय :

5.49 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिन भर से माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग से संबंधित बजट पर चर्चा को सुन रहा हूं। कुछ लोगों ने तो अपनी बात सही ढंग से रखी है, लेकिन कुछ लोगों ने इधर-उधर की बातों में समय बीता दिया। मैं आज प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज विभाग, ऊर्जा विभाग, जन सम्पर्क विभाग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, परिवहन विभाग आदि विभागों की अनुदान मांगों का परंपरानुसार विरोध करता हूं और अपनी बात थोड़े से खुशनुमा माहौल में रखना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यह आपका पहला लंबा भाषण होगा और मेरा भी पहला है। इसलिए दोनों तरफ से भूल-चूक माफ हो जानी चाहिए। आप समझ रहे हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- वह सुन रहे हैं। समझ नहीं रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता जी से आग्रह करूंगा कि इस पहली चुनी हुई सरकार को दो महीने कम्प्लीट हुए हैं। आपको तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए कि मैं आपको कहता हूं कि आप अच्छा करिये। फिर अगले बजट में बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी शुरूआत नहीं हुई है। यदि लंबा भाषण होगा तो तो मजा कहां से आएगा।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसे भी उनका स्वभाव नहीं है। आप चिंता मत करिये। (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- मैं आपको सीधे संबोधित कर रहा हूं।

जब तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए।

ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रोए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- वाह-वाह। इरशाद।

डा. चरण दास महंत :- समझ गए महोदय । कोई करके जाईए, ताकि कोई तीसरा लाईन न जोड़े । ऐसी करनी न करो, पीछे सबे हँसे कोए । यह मेरा आप आशीर्वाद समझना चाहें तो आशीर्वाद समझ लें, उम्र में आपसे बड़ा हूं । मित्र समझना है तो मित्र समझ लीजिए। मैं अध्यक्ष जी के सामने, सबके सामने कहना चाहता हूं कि आपका असली मित्र मैं ही हूं, बाकी सब दुश्मन बचे हैं । (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- वह तो पहले से पता है ।

डा. चरण दास महंत :- पता है न । इसलिए ईश्वर ने जब आपको दिया है, भगवान राम ने दिया है, कह देता हूं । यह जो आपको जवाबदारी मिली है, उसको छत्तीसगढ़ की सेवा में बिताईए । अभी दो महीने नहीं हुए हैं, बहुत से लोग लगातार आपके बारे में यही कह रहे हैं कि यह तो रिमोर्ट कंट्रोल की सरकार है, मैं नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और ऐसे व्यक्ति को सुझाव देना चाहता हूं कि ये जानते होंगे, कई लोग जानते होंगे । अध्यक्ष महोदय, सुकरात जी ने कहा था, कहा था नहीं, कह गए। वे राजनीतिक विचारक रहे, बहुत बड़ा फिलासफर रहे तो आप कैसे लोगों को अपने ईर्द-गिर्द छॉटो कि आपकी बदनामी न हो, यह मैं चाहता हूं। सुकरात जी के अनुसार वह जो नहीं जानता, वह जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वह नहीं जानता, वह मुर्ख होता है । उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए । जो नहीं जानता और जानता है कि वह नहीं जानता, वह बहुत सीधा, सरल होता है, उसको सिखाईए । जो जानता है और नहीं जानता, वह जानता है कि वह नहीं जानता। वह जो जानता है और नहीं जानता कि वह जानता है । सुकरात जी के अनुसार वह आदमी सोया हुआ है । उसको जगाईए, ताकि आने वाले समय में आपका काम कर सके और जो जानता है और जानता है कि वह जानता है, वह बहुत बुद्धिमान आदमी है । चन्द्राकर जी जैसे, उसे अपने पीछे लगा लीजिए या उसकी पीछे लग जाईए, यह मेरा कहना है (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पहचानते हैं, यह बता दीजिए ।

डा. चरण दास महंत :- मैं तो आपको जानता हूं और आप मुझे पहचानता हो और हम एक दूसरे की जानते हैं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि आपको दो महीने हो गए । अब यह सरकार विष्णु देव जी की सरकार है । सुबह थोड़ी देर के लिए अग्रवाल साहब से हमारी बहस हो रही थी कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । अब मैं क्या कहूं ? यह विष्णु देव जी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी की सरकार है ? यह तीनों अलग-अलग बातें हैं साहब । आप ही तय कर लीजिए । हमने, हमारे लोगों ने, हमने तो नहीं, छत्तीसगढ़ के लोगों ने एक भोले-भाले आदिवासी को मुख्यमंत्री चुना । लोगों ने आप पर विश्वास किया । हमको तो आपकी गारंटी

चाहिए, हम किसी दूसरे की गारंटी पर विश्वास नहीं करने वाले हैं । आप जिस तरह से सीधे हैं, सादे हैं, सरल हैं, सहज हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय भी इसी गुणों के कारण 15 साल निकाल दिए । उनकी क्या विशेषता रही कि उन्होंने कोई रिमोर्ट कंट्रोल का उपयोग नहीं किया । जो कुछ था, यहीं था । छत्तीसगढ़ से ही कंट्रोल था । रिमोट कन्ट्रोल कहां है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप उस रिमोट कन्ट्रोल के अनुसार मत चलिये। आप यही रहिये और हमें आपकी गारन्टी चाहिए। मोदी जी की गारन्टी नहीं चाहिए। क्योंकि मोदी जी की गारन्टी फेल हो चुकी है। ये बहुत कह रहे थे- मोदी जी की गारन्टी। मैं बताऊ ? दो करोड़ लोगों को नौकरी हर साल की गारन्टी।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा।

डॉ. चरण दास महंत :- गड़बड़ हो जायेगा भाई, थोड़ी देर रूक जा।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी नेता प्रतिपक्ष महोदय बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री एकदम भोले-भाले, सीधे-साधे हैं। और कई प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं। भोले-भाले तो हैं, आदिवासी भी हैं। लेकिन वह काबिल मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें बनाया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरण दास महंत :- मैं कहां बोल रहा हूं नाकाबिल हैं ? मैं बोल रहा हूं कि काबिल हैं, और बेहतर काबिल बनिये। जैसे हमारे महाराज डॉ. रमन सिंह जी ने 15 साल चलाया है, आप और चलाईये, हम उनको आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। मगर आप लोग जो इधर-उधर से घुमा रहे हो कि यह आपकी सरकार नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, मोदी जी की सरकार है, वह जैसा चाहेंगे, वैसा होगा।

श्री प्रणव कुमार मरपची :- आप तो रिमोट कन्ट्रोल की बात कर रहे हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- नइ समझस बाबू, अभी बैठ जा। अध्यक्ष महोदय, दो करोड़ नौकरी की गारंटी-फेल, किसान की आय दोगुनी करने वाली बात- फेल, काला धन वापस लाने वाला- फेल, महंगाई कम करने की गारन्टी- फेल, हर खाते में 15 लाख पहुंचाने की गारन्टी-फेल, महिला सुरक्षा और सम्मान की गारन्टी-फेल, सौ स्मार्ट सिटी बनाने की गारन्टी-फेल, रूपये को मजबूत करने की गारन्टी- फेल, चीन को लाल आंख दिखाने की गारन्टी- फेल, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला गारन्टी-फेल।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, नेता जी इसीलिए 10 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है, 15 साल और चलेगी। गारन्टी पर चलेगी। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतकर मोदी जी को देगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- रूक जावा, रूक जावा, दू महीना रूक जावा।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको सुनूंगा। मै यह कह रहा हूं कि गारन्टी हमारे लिए फेल है, हमें आपकी गारन्टी चाहिए।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी बोलते हैं तो सुनना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जी पहली बार बोल रहे हैं। आपके नेता जी भी बोलेंगे तो हम भी टोकेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम तो अनुमति ले रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत उस कुर्सी में (आसंदी पर) बैठते थे इन लोगों को ज्यादा महत्व देते थे। यह चिल्ला-चिल्ला कर बोलते थे। थोड़ा-बहुत लज्जा करो, नेता प्रतिपक्ष पहली बार बोल रहे हैं, बाद में बोलो।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे अनुमति ले रहे हैं। आप अनुमति देंगे, तब बोलेंगे।

डॉ. चरण दास महंत :- हम अनुमति दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी तरह खड़े होकर जबर्दस्ती नहीं बोल रहे हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं आपको अनुमति दे रहा हूं, आप बोलो न।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब अध्यक्ष जी बोलेंगे तब बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये।

डॉ. चरण दास महंत :- बोलिये, कोई बात नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप जिनकी बात कर रहे हैं वह सन् 2014 की बात है। सन् 2014 के बाद 2019 में मोदी जी को एक और मेन्डेट मिल गया, जो 283 सीट से 303 सीट का था। अब फिर नया मौका आ गया है, आप फिर मेन्डेट देखियेगा। मैं यह कह रहा हूं। तो आप कहां सन् 2014 की बात को लेकर बैठे हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि हमारे लिए मोदी जी की गारन्टी फेल है। भइया, आप अपनी गारन्टी बनाओ न, आपको किसने रोका है ? आपने मोदी जी की कितनी गारन्टी को शामिल किया है, वह गिना देता हूं। आपने गारन्टी की बात की है।

अध्यक्ष महोदय :- आप जारी रखिये। नहीं-नहीं, आप जारी रखिये, उधर जवाब देने की जरूरत नहीं है।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में छत्तीसगढ़ की जवानी और छत्तीसगढ़ की पानी का ध्यान नहीं रखा है। मोदी जी की गारन्टी के नाम ने आपको सत्ता तो दिला दिया, आपने सत्ता पा ली। लेकिन आपने उनकी गारन्टी को लिखा था तो आपने अपने विभाग में कौन-कौन सी गारन्टी को शामिल किया है, बता सकते हैं ? एक भी गारन्टी शामिल है क्या ? मैं पढ़ देता हूं।

खनन चाहे छोट हो या बड़ा हो, हर प्रभावित व्यक्ति को रोजगार, पुनर्वास, मुआवजा देंगे। आपके बजट में है ? छत्तीसगढ़ ग्रीन इन्वायर्नमेंट रूम की स्थापना कर प्रदूषण नियंत्रण का काम करने वाले हैं, आपके बजट से नदारद है ? चन्द्राकर जी, आप तो बहुत ध्यान रखते हैं । छत्तीसगढ़ क्लाईमेट जस्टिस मास्टर प्लॉन तैयार कर कुल बिजली उत्पादन में नवीनीकरण, उर्जा उत्पादन की हिस्सेदारी 25

प्रतिशत तक बढ़ाने वाले थे, आपके बजट में शामिल है ? कौशिक जी, अभी आप बिजली की बात कर रहे थे । दूध के संग्रहण हेतु खरीदी मूल्य निर्धारित किया जाना था, कितना मूल्य निर्धारित किये हो भईया ? मछुआरा संघों को उनका पारंपरिक हक दिया जाना था, चलो दो ही महीने हैं, मान लेते हैं देने वाले हैं ? स्थानीय ईकाइयों एवं पंचायती राज को खनन संबंधी अधिकार देने वाले थे ? दो महीने में नहीं हो पाये हैं, आगे दे दीजिएगा ? प्रदेश के कर्मचारियों को केनद्र सरकार के समान डी.ए.देने वाले थे, दो महीने हुये हैं, दो-तीन बैठक हो चुकी है, उसको दे सकते थे, आप शामिल कर सकते थे, नहीं किया है ? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आदिवासी हैं, यह हम सब जानते हैं । मोदी जी की गारण्टी थी कि प्रत्येक जनजातीय परिवार को दो बकरा देंगे, आ गया, बजट में प्रसताव किया है ? आपके मोदी जी की गारण्टी को दिखाऊं क्या ? मुख्यमंत्री जी 1 लाख रिक्त पदों की भर्ती सुनिश्चित करने वाले थे ? कुछ जारी हुआ है, विधान सभा के पहले विज्ञापन आ जायेगा, पता नहीं कितने हैं ? आपने मोदी जी की अनेक गारण्टी को वोट मांगने के लिये लाया था, यह आपके बजट में शामिल नहीं हुआ है । शामिल आपने नहीं किया है, शामिल उधर वालों ने किया होगा ? रिमोट कंट्रोल वही है । आप सीधी-सीधी बात नहीं कर रहे हैं । जब मुख्यमंत्री जी के ही विभाग में मोदी जी की गारण्टी को शामिल नहीं किया जा रहा है, आने वाले समय में क्या करेंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपके विभाग में खनिज संचालनालय में 40 प्रतिशत पद रिक्त है, सामान्य प्रशासन विभाग में 536 पद रिक्त है, राज्य प्रशासनिक सेवा में 13 प्रतिशत रिक्त है, मंत्रालयीन स्थापना में 24 परशेंट रिक्त है, लोक आयोग में 25 प्रतिशत रिक्त है, विशेष अन्वेंशण में 61 प्रतिशत रिक्त है, एंटी करप्शन में 36 प्रतिशत खाली है, आर्थिक अपराध अन्वेंषण में 40 प्रतिशत खाली है । एक तरफ सरकार यह कहती है कि भ्रष्ट्राचार मुक्त शासन देंगे और वही छ.ग. विभागीय जांच आयुक्त कार्यालय में 11 पद में से सिर्फ 6 लोग काम कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या कहू ? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास छोटे-बड़े मिलाकर कुल 14 विभाग हैं और 14 विभाग में से एक भी विभाग में मोदी जी की गारण्टी शामिल नहीं है ? चेक करवा लीजिए । हम अपनी बात कर रहे हैं, हमने पिछले बजट में अटल नगर, नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से स्थापना भी की और 2 करोड़ 51 लाख का प्रावधान किया था । चन्द्राकर जी, आपको याद है, सुन रहे हैं ना ? आपने उसी का नकल नया रायपुर अटल नगर में उसका नाम बदलकर क्या किया, लावलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है और उसमें 1 करोड़ का प्रावधान रखा है । हमने 2.50 करोड़ का रखा था और आपने 1 करोड़ का रखा है । नकल भी पूरा नहीं हुआ है ? मूणत जी, आप घबराईये मत, मैं उनका मित्र हूँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ । अगर बुरा न माने तो विष्णु जी आपके घर के लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ, आपके घर में एक लक्ष्मी जी है, वह बहुत पूजा-पाठ करती है, मैं पीछे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके घर में एक लक्ष्मी है, जो बहुत धार्मिक है, बहुत पूजा-पाठ करती है, मुझे आपके आजू-बाजू के लोगों ने कहा है कि आप उसी के पूजा-पाठ के कारण मुख्यमंत्री बने हो । यह सही

है ? यह लोग तो आपको विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही निकाल दिये थे। आपको याद हैं ? मैंने सुना है कि आपकी जो लक्ष्मी हैं, वह बहुत अच्छा भाषण भी देती हैं। आप उनको मेरा प्रणाम कह दीजियेगा और यदि आप उनका पांव छूते हैं तो मेरी तरफ से छू दीजियेगा। (हंसी) मगर मैं दूसरी बात कहने वाला हूं कि सरकार बनने के बाद जो विष्णु जी की असली लक्ष्मी है, जो रात में उल्लू मैं बैठकर आती है, उस लक्ष्मी जी की बात पर आ जाते हैं। वह आपके घर आपको बिना बताये आ चुकी है। आपके अड़ोस-पड़ोस को मालूम है, आपके संघ के साथियों को मालूम है। आपको नाराजगी है, आपके लोगों को नाराजगी है। मगर वह कहां से आयी ? इसके बारे में आप सचेत रहिये। मैं सिर्फ आपको सचेत कर रहा हूं। यदि मैं कबीर साहेब के शब्दों में सचेत करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत नजदीकी है। आप कहें तो सुना देता हूं ?

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल सुनाईये।

डॉ. चरणदास महंत :-

"माया महा ठगनी हम जानी।

तिरगुन फांसि लिये कर डोलै, बोलै अमृत बानी।

केशव के कमला होइ बैठी, (केशव मतलब विष्णु) (कमला मतलब लक्ष्मी)

शिव के भवन भवानी।

पंडा के मूरत होइ बैठी, तीरथहू में पानी।

जोगी के जोगिन होइ बैठी, काहू के कौड़ी कानी। (जो बिल्कुल गरीब आदमी है, जिसके पास कौड़ी कानी भी नहीं रहती, वह भी उसकी माया ही है।)

भक्तन के भक्तिन होइ बैठी, ब्रम्हा के ब्रम्हानी।

कहैं कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी।।

अध्यक्ष महोदय, यह माया कहीं न कहीं आ ही जाती है। आपके घर हो, मेरे घर हो और इनके घर तो आना ही है क्योंकि यह मुख्यमंत्री बन गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- पिछले 05 साल लोगों को याद नहीं आयी।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी जगह पर बैठा था। (हंसी) वहां से याद करा ही नहीं सकता था।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, महंत जी कितनी विद्वतापूर्ण भाषण दे रहे हैं। हम मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- महंत जी, आपके किनारे में बैठने वाले सदस्य को आप पिछले 05 सालों में इन्हीं सब बातों को क्यों नहीं बता दिये ? आज इतना बुरा हाल क्यों हुआ होता ? (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- मेरी दूरी थोड़ी ज्यादा थी। मैं ऊपर बैठता था। अभी दो महीने ही हुए हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मुझे आपके पीछे बैठे हुए साहब ने समझा दिया है कि अभी दो महीने हुए हैं, रूक जाईये, आगे बहुत समय है, अगली बार करेंगे। आपके लोग अभी से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात पर आरोप लगाने लगे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। यही कह रहे हैं कि वह लक्ष्मी जो उल्लू पर सवार होकर आती है वह विष्णु जी के राज में आ चुकी है और हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। पहले ही स्लॉट में आई.ए.एस पोस्टिंग के जरिये चुपचाप रात में 100 करोड़ गटक गये, ऐसा पेपर में आया था। बहुत हल्ला हुआ। संघ के भाई बहुत गर्म हुए। विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मी जी अंदर आ रही हैं। राम धुन पीछे बज रहा है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी, अगर आप ऐसी कहानी पढ़ते हैं, आपको मालूम है। आप कबीर के अनुयायी है और कबीरा बोले यह तो आप जानते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आपको भी कोई कुछ कह देगा और आप उसे आप एक आरोप के ऊपर ले आयेंगे।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं आरोप कहां लगा रहा हूं ? मैं इनके ऊपर तो आरोप लगा ही नहीं रहा हूं।

श्री राजेश मूणत :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो कह रहा हूं कि पहले जहां लक्ष्मी आ रही थी और जिन-जिन लोगों ने लक्ष्मी के दर्शन किये हैं, वह आधे तो अंदर है, आधे बेल पर हैं और आधे रेल पर हैं। अब आपने उनके बारे में कभी नहीं बोला और अभी सरकार बने दो महीने हुए हैं और आपने बोलना चालू कर दिया कि 100 करोड़ रूपये गटक गये। सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए कहता हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, जो लोग कह रहे हैं, मैं तो वह बोल रहा हूं।

श्री राजेश मूणत :- मैं आपसे इसलिये यह बात कह रहा हूं क्योंकि आप इतने सीनियर हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिये आपकी और हमारी बात हैं। क्या मैं नहीं कहूं ?

अध्यक्ष महोदय :- राजेश जी, ठीक है।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं यह नहीं कहूं। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मैं नहीं कहूंगा, छोड़ देता हूँ।

श्री राजेश मूणत :- गुरूदेव, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो आपका जितना आदर करता हूँ, जितना सम्मान करता हूँ ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आज तक किसी का सम्मान नहीं किया है।

श्री राजेश मूणत :- नहीं। वह तो ...(हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जिनको-जिनको इंगित करना था, वह यहां कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश बढ़िया चारागाह है, यह हम सब जानते हैं। यहां बहुत लोग चरने ही आते हैं, बहुत लोग चराते भी हैं और बहुत लोग चराकर चले भी गयें। माननीय किरण देव

जी को आपत्ति थी, आज सदन में वह नहीं दिख रहे हैं मैं कुछ नहीं कहूंगा। यहां कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। भाई माननीय राजेश मूणत जी को बहुत तकलीफ हो रही है इसलिए मैं नहीं कहूंगा। मैं इन बातों को छोड़ देता हूँ। साहब, अच्छा, आप यह बताईये कि आपकी सरकार को बने 2 महीने हो गए। इन दो महीनों में मुख्यमंत्री की सुरक्षा तो बदली जा सकती थी, लेकिन यह आज तक नहीं बदली।

श्री राजेश मूणत :- साहब, इनकी यही तो उदारता है।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिये, ठीक है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय विष्णु देव सरकार की यह उदारता है कि आप भी सालों साल से इस प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है। जब भी कोई नई सरकार आती है, डी.जी.पी. को हटा दो, सी.एस. को हटा दो।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी डी.जी.पी. की बात ही नहीं की है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में माननीय विष्णु देव जी की सरकार ने अधिकारियों को काम करने का अवसर दिया है। आप अच्छे काम करके जाईये। आपकी पोस्टिंग अपने आप होगी। यह माननीय विष्णु देव जी के सरकार की गारण्टी है।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिए, ठीक है। आज भी सदन में माननीय गृह मंत्री जी नहीं दिख रहे हैं। कवर्धा में हिन्दुओं का गला रेंता जा रहा है। वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन घटनाएं हो गईं। अभी भी जवान शहीद हो रहे हैं। यहां छत्तीसगढ़ महतारी रो रही है। उधर छत्तीसगढ़ महतारी का कोई नाम लेवा नहीं दिख रहा है। हम क्या करें? ठीक है। हम लोग बोरे बासी खिलाते थे, आप खाते थे। अब, आप लोग लिट्टी चोखा में पेट भरना चाहते हैं तो आप पेट भर लिट्टी चोखा खाईये। आपको हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। हम लोग इसमें कुछ नहीं कहेंगे। मगर इनका बजट बिल्कुल चुनाव दृष्टि से बना हुआ, हमको तो छलावा नज़र आ रहा है। इसलिए मैं, आपको कहूंगा, मैं किसी दूसरे को नहीं कहूंगा। केवल आप सचेत हो जाईये। नहीं तो फिर यह लोग वह दिन तलाशेंगे। आदिवासी विश्व दिवस कब है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी आदर्श समाज के लिए सबसे बड़ी सामाजिक सद्भाव की आवश्यकता होती है। क्या हम इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बना रहे हैं, क्या हम सामाजिक सद्भाव बनाये रखना चाहते हैं। सामाजिक सद्भाव को ध्वस्त करके, आप पूरी सरकार चलाना चाहेंगे या आपकी सरकार के लोग चलना चाहेंगे तो यह उचित नहीं होगा। बड़ी-बड़ी बातें कर देने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति और समाज की उदारता ही आदमी को बड़ा बनाता है। इसलिए ईश्वर ने आपको बक्शा है। भगवान राम ने आपको बनाया है। आपने अवतार लिया है यह बहुत खुशी की बात है। इस प्रदेश में आप अच्छा काम करिये। हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं। जहां भी आप सकारात्मक काम करेंगे, हम आपको मदद करेंगे। जब हम इधर-उधर की बात सुनेंगे तो आपको हम प्यार से सुनाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी कटौती प्रस्तावों पर बात करना चाहूंगा। मगर जो आपकी नियत और नीति के बीच अंतर दिख रहा है। वह बहुत ही सोचनीय है। आपकी सरकार को बने 2 महीने हो गए, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी तक आपने योजनाएं नहीं बनायीं हैं। शायद आप लोग योजनाएं बनाने वालों को नहीं बुला पाये होंगे या अभी अधिकारी लोग जम नहीं पाये हैं। यह विषय भी छोड़ देते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। वह कहते हैं कि "पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं।" यह 3 महीने में ही दिख जाना चाहिए था। आपकी सरकार को बने 3 महीने हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण करने आता है, नहीं आता है, करेंगे या नहीं करेंगे, भाई धर्मजीत सिंह जी, यह तो 3 महीने में दिख जाना चाहिए। अराजकता जिस ढंग से कवर्धा से इधर आ रही है और आज उधर प्रतापपुर तक पहुंच गई है, वह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जिस ढंग से कम से कम समय हम लोगों को सुनने के लिए यहां दे रहे हैं, मेरे ख्याल से 5 फरवरी से बजट सत्र प्रारंभ हुआ है। आप जब यहां आयेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, हमारी सुनेंगे नहीं, हमारी जानेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। यह कौन है जो आपको यहां आने से रोकता है? यह कौन है जो कहता है कि आप विधान सभा मत जाओ? वह कौन रिमोट कंटोल करने वाला व्यक्ति है जो आपको हम लोगों से मिलने को रोकता है? उसको आप ही तलाशिये। हम नहीं तलाश पा रहे हैं या मूणत जी तलाश के बता दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही के मंत्री लोग आये थे और दुर्भाग्य रहा कि आप उस समय बीमार हो गये थे। हम सब लोग बैठकर झेले तो नहीं हैं, सुने हैं। मनसुख एल. मंडाविया जी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, दोनों के उद्‌बोधन का सारांश यह था किसी भी निर्वाचित सरकार की नीतियां और योजनाएं लोक कल्याण के लिए होती हैं। हमें इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उनका कहना था कि अगर योजनाओं को क्रियान्वयन करने वाली सरकार भले ही आपके दल की न हो, परंतु यदि उस योजना का लाभ आपके क्षेत्र की जनता को, राज्य की जनता को मिलता है तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका पहला प्रयास यह होना चाहिए कि योजना का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। ठीक है, महाराज। परंतु क्या हो रहा है? हमारी सरकार ने इसी उद्‌देश्य से कुछ गरीबों के लिए, कुछ आदिवासी के लिए, कुछ यहां की उन्नति के लिए योजनाएं बनाईं, आपने उसको अपने बजट में उठाकर रद्‌दी की टोकरी में फेंक दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसे?

डॉ. चरणदास महंत :- मैं आपके जितना समय नहीं लूंगा, मैं आंकड़ों में नहीं फंसने वाला। आपके बहकावे में नहीं आने वाला हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज संपदा से परिपूर्ण जो हमारा छत्तीसगढ़ है, उसके बारे में हम लोग सोचते थे कि और बेहतर ढंग से काम होगा। हमारी तो सिंगल इंजन की सरकार थी, अभी आपकी डबल इंजन की सरकार हो गई है। कौशिक जी को डबल इंजन का हेलीकॉप्टर भी चाहिए। यानि डबल इंजन से हर काम होंगे, यह सोच रहे थे। मगर डबल इंजन से एक ही काम

करना है, छत्तीसगढ़ का दोहन ही आप डबल इंजन से करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के पेड़ ही डबल इंजन से काटना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में अंबानी जी को डबल इंजन से ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यहां के गरीबों को, आदिवासियों को आपके डबल इंजन से कुछ नहीं मिलेगा ? यह कैसा डबल इंजन है ? यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन पर आ जायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की सरकार छत्तीसगढ़ में भले न हो, मगर हमको संतोष तो है। अगर हमने प्रति क्विंटल धान के 2500 रुपये नहीं दिये होते तो आज आप 3100 रुपये नहीं बांटते। इसका संतोष है। हम लोगों को इस बात की भी संतोष है कि महाराज, अगर हम 20 क्वंटिल नहीं लखि होते तो आप 21 क्विंटल नहीं दिये होते। (मेजों की थपथपाहट) यह जो हमने बुनियाद रखी है जिस पर आप सीना तानकर खड़े हैं। तेंदूपत्ता संग्राहको को 4500 रुपये नहीं देते तो आप 5000 रुपये नहीं देते। महाराज, बाकी बातें आपको क्या कहें ? अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बातें करना चाहता था, मगर लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं होगा। आप जिस धीमी गति से 2 महीने निकाले हैं । दो महीने में चुनाव आ जायेगा। रिजल्ट में दिख जायेगा कि किस योजना से कितना लाभ मिला है? आप किस-किस मंत्री को मंत्री को अंदर करेंगे, किस-किस मंत्री को बाहर करेंगे, यह आप ही सोचिये। लेकिन हम तो कह रहे थे कि जैसे आप आए हैं, काम शुरू कर दीजिये, क्योंकि आज ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज ही वह समय है, जिसमें आप काम कर सकते हैं। कल को किसने देखा है? "काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब।" तो आप यह कल की बातों पर हम लोगों को लेजाना चाहते हैं। ठीक है। यदि आपके लोगों को बुरा न लगे तो मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं। आप लोग छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए जो जिलाध्यक्षों की पदस्थापना की नियुक्ति करते हैं, आप उसको 6 महीने, 8 महीने में बदलने के बजाय उसको एक निश्चित समय बना लीजिये कि हम दो साल नियुक्ति नहीं करेंगे ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो विकास के काम है, वह उलझा न करें।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं एक मिनट बोल लूं? सिर्फ आधा लाईन बोलना चाहता हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- बोलिये न।

श्री धरम लाल कौशिक :- साहब, पहले यहां के कलेक्टर, एस.पी. और बाकी अधिकारी यह महसूस करते थे कि हम जिस जिला में जायेंगे, वहां हमको दो-ढाई साल काम करने का अवसर मिलेगा और उन्होंने काम करके छत्तीसगढ़ को आगे भी बढ़ाया। जो Renewal की सिस्टम आया है, वह Renewal के कारण सारा मामला गड़बड़ा गया। आप सुझाव दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं आयेगी, क्योंकि अब Renewal वाली सरकार नहीं है। इसलिए उनको पूरा अधिकार औरे पूरा समय मिलेगा।

डॉ. चरण दास महंत :- बिल्कुल। आपका धन्यवाद। मैंने आपकी Renewal की बात को नहीं समझा, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप सभी सदस्यों से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। उनका जवाब आयेगा। इसलिए मुझे लगता नहीं कि किसी को अलग से स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। सारा जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे और वह सक्षम हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- आपने शासकीय कर्मचारियों को जो डी.ए. की भुगतान देने की घोषणा की थी। वह संभवत: नहीं हो पाया है। राज्य के जितने संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, जिनको आपने नियमितीकरण करने की बात कही थी, वह अभी तक नहीं हो पाया है। राज्य में खनिज दोहन की आपको नई पारदर्शी नीतियां बनानी थी। शायद दो महीना कम ही है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आप उसकी नीति बना लीजिये। राज्य में जिस तरह से खनिजों का दोहन हो रहा है या हुआ है, वह सब कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। एक नियम-कानून जरूर होना चाहिए। कौशिक जी जिस बात की चिंता कर रहे थे कि सौर ऊर्जा का सृजन करेंगे। सौर ऊर्जा गांव के घरों में लगेगा तो उसका भी तो नियम होगा? यहां तो 75-80 प्रतिशत गरीबों के घर हैं। जहां लोग खपरैल में रहते हैं, उस खपरैल में आप कैसे सौर ऊर्जा का सृजन करेंगे? सौर ऊर्जा को कैसे बनाओगे? जो सीमेंटेड छत है, उसमें तो सौर ऊर्जा लग जायेगी, लेकिन साहब, यह मिट्टी में घरों में कैसा होगा? उसको लोकसभा के बाद बतायेंगे कि वह कैसा होगा?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- मोदी जी 18 लाख घर दे रहे हैं।

डॉ. चरण दास महंत :- अच्छा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम सबको पक्का घर दे रहे हैं तो सोलर लग जायेगा।

डॉ. चरण दास महंत :- ठीक है। मतलब आप उन लागों को जो 18 लाख घर देने वाले हैं। आप देने वाले हैं। शायद आप एक साल में 2 लाख घर देंगे, दो साल में 3-4 लाख घर देंगे तो उन घरों में सौर ऊर्जा चलेगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, 8 लाख देंगे।

डॉ. चरण दास महंत :- वह 2047 तक चलेगा, सर।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी इधर देखकर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा डायलाग ठीक नहीं है। मैं बैठा हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- Sorry sir. अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी को देखकर हम लोगों की आदत थोड़ी खराब हो गई है। साहब, वह कभी भी सीधा बात नहीं करते हैं। वह ऐसे उस तरह से बात करते थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ओ अइसे धीमी गति से समाचार चलही ता सब झन सुत जाही।

डॉ. चरण दास महंत :- सर, हम लोग उनकी आदत देखकर थोड़ा-सा बिगड़ चुके हैं। मूणत जी, मैं आबकारी के बारे में कुछ कहूं या ना कहूं?

अध्यक्ष महोदय :- अब आप पूछेंगे तो फिर जवाब आता रहेगा?

डॉ. चरण दास महंत :- आबकारी के बारे आप लोग ई.ओ.डब्ल्यू. से छापे चला रहे हैं।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो आग्रह करूंगा कि आपको सब बोलना चाहिए, लेकिन इतना ध्यान आपको भी है कि आप वहां थे, निगाहें यहीं थी। कोई चीज छिपी हुई नहीं है। आईने में चेहरा मेरा भी दिखता है, आईने में चेहरा तेरा भी दिखता है।

अध्यक्ष महोदय :- आज सब तैयारी करके आए हैं, ऐसा नहीं है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरी बारी नहीं है उन्हीं की बारी है । (हंसी) प्रदेश की जनता की समस्या के लिये आपने लोक गारंटी बनाया है । लोकसेवा गारंटी कानून फेल हो चुका है । लोकसेवा गारंटी कानून का पालन आप सबसे पहले अपने मंत्रालय से शुरू करें, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हम निवेदन करते हैं और जितने भी निर्माण कार्य थे, उनको तो आप लोगों ने ए.एस. और टी.एस. के चक्कर में बंद कर दिया, उसमें जल्दी कर लीजिये । चूंकि हमारे विधायकगण भी परेशान हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता भी परेशान है और आपने जितने निर्माण कार्य रोक दिये हैं उनको जल्दी शुरू करवा दीजिये, यह मेरा आपसे निवेदन है । आपने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह वर्ष 2024-25 तो ठीक है, आपने जो वर्ष 2024-25 का नाम लिख दिया है लेकिन उसमें आपने वर्ष 2047 के सपने दिखाये हैं। वर्ष 2047 में हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे यह तो कह नहीं सकते लेकिन आपके वित्तमंत्री जी ने जो सपना दिखाया है वहां तक पहुंचने में हम लोग शायद बूढ़े हो जायेंगे या रहेंगे भी नहीं इसलिये आप लोगों का जो विजन है उसको थोड़ा बदलिये । महाराज, सरकार का तख्ता पलट करना ही विजन नहीं होता । कुछ करिये । शिक्षा, सड़क, पुलिया जितने भी कार्यों का आपके इसमें समावेश है, मैं उन पर कुछ नहीं कहना चाहता । सरकार की नीति अच्छी हो सकती है लेकिन कुछ लोगों को देखकर लग रहा है कि नीयत में कुछ खोट है । प्रदेश में पूंजी कौन लगायेगा ? यह अब तक तय नहीं हो पा रहा है । हम लोग खोज डाले कि कहां से पूंजी आ रही है, कहां से जा रही है और अगर इसे आपके नरेन्द्र मोदी जी तय करेंगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता । यदि आपको बुरा लग रहा है तो बुरा लगे । मैं उसमें ज्यादा नहीं कहूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पास जो मछली पालन विभाग है । हमारी सरकार ने तो इसे चूंकि हमारे साथियों ने भी कहा है कि हमने इसे खेती का दर्जा दिया था और हम चाहते थे चूंकि यह एक ऐसा साधन है जिससे हमारे लोगों के जीवन-यापन करने की व्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी इसलिये कृषि पालन और मछली पालन पर आप इसमें ज्यादा ध्यान देंगे । ऐसा मेरा निवेदन है । खनिज संसाधन का जो दुरूपयोग आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं मैं तो नहीं जानता लेकिन डी.एम.एफ. के मामले में आपकी कुछ स्पष्ट नीति बन जानी चाहिए और यह नीति बनने के बाद मैं समझता हूं कि किसी की गुंजाईश यह नहीं रहेगी कि इतना पैसा खा गया, इतना पैसा ले गया । अभी-अभी चूंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि कलेक्टर लोगों की जो मनमानी चल रही है कि किसको 1 करोड़ देना है, किसको 2 करोड़

देना है, किसको नहीं देना है, कहां किस बिल्डिंग में लगना है, कहां फर्नीचर में लगना है उसको आप निर्धारित करें तो यह ज्यादा बेहतर है और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन हो और छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के रहवासी और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो रहते हैं यह उनके काम आये केवल कॉर्पोरेट लोग लूटने की कोशिश न करें । जिस ढंग से हम सुन रहे हैं कि यहां कॉर्पोरेट लगायेंगे, हमारा हसदेव अरंड ले जायेंगे । हमारे हसदेव नहर का पानी ले जायेंगे । बस्तर के जंगल ले जायेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे ? इसी तरह से हम लोगों ने बस्तर कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड का गठन किया था और जगदलपुर में विधिवत् चालू करके उसमें भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं उसको हमने शुरू कर दिया था । अब आपने शायद इसको बंद कर दिया । भाई लखेश्वर जी बता रहे हैं कि 2100 लोगों की भर्ती की गयी थी । यह तो बस्तरवालों के लिये था, कोई बिलासपुरवालों के लिये नहीं था, कोई अंबिकापुरवालों के लिये नहीं था, बस्तर के लिये था । इसे आपको बंद नहीं करना चाहिए था, ऐसा मेरा कहना था, कहना है, कहता रहूंगा । आपने जिस ढंग से जल्दी-जल्दी में बजट बनाये हैं । मैंने उसमें देखा तो 6-6 विभाग का कुछ भी दिख ही नहीं रहा है । आपका वो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जो आपने नीति समाज के अंतिम छोर के लिये बनाई थी, उस योजना का लाभ तो मिल जाये न। उस योजना का नाम भी है। वर्तमान में जो वनांचल क्षेत्र हैं, वन विभाग का जो मैंने ध्यानाकर्षण भी लगाया था, वे नंगे तारों से आजकल भरे पड़े हैं। कुछ में विद्युत विभाग का दोष है या वन विभाग का दोष है, इसे सोच-विचार कर लीजिए। मेरे ख्याल से हमारी जब सरकार थी, हमने प्रस्ताव भेजा था कि ये जो नंगे तार लगे हैं, उसको हम इंसुलेटेड वायर से लगायेंगे और उसमें कुछ हजार का खर्चा है। अब वह खर्चा को वन विभाग करेगा या खर्चा ऊर्जा विभाग करेगा, ये अभी तक नहीं है और इन नंगे तारों के कारण अब तक 13 जंगली जानवर मर चुके हैं और आपको बता दूं ये आपके और हमारे दोनों के लिए लज्जा की बात है। इसमें कुछ मानव की भी हत्या हुई है। आदमी लोग भी मरे हैं, जिसको छिपा दिया गया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि ये सब काम करिए। आपको ईश्वर ने अवसर दिया है। पंप कनेक्शन के बारे में हमारे साथियों ने बता दिया है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। सूचना प्रौद्योगिकी जन शिकायत निवारण, ये सब आपके विभाग हैं और स्वास्थ्य विभाग के हमारे मंत्री जी बैठे हैं। आज मैंने सुबह देखा, थोड़े तेज-तर्रार दिख रहे हैं। इसलिए मैं आपको ही कह देता हूं। उनको निर्देश दीजिए कि जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं, उन चिकित्सालयों में जो उपचार हो, वह अच्छे तकनीक से होना चाहिए। अच्छे तकनीक से हमारे गरीबों का उपचार होना शुरू हो जाये। महंगी-महंगी मशीनें हमारे यहां आकर पड़ी हुई हैं। स्थापित तो हुई हैं, मगर उसे चलाने वाला नहीं है। तो चलाने वाले की पहले भर्ती कर लें और दवाई की जैसी बात आयी, उसमें कुछ लोगों का ट्रांसफर किया है। मैं चाहता हूं कि आप पहले भर्ती कर लें और इसमें भी काम चालू हो जाये। सरकार ने किसानों के लगभग 8 साल पुराने धान की प्रोत्साहन राशि 3700 करोड़ रूपये का भुगतान किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दावे के साथ इस सदन में कहना

चाहता हूं कि प्रदेश के लगभग सवा लाख किसानों के खाते में आज तक आपकी बोनस राशि नहीं पहुंची है। ये मेरा आरोप नहीं हैं, आप जांच करा लीजिए। इसमें गलती उस किसान की नहीं है। गलती सरकार के तंत्र की है। इसका निराकरण आप करेंगे तो खुशी होगी। पशुधन मामले में बहुत सारे लोगों ने कहा है। आपने सुना होगा अपने कक्ष से हम लोगों ने 163 मोबाइल यूनिट बनाया था और मोबाइल यूनिट से बहुत से इलाज करते थे। उसमें वेटेरनरी डॉक्टर था। उसमें हेल्पर रहता था और पशुधन की हम लोगों ने सुरक्षा करने की कोशिश की है। उसको आप लोग देख लीजिए और करिए। सर, एक परिवहन विभाग हुआ करता था और इसमें आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी की सरकार ने अब कहूं या न कहूं आप आरोप मान लेंगे। दो साल की बात है, मैं छोड़ देता हूं। छोडिए। आप लोगों ने साहब चेकपोस्ट बंद किया था। मैं इशारे में कह देता हूं। उससे कितना नुकसान हुआ? कितना फायदा हुआ? आप बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते। मैं यह जरूर कह सकता हूं कि हमारी सरकार जब दिसंबर में आयी तो जुलाई, 2020 में चेकपोस्ट और उड़नदस्तों के पुन:संचालित करने से हमको वर्ष 2020-21 में 66 करोड़ और 42 लाख का फायदा हुआ और वर्ष 2022-23 में लगभग 213 करोड़ का फायदा हुआ और आपने उसका 400 करोड़ का नुकसान उठाया था। यह आपकी नीति थी।

श्री राजेश मूणत :- जिस दिन मैंने चेक पोस्ट बंद किया था । उस समय 600 करोड़ रूपया राजस्व था, 2017 में । ये टेक्सेस प्रणाली के अंदर सब अलग-अलग हैं, यह सब जानते हैं नेता जी, अब आगे इस पर कोइ बात करें तो अच्छा नहीं है ।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिए छोड़िए । मैं तो कह रहा हूं कि आपकी नीति से 400 करोड़ का नुकसान हुआ । अब आपने आबकारी विभाग क्यों रख लिया साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ? आबकारी विभाग अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने अपने पास नहीं रखा । इसमें बिल्कुल बदनामी का घर है, आपने रख लिया । विमानन विभाग ठीक है, आप नया विमान खरीदिए, मैं भी कहना चाहूंगा, नया हेलीकॉप्टर खरीदिए, मैं भी कहना चाहूंगा । अगर विमान का काम आपको नहीं है तो किराये पर भी दीजिए ताकि आपका खर्चा निकलता रहे । हमारे बिलासपुर-अंबिकापुर-बिलासपुर चालू करा दीजिए । बिलासपुर-दिल्ली, बिलासपुर-इंदौर-रायपुर चालू करा दीजिए । प्रयोगराज-बिलासपुर-जबलपुर भी बंद हो गया है । यह सब बातें हमारी साथियों ने भी कही है, मैं आपको याद दिला रहा हूं । इसी के साथ, चूंकि मेरी बातें बुरी लग रही हैं, आपको तो नहीं लग रही हैं, आपके लोगों को लग रही हैं इसलिए मैं अपनी बातें समाप्त करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मांगों का विरोध करता हूं और अपनी बातें समाप्त करता हूं, धन्यवाद् ।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे पास जो विभाग है उन पर दिन भर चर्चा हो रही है, अब समापन की ओर है । आज की चर्चा श्री कुंवर सिंह निषाद जी ने प्रारंभ की, नेता प्रतिपक्ष और हमारे पूर्व स्पीकर, धरमलाल कौशिक और अजय चंद्राकर जी सहित कुल 18 सम्मानित विधायकों ने इसमें भाग लिया, मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद् देता हूं । चर्चा के दौरान

बहुत से सदस्यों की तरफ से अच्छे सुझाव भी आए हैं और उनके क्षेत्र की मांग भी आई है उन सबको हमारे अधिकारियों ने नोट किया है । इस संबंध में उनको समय पर अवगत कराया भी जाएगा । मेरे विभागों में जो काम हुए हैं, मैं उन पर बाद में आऊंगा । उसके पहले आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, जो हमारे परम् मित्र हैं, आज के समय से नहीं, मध्यप्रदेश के समय से । मध्यप्रदेश में वे गृहमंत्री थे तब हम लोग विधायक थे, तब से दोस्ती है। उस समय वे पॉकिट में गुड़ाखू पकड़े रहते थे (हंसी) कुर्ता के जेब में पॉलीथीन में गुड़ाखू रखते थे । (नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत द्वारा कुर्ते की जेब से गुड़ाखू की पॉलीथील निकालकर दिखाने पर) अच्छा, आज भी है, चलिए आपने आदत छोड़ी नहीं है (हंसी) । उस समय से हम लोगों की दोस्ती है। आपने बहुत अच्छे सुझाव हमारे हित में दिया है इसके लिए हम उनक आभारी रहेंगे। घर तक की भी चिंता कर रहे हैं, इसके लिए भी हम आभारी रहेंगे । हमारे घर में हमारी धर्मपत्नी कितना पूजा पाठ करती हैं, इतना भी मालूम है तो हमारे मित्र को हमारी तरफ से धन्यवाद् । आज उनका बहुत अच्छा उपदेश हमको सुनने को मिला । बीच-बीच में मिलता भी रहा है और आज प्रारंभ में ही उन्होंने कहा कि परम्परा के अनुसार इन मांगों का विरोध करेंगे तो इसी से समझ में आता है कि वे हमारे परम् मित्र हैं । चूंकि वे नेता प्रतिपक्ष हैं इसलिए उनकी मजबूरी है कि वे विरोध करेंगे । मैं समझता हूं कि जितना उपदेश उन्होंने आज हमें दिया है, यही उपदेश बगल वाले को पिछले पांच साल दिए होते (मेजो की थपथपाहट) तो शायद हमारी जगह आप होते और हम लोग उस तरफ होते ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने सुन लिया, बाकी कौन सुनता है। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

श्री विष्णुदेव साय :- आपने कई तरह से सुझाव भी दिए। आपको विधान सभा आने से कौन रोकता है। ऐसा कोई रोकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। हम जो चाहें और वह हो नहीं। (मेजों की थपथपाहट) हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा उपकार है कि एक गांव के छोटे से किसान के बेटे को दो-दो बार विधायक बनाया, चार-चार बार सांसद बनाया, तीन-तीन बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया और मोदी जी के शासनकाल में राज्यमंत्री का दायित्व मिला, आज मुख्यमंत्री का दायित्व मिला। (मेजों की थपथपाहट) मैं यह बता दूं, यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह पार्टी हमसे कभी पूछी भी नहीं कि आपको यह बना रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि हमको कौन रोक सकता है। कुछ मजबूरियां थी, इसलिए हम विधान सभा में नहीं आ पाये थे। मोदी की गारंटी की सरकार बोल रहे थे, यह तो है ही। आज नरेन्द्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, यह आपको भी मालूम है। (मेजों की थपथपाहट) आज मोदी जी के कारण पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। एक समय आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री होते थे, विदेश में कभी किसी बैठक में चले जाते थे तो कहां डूबके रहते थे, पता नहीं चलता था। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो दुनिया की महाशक्ति है, उनके भी राष्ट्रपति आज कहीं न कहीं निगाहें लगाकर देखते रहते हैं कि भारत के नरेन्द्र मोदी जी कहां पर है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री विष्णुदेव साय :- आप बाद में बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा किसी पर कोई टिप्पणी नही हैं। मैं आपकी सिर्फ एक ही बात को बोल रहा हूं, भारत के जो भी प्रधानमंत्री हुए, आपने नरेन्द्र मोदी जी के लिए कहा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री जब विदेश के दौरे पर गया है तो भारत का रिप्रजेनटेटिव बनकर गया है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में रेड कार्पेट बिछा था, रेड कार्पेट बिझने वाले वे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके अलावा और उनके बाद अभी तक किसी के लिए रेड कार्पेट नहीं बिझा है।

श्री विष्णुदेव साय :- ठीक है, मैं उनके उपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन जो वास्तविकता है, उसको दुनिया देख रही है। (मेजों की थपथपाहट) मोदी की गारंटी में आज इस देश का बच्चा-बच्चा विश्वास कर रहा है। आज एक छोटे से गांव के बच्चे को भी पूछेंगे, वे किसी को जाने या नहीं लेकिन देश का प्रधानमंत्री कौन है तो नरेन्द्र मोदी जी को जानते हैं। (मेजों की थपथपाहट) आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री जी और पार्टी का ध्येय वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। (मेजों की थपथपाहट) इस पर देश की जनता विश्वास कर चुकी है। इसीलिए आज 10 साल से मोदी जी लगातार हर बार बढ़त बनाकर प्रधानमंत्री बने हैं, अगले बार भी बनने वाले हैं। (मेजों की थपथपाहट) इस बार 300 से भी ज्यादा सीट लाने वाले हैं, एन.डी.ए. का 400 से पार होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त किया है तो 370 से ज्यादा सीट आने वाली है।(मेजों की थपथपाहट) इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पिछले पांच साल आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने भारी जनादेश के साथ सरकार में बैठाई थी, आज उतनी सीट हम लोगों के पास नहीं है। आप लोगों की 70, 71 सीट पहुंच गयी थी, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में 36 वादा किये थे लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बार-बार कहता रहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में एक भी वादा पूरा की है तो हमको बता दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। हमारा कई बार वक्तव्य आया। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन आपने शायद पांच साल में छत्तीसगढ़ में एक भी वादा पूरा नहीं किए। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता आज आप लोगों को उस तरफ बैठा दी है। खैर, लोकतंत्र में यह सब होता रहता है। मैंने कहा है कि आज की चर्चा में हमारे जितने माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और उनकी जो भी मांग और सुझाव हैं, उनको सबका जवाब मिलेगा। हमारे अजय चंद्राकर जी पक्षियों की जनगणना पर टिप्पणी कर रहे थे। पक्षी धन। पक्षी धन का मतलब उड़ने वाला पक्षी नहीं है। हमारे पशुपालन विभाग में उसकी अलग से परिभाषा है। जैसे - मुर्गी, बतख, बटेर हैं। जो पालतू होते हैं, उनकी जनगणना होती है और वह पक्षी धन में आता है। शायद आपको मालूम नहीं रहा होगा कि पक्षी धन क्या होता है तो मैंने आपको इससे अवगत कराना चाहा। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 महीने में हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। मोदी की गारंटी को पूरा करने के हिसाब से बहुत कुछ किया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने अपने राज्यांश की व्यवस्था कर ली है। हम 12 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 3,500 करोड़ रूपये भेज चुके हैं। हम P.S.C. घोटाला की जांच C.B.I. को सौंप चुके हैं। हमने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा है और हम धान की कीमत 3,100 रूपये प्रति क्विंटल भी देंगे। M.S.P. मिल गया है और अंतर की राशि का जुगाड़ हम लोगों के पास हो गया है। हम बहुत जल्दी किसानों के खातों में अंतर की राशि को भी भेजने वाले हैं। शायद पिछले चुनाव में हमने विवाहित महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रूपये देने की बात कही थी। तो शायद आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने प्रतिवर्ष उनको 15,000 रूपये देने की बात की थी। जब हम लोगों ने प्रतिवर्ष महिलाओं को 12,000 रूपये की बात कही थी तो प्रतिवर्ष 15,000 रूपये देने की बात हुई थी। लेकिन आप लोग छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुके हैं। अब आप कुछ भी बोलेंगे तो जनता आप पर विश्वास करने वाली नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं हमने पिछले 2 महीने में विभागवार जो कार्य किए हैं, वह सदन के सामने रखना चाहूंगा। पहला सामान्य प्रशासन विभाग, प्रशासनिक सुदृढ़ता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। मंत्रालय में डिजीटल सचिवालय परियोजना का क्रियान्वयन चिप्स के सहयोग से किया जा रहा है। परियोजना के तहत् मंत्रालय में पदस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन, अवकाश आवेदन एवं अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इसके लिए कम्प्यूटर, स्कैनर तथा फोटोकॉपी मशीन खरीदने के लिए 90 लाख रूपये का प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत् मंत्रालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 14 पहले के सेटअप के वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न संवर्गों के 134 पदों के सृजन के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत् संस्कृति विभाग प्रकोष्ठ के गठन के लिए 6 नवीन पदों का सृजन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए 30 लाख रूपये का प्रावधान बजट में किया गया है। लोक सेवा आयोग में हुई अनियमितता की जांच हमने C.B.I. से कराने का निर्णय लिया है। राज्य शासन द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं को U.P.S.C. की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार के विभिन्न मामले जो पहले से प्रचलित हैं, जैसे - शराब घोटाला, कोयला घोटाला, D.M.F. घोटाला में संलिप्त व्यक्तियों तथा अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रकरण पंजीबद्ध किये जा रहे हैं। एण्टी करप्शन ब्यूरों कार्यालय को अधिक सशक्त बनाने के लिए दुर्ग संभाग के एण्टी करप्शन ब्यूरों क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए विभिन्न संवर्गों के 35 पदों के सृजन के लिए 1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरों में 6 नवीन पदों के सृजन के लिए 20 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । मुख्यमंत्री

अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं आवागमन से संबंधित अधोसंरचनाओं के रख-रखाव एवं उन्नयन संबंधी कार्यों के लिए 50.01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी आम निर्वाचन सम्पन्न कराने और नियमित कार्य संपादन के लिए 84 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग । राजस्व संग्रहण में वृद्धि, आबकारी कर आवंचन के प्रकरणों पर नियंत्रण के लिए प्रशासकीय व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी, इसके लिए विभागीय पदों में वृद्धि निरीक्षण हेतु वाहन व्यवस्था एवं मानीटरिंग हेतु कम्प्यूटर उपकरण के लिए प्रावधान किया गया है । आबकारी विभाग के अंतर्गत जिला स्तर पर अपराधों के प्रभावी नियंत्रण तथा प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही के लिए जिला स्तरीय उड़नदस्ता के गठन के लिए 188 नवीन पदों के सृजन हेतु 1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । आबकारी विभाग के अंतर्गत अन्य राज्यों से मदिरा तथा मादक द्रव्यों के अवैध परिवहन पर रोकथाम के प्रभावी नियंत्रण हेतु आबकारी थानों और जांच चौकियों के गठन के लिए 325 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा । इसके लिए 1 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । राजस्व संग्रहण में वृद्धि एवं प्रशासकीय कसावट लाने के लिए आबकारी विभाग के विभिन्न कार्यालयों में लिपिकीय श्रेणी के 168 पदों में वृद्धि की गई है । इसके लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । आबकारी विभाग के अंतर्गत उपलंभन कार्य तथा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रतिस्थापन मद में 10 वाहन एवं 15 नवीन वाहनों के लिए 2 करोड़, 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । तकनीकी आधारित रिफार्म एवं सुशासन को सुशासन से कर आवंचन पर नियंत्रण के लिए सेन्ट्रल कमांड एवं कंट्रोल सेन्टर हेतु 1 करोड़ रूपए तथा कम्प्यूटर तथा उपकरणों के लिए 20 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग । ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के माध्यम से किसानों को नि:शुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 3500 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) किसानों को 3 एच.पी. तक कृषि पम्पों के बिजली बिल में 6 हजार यूनिट प्रतिवर्ष एवं 3 से 5 एच.पी. के कृषि पम्प के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रतिवर्ष छूट दी जा रही है । (मेजों की थपथपाहट) प्रदेश के लगभग 6,94,399 किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं । कृषि पम्पों के ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । इससे 20 हजार कृषि पम्पों का ऊर्जीकरण संभव हो पाएगा । कृषि पम्पों के ऊर्जीकरण के लिए प्रति पम्प 1 लाख रूपए एवं अधिकतम डेढ़ लाख रूपए तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है । घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयक में हाफ बिजली बिल के अंतर्गत राहत प्रदान की जा रही है । 45,62,443 घरेलू उपभोक्ता इस योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं । घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल

में रियायत देने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 1274 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । इस योजना का विस्तार भिलाई स्टील प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन लायसेंसी एरिया, भिलाई टाऊनशिप एरिया के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी किया गया है । इसके लिए वर्ष 2024-25 के बजट में लगभग 8500 घरेलू उपभोक्ताओं को रियायत देने के लिए 8 करोड़, 53 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । रिवेंम्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत 244 करोड़, 18 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार Revamped Distribution Sector scheme प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2024-25 तक वाणिज्यक एवं तकनीकी हानि ATC लॉस को 12 से 15 प्रतिशत क सीमित करना एवं एवरेज कास्ट आफ सप्लाई एवं एवरेज रेवेन्यु रियलाइजेशन के अन्तर को शून्य करना है। इस योजना का उद्देश्य बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाना तथा सामर्थय में सुधार करना है। इसके लिए कृषि फीडर को अलग किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत 11 के.व्ही. एवं 33 के.व्ही. लाईनों की स्थापना निम्न दाब एल.टी लाईनों में बेयर कंडक्टर के स्थान पर ए.बी. केबल की स्थापना का कार्य किया जायेगा। बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को दी जा रही रियायतों के लिए 539 करोड़ 60 लाख का प्रावधान बजट में किया गया है।

मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 106 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पी.एम.कुसुम योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य विकेन्द्रीकृत सौर उर्जा एवं अन्य नवीनीकरण उर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के अतिरिक्त किसानों को अतिरिक्त आय का स्त्रोत प्रदान किया जाना है। पूंजीगत व्यय, विद्युत पारेषण, उत्पादन, वितरण कम्पनी के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट मीटर टेस्टिंग बैंच की स्थापना के लिए 9 करोड़ 27 लाख का प्रावधान किया गया है। पावर कम्पनी के ऋण को टेक ओवर के लिए 454 करोड 62 लाख का प्रावधान किया गया है। उदय योजना के अन्तर्गत सी.एस.पी.डी.सी.एल. को अनुदान के लिए 53 करोड़ 39 लाख का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ अक्षय उर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के अन्तर्गत सौर सुजला योजना के लिए 670 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इन्दिरा गांव गंगा योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सौर सामुदायिक सिंचाई योजना नवीन मद के अन्तर्गत 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सौर उर्जा आधारित योजनाओं के लिए सहायक अनुदान मार्केट मोड योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उर्जा शिक्षा उद्यान के लिए 9 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ग्रीड कनेक्टेड सोलर रूपटाफ प्रोग्राम के अन्तर्गत 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास एजेंसी को सहायक अनुदान के लिए 37 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार पुशपालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने 513.01 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अन्तर्गत डेयरी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। राज्य पोषित व्यक्ति मूलक योजनाओं से भी हम पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने इसके लिए 11 करोड़ 01 लाख रूपये की राशि का प्रावधान किया है। दुग्ध संघो को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादकों को प्रेरित करने के लिए शासन द्वारा ढाई रूपये प्रति लीटर परिवहन अनुदान दिया जा रहा है। परिवहन अनुदान हेतु 6 करोड़ रूपये का प्रावधान है। पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण के लिए 17 करोड़ 89 लाख 50 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। पशु संवर्द्धन एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए भी 63 करोड़ 75 लाख 55 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के रूप में मानदेय दिए जाने के लिए 4 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में पशु चिकित्सा सेवाएं त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट कार्य कर रही है। इसे काल सेन्टर के हेल्प लाईन 1962 से भी जोड़ा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मछली पालन विभाग, प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिये हम विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं । इस साल हमने मछली पालकों के लिये चलाई जा रही हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिये 180 करोड़ 4 लाख रूपये का प्रावधान किया है, जो गत वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत अधिक है । अध्यक्ष महोदय, मछली पालन के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राज्य में एक्वापार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है । इस साल मत्स्य बीज उत्पादन 365 करोड़ से बढ़कर 405 करोड़ होने की संभावना है । इस वर्ष मत्स्य उत्पादन में 13.10 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है । मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हम महासमुंद, सक्ती, राजनांदगांव, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तथा जशपुर जिले में नवीन मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की स्थापना कर रहे हैं । प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत एक्वापार्क की स्थापना के लिये 5 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है । कामधेनु विश्वविद्यालय में मत्स्य काम्पलेक्स के परिचालन के लिये 20 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है । प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला हितग्राहियों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज साधन विभाग हमने खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिये, खनिज परिवहन हेतु ऑनलाईन ई ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुन: आरंभ कर दी है। वित्तीय वर्ष के अंत तक खनिजों के माध्यम से 13 हजार करोड़ रूपये का खनिज राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है । खनिज विभाग द्वारा वर्तमान सत्र में खनिजों के खोज एवं अन्वेंषण हेतु 26 परियोजनायें संचालित की जा रही है । आगामी वर्षों में विभिन्न खनिजों के कुल 53 ब्लॉक आबंटन ई नीलामी के माध्यम से

होगा । इज ऑफ डूइंग बिजनेस की परिकल्पना के साथ खनन क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने वेब आधारित योजना खनिज ऑनलाईन व्यवस्था आरंभ की जा रही है । बी.एम.एफ. फण्ड में दिसम्बर 2023 तक कुल 12,396 करोड़ रूपये का अंशदान प्राप्त किया गया है । इसके माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से किये जायेंगे । प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान बनाने के लिये रेत उपलबध कराई जा रही है । लीज स्थलों पर छोटी गाड़ी से रेत ले जाने की सुविधा प्रदान की गई है । सातवां जनसंपर्क विभाग, शासन के किसी भी योजना की सफलता के लिये यह बहुत जरूरी है कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से उसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचे, ताकि आम जनता जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके । राज्य सरकार के जनकल्याणकारी नीतियों और विकास योजनाओं का मीडिया के सहयोग से जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है । राज्य स्तर पर समाचार पत्र- पत्रिकाओं, न्यूज वेबसाईटों और पोर्टलों की संख्या बढ़ रही है । प्रिन्ट मीडिया के लिये वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में प्रदर्शन विज्ञापन हेतु 110 करोड़ रूपये तथा वर्गीकृत विज्ञापन के लिये 22 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । अध्यक्ष महोदय, विभाग में क्षेत्र प्रचार के तहत परंपरागत रूप से होर्डिंग्स, प्रदर्शनी, कला जत्था, वॉल पेंटिंग, आदि तरीकों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है ।इस मद में 120 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है । शासन द्वारा संचालित विभिनन विभागों की विकास योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर होर्डिग्स लगाये जा रहे हैं । इसी तरह गणतंत्र दिवस पर झांकी आदि के लिये विशेष अवसरों पर प्रचार-प्रसार मद में 2 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है । इलेक्ट्रानिक मीडिया मद से राष्ट्रीय न्यूज चैनलों, प्रादेशिक न्यूज चैनलों, अन्य बहुराज्यीय न्यूज चैनलों, रेडियो, सिनेमा आदि को राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, उपलब्धियों के विज्ञापन जारी किये जाते हैं । चैनलों की संख्या में गुणोत्तर वृद्धि होने से बजट काफी कम प्रतीत होता है और प्रचार-प्रसार के उद्येश्य में बाधा आती है । वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये इसके लिये 90 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है । न्यू मीडिया के नाम से आकार ले रहे क्षेत्र में वेब पोर्टल, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे ट्यूटर, फेस बुक, यू ट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य कई प्लेटफार्म आते हैं, जिसमें व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ओ.टी.टी. प्लेटफार्म पर भी शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। इससे एक बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इस मद में 40 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है।

प्रकाशन मद के तहत महत्वपूर्ण विशेष अवसरों पर शासकीय प्रचार साहित्य का प्रकाशन कॉपी, टेबल, बुक, पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, लघु पुस्तिका, पोस्टर, पॉम्प्लेट, ब्रोशर, फोल्डर आदि का प्रकाशन किया जाता है। इस मद में 20 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सहायता। मीडिया प्रतिनिधियों और उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को बीमारी या दुर्घटना में आहत होने पर ईलाज के लिये शासन की ओर से चिकित्सा सहायता अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है, इसके लिये 01 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकारिता पुरस्कार। जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदेश के पत्रकारों को विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर रचनात्मक एवं अनुसंधान पूर्ण लेखन के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वर्गीय चंदूलाल चन्द्राकर और मधुकर खेल स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारों की स्थापना की गयी है, इसके लिये ढाई-ढाई लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान निधि। पत्रकारिता के क्षेत्र में समर्पित हमारे वरिष्ठम पत्रकार साथी सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें, इस दृष्टि से उन्हें नियमित आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिये प्रदेश में मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना संचालित है। इसके तहत पत्रकारों को प्रतिमाह 10 हजार रूपये सम्मान निधि के रूप में दिया जाता है। वर्तमान में 29 वरिष्ठ मीडियाकर्मियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिये 36 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित माधव राव सप्रे रचनात्मकता सम्मान। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा मीडिया में रचनात्मक कार्यों के लिये ऐसे मनुष्यों को सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने अपनी अद्वित्य रचनात्मकता एवं हिन्दी भाषा के प्रति अपने समर्पन से अपने राज्य का गौरव बढ़ाया है, इन्हें प्रतिवर्ष 01 लाख रूपये की राशि का पंडित माधव राव सप्रे रचनात्मकता सम्मान पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु ढाई लाख रूपये बजट में रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी उपयोजना। इसके अंतर्गत जनसंपर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, उपलब्धियों और महत्वपूर्ण निर्णयों का व्यापक प्रचार-प्रसार, चलित प्रदर्शनी वाहन, नाचा दल, सूचना शिविर, प्रचार-सामग्री, फिल्म प्रदर्शन दीवार लेखन आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार के लिये 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुनर्वास विभाग। पुनर्वास विभाग का गठन वर्ष 1964 में पूर्व पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश से आये विस्थापित परिवारों को बसाने के लिये किया गया था। इस विभाग के अंतर्गत दो कार्यालय संचालित हैं। एक, पुनर्वास आयुक्त कार्यालय एवं दूसरा, कार्यालय कमांडेंट माना शिविर। पुनर्वास आयुक्त कार्यालय के लिये वर्ष 2024-25 के लिये 62.32 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। कार्यालय कमांडेंट फीएल होम्स, माना शिविर के संचालन के लिये स्थापना व्यय विस्थापित परिवारों को राहत सुविधा प्रदाय बिजली, जल, प्रभार, स्थायी बसाहट आदि के लिये 271.10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग। सरकार गठन के बाद से परिवहन विभाग से संबंधित सेवाओं का लगातार आधुनिकीकरण किया जा रहा है। विभाग की समस्त सुविधाएं ऑनलाईन की जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश की आम जनता को सुगम एवं पारदर्शी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सभी परिवहन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। राज्य भर में 489 परिवहन सेवा केंद्र की स्थापना की गयी है। जहां आवेदकों को लर्निंग लाईसेंस, ड्राईविंग लाईसेंस की उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही राज्य में लर्निंग लाईसेंस को तत्काल प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। परिवहन विभाग में प्राप्त होने वाले टैक्स एवं फीस की 100 प्रतिशत राशि ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त की जा रही है, जिससे राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता आयी है। आधार अधिप्रमाणन से ड्राईविंग लाईसेंस वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र सहित 22 तरह की सेवाओं के लिये घर पहुंच सुविधा उपलबध है। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 07 दिनों में दस्तावेज आर.सी., डी.एल., स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोगों के घर पहुंचाया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रीक वाहन नीति, हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रख कर इलेक्ट्रीक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। जिसके अंतर्गत पंजीकृत इलेक्ट्रीक वाहनों को सब्सीडी प्रदान की जा रही है। ए.एन.पी.आर. कैमरा, इस योजना के तहत लिकेज मार्गों पर ए.एन.पी.आर. कैमरा स्थापित किया जा रहा है, जिससे फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना संचालित वाहनों पर ई-चालान की कार्यवाही की जा सके ताकि अनफिट वाहनों से होने वाले सड़क दुर्घटनाओं से दुर्घटना में प्रभावी कमी लायी जा सके। अभी तक 12 स्थानों पर कैमरा संचालित हो रहे हैं। इस वर्ष 25 नये स्थानों पर कैमरा लगाया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्हीकल ट्रेनिंग प्लेटफार्म कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया फ्रेम के तहत सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस एवं एमरजेंसी बटन लगाने का निर्णय लिया गया है इसके लिए 15.40 करोड़ रूपये की लागत अनुमानित है। जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्र द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जायेगा। लर्निंग लाईसेंस बनाने के लिए परिवहन सुविधा केन्द्रों को अधिकृत किया गया है। इसे रोजगारोन्मुखी बनाने भविष्य में परिवहन केन्द्रों की संख्या 1000 तक करने की योजना है। डायल 112 केन्द्र के कंट्रोल सेन्टर में ही परिवहन डेस्क बोर्ड का भी निर्माण किया गया है। किसी भी आपात स्थिति में पेनिक बटन को दबाने से तत्काल ही सूचना परिवहन विभाग की कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से पुलिस विभाग के डायल 112 में चला जाएगा। इसका संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वेव्रिज की स्थापना। परिवहन विभाग द्वारा अंतर्राज्जीय परिवहन चेक पोस्ट एवं परिवहन उड़नदस्ता के द्वारा ओव्हर लोडिंग की जांच के लिए वेव्रिज की स्थापना की जा रही

है। वेव्रिज की लागत राशि 15.34 करोड़ रूपये है। राज्य में कुल 42 वेव्रिज की स्थापना की जानी है। इसके लिए 15.34 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। यहां 19 स्थानों पर वेव्रिज स्थापित किया जा चुका है। शेष स्थानों पर शीघ्र स्थापित किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंस्पैक्शन एवं सर्टीफिकेशन सेंटर। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर में इंस्पैक्शन एवं सर्टीफिकेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। राज्य के 8 शहरों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव में पी.पी.पी. के माध्यम से ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर की स्थापना की जा रही है इसके तहत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेन्टर की स्थापना की जा चुकी है एवं संचालन किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा। आम जनता को पुरानी और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने हेतु यह सुविधा प्रदान की जा रही है। रायपुर जिले में आर.वी.एस.एफ. शुरू किया जा चुका है तथा जगदलपुर में कार्य प्रगति पर है। दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में आर.वी.एस.एफ. शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है। पुराने वाहन को स्क्रैप कर, नये वाहन खरीदने पर नये वाहन के टैक्स में छूट प्रदान की जायेगी। आर. वी.एस.एफ. के माध्यम से स्क्रैप कराने पर पुराने वाहन के बकाया टैक्स में 1 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ई-ट्रैक। छत्तीसगढ़ के समस्त परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्रायविंग टेस्ट ट्रेक का निर्माण किया जाना है। ऑटोमेटेड ड्रायविंग टेस्ट ट्रेक अत्याधुनिक सेंसर आधारित कम्प्यूटराईज्ड ड्रायविंग ट्रेक होगा। महासमुंद, कोरिया में जिला परिवहन कार्यालय और 10 स्थलों पर चेक पोस्ट के लिए 9 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। परिवहन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों की स्थापना, व्यय एवं संचालन हेतु व्हिकल ट्रेकिंग प्लेटफार्म स्टेट गैरेज के अंतर्गत मोटर गैरेज, सचिवालय एवं पेट्रोल व्यय के लिए कुल 162 करोड़ 53 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामोद्योग विभाग। ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए तथा इसके माध्यम से अधिकाधिक लोगों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के लिए हमने 266 करोड़ 13 लाख 65 हजार रुपये का प्रावधान किया है। हमने बुनकरों एवं शिल्पियों की कला को बढावा देने के लिए एवं इनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए 80 करोड़ रुपये की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना का निर्णय लिया है। सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में नवीन जिला हथकरघा कार्यालय की स्थापना के लिए 95 लाख रुपये का प्रावधान किया है। हम कोसा उत्पादन को भी बढ़ावा देने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं। कुकुन संग्रहण से आदिवासी अंचलों के हितग्राहियों को सीधा लाभ हो, इसके लिए हमने 8 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है। शहतूत की उन्नत प्रजाति के पौधों के रोपण तथा क्रीमीपालन हेतु 527 एकड़ भूमि में प्रति हितग्राही, प्रति एकड़ कुल 5 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा

है। हम रायगढ़, सरगुजा, दुर्ग और धमतरी में नवीन खादी भंडार भी प्रारंभ करेंगे ताकि खादी के वस्त्रों के विक्रय की अधिक सुविधा उपलब्ध हो सके। हम माटी शिल्पियों को भी प्रोत्साहित करेंगे। इनके लिए नि:शुल्क चाक वितरण, ब्लेजिंग यूनिट का संचालन एवं शिल्पियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विपणन के लिये 6 करोड़ 23 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। नवीन बुनाई एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण एवं यहां बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। हम हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण, औजार उपलब्ध कराने, पुरस्कृत करने एवं आंशिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए 30 करोड़, 50 लाख 8 हजार रुपये का बजट रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिये 4 करोड रुपये का बजट में प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विमानन विभाग, देश भर में विमानन अधोसरंचना को बेहतर करने की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बड़े कार्य किये हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में विमानन अधोसरंचना का विकास करेंगे, ताकि अधिकाधिक संख्या में लोग विमानन सेवा का लाभ ले सकें। हमारी कोशिश होगी कि देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, कोलकत्ता, हैदराबाद, प्रयागराज, जबलपुर जैसे शहरों के लिए विमान सेवाओं का संचालन आरंभ हो। इसके लिए Alliance Air Company से बात की जा रही है। बस्तर क्षेत्रवासियों को दिल्ली के लिए विमान उपलब्ध कराने के लिए Alliance Air Company के दिल्ली, जबलपुर विमान सेवा का विस्तार जगदलपुर तक करने के लिए बजट में 12 करोड़ रुपये की बी.जी.एफ. सहायता का प्रावधान किया गया है। हमारी कोशिश है कि खराब मौसम में विमानों की सफल लैंडिंग हो, इसके लिए हम पी.बी.एन. एप्रोच प्रणाली की स्थापना पर कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताने हुए खुशी हो रही है कि जगदलपुर एयरपोर्ट में इस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है। (मेजों की थपथपाहट) विमानतलों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमने जगदलपुर, अंबिकापुर तथा बिलासपुर एयरपोर्ट में सुरक्षा उपकरण एवं अग्नि शमन वाहन खरीदी हेतु बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए चकरभांठा में सेना से 1012 एकड़ भूमि वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है। सेना द्वारा उनकी 286 एकड़ भूमि में एयरपोर्ट विकास की स्वीकृति जारी कर दी गई है। अंबिकापुर एयरपोर्ट को भी हम उसी श्रेणी में विकसित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट को लाईसेंस अतिशीघ्र जारी हो और यहां से विमान सेवा का संचालन प्रारंभ हो जाये। (मेजों की थपथपाहट) प्रदेश में विमानन अधोसंरचना के विकास हेतु बलरामपुर हवाई पट्टी के उन्नयन के लिये बजट में 1200 करोड़ रुपये तथा जशपुर हवाई पट्टी के उन्नयन के लिये 412 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। कोरबा में हवाई पट्टी के विकास के लिए बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आर.सी.एस. एयरपोर्ट जगदलपुर,

बिलासपुर, अंबिकापुर के नियमित संधारण व रखरखाव हेतु बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर एयरपोर्ट के कुशल संचालन व प्रबंधन के लिये एक-एक सुरक्षा अधिकारी सहित 7-7 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हमारी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बजट में इस बार 109 करोड़ रूपये की वृद्धि की है, जोकि लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि है। शासन की विभिन्न योजनाओं के मॉनिटरिंग के लिए हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल तैयार किया है। इससे हम न केवल हितग्राहियों से फीडबैक ले सकेंगे, अपितु इसके आंकड़ों के आधार पर नवीन योजनाओं का निर्माण कर सकेंगे और नीतिगत निर्णय भी ले सकेंगे। हम विभिन्न क्षेत्रों में A.I. तथा 5G को बढ़ावा देंगे। इसके लिए 5 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। पंचायतों में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए डिजिटल छत्तीसगढ़ के माध्यम से काम करेंगे। इसके लिए हमने 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। पी.एम. वाणी परियोजना के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से Wi-Fi से जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए 37 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। आई..टी. और आई..टी. आधारित सेवाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। भारत नेट परियोजना में अधोसंरचना के संचालन एवं रख-रखाव हेतु राज्य बजट से 46 करोड़ रूपये की कुल निधि का प्रावधान किया गया है। इससे गांव-गांव तक इंटरनेट और मोबाईल connectivity सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। भिलाई में Center of excellence की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 2 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। 36 आई.एन.सी. में स्टार्टअप प्रमोशन के लिए 9 करोड़ 60 रूपये का बजट रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-1 सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत चार सौ पचहत्तर करोड़ उनचालीस लाख इक्यासी हजार रूपये, मांग संख्या-2 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के अंतर्गत चौहत्तर करोड़ अठारह लाख उनतीस हजार रूपये, मांग संख्या-7 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अंतर्गत चार सौ बत्तीस करोड़ तीन लाख चवालीस हजार रूपये, मांग संख्या-12 ऊर्जा विभाग के अंतर्गत तीन हजार नौ सौ नब्बे करोड़ छप्पन लाख नवासी हजार रूपये, मांग संख्या-14 पशुपालन विभाग के अंतर्गत पांच सौ तेरह करोड़ एक लाख अठावन हजार रूपये, मांग संख्या-16 मछली पालन विभाग के अंतर्गत एक सौ छः करोड़ उन्नीस लाख उनचास हजार रूपये, मांग संख्या-25 खनिज साधन विभाग के अंतर्गत तेरह सौ चालीस करोड़ बांसठ लाख तिहत्तर हजार रूपये, मांग संख्या-32 जनसम्पर्क विभाग के अंतर्गत चार सौ तिरालीस करोड़ सतासी लाख बीस हजार रूपये, मांग संख्या-35 पुनर्वास विभाग के अंतर्गत दो करोड़ पचहत्तर लाख चालीस हजार रूपये, मांग संख्या-36 परिवहन विभाग के अंतर्गत एक सौ इक्यावन

करोड़ आठ लाख बीस हजार रूपये, मांग संख्या-56 ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत दो सौ सत्रह करोड़ इकतीस लाख चौहत्तर हजार रूपये मांग संख्या-60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के अंतर्गत दो सौ आठ करोड़ तिरपन लाख रूपये, मांग संख्या-65 विमानन विभाग के अंतर्गत दो सौ करोड़ अड़तालीस लाख छत्तीस हजार रूपये तथा मांग संख्या-71 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत दो सौ पैसठ करोड़ पचहत्तर लाख पन्चानवे हजार रूपये, इस तरह मैं सामान्य सदन से अनुरोध करता हूं कि मेरे विभागों से संबंधित कुल आठ हजार चार सौ इक्कीस करोड़ बयालीस लाख आठ हजार रूपये की अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पारित करें। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने आपसे एक आग्रह किया था। मैं आशा करता हूं। अब आगे आपके ऊपर है। मैं पशुपालन विभाग में आपको लिखकर दिया था।

श्री विष्णु देव साय :- आदरणीय धरम लाल जी ने मीसाबंदियों के लिए चिंता की है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मीसाबंदी अर्थात् लोकतंत्र सेनानियों, जो ईमरजेंसी के समय 19-19 महीने जेल में रहे, जिसके कारण उनकी परिवार की दुर्गति हो गई और अपनी सरकार में उनको सम्मान निधि देते थे, वह फिर फिर से चालू होगा। यह मैं आपको आवश्वस्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अजय चंद्राकर जी दूध बेचने वालों की बहुत चिंता कर रहे हैं तो उनकी जो मांग है, मिल्क रूट और...।

श्री अजय चंद्राकर :- मिल्क रूट और चिलिंग प्लांट विधानसभा में ।

श्री विष्णुदेव साय :- हां, चिलिंग प्लांट तो उसकी मैं घोषणा करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- मुख्यमंत्री जी, एको ठन महूं ला कर देवा साहब ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने केवल तखतपुर में एक बिजली का डिविजनल ऑफिस खोलने की मांग की है । मुझे 3 जिलों में जाना पड़ता है, पेण्ड्रा-गौरेला से अलग देखना पड़ता है । मुंगेली में अलग जाना पड़ता है और बिलासपुर में अलग तो बोल दीजिये खोलेंगे करके ।

श्री विष्णुदेव साय :- हो जायेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जी, धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या - 1, 7, 12, 14, 16, 25, 32, 35, 36, 56, 65, 71 पर कटौती पस्ताव स्वीकृत किये जायें ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

मांग संख्या - 1 **सामान्य प्रशासन के लिये -** चार सौ पचहत्तर करोड़, उनचालीस लाख, इक्यासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 2 **सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये -** चौहत्तर करोड़, अठारह लाख, उनतीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 7 **वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिये -** चार सौ बत्तीस करोड़, तीन लाख, चवालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 12 **ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय के लिये -** तीन हजार नौ सौ नब्बे करोड़, छप्पन लाख, नवासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 14 **पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिये -** पांच सौ तेरह करोड़, एक लाख, अठावन हजार रूपये,

मांग संख्या - 16 **मछली पालन के लिय -** एक सौ छः करोड़, उन्नीस लाख, उनचास हजार रूपये,

मांग संख्या - 25 **खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिये -** एक हजार तीन सौ चालीस करोड़, बांसठ लाख, तिहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 32 **जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय के लिये -** चार सौ तिरालीस करोड़, सतासी लाख, बीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 35 **पुनर्वास के लिये-** दो करोड़, पचहत्तर लाख, चालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 36 **परिवहन के लिये -** एक सौ इक्यावन करोड़, आठ लाख, बीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 56 **ग्रामोद्योग के लिये -** दो सौ सत्रह करोड़, इकतीस लाख, चौहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 60 **जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिये -** दो सौ आठ करोड़, तिरपन लाख रूपये,

मांग संख्या - 65 **विमानन विभाग के लिये -** दो सौ करोड़, अड़तालीस लाख, छतीस हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 71 **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिये -** दो सौ पैसठ करोड़, पचहत्तर लाख, पन्चानवे हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

समय :

7.29 बजे

शासकीय विधि विषय कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक- 2) विधेयक, 2024 (क्रमांक-4 सन् 2024)

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2024 (क्रमांक-4 सन् 2024) का पुर:स्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024 को 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(सायं 07 बजकर 30 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 27 फरवरी, 2024 (फाल्गुन-8 शक संवत् 1945) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की गयी)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 26 फरवरी, 2024

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं